

वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट

अंक संख्या 21



भारतीय रिज़र्व बैंक
जुलाई 2020

© भारतीय रिज़र्व बैंक

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस सामग्री के उद्धरण की अनुमति है, बशर्ते स्रोत को दर्शाया जाए।

यह प्रकाशन इंटरनेट <http://www.rbi.org.in> पर भी उपलब्ध है।

इस रिपोर्ट के फीडबैक fsu@rbi.org.in को भेजें।

वित्तीय स्थिरता इकाई, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई 400001 द्वारा प्रकाशित तथा ऐक्मे पैक्स और प्रिंट(1)प्रा.लि., ए विंग,
गाला नं.73, विरवानी इंड्रस्ट्रियल इस्टेट, गोरेगाँव ईस्ट, मुंबई – 400063 द्वारा अभिकल्पित एवं मुद्रित।

आमुख

हम सभी कोविड-19 महामारी के कारण आए अप्रत्याशित हालात में हैं, जिसने कल्पनातीत मानवीय और आर्थिक क्षति पहुंचाई है। इसके प्रसार, प्रचंडता और समाधि ने अतीव अनिश्चय पैदा कर दिया है, जिसका अनुभव हमें अपने जीवन-काल में कभी नहीं हुआ था। इसके कारण कमजोर और वंचित लोगों को खासतौर पर बहुत गंभीर जीवन हानि हुई है।

सभी देशों की सरकारों, केन्द्रीय बैंकों और अन्य लोक-एजेन्सियों ने वित्तीय दबाव का उन्मूलन करने और विश्वास बढ़ाने के लिए समन्वित प्रयास किए हैं। इन नीतिगत प्रतिक्रियाओं से वित्तीय प्रणाली और बाजारों में स्थायित्व आया है, यद्यपि परिदृश्य अत्यधिक अनिश्चित बना हुआ है।

यह रिपोर्ट वित्तीय बाजारों के कतिपय खंडों में गतिविधियों और वास्तविक क्षेत्र के क्रियाकलापों के बीच बढ़ती हुई असंबद्धता के साथ ही आई है। महामारी से ग्रस्त भारत संवृद्धि संयमन के काल-खंड में है। वैश्विक घटनाओं के प्रभावों से मांग की स्थितियों और आपूर्ति शृंखलाओं में चल रहे व्यवधान और भी प्रखर हो गए हैं। अभी हाल ही में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन से क्रमागत सुधार दिखाई देना शुरू हुआ है।

आगे जो चुनौतियां हैं उनका समाधान वित्तीय प्रणाली के दीर्घावधिक स्थायित्व को बचाए रखने के महती प्रयोजन के साथ करना होगा, जो कि बहाली को पोषित करने के लिए काफी अहम है। आगे चलकर एक बार जब हम महामारी उपरांत के चरण में प्रवेश कर जाते हैं तो हमारा फोकस विनियामक और अन्य अवसर्जनाओं में अंश-दर-अंश ढील देने पर रहेगा। वित्तीय मध्यस्थों को अपने कारोबारी मॉडलों को फिर से देखना होगा। आस्ति बाजारों को अव्यवधानित तरीके से नए दस्तूर अपनाने होंगे। प्रसंक्रमण का जोखिम यह अपेक्षा करता है कि वित्तीय प्रणाली के सभी हिस्सेदार निरंतर सतर्क रहें।

भारत में वित्तीय प्रणाली सुदृढ़ रही, इसके बावजूद, वर्तमान परिवेश में वित्तीय मध्यस्थों के लिए जरूरी है कि पूर्वसक्रिय रूप से पूंजी को बढ़ाने और समुत्थानशीलता में सुधार करने को उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। सामने आ रहे परिवेश में, यद्यपि जोखिम प्रबंधन को विवेकपूर्ण रखना होगा, तथापि जोखिम से बचने की चरम अवस्था से सभी के लिए प्रतिकूल परिणाम मिलेंगे।

सामाजिक दूरी के इस समय में सूचना प्रौद्योगिकी के प्लेटफार्मों ने अच्छा काम किया है और इन फायदों का समेकन करने की जरूरत है। साइबर सुरक्षा विषयक समझौते के लिए कोई गुंजाइश नहीं है।

कारोबार, निवेशकों और उपभोक्ताओं में भरोसा कायम करने के लिए वित्तीय क्षेत्र का स्थायित्व एक बड़ी पूर्वापेक्षा है। हमें अत्यधिक चौकन्ना रहने और ध्यान केन्द्रित रखने की जरूरत है।

शक्तिकांत दास

गवर्नर

24 जुलाई 2020

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.
आमुख	
चयनित संक्षिप्ताक्षरों की सूची	i-iii
विहंगावलोकन	1
अध्याय I : समष्टि-वित्तीय जोखिम	3
वैश्विक परिदृश्य	3
समष्टि आर्थिक गतिविधियां एवं संभावनाएं	3
पूंजी प्रवाह और विनिमय-दर उतार-चढ़ाव	6
उभरते बाजारों में जोखिम-रहित व्यापार और आस्ति-बाजार की संक्रामकता	6
पण्य बाजार स्पिलओवर	7
घरेलू समष्टि-वित्तीय गतिविधियां	8
हाल की समष्टि-आर्थिक प्रगति	8
कॉरपोरेट क्षेत्र	10
ऋण स्थगन और बैंक ऋण	11
गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता में गतिविधियां	15
आवास बाजार	19
प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण	20
अध्याय II : वित्तीय संस्थाएं: सुदृढ़ता और समुत्थानशक्ति	21
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	21
निष्पादन – परिसंपत्तियां और अर्जन	22
परिसंपत्ति गुणवत्ता और पूंजी पर्याप्तता	23
क्षेत्रवार परिसंपत्ति गुणवत्ता	24
बड़े उधारकर्ताओं की ऋण गुणवत्ता	25
जोखिम	27
आघात सहनीयता – समष्टि तनाव परीक्षण	27
संवेदनशीलता विश्लेषण	29
उपरिगामी दबाव परीक्षण – क्रेडिट, बाजार और चलनिधि जोखिम	35
उपरिगामी दबाव परीक्षण : डेरिवेटिव पोर्टफोलियो	36
अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक	37
दबाव परीक्षण – क्रेडिट जोखिम	37
दबाव परीक्षण – चलनिधि जोखिम	37
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	38
आस्ति-गुणवत्ता और पूंजी पर्याप्तता	38
कोविड-19 के बाद की प्रतिक्रिया	38
दबाव परीक्षण	39
एसएमए अनुपात विश्लेषण	39
अंतरसंबद्धता	41
वित्तीय प्रणाली का नेटवर्क	41
संक्रमण विश्लेषण	49

	पृष्ठ सं.
अध्याय III : वित्तीय क्षेत्र में विनियामकीय पहल	53
मौद्रिक नीति	53
निधीयन एवं बाजार में चलनिधि	54
आस्ति खरीद	55
ऋण सुविधा	56
समष्टिगत विवेकसम्मत नीतियां	58
घरेलू गतिविधियां	62
साइबर सुरक्षा	63
भुगतान एवं निपटान प्रणालियां	64
समाधान और वसूली	64
गेर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	66
म्यूचुअल फंड	67
पूँजी संग्रहण: इक्विटी और कॉर्पोरेट बॉन्ड	69
क्रेडिट रेटिंग	71
पण्य डेरिवेटिव बाजार	72
बीमा	74
पेंशन फंड	76
अनुबंध 1 : प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण	78
अनुबंध 2 : कार्यप्रणालियां	84
अनुबंध 3 : महत्वपूर्ण विनियामक उपाय	97

बॉक्सों की सूची

2.1	महामारी से वित्तीय संकट – नेटवर्क और संक्रमण को समझने की महत्ता	41
3.1	कोविड-19 : प्रमुख क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत जी-एसआईबी का पुनरावलोकन	60
3.2	विपत्ति जोखिम बीमा	74

चार्ट की सूची

1.1	ग्लोबल क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई)	4
1.2	विश्व मर्चेडाइज व्यापार की मात्रात्मक वृद्धि	4
1.3	ग्लोबल लीवरेज	5
1.4	उभरते बाजारों(ईएम) का लीवरेज	5
1.5	ईईएम दैनिक प्रवाह(28 दिवसीय चल औसत)	6
1.6	उभरते बाजार के बांडों पर प्रतिलाभ(वार्षिकीकृत)	7
1.7	पूंजी बाजार प्रतिलाभ और उभरते बाजार के पोर्टफोलियो प्रवाह	7
1.8	ब्रेंट फ्यूचर्स	7
1.9	निवल उधारियां(केंद्र और राज्य सरकारें) और जी-सेक 10-वर्षीय प्रतिफल	9
1.10	भारत के पण्य व्यापार में वृद्धि	9
1.11	विदेशी पोर्टफोलियो निवेश प्रवाह	9
1.12	एफपीआई प्रवाह- उभरते बाजार	10
1.13	विनिमय दर में उतार-चढ़ाव और देखी गई अस्थिरता	10
1.14	लीवरेज और लाभप्रदता- स्वामित्व द्वारा सूचीबद्ध गैर-वित्तीय फ़र्म	11
1.15	लीवरेज और लाभप्रदता- रेटिंग वाली सूचीबद्ध गैर-पीएसयू और गैर-वित्तीय फ़र्म	11
1.16	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण वृद्धि	11
1.17	उधारकर्ता श्रेणियों/उधारदाता समूहों का मार्च 2020 को थोक ऋण बकाया	12
1.18	विभिन्न उधारकर्ता श्रेणियों में थोक ऋण बकाया(पिछले तीन वर्षों से अधिक के सीएजीआर पर आधारित)	12
1.19	अधिशेष चलनिधि/एनडीटीएल- चयनित पीएसबी और बड़े पीवीबी	14
1.20	दीर्घकालिक रेटिंग गति और ऑब्लीगर्स की संख्या	14
1.21	डाउनग्रेडेड कंपनियों का वृद्धिशील जीएनपीए अनुपात	15
1.22	सरकारी प्रतिभूति/टी. बिलों/सीबीएलओ और स्प्रेड उत्पादों में म्यूचुअल फंड निवेश	16
1.23	तीन योजनाओं के रिबेस्ड निवल आस्ति मूल्यों में प्रतिनिधि उतार-चढ़ाव	16
1.24	ऋण और इक्विटी फंड का निवेशक प्रोफ़ाइल	17
1.25	लिक्विड फंड में अतिरिक्त रिटर्न	17
1.26	सीपी निर्गमन: गैर-पीएसयू ऑब्लीगर्स	18
1.27	एनसीडी निर्गमन: गैर-पीएसयू ऑब्लीगर्स	18
1.28	सीपी निर्गमन: गैर-वित्तीय गैर-पीएसयू ऑब्लीगर्स	18
1.29	एनसीडी निर्गमन: गैर-वित्तीय गैर-पीएसयू ऑब्लीगर्स	18
1.30	मकान लॉन्च और बिक्री	19

	पृष्ठ सं.	
1.31	अनबिके इन्वेंटरी और इन्वेंटरी ओवरहैंग	19
1.32	शहर-वार भारित औसत मूल्य वृद्धि	20
2.1	चुनिंदा कार्य निष्पादन संकेतक	22
2.2	चुनिंदा परिसंपत्ति गुणवत्ता संकेतक	23
2.3	क्षेत्रवार परिसंपत्ति गुणवत्ता संकेतक	25
2.4	बड़े उधारकर्ताओं के चुनिंदा परिसंपत्ति गुणवत्ता संकेतक	26
2.5	बैंकिंग स्थिरता मानचित्र	27
2.6	समष्टि आर्थिक परिदृश्य मूल्यांकन	27
2.7	एससीबी के जीएनपीए अनुपात का पूर्वानुमान	28
2.8	सीआरएआर पूर्वानुमान	28
2.9	सीईटी 1 पूंजी अनुपात की जांच	29
2.10	क्रेडिट जोखिम-आघात और परिणाम	30
2.11	बैंकों का सीआरएआर-वार वितरण	30
2.12	सीआरएआर में बदलाव की सीमा	31
2.13	ऋण संकेंद्रण जोखिम: वैयक्तिक उधारकर्ता-दबावग्रस्त अग्रिम	31
2.14	ऋण संकेंद्रण जोखिम: वैयक्तिक उधारकर्ता-एक्सपोजर	32
2.15	व्यापार बही पोर्टफोलियो : बैंक समूहवार	33
2.16	प्रतिफल वक्र (जी-सेक) और दिसंबर 2019 से अवधियों के प्रतिफलों में परिवर्तन	33
2.17	इक्विटी कीमत जोखिम	34
2.18	चलनिधि जोखिम- आघात और परिणाम	35
2.19	उपरिगामी दबाव परीक्षण-क्रेडिट और बाजार जोखिम-सीआरएआर पर प्रभाव	35
2.20	उपरिगामी दबाव परीक्षण- चलनिधि जोखिम	36
2.21	कुल डेरिवेटिव पोर्टफोलियो का निवल एमटीएम-चुनिंदा बैंक, मार्च 2020	36
2.22	दबाव परीक्षण- चुनिंदा बैंकों के डेरिवेटिव पोर्टफोलियो पर आघातों का प्रभाव- (आघात की स्थिति में निवल एमटीएम में बदलाव)	37
2.23	गैर-पीएसयू एनबीएफसी/एचएफसी-निधीकृत राशि जो बैंको पर बकाया है	40
2.24	वित्तीय प्रणाली में संस्थाओं के बीच द्विपक्षीय एक्सपोजर	42
2.25	वित्तीय प्रणाली का नेटवर्क प्लॉट, मार्च 2020	43
2.26	संस्थानों के निवल प्राप्य राशियाँ(सकारात्मक)/देय राशियाँ(नकारात्मक)	43
2.27	अंतर-बैंक बाजार	44
2.28	अंतर-बैंक बाजार में विभिन्न बैंक समूह	44
2.29	निधि आधारित अंतर-बैंक बाजार की संरचना	44
2.30	भारतीय बैंकिंग प्रणाली का नेटवर्क ढांचा(एससीबी+एसयूसीबी)- मार्च 2020	45
2.31	बैंकिंग प्रणाली(एससीबी) की संयोजकता सांख्यिकी	46
2.32	वित्तीय प्रणाली से एएमसी-एमएफ की सकल प्राप्तियाँ	46
2.33	वित्तीय प्रणाली से बीमा कंपनी की सकल प्राप्तियाँ	47

2.34	वित्तीय प्रणाली से एआईएफआई की सकल प्राप्तियों	47
2.35	वित्तीय प्रणाली को एनबीएफसी की सकल देयताएं	48
2.36	वित्तीय प्रणाली को एचएफसी की सकल देयताएं	48
2.37	समष्टि आर्थिक आघातों के बाद संक्रामक हानियां	51
3.1	निम्नवर्गीकृत कॉर्पोरेट बॉन्ड में एमएफ़ का जोखिम	68
3.2	90 से कम दिन वाले लिखतों में निधियों का अभिनियोजन	69
3.3	90 से अधिक दिन वाले लिखतों में निधियों का अभिनियोजन	69
3.4	पूंजी बाजारों में पूंजी उगाही	70
3.5	इक्विटी और ऋण निर्गमों के माध्यम से पूंजी उगाही	70
3.6	कॉर्पोरेट बॉन्ड के श्रेणी-वार निर्गमकर्ता और अभिदाता	71
3.7	श्रेणी-वार निर्गमकर्ता और अभिदाता(सार्वजनिक और निजी)	71
3.8	सूचीबद्ध कंपनियों के ऋण निर्गम-रेटिंग कार्रवाई के अनुसार-सीआरए-वार	72
3.9	प्रतिशत में वैश्विक पण्य कीमतों में परिवर्तन (20 जनवरी 2020 - 21 अप्रैल 2020)	72
3.10	घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पण्य वायदा सूचकांकों की गति	73
3.11	शेयर बाजार में पण्य डेरिवेटिव टर्नओवर की एक झलक	74

सारणियों की सूची पृष्ठ सं.

1.1	संवृद्धि अनुमान	4
1.2	अमरीकी मुद्रा बाजार	6
1.3	ब्रेंट आप्शंस ओपेन इंटररेस्ट	7
1.4	30 अप्रैल 2020 तक लिए गए ऋण स्थगन का विश्लेषण	12
1.5	भिन्न भिन्न थोक ऋण वृद्धि	13
1.6	स्वामित्व पर आधारित भिन्न भिन्न थोक ऋण वृद्धि	13
1.7	गैर-पीएसयू ऑब्लिगर्स में भिन्न भिन्न थोक ऋण वृद्धि	13
1.8	विभिन्न ट्रांजिशन ऋण समूहों में थोक ऋण वृद्धि	13
1.9	क्षेत्रगत ऋण वृद्धि	14
1.10	एससीबी के कार्यनिष्पादन पोर्टफोलियो और उनकी संरचना	15
1.11	एससीबी के मानक पोर्टफोलियो का रेटिंग संवितरण	15
1.12	कार्यनिष्पादन का रेटिंग संवितरण लेकिन एससीबी के अतिसंवेदनशील पोर्टफोलियो (एसएमए- ½)	15
1.13	म्यूचुअल फंड्स द्वारा रिसोर्स मोबिलाइजेशन में रुझान	16
1.14	गैर-वित्तीय गैर-पीएसयू ऑब्लिगर्स के सीपी और एनसीडी के निर्गम और निकट अवधि परिपक्वता	19
2.1	अच्छी गुणवत्ता की परिसंपत्तियों के उच्च हिस्से वाले शीर्ष 10 उद्योग	29
2.2	ऋण संकेंद्रण जोखिम-समूह उधारकर्ता- एक्सपोजर	32
2.3	प्रणाली स्तर सीआरएआर में गिरावट	32
2.4	एफएस पोर्टफोलियो का अवधिवार पीवी01 वितरण	33
2.5	अन्य परिचालन आय(ओओआई)-प्रतिभूति कारोबार की लाभ/(हानि)	34

2.6	एचएफटी पोर्टफोलियो का अवधिवार पीवी01 वितरण	34
2.7	ब्याज दर जोखिम- बैंक समूह- आघात और प्रभाव	34
2.8	एनबीएफसी की आस्ति गुणवत्ता और सीआरएआर	38
2.9	गैर-पीएसयू ऑब्लिगेंस को दिए गए ऋणों में एसएमए (एसएमए 1 और 2) रेटिंग श्रेणी का हिस्सा	39
2.10	रेटिंग श्रेणी का हिस्सा- गैर-पीएसयू गैर वित्तीय ऑब्लिगेंस को मानक ऋण (0 दिवसीय पूर्व देयक और एसएमए-0)	39
2.11	गैर-पीएसयू एनबीएफसी को दिए गए बैंक ऋणों की आस्ति हानि स्थिति, मार्च 2020	40
2.12	गैर-पीएसयू एचएफसी को दिए गए बैंक ऋणों की आस्ति हानि स्थिति, मार्च 2020	40
2.13	गैर-पीएसयू एनबीएफसी/एचएफसी के सीपी और एनएसडी के निर्गम और निकट अवधि परिपक्वता	41
2.14	वित्तीय प्रणाली से वित्तीय मध्यस्थों के चुनिंदा वर्गों को निवल निधीयन के स्रोत	49
2.15	बैंक की विफलता के कारण संक्रामक हानियाँ – मार्च 2020	50
2.16	गैर-पीएसयू एनबीएफसी की विफलता के कारण संक्रामक हानियाँ- मार्च 2020	50
2.17	एचएफसी की विफलता के कारण संक्रमण हानियाँ- मार्च 2020	50
3.1	कोविड-19 चलनिधि की सुविधाएं	54
3.2	ऋण सहायता संबंधी हस्तक्षेप	56
3.3	बैंकिंग क्षेत्र के लिए चुनिंदा विनियामकीय नीतिगत उपाय	59
3.4	कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया(सीआईआरपी)	65
3.5	सीआईआरपी के तहत सीडी का क्षेत्रवार वितरण	65
3.6	कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया की शुरुआत	65
3.7	31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार सीआईआरपी की अवस्था	66
3.8	परिसमापन के आदेश के साथ सीआईआरपी की समाप्ति होना	66
3.9	एनबीएफसी के तुलन-पत्र	66
3.10	एनबीएफसी क्षेत्र की देयता संरचना-दिसंबर 2019	67
3.11	अवधि के अंत में आस्तियों-बी-30 बनाम टी-30 शहर	67
3.12	2019- 20 में एसआईपी(01 अक्टूबर 2019 से मार्च 2020)	68
3.13	2019-20 में एसआईपी(अप्रैल 2020)	68
3.14	एसआईपी बनाम गैर-एसआईपी निवल अंतर्वाह(करोड़ रुपए)	68
3.15	अप्रैल 2020 में प्राथमिक बाजार में जुटाई गयी निधि	70
3.16	पण्य डेरिवेटिव में खंड-वार टर्नओवर	73
3.17	अभिदाता और एयूएम: एनपीएस और एपीवाई	77

चयनित संक्षिप्ताक्षरों की सूची

एसीबी	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति	सीआरएआर	जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात
एसीसी	अतिरिक्त क्रेडिट दावा	सीआरआईएलसी	बड़े ऋणों की जानकारी की केंद्रीय रिपोर्टिंजरि
एई	उन्नत अर्थव्यवस्थाएं	सीआरआर	आरक्षित नकदी निधि अनुपात
एएफएस	बिक्री हेतु उपलब्ध	सीएसएफ	समेकित ऋण-शोधन निधि
एआईएफआई	अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं	सीएसआईटीई	साइबर सुरक्षा और आईटी जोखिम
एमसी	आस्ति प्रबंधन कंपनियां	सीटीआरएफ	आकस्मिक मीयादी रेपो सुविधा
एमएफआई	भारतीय पारस्परिक निधि संघ	ईबीपीटी	लाभ और कर पूर्व अर्जन
एपीपी	आस्ति खरीद कार्यक्रम	यू.के.बैं.	यूरोपीय केंद्रीय बैंक
एपीवाई	अटल पेंशन योजना	ईसीएल	प्रत्याशित क्रेडिट हानि
एआरसी	आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी	ईआईएफ	यूरोपीय निवेश निधि
एयूएम	प्रबंधनाधीन आस्तियां	ईएम	उभरते बाज़ार
बीसीबीएस	बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति	ईपीएफ	कर्मचारी भविष्य निधि
बीआईएफआर	औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड	ईटीएफ	विनिमय व्यापारित निधि
बीओई	बैंक ऑफ इंग्लैंड	ईयू	यूरोपीय संघ
बीओजे	बैंक ऑफ जापान	एफबी	विदेशी बैंक
बीएसआई	बैंकिंग स्थिरता संकेतक	एफडीआई	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
सीएजीआर	चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर	एफआईआई	विदेशी संस्थागत निवेशक
सीबीएलओ	संपार्श्विकीकृत उधार लेन-देन संबंधी दायित्व	एफआई	वित्तीय संस्था
सीसीबी	प्रतिचक्रीय पूंजी बफर	एफपीआई	विदेशी पोर्टफोलियो निवेश
सीडी	कॉर्पोरेट देनदार/जमा प्रमाणपत्र	एफएसबी	वित्तीय स्थिरता बोर्ड
सर्ट-इन	भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम	एफएसडीसी	वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद
सीईटी	सामान्य इक्विटी टियर	एफएसपी	वित्तीय सेवा प्रदाता
सीआईआरपी	कॉर्पोरेट शोधन-अक्षमता समाधान प्रक्रिया	जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
कोविड-19	कोरोना वायरस रोग 2019	जीएफसी	वैश्विक वित्तीय संकट
सीपी	वाणिज्यिक पत्र	जीएफएसआर	वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट
सीपीआई	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	जीएनपीए	सकल अनर्जक आस्तियां
सीआरए	क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां	जी-एसआईबी	प्रणालीगत रूप से वैश्विक महत्वपूर्ण बैंक
		एचएफसी	आवास वित्त कंपनियां
		एचएफटी	ट्रेडिंग के लिए धारित
		एचक्यूएलए	उच्च गुणवत्ता चलनिधि आस्तियां
		आईआईएस	अंतरराष्ट्रीय बीमा पर्यवेक्षक संघ

आईबीसी	दिवाला और शोधन कोड	एनसीडी	अपरिवर्तनीय डिबेंचर
आईईए	अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी	एनसीएलटी	राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण
आईएफसीआई	भारत का औद्योगिक वित्त निगम	एनडीटीएल	निवल मांग और मीयादी देयताएं
आईआईएफ	अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थान	एनईएफटी	राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण
आईएमएफ	अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष	एनआईआई	निवल ब्याज आय
आईओएससीओ	अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन	एनआईएम	निवल ब्याज मार्जिन(निम)
आईआरएसी	आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण	एनएनपीए	निवल अनर्जक आस्तियां
आईआरएसीपी	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण	एनपीए	अनर्जक आस्ति
आईआरडीएआई	भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण	एनपीएस	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली
जेजीबी	जापानी सरकारी बॉड	एनएसएफई	वित्तीय शिक्षा हेतु राष्ट्रीय रणनीति
केसीसी	किसान क्रेडिट कार्ड	ओसी	परिचालन लेनदार
केवाईसी	अपने ग्राहक को जानिए	ओईसीडी	आर्थिक सहयोग और विकास संगठन
एलबी	बड़े उधारकर्ता	ओएमओ	खुले बाजार के परिचालन
एलसीआर	चलनिधि व्याप्ति/कवरेज अनुपात	ओओआई	अन्य परिचालन आय
एलटी	दीर्घावधि	ओपेक	पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन
एमएफ	पारस्परिक निधि(म्यूच्युअल फंड)	पीईएलटीआरओ	महामारी आपाती दीर्घावधि पुनर्वित्त परिचालन
एमएफआई	सूक्ष्म वित्त संस्था	पीईपीपी	महामारी आपाती क्रय कार्यक्रम
एमएसएमई	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	पीएफआरडीए	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
एमटीएम	बाजार भाव पर दर्शाना	पीएमएफबीवाई	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
मुद्रा	माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी	पीएमआई	क्रय प्रबंधक सूचकांक
नाबार्ड	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	पीएसबी	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
एनएवी	निवल आस्ति मूल्य	पीएसयू	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
एनबीएफसी	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	पीवीबी	निजी क्षेत्र के बैंक
एनबीएफसी-डी	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – जमाराशि स्वीकारने वाली	क्यूई	मात्रात्मक सुलभता/शिथिलता
एनबीएफसी-एनडी-एसआई	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण	क्यूआईपी	अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन
		आरईआईटी	स्थावर संपदा निवेश न्यास
		आरओए	आस्तियों पर प्रतिलाभ
		आरओई	इक्विटी पर प्रतिलाभ

आरटीजीएस	तत्काल सकल निपटान	एसयूसीबी	अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक
एससीबी	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	टीसीएस	स्रोत पर कर एकत्रित
मा.वि	मानक विचलन	टीडीएस	स्रोत पर कर कटौती
सिडबी	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	टीएफएसएमई	लघु से मध्यम आकार के उद्यमों हेतु अतिरिक्त प्रोत्साहन के साथ मीयादी निधीयन योजना
एसई	पर्यवेक्षी इकाई	टीएलटीआरओ	लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन
एसएफबी	लघु वित्त बैंक	यूसीबी	शहरी सहकारी बैंक
एसआईपी	सुनियोजित निवेश योजनाएं	यूएनसीटीएडी	संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन
एसएलआर	सांविधिक चलनिधि अनुपात	वीएआर	जोखिम पर मूल्य
एसएमए	विशेष उल्लेख खाता	डब्ल्यूईओ	विश्व आर्थिक परिदृश्य
प्र.जो.स.	प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण	डब्ल्यूटीआई	वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट
एसटी	अल्पावधि		

विहगावलोकन

समष्टि वित्तीय जोखिम

वैश्विक अर्थव्यवस्था एक तीक्ष्ण और व्यापक स्तरीय संकुचन का सामना कर रही है क्योंकि पहले ही से लड़खड़ा रही और धीमी पड़ रही समष्टि आर्थिक स्थितियों से ज्यादा असर कोविड-19 ने दिखाया। केन्द्रीय बैंकों और सरकारों द्वारा दृढ़संकल्प और व्यापक दायरे वाले क्रियाकलापों से वित्तीय बाजारों में सामान्य स्थिति का सूत्रपात हुआ है, लेकिन हालात की बहाली बहुत से कारकों पर निर्भर है, खासकर इस महामारी की प्रचंडता और कालावधि और टीके की खोज पर। विश्वव्यापी भू-राजनीतिक तनावों, अति-उत्तोलित गैर वित्तीय क्षेत्रों – खासकर सरकारों, कारोबारों और परिवारों के बीच ऋण के उच्च स्तरों – नौकरियों के छूटने और आय में कमी ने परिदृश्य पर अनिश्चितता को बढ़ा दिया है।

घरेलू अर्थव्यवस्था और बाजार

घरेलू मोर्चे पर देखें तो लॉकडाउन जनित व्यवधानों से आपूर्ति और मांग पक्ष के कारकों दोनों ही पर, ग्राहक के घटे हुए भरोसे और जोखिम से बचाव के कारण अल्पावधिक आर्थिक प्रत्याशाओं पर गंभीर कुप्रभाव पड़ा है। यद्यपि वित्तीय क्षेत्र के नियामकों और सरकार ने नीतिगत उपाय किए हैं ताकि वित्तीय मध्यस्थता प्रकाश्यों को सामान्य तौर पर सुनिश्चित किया जा सके, और समाज के वंचित वर्गों पर आई आफत को खतम किया जा सके, अल्पावधिक आर्थिक प्रत्याशाओं में गिरावट के जोखिम को कम किया जा सके। नीतिगत उपायों ने अभी तक तो वित्तीय बाजारों को जड़ता से बचाए रखा है, और चलनिधि का दबाव झेल रही वित्तीय संस्थाओं और परिवारों को राहत दी है। परिणामस्वरूप, उधार लेने की लागत में गिरावट आई और अद्रव्यता अधिमूल्य कम हुआ है। इसके बावजूद, जोखिम से बचने की धारणा और निष्प्रभ मांग ने बैंकों और गैर- बैंकों दोनों ही से अर्थव्यवस्था में वित्त के सम्पूर्ण प्रवाह को बाधित किया है।

वित्तीय संस्थाएं : प्रबलता और समुत्थानशीलता

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों(एससीबी)¹ की क्रेडिट संवृद्धि (साल-दर-साल), जो कि सन 2019-20 की पहली छमाही के

दौरान काफी कमजोर हो चुकी थी, मार्च 2020 तक लुढ़क कर 5.9 प्रतिशत पर आ गई और जून 2020 के आरंभ तक शांत पड़ी रही। यह संयमन सभी बैंक समूहों में परिव्याप्त रहा।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में पूंजी और जोखिम-भारित आस्तियों का अनुपात (सीआरएआर) सितम्बर 2019 के 15.0 प्रतिशत से घटकर मार्च 2020 में 14.8 प्रतिशत पर आ गया; इसी अवधि के दौरान गैर-निष्पादक आस्तियों (जीएनपीए) का अनुपात 9.3 प्रतिशत से घटकर 8.5 प्रतिशत पर आ गया और सकल प्रावधान औसत (पीसीआर) 61.6 प्रतिशत से सुधर कर 65.4 प्रतिशत पर आ गया।

क्रेडिट जोखिम हेतु समष्टि दबाव परीक्षण से प्रकट होता है कि आधार-रेखा परिदृश्य में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का जीएनपीए अनुपात मार्च 2020 के 8.5 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2021 तक बढ़कर 12.5 प्रतिशत हो सकता है। यदि समष्टि आर्थिक परिवेश में और बदतरी होती है तो बहुत प्रखर दबाव में यह अनुपात बढ़कर 14.7 प्रतिशत तक हो सकता है।

नेटवर्क विश्लेषण की दृष्टि से देखें तो वित्तीय प्रणाली के घटकों के बीच बकाया द्विपक्षीय जोखिम सन 2019-20 के दौरान कम हुए। अन्तर क्षेत्रकीय जोखिमों की दृष्टि से आरिष्ठ प्रबंधन कंपनियों / म्यूचुअल फंडों (एमसी-एमएफ), के बाद बीमा कंपनियों प्रणाली में सबसे बड़े निधि प्रदाताओं में रहे, जबकि गैर-बैंकिंग कंपनियों (एनबीएफसी), और इनके बाद आवासन वित्तपोषण कंपनियों सबसे बड़े निधि प्राप्तकर्ताओं में रहे। वित्तीय प्रणाली से प्राप्य राशियों के संबंध में एमसी-एमएफ में तेज गिरावट दर्ज हुई, जबकि सरकारी क्षेत्र के बैंकों और बीमा कंपनियों ने बढ़ोतरी का अनुभव किया। एनबीएफसी और एचएफसी की देय-राशियों में मामूली बढ़ोतरी हुई।

अन्तर बैंक बाजार का आकार निरंतर संकुचित होता गया, जो किसी बैंक/ एनबीएफसी/एचएफसी की प्रकल्पनागत विशिष्ट संवेदी विफलता और समष्टि आर्थिक दबाव से होने वाली हानियों के प्रति सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बेहतर पूंजीकरण सहित संक्रमणकारी जोखिम में कमी की तरफ ले गया।

¹ एससीबी, इस विश्लेषण के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक और विदेशी बैंक शामिल हैं। विश्लेषण रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षी विवरणों पर आधारित हैं जिसमें केवल उनके घरेलू परिचालनों को शामिल किया गया है।

वित्तीय क्षेत्र में विनियामक प्रयास

भारत में वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों ने मौद्रिक सहायता और विनियामक राहत के रूप में प्रयास किए हैं ताकि कोविड-19 के कुप्रभाव को कम किया जा सके। महत्वपूर्ण विनियामक कार्रवाई की गई हैं ताकि लॉकडाउन के कारण आई प्रचालनगत बाधाओं को दूर किया जा सके और साथ ही बाजार के सहभागियों द्वारा जोखिम से बचने की प्रखर धारणा को देखते हुए बाजार की सत्यनिष्ठा और सहनशीलता को बरकरार रखा जा सके। आगे चलकर अब यह फोकस समाज के बड़े हिस्से को महामारी से अप्रभावी रखने से हटकर महामारी उपरांत अनुसहायता और समर्थन पैकेजों में अंश-दर-अंश ढील देने पर रहेगा, तो चुनौती यही रहेगी कि बाजारों और वित्तीय मध्यस्थों की सेहत पर असर डाले बिना सामान्य स्थिति बन सके।

प्रणालीगत जोखिम का आकलन

भारतीय वित्तीय प्रणाली, आर्थिक प्रत्याशाओं में गिरावट के महत्वपूर्ण जोखिम के बावजूद, सुस्थिर बनी हुई है। नवीनतम प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण के अनुसार, सभी प्रमुख जोखिम समूहों, यथा - वैश्विक जोखिम, समष्टि आर्थिक हालात के बारे में जोखिम प्रत्याशाएं, वित्तीय बाजार के जोखिम और संस्थागत स्थितियों को 'उच्च' के तौर पर माना गया, जो वित्तीय प्रणाली को प्रभावित करती हैं। समष्टि आर्थिक जोखिमों में घरेलू संवृद्धि के लिए जोखिम और राजकोषीय व्यवस्था कार्यों को 'अति उच्च' के तौर पर माना गया, जबकि पूंजी प्रवाह की प्रतिलोमता/धीमेपन, कार्पोरेट क्षेत्र की कमजोरियों, भूसम्पदा कीमतों और परिवारों की बचतों के कारण होने वाले जोखिमों को 'उच्च' के तौर पर माना गया।

अध्याय I समष्टि-वित्तीय जोखिम

कोविड-19 महामारी के प्रकोप का प्रभाव संपूर्ण विश्व पर अप्रत्याशित है और इससे जन और जीवन दोनों तबाह हो रहे हैं। सरकारी प्राधिकारियों ने इसके प्रसार को नियंत्रित करने तथा इसके हानिकारक परिणामों को दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई की है। भारत में राजकोषीय एवं मौद्रिक प्रोत्साहन मिल जाने से वित्तीय बाजार काफी हद तक स्थिर बने रहे हैं। बैंक क्रेडिट का धीमापन जोखिम विमुखता का स्पष्ट संकेत देता है। विदेशी मुद्रा के पर्याप्त भंडार ने इस स्थिति को बफर प्रदान किया है। जो भी हो, वित्तीय बाजार की आशावादिता और वास्तविक अर्थव्यवस्था के कमजोर होने के बीच कुछ तो छूट रहा है। इस महामारी में वित्तीय भेद्यता को जहां अत्यधिक तीव्र कर देने का दम है, वहीं भयंकर आर्थिक गिरावट की हालत में कारपोरेट्स एवं गृहस्थों का बोझ बढ़ा देने का भी है। इसके अलावा, भारत की विकास संबंधी कार्यनीति की विशिष्ट अपेक्षाओं का अनुकूलन करते हुए विश्व की सर्वोत्तम प्रथाओं एवं मानकों के अनुरूप वित्तीय क्षेत्र के सुधार की पुनः शुरुआत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

प्रस्तावना

1.1 कोविड-19 महामारी ने विश्व की आर्थिक गतिविधियों को ठप्प सा कर दिया है, और जिस प्रकार से यह संपूर्ण विश्व को प्रभावित कर रही है तथा जान व माल का नुकसान हो रहा है, वह सब अत्यधिक अप्रत्याशित है। सरकारी प्राधिकारियों ने भी मौद्रिक एवं राजकोषीय सहायता से बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई की है और इसके प्रकोप एवं हानिकारक परिणामों को रोकने के लिए स्वास्थ्य चिकित्सा संबंधी एवं प्रशासनिक उपाय किए हैं। नीतिगत जवाबी कार्रवाई का प्रमुख उद्देश्य यह है कि वित्तीय बाजार को फ्रीज होने बचाया जाए, वित्तीय मध्यस्थताओं को दबावरहित एवं उन्हें सामान्य कार्यशील हालत में रखा जा सके, और जीवनदायिनी वित्त प्रवाह को जारी रखा जाए, खासतौर से उनको जो प्रभावित हैं तथा जिन्हें यह सुविधा नहीं मिल पा रही है, साथ ही वित्तीय स्थिरता को कायम रखते हुए सुदृढ़, वहनीय तथा समावेशी संवृद्धि को बनाए रखा जा सके।

1.2 इस परिदृश्य में, इस अध्याय में वैश्विक मैक्रो-इकानामिक एवं वित्तीय बाजार की घटनाओं का खाका प्रस्तुत किया गया है। भाग 1.1 में महामारी द्वारा उत्पन्न चुनौतियों जैसे सीमापार प्रवाहों का अचानक रुक जाना/विपरीत हो जाना, आस्तित्व बाजार की अस्थिरता तथा संक्रामकता, एवं पण्य बाजार की भेद्यता का परीक्षण किया गया है। भाग 1.2 में कारपोरेट क्षेत्र की समुत्थानशीलता तथा बैंक एवं गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता में उभरते समीकरणों पर चर्चा की गई है। अध्याय के अंत में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर किए जाने वाले

प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण में प्राप्त प्रतिक्रियाओं का उल्लेख किया गया है।

1.1 वैश्विक परिदृश्य

1.1.1 मैक्रोइकोनॉमिक प्रगति एवं संभावनाएं

1.3 कोविड-19 से होने वाले आसन्न विवर्तनिक (टेकटोनिक) बदलाव का जो पहला संकेत मिल सकता था वह जनवरी 2020 में वैश्विक वित्तीय बाजार में बढ़ती हुई अस्थिरता में साफ नज़र आया जिसमें अफरा-तफरी की हालत में अपबिक्री की गई, उन्नत और उभरती जैसी सभी अर्थव्यवस्थाएं सुरक्षित स्थानों पर जाने लगीं एवं उनके इक्विटी बाजार में सभी स्तरों पर संपदा का क्षरण होने लगा। शासकीय बांड के प्रतिफल सर्वाधिक रूप से गिर गए और चलनिधि के दबाव ने बाजार को स्थिर आय वाला बनाए रखने के प्रति चुनौती पैदा कर दी। वस्तुओं के मूल्यों में हुए उतार-चढ़ाव से मांग में भी प्रारंभिक कमजोरी देखी गई, खासतौर से कच्चे तेल की कीमतों में, हालांकि इसकी बाधित आपूर्ति ने खाद्यान्न के मूल्यों को बढ़ा देने का दबाव बनाए रखा। यह महामारी जिस विस्फोटक रूप से और जिस गति से फैली, उसके चलते लॉकडाउन और सामाजिक-दूरी ने 200 देशों में आर्थिक गतिविधियों को ठप्प कर दिया, ये रिपोर्ट प्रेस में जाने की तारीख तक 14.3 मिलियन लोग संक्रमित हो चुके थे तथा 0.6 मिलियन लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की जीडीपी वृद्धि में तीव्र गिरावट हुई थी जो 2020 की पहली तिमाही में (-) 3.4 प्रतिशत से लेकर (-) 14.2 प्रतिशत तक थी, और उभरते बाजार की अर्थव्यवस्थाओं में यह गिरावट (-) 2.9 प्रतिशत से (-) 6.8 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष आधार पर) थी जो आगे चलकर और

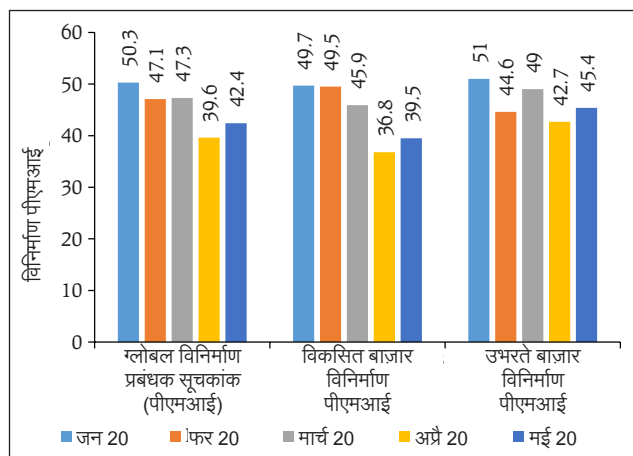
भी खराब हो गई और विनिर्माण क्षेत्र धराशायी हो गया जैसाकि क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) से ज्ञात होता है और जो ग्राफ के गिरावट वाले क्षेत्र में लुढ़क गया। हालांकि उत्पादन में गिरावट की जो स्थिति थी, अप्रैल 2020 के बाद नई स्थितियां उत्पन्न हुईं एवं रोजगार बेहतर हुए, फिर भी वह 22 वर्ष के सर्वेक्षण के इतिहास में सबसे न्यूनतम स्तर पर दर्ज की गई थी (चार्ट 1.1)। कच्चे तेल की कीमतें मार्च और अप्रैल के उत्तरार्ध में तेजी से गिरने के बाद संभली हैं; ब्रेंट कच्चा तेल 30 जून, 2020 को 40 अमरीकी डालर प्रति बैरल की कीमत पर ट्रेड किया गया था, जो अप्रैल 2020 के न्यून स्तर से अधिक था।

1.4 इस बीच, जून, 2020 में आयोजित व्यापार और विकास से संबंधित यूनाइटेड नेशंस (यूएनसीटीएडी) के सम्मेलन में वैश्विक व्यापार मूल्य के हिसाब से 2020 की पहली तिमाही में 7.27 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) घटा है और यह उम्मीद की जाती है कि दूसरी तिमाही में इसमें और ज्यादा गिरावट आएगी (चार्ट 1.2)।

1.5 अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने इस बेसलाइन की मान्यता के आधार पर कि 2020 की दूसरी छमाही में गतिविधियों में धीरे-धीरे बहाली शुरू हो जाएगी, यह अनुमान दिया है कि 2020 में विश्व का उत्पादन 4.9 प्रतिशत घट जाएगा (सारणी 1.1)। ओईसीडी ने “दोहरी – मार” पड़ने जैसे हालात का अनुमान दिया है जिसमें संक्रमण की दूसरी लहर 2020 के बाद के हिस्से में फैलेगी; इन हालात में वैश्विक अर्थव्यवस्था 2020 में 7.6 प्रतिशत तक गिर सकती है।

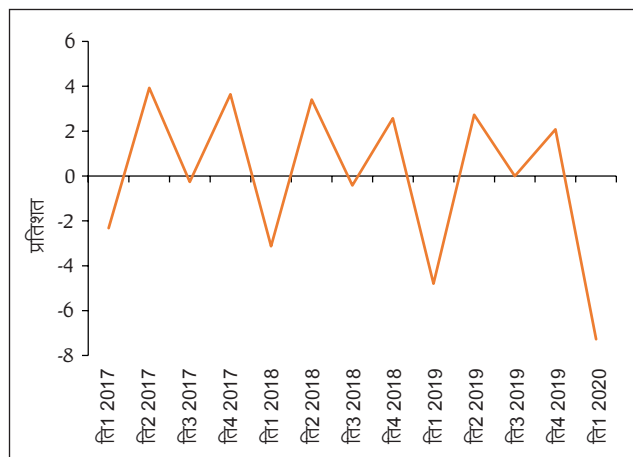
1.6 इस पृष्ठभूमि में, स्विफ्ट और केंद्रीय बैंक के अप्रत्याशित उपायों से आस्तियों के मूल्य बहाल हुए हैं, क्रेडिट-स्प्रेड अपने पहले के शीर्ष स्तर से काफी गट गए हैं और उभरते बाजारों के प्रति निवेशकों की भावनाओं को बेहतर बनाने में मदद मिली है। लेकिन, जबरदस्त आर्थिक गिरावट की स्थिति में यह महामारी कार्पोरेट एवं गृहस्थों के कर्ज भार बढ़ाने के साथ वित्तीय भेद्यता को तीव्र कर सकती है। पूरे विश्व में बैंक आस्तियों के अशोध्य होने की घटनाओं से गुजर रहे हैं, इसलिए उन्होंने समझदारी से काम लेते हुए इसके लिए प्रावधान सामान्य रूप से बढ़ा दिए हैं। आस्तियों की निष्क्रियता का बैंकिंग क्षेत्र की पूंजी और लाभप्रदता पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए बैंकिंग पर्यवेक्षण से संबंधित बासेल समिति ने फारबियरेंस/ऋण अधिस्थगन जैसी कार्यनीतियों को तब तक अपनाए जाने का समर्थन किया है जब तक पर्यवेक्षक यह सुनिश्चित करते रहें कि बैंक उदारता का उपयोग समझदारी कर रहे हैं और उनका प्रकटीकरण विधिवत किया जा रहा है ताकि बाजार के सहभागी बैंकों द्वारा की जा रही

चार्ट 1.1: ग्लोबल क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई)



स्रोत: ब्लूमबर्ग

चार्ट 1.2: विश्व मर्चेडाइज व्यापार की मात्रात्मक वृद्धि (तिमाही दर तिमाही)



स्रोत: व्यापार और विकास पर यूनाइटेड नेशंस सम्मेलन (अंकटाड)

सारणी 1.1: संवृद्धि अनुमान

	2019	2020*	2021*
विश्व उत्पादन	2.9	(-4.9)	5.4
विकसित अर्थव्यवस्थाएं	1.7	(-8.0)	4.8
उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं	3.7	(-3.0)	5.9

टिप्पणी : अनुमान*

स्रोत: वर्ल्ड इकॉनामिक आउटलुक (डबल्यूओ) अद्यतन: जून, 2020, आईएमएफ

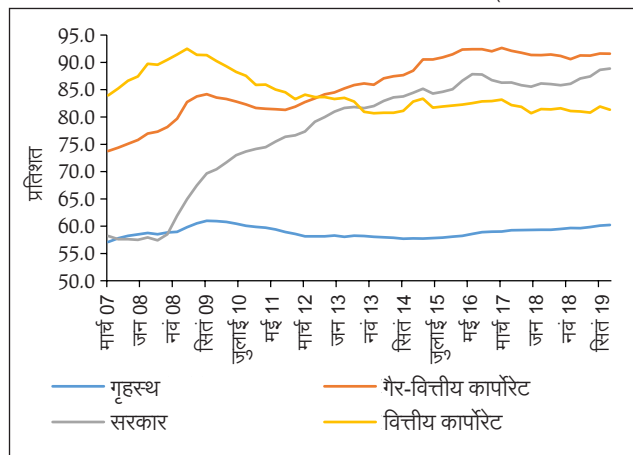
इस प्रकार की कार्रवाई का मूल्यांकन कर सकें और उससे पड़ने वाले प्रभाव के औचित्य को समझ सकें। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी हालिया जून 2020 की वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में यह चेतावनी दी है कि विश्व की वित्तीय स्थिति बेसलाइन परिदृश्य से कहीं ज्यादा कठोर बन सकती है। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि 'स्विफ्ट' के चलते हाल के समय में वित्तीय स्थितियों का सहज बनना, साहसिक और अप्रत्याशित नीतिगत उपायों ने आस्तियों के मूल्यों को बढ़ा दिया है। फलस्वरूप, वित्तीय बाजार की आशावादिता तथा वास्तविक अर्थव्यवस्था की कमजोरी दोनों एक-दूसरे से जुड़ी नज़र नहीं आ रही हैं, क्योंकि भावनागत जोखिम कभी बढ़ जाता है तो कभी घट जाता है। इससे अन्य वित्तीय प्रणाली की भेद्यता का पर्दाफाश होता है जैसे कुछेक अर्थव्यवस्थाओं जो पुनर्वित्तपोषण के जोखिम से जूझ रही हैं, उनकी बाजार तक पहुंच को सीमित कर दिया जाना। राष्ट्र के प्राधिकारियों को यह सूचित किया गया है कि वे अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने और दुबारा बहाली की कार्रवाई करते समय वित्तीय भेद्यता पर कड़ी निगरानी रखें तथा वित्तीय स्थिरता की रक्षा करें।

1.7 गंभीर स्वरूप की चिंताओं में उल्लेखनीय चिंता यह है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) के समय से कहीं ज्यादा इस समय लीवरेज्ड है। सभी क्षेत्रों में वैश्विक कर्ज बढ़ गया है और 2019 की चौथी तिमाही में 255 ट्रिलियन अमरीकी डालर हो गया है। यह सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 322 प्रतिशत से भी अधिक है (चार्ट 1.3)। वैश्विक कर्ज इस समय वित्तीय संकट के समय के कर्ज से तकरीबन 40 प्रतिशतता बिंदु (87 ट्रिलियन अमरीकी डालर) अधिक है। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान (आईआईएफ) ने सावधान किया है कि यदि सरकारी निवल उधार वर्ष 2019 के स्तर से दो गुना हो जाता है और वैश्विक आर्थिक गतिविधियों में 3 प्रतिशत की गिरावट आ जाती है (सांकेतिक रूप से – आईएमएफ की अनुमानों की अपेक्षा धीमे परिणाम), तो विश्व का कर्ज 2020 में जीडीपी के 322 प्रतिशत से बढ़कर 342 प्रतिशत से अधिक का हो जाएगा। अतः कोविड-19 के बाद की दुनिया में चुनौती इस बात की होगी कि किस तरकीब से बिना किसी रुकावट के “बॉल को वापस अपने खाने में” लाया जा सके – वास्तविक अर्थव्यवस्था के जिम्मे वित्तीय दावों को किस तरह इक्विटी में परिवर्तित किया जा सके।

1.8 वैश्विक वित्तीय संकट के समय से लेकर अब तक उभरते बाजारों (ईएम) की वित्तीय देयताएं काफी बढ़ गई हैं; 30 प्रमुख

चार्ट 1.3 : ग्लोबल लीवरेज

(जीडीपी का प्रतिशत)

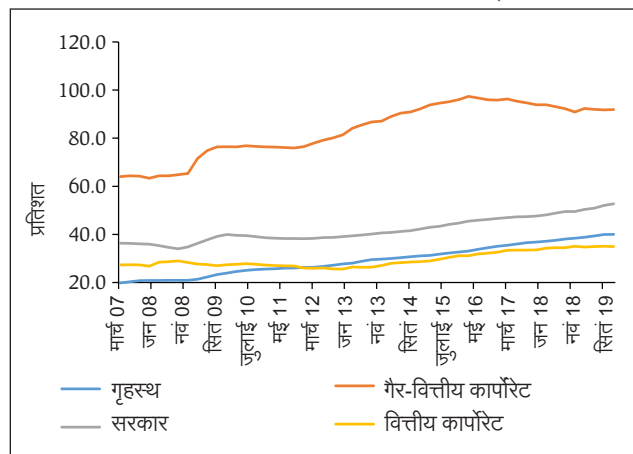


स्रोत: इंटरनेशनल इस्टीमेट्स ऑफ फाइनेंस (आईएआईएफ)

ईएम (ईएम-30) का कर्ज 2007 की चौथी तिमाही के 22 ट्रिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 2019 की चौथी तिमाही में 71 ट्रिलियन अमरीकी डालर हो गया है। इसके अलावा, जीडीपी के अनुपात की तुलना में उनका लीवरेज 2007 की चौथी तिमाही के 147 प्रतिशत से बढ़कर इस अवधि में 220 प्रतिशत हो गया है (चार्ट 1.4)। ईएम-30 का विदेशी मुद्रा कर्ज 2017 की चौथी तिमाही में बढ़कर 5.3 ट्रिलियन अमरीकी डालर हो गया था जिसमें से उन्हें दिसंबर 2020 तक 0.73 ट्रिलियन अमरीकी डालर के पुनर्वित्त की आवश्यकता होगी। चीन को छोड़कर ईएम का विदेश मुद्रा कर्ज वित्तीय क्षेत्र के बाहर 20 प्रतिशत था। वर्ष 2020 के अंत तक 20 ट्रिलियन अमरीकी डालर से अधिक के ग्लोबल बांडों और ऋणों की चुकौती देय हो जाएगी, जिसमें से ईएम का हिस्सा 4.3 ट्रिलियन अमरीकी डालर होगा।

चार्ट 1.4 : उभरते बाजारों (ईएम) का लीवरेज

(जीडीपी का प्रतिशत)



स्रोत: इंटरनेशनल इस्टीमेट्स ऑफ फाइनेंस (आईएआईएफ)

1.1.2 पूंजी प्रवाह और विनिमय-दर उतार-चढ़ाव

1.9 कोविड-19 का प्रकोप शुरू होने से लेकर अब तक संचयी पूंजी बहिर्वाह, जीएफसी तथा डार्फ-स्ट्रेस की घटनाओं जैसे टेपर टैंट्रम 2013 के समय के बहिर्वाह से पहले ही काफी अधिक हैं (चार्ट 1.5); हालांकि भावनाएं वापस हो रही हैं, पूंजी का प्रवाह वापस ईएमई की ओर होने लगा है, अलबत्ता उनमें काफी विभेद है और उनका पुनः आबंटन हुआ है। पूंजी प्रवाह में किसी भी प्रकार का अचानक अवरोध ईएम को उच्च जोखिम में डाल देगा क्योंकि उन्हें आसन्न बाह्य कर्ज परिशोधन की स्थिति में बाहरी वित्तपोषण की अत्यधिक आवश्यकता है। वस्तुओं का निर्यात करने वाले उभरते बाजारों को व्यापार की शर्तों में भारी नुकसान उठाना पड़ेगा।

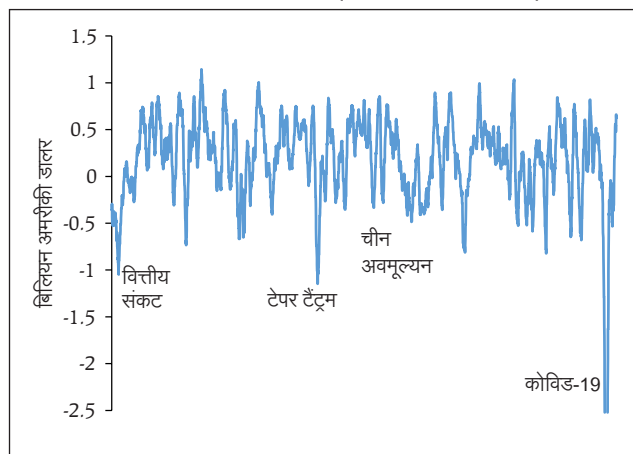
1.10 ग्लोबल बांड मार्केट में मूल्यों का निर्धारण यूरोप में लंबे समय से चली आ रही आर्थिक मंदी तथा महामारी लॉकडाउन के बाद अमरीका में आई हलकी बहाली के तहत किया जा रहा है। बाजार की भावनाओं में अंतर्निहित असहजता में इतना दम है कि वह ईएम में आस्तियों के मूल्यों तथा विनिमय-दर में अस्थिरता पैदा कर सकता है, साथ ही इसका प्रभाव वास्तविक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है।

1.11 वैश्विक वित्तीय परिदृश्य पर इस बात का भय मंडरा रहा है कि डालर की कमी हो जाएगी और आर्थिक बहाली बाधित हो जाएगी। अक्टूबर 2019 की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में इस बात को रेखांकित किया गया था कि जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा प्रतिफल की खोज में सीमापार के पोर्टफोलियो में आबंटन को बढ़ाया गया है और इस प्रकार की आस्तियों का अधिकांश हिस्सा अमरीकी डालर में है। इस प्रकार से सीमापार के पोर्टफोलियो आबंटन से करेंसी और ड्यूरेशन दोनों में असंतुलन पैदा हो जाता है, जिससे जोखिम के फैलने का एक और चैनल खुल जाता है। रिपोर्ट में यह भी चेतावनी दी गई थी कि कम किंतु लंबे समय तक मिलने वाला प्रतिफल संस्थागत निवेशकों को इस बात के लिए उद्यत करेगा कि वे अधिक जोखिमपूर्ण र अचलनिधीय निवेश करें ताकि उनके लक्ष्य किए गए प्रतिलाभ अर्जित किए जा सकें। इस प्रकार से जोखिम उठाने से निवेश फंडों, पेंशन फंड, तथा जीवन-बीमाकर्ताओं में वित्तीय भेद्यता को बढ़ावा मिलेगा जिसका वित्तीय स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। चलायमान-मुद्रा जैसी देयताओं (सारणी 1.2) के कारण फंडिंग बाजार पर पड़े हालिया दबाव के अमरीकी फेडरल रिज़र्व (फेड) को रेपो और स्वैप के रूप में हस्तक्षेप करना पड़ा है।

1.1.3 उभरते बाजारों में जोखिम-रहित व्यापार और आस्ति-बाजार की संक्रामकता

1.12 ईएम के स्थानीय करेंसी बांड पोर्टफोलियो के प्रतिलाभ सितंबर 2018 के स्तर की अपेक्षा कहीं अधिक थे, जिसका

चार्ट 1.5: ईएम दैनिक प्रवाह (28 दिवसीय चल औसत)



टिप्पणी : 22 जून, 2020 की स्थिति
स्रोत: आईआईएफ

सारणी : 1.2 अमरीकी मुद्रा बाजार

	बकाया/कुल आस्तियां (बिलियन अमरीकी डालर)	संवृद्धि, ति4: 2018, ति4: 2019 (प्रतिशत)	औसत वार्षिक संवृद्धि (प्रतिशत)
कुल चलायमान मुद्रा जैसी देयताएं*	15,517	9.80	4.00
गैर-बीमाकृत जमा राशियां	5,173	6.60	10.60
पुनःक्रय करार	3,998	12.50	5.90
घरेलू मुद्रा बाजार निधि**	3,604	18.60	4.30
कमर्शियल पेपर	1,045	4.90	2.10
प्रतिभूति उधार देना***	578	(-)3.70	5.60
बांड म्युचुअल फंड	4,440	16.70	9.00

टिप्पणी : ये आंकड़े 2019 की चौथी तिमाही तक के हैं। संवृद्धि दरों की माप वर्ष की चौथी तिमाही से तत्काल पूर्ववर्ती अवधि के अंतिम वर्ष की चौथी तिमाही से होते हुए की गई है।
* औसत वार्षिक संवृद्धि 2003 की चौथी तिमाही से 2019 की तीसरी तिमाही तक
** औसत वार्षिक संवृद्धि 2001 की चौथी तिमाही से 2019 की तीसरी तिमाही तक
*** औसत वार्षिक संवृद्धि 2000 की चौथी तिमाही से 2019 की तीसरी तिमाही तक
स्रोत: वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, मई 2020। फेडरल रिज़र्व सिस्टम बोर्ड आफ गवर्नर्स। <https://www.federalreserve.gov/publications/files/financial-stability-report-20200515.pdf> पर उपलब्ध

कारण असाधारण रूप से मौद्रिक नीति का प्रोत्साहन दिया जाना था (चार्ट 1.5)। हाल के समय में अमरीकी डालर के प्रतिलाभ स्थानीय करेंसी के प्रतिलाभ से कम रहे हैं, जिससे हेजिंग-लागतें बढ़ गई हैं।

1.13 कुछ इसी प्रकार का पैटर्न इक्विटी बाज़ार में अपनाया जा रहा है (चार्ट 1.7)। लेकिन, करेंसी-दर के उतार-चढ़ाव और ईएम प्रवाहों (ईएम-ईटीएफ अमरीकी डालर प्रतिलाभ और ईएम इक्विटी प्रवाहों में तकरीबन एक-के बाद एक करेसपोंडेंट में दिखाई देता है) के बीच फीडबैक-लूप, ईएम करेंसी मूल्यहास सहित ईएम आस्ति अपविक्रय के सभी स्तरों से परिलक्षित होता है। सूचकांक का समावेश विशेष प्रकार के जोखिम के लिए बफर सिद्ध हो सकता है, किंतु इससे यह भी संभव है कि जब विश्व में स्पिलओवर की घटनाएं हो रही हों तो ईएम आस्तियों के अपविक्रय को देखते हुए करेंसियों में अस्थिरता पैदा होना अवांछित है।

1.1.14 पण्य बाज़ार स्पिलओवर

1.14 इसी बीच, मांग के तेज़ी से कम हो जाने से ब्रेंट-फ्यूचर्स की फार्वर्ड-वक्र पश्चगति के बजाय कैटेंगो में तबदील हो गई है (चार्ट 1.8)। 21 अप्रैल 2020 को वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डबल्यूटीआई) क्यूड फ्यूचर्स के ऋणात्मक मूल्य की रीडिंग तंग भंडारण स्थिति की ओर इशारा करती है, लेकिन साथ ही बेंचमार्क रोलओवर संबंधी तकनीकी स्थिति की ओर भी संकेत करती है।

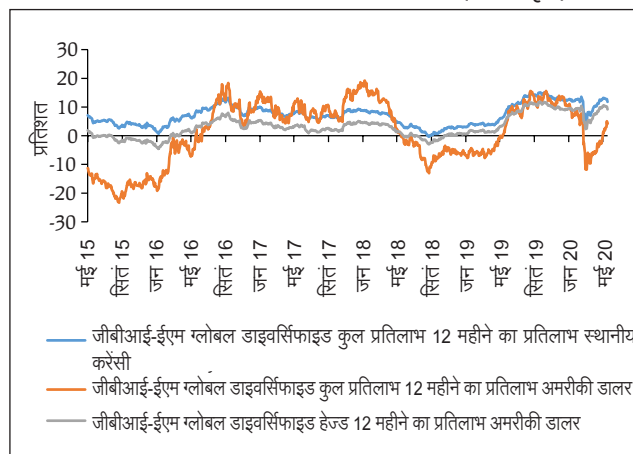
1.15 ब्रेंट आप्शंस (पुट और काल दोनों) में खुली दिलचस्पी, जहां 40 अमरीकी डालर से अधिक की काल स्ट्राइक दर 20 अमरीकी डालर से कम की पुट स्ट्राइक दर पर वर्चस्व बनाए हुए हैं, से आशय है कि बाज़ार ने आगे चलकर कच्चे तेल की ऐसी न्यून कीमतों को निश्चित रूप से भुनाया होगा। (सारणी 1.3)।

सारणी 1.3 : ब्रेंट आप्शंस ओपेन इंटररेस्ट (26 जून, 2020 की स्थिति)

	संविदाएं समाप्त होने की तारीख			
	सितं 20	अक्तूबर 20	नवंबर 20	दिसं 20
पुट्स, अमरीकी डालर 0-20 की स्ट्राइक के बीच	13.078	4.831	1.023	34.037
काल, अमरीकी डालर 40 की स्ट्राइक से अधिक	2,59,200	60,378	25,895	4,54,012

स्रोत: ब्लूमबर्ग

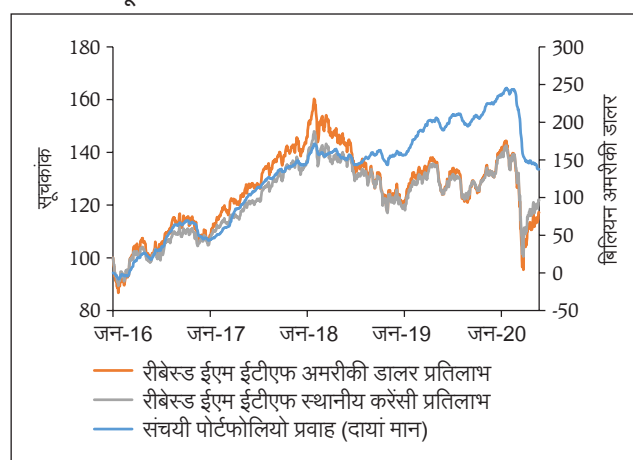
चार्ट 1.6 : उभरते बाज़ार के बांडों पर प्रतिलाभ (वार्षिकीकृत)



स्रोत: जेपी मार्गन

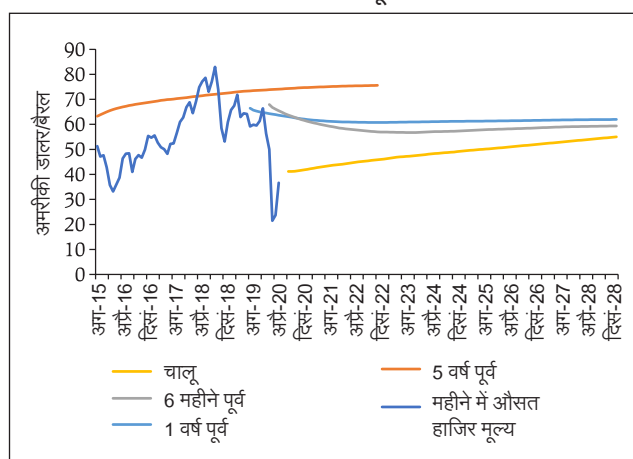
टिप्पणी : ये जानकारी ऐसे स्रोतों से ली गई है जिसे भरोसेमंद माना जा सकता है, किंतु जे पी मार्गन इसकी संपूर्णता या सटीकता का वादा नहीं करता है। इस सूचकांक का इस्तेमाल अनुमति प्राप्त करके किया गया है। जेपी मार्गन से लिखित पूर्व अनुमोदन के बिना इसे कापी, इस्तेमाल या वितरण नहीं किया गया होता। कापीराइट: 2020, जेपी मार्गन चैस एंड कं. समस्त अधिकार

चार्ट 1.7 : पूंजी बाज़ार प्रतिलाभ और उभरते बाज़ार के पोर्टफोलियो प्रवाह



स्रोत: ब्लूमबर्ग और आईआईएफ

चार्ट 1.8 : ब्रेंट फ्यूचर्स



टिप्पणी: 26 जून, 2020 की स्थिति के अनुसार

स्रोत: ब्लूमबर्ग

1.16 अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) ने अपनी जून 2020 की तेल बाजार रिपोर्ट में यह अनुमान प्रकट किया है कि विश्व में तेल की मांग 8.1 मिलियन बैरल प्रतिदिन कम हो जाएगी, जो इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट होगी और बाद में इसमें सुधार होगा जो 2021 में 5.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन हो जाएगी। चीन में तेल की मांग मार्च-अप्रैल में तेजी से बहाल हो गई है और भारत में इसकी मांग मई में तीव्र रूप से बढ़ गई थी। आपूर्ति पक्ष को देखें तो पेट्रोलियम निर्यात राष्ट्रों प्लस (ओपेक प्लस) से उत्पादन में अत्यधिक कटौती तथा अन्य गैर-ओपेक उत्पादनकर्ताओं से आपूर्ति में तीव्र गिरावट के चलते विश्व में तेल उत्पादन मई में 12 मिलियन बैरल प्रतिदिन की जबरदस्त कमी हुई थी। बाजार को आगे और भी पुनः संतुलित करने की दृष्टि से ओपेक प्लस ने 6 जून को यह निर्णय लिया था कि जुलाई के दौरान उनकी यह ऐतिहासिक उत्पादन कटौती लगभग 10 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक जारी रहेगी।

1.17 औद्योगिक क्षेत्र में धातुओं की मांग में काफी कमी हुई और उनके मूल्य 2020 की शुरुआत में काफी कम थे, हालांकि इसमें हुई गिरावट कच्चे तेल में आई गिरावट जैसी नहीं थी। तेल की तरह नहीं, जिसमें हाजिर बाजार मूल्यों को काफी हद तक अल्पकाल में इन्वेंट्री ओवरहैंग के कारण प्रभावित होने की संभावना रहती है, औद्योगिक धातुओं के मूल्यों का पुनः संतुलन इन्वेंट्री मामलों के प्रति संवेदनशील नहीं होते हैं, अर्थात् यदि मांग पुनः संतुलित हो जाती है तो मूल्यों में काफी तेजी से बहाली पैदा हो सकती है।

1.18 वस्तुओं के मूल्यों से पड़ने वाला प्रतिकूल आघात विभिन्न चैनबलों के माध्यम से वित्तीय अस्थिरता पैदा कर सकता है। पहला, वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट से वस्तुओं का निर्यात करने वाले देशों की अपने अंतरराष्ट्रीय कर्ज के दायित्व को पूरा करने की क्षमता बिगड़ सकती है, जिससे वे जोखिम-रहित तरीकों को अपनाने की कोशिश करेंगे और कुल मिलाकर उभरते बाजारों के पूंजी प्रवाह प्रभावित होंगे। दूसरा, बजटीय प्रस्ताव में कमी हो जाने से यह हो सकता है कि कुछ वस्तुओं के निर्यातकर्ता अपनी अंतरराष्ट्रीय राशियों को आहरित कर लें जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बैंकिंग क्षेत्र की चलनिधि को अत्यधिक नुकसान पहुंच सकता है।

1.2 घरेलू समष्टि वित्तीय गतिविधियां

आठ तिमाहियों की लंबी गिरावट उपरांत 2019-20 में भारत में जीडीपी संवृद्धि, जीएफसी से अल्पकालिक मंदी में अपने निम्नतम स्तर 4.2 प्रतिशत पर पहुंच गई, इसके साथ ही 2019-20 की चौथी तिमाही में संवृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) 3.1 प्रतिशत रही

जो वर्तमान जीडीपी क्रम (2011-12 पर आधारित) के इतिहास में सबसे कम है।

1.2.1 हाल की समष्टि-आर्थिक प्रगति

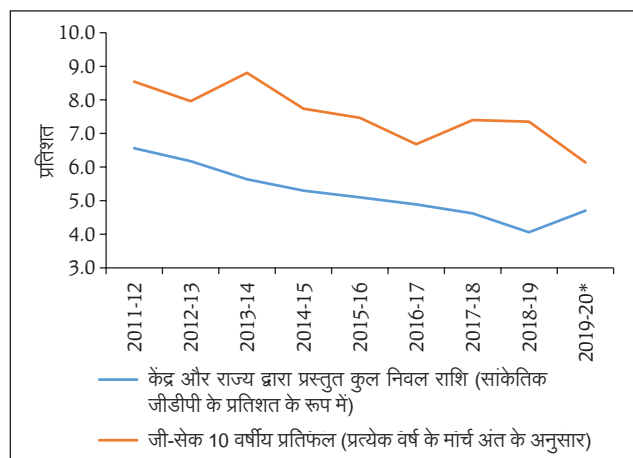
1.20 उच्च आवृत्ति संकेतक इस बात की ओर इशारा करते हैं कि मार्च 2020 के प्रारंभ से ही शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र के सभी खंडों में मांग में तीव्र गिरावट हो गई थी। वस्तुतः, घरेलू स्तर पर आर्थिक गतिविधियां अप्रैल 2020 में तो ठप्प पड़ गई थीं, हालांकि कई क्षेत्रों में यह गिरावट मई 2020 से उतनी विकराल नहीं थी। जून 2020 के लिए प्राप्त होने वाले प्रारंभिक आंकड़ों से पता चलता है कि स्थिरांक सी स्थिति पैदा हो गई थी जो कोविड-19 के स्तर से काफी नीचे थी। लेकिन कृषि और संबद्ध गतिविधियों में लगातार समुत्थानशीलता दिखाई दी क्योंकि इस बार उत्पादन सबसे अधिक हुआ था और चावल एवं गेहूं का भंडार पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था। इस बात के पूर्वानुमान ने कि वर्ष 2020-21 में सामान्य से अधिक वर्षा होगी, भी कृषि के लिए अच्छा शकुन साबित हुआ। पीएमआई (विनिर्माण) भी लगातार बढ़ता रहा जो अप्रैल के 27.4 से बढ़कर मई में 30.8 और आगे बढ़कर जून में 47.2 हो गया था। संपूर्ण राजकोषीय वर्ष में अभी भी माहमारी की अवधि को लेकर अत्यधिक अनिश्चितता बनी हुई है। इस प्रकार, संवृद्धि के प्रति जोखिमों के बढ़ने का खतरा बना रहेगा तथा आर्थिक गतिविधियों की पूरी तरह से बहाली आकस्मिक ही रहेगी जो इस बात पर निर्भर करेगी कि अवसंरचना की हालत तीव्र बनी रहे, मांग की स्थिति में सुधार हो तथा बाधित आपूर्ति का समाधान हो सके, इसके अलावा वैश्विक कारक जैसे व्यापार और वित्तीय परिस्थितियों पर भी निर्भर करेगा।

1.21 वर्ष 2020-21 में केंद्र सरकार के वित्त में थोड़ी गिरावट आने की संभावना बन सकती है, साथ ही कोविड-19 संबंधी बाधाओं के कारण राजकोषीय राजस्व बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है, यहां तक कि राजकोषीय प्रोत्साहन के कारण व्यय की स्थिति दबाव में आ सकती है। राज्य वित्त के मामले में फेडरल के कम अंतरण से उत्पन्न अतिरिक्त बोझ से जोखिम बढ़ते जाने की संभावना बन सकती है। 2019-20 में सामान्य सरकार द्वारा ली गई निवल उधारी में तीव्र वृद्धि हुई थी (चार्ट 1.9)। कई प्रकार के उपाय किए गए हैं, साथ ही अर्थोपाय की सीमा में वृद्धि, राज्यों पर मोचन संबंधी दबाव को सहज बनाने के लिए समेकित डूबंत निधि (सीएसएफ) से आहरण संचालन नियमों में छूट प्रदान की गई तथा रिजर्व बैंक के चलनिधि सहायता उपाय से अब तक बान्ड बाजारों पर पड़ने वाले प्रभावों (स्पिलओवर) को नियंत्रित रखा जा सका है।

1.22 कम व्यापार घाटा और निवल अदृश्य प्राप्ति में तीव्र वृद्धि के कारण चालू खाता शेष 2019-20 की चौथी तिमाही के दौरान थोड़े अधिशेष (जीडीपी का 0.1 प्रतिशत) में परिवर्तित हो गया। भारत का पण्य निर्यात 2019-20 की पहली छमाही में 2.5 प्रतिशत के संकुचन की तुलना में दूसरी छमाही में 7.6 प्रतिशत संकुचित हो गया। आयात में 2019-20 की पहली छमाही में 5.2 प्रतिशत की गिरावट के बाद 2019-20 की दूसरी छमाही में 10.5 प्रतिशत की गिरावट आई (चार्ट 1.10)। अप्रैल-मई 2020-21 के दौरान, आयात और निर्यात क्रमशः 47.5 प्रतिशत और 54.7 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) संकुचन के साथ एका-एक गिर गए। भारत का व्यापार घाटा मई 2020 में 3.1 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा जो फरवरी 2009 के बाद से दर्ज सबसे कम व्यापार घाटा था। अप्रैल 2020 की तुलना में मई के दौरान व्यापार घाटा और भी कम हो गया जो मई में निर्यात में आयात से अधिक सुधार के कारण था।

1.23 विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) प्रवाह, जिसमें फरवरी 2020 तक निवल अंतर्वाह दर्ज किया गया, मार्च 2020 से निवल बहिर्वाह में परिवर्तित हो गया। वर्ष 2019-20 के दौरान एफपीआई 3 बिलियन अमरीकी डॉलर के निवल विक्रेता बन गए, ऐसा मुख्य रूप से मार्च 2020 के दौरान 16 बिलियन अमरीकी डॉलर की बिकवाली के कारण हुआ, यह अब तक के सबसे ऊँचे एफपीआई मासिक निवल बहिर्वाह में से एक है, हालांकि एफपीआई प्रवाह ने मई और जून में महत्वपूर्ण बहाली को दर्शाया है (चार्ट 1.11)।

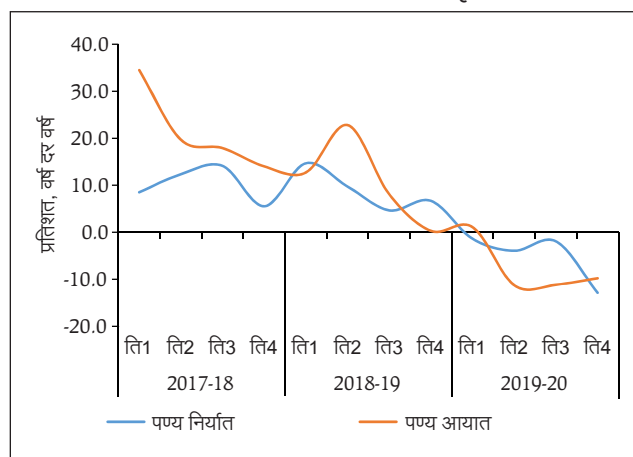
चार्ट 1.9: निवल उधारियां (केंद्र और राज्य सरकारें) और जी-सेक 10-वर्षीय प्रतिफल



टिप्पणी : *जीडीपी पहला अग्रिम अनुमान।

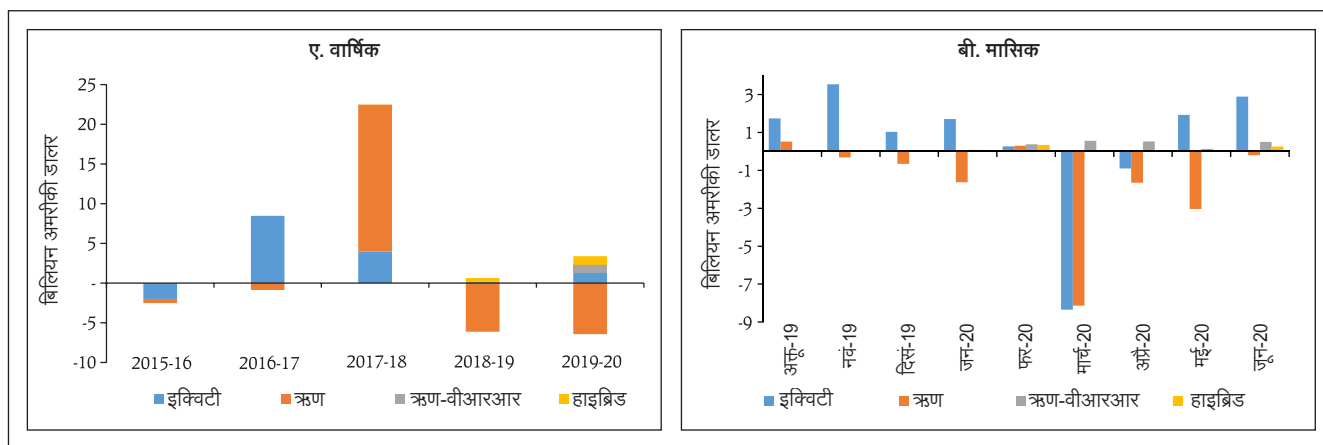
स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई)

चार्ट 1.10: भारत के पण्य व्यापार में वृद्धि



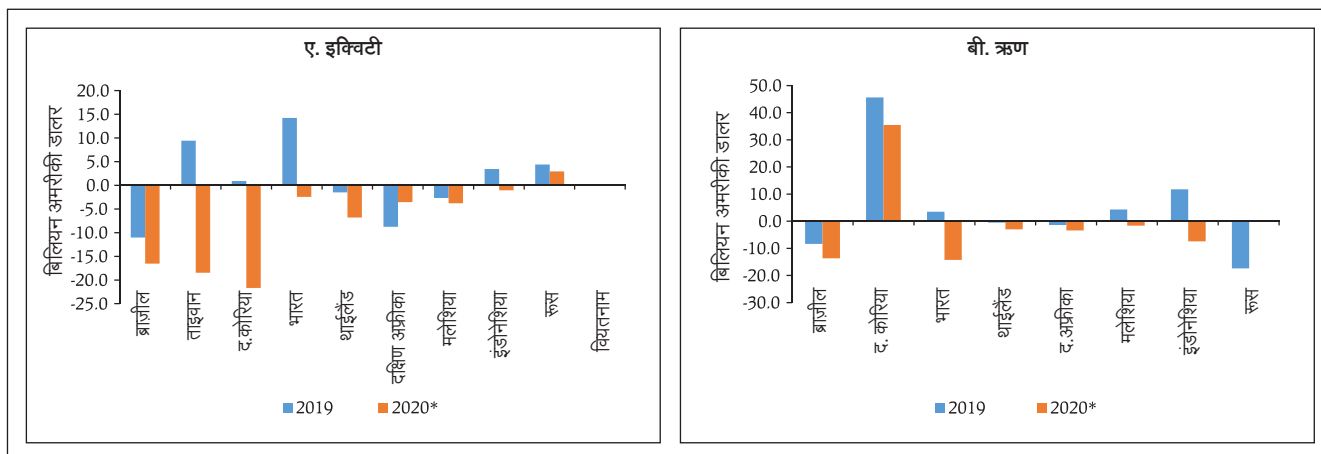
स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना और अंक संकलन महानिदेशालय (डीजीसीआई&एस)

चार्ट 1.11: विदेशी पोर्टफोलियो निवेश प्रवाह



स्रोत: नेशनल सिक्युरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)

चार्ट 1.12: एफपीआई प्रवाह – उभरते बाजार



टिप्पणी: 30 जून 2020 के अनुसार
 स्रोत: ब्लूमबर्ग

1.24 भारत की तुलना में उभरते बाजारों के पोर्टफोलियो प्रवाहों का तुलनात्मक विश्लेषण सामान्य तौर पर जोखिम प्रतिकूल व्यवहार को दर्शाता है (चार्ट 1.12)।

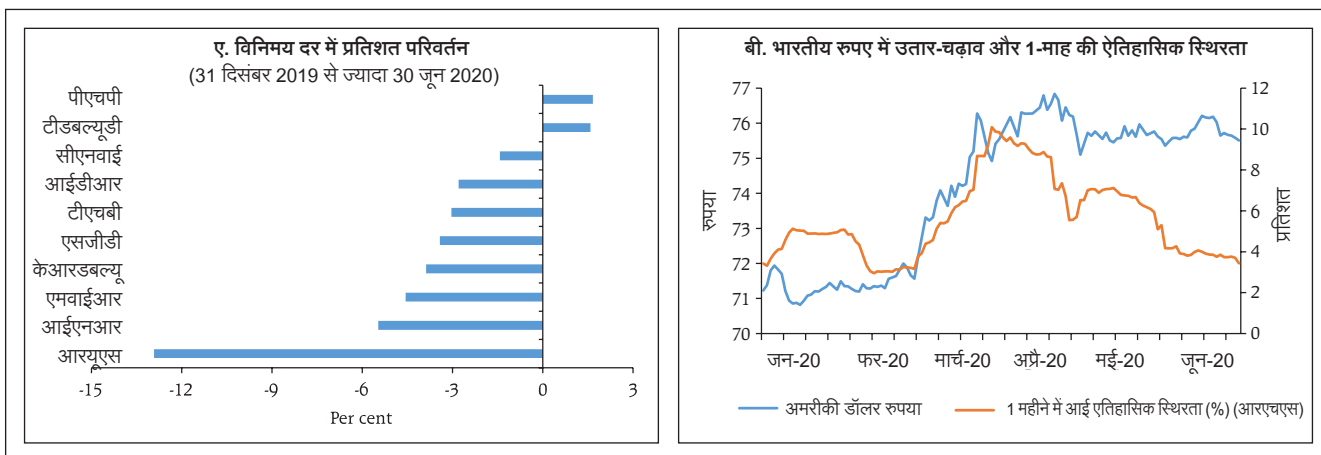
1.25 विदेशी विनिमय बाजार में, भारतीय रुपए के मूल्य में वर्ष के प्रारम्भ से वर्तमान तारीख तक समकक्ष ईएम मुद्राओं के सापेक्ष गिरावट आई है, हालांकि, हाल के समाहों में, इसने मूल्यवृद्धि के साथ कारोबार किया है और इसकी अंतर्निहित अस्थिरता में कमी आई है (चार्ट 1.13)।

1.2.2 कॉरपोरेट क्षेत्र

1.26 निजी कॉरपोरेट क्षेत्र का निष्पादन 2019-20 की क्रमिक तिमाहियों में और भी खराब हो गया और कोविड-19 महामारी

के कारण अंतिम तिमाही के दौरान संकुचन की स्थिति विशेषरूप से गंभीर रही। वर्ष के दौरान, 1640 सूचीबद्ध निजी गैर-वित्तीय कंपनियों की नाममात्रेण बिकवाली और निवल लाभ में, सितंबर 2019 की कॉरपोरेट कर दर कटौती के बावजूद, क्रमशः 3.4 प्रतिशत (2019-20 की चौथी तिमाही में 10.2 प्रतिशत) और 19.3 प्रतिशत (2019-20 की चौथी तिमाही में 65.4 प्रतिशत) की गिरावट (वर्ष दर वर्ष) हुई, इस कटौती से प्रभावी कर दर (कर पूर्व लाभ से कर प्रावधान का अनुपात) 2019-20 में वर्ष-दर-वर्ष लगभग 3.0 प्रतिशत नीचे आ गई। ऐसा विनिर्माण कंपनियों के कमजोर प्रदर्शन के चलते था क्योंकि सेवा क्षेत्र की कंपनियाँ विशेष रूप से वे जो आईटी क्षेत्र में थीं, सकारात्मक स्थिति रहीं।

चार्ट 1.13: विनिमय दर में उतार-चढ़ाव और देखी गई अस्थिरता



स्रोत: ब्लूमबर्ग

1.27 हाल के वर्षों में निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र की डेलीवरेजिंग में 2019-20 की दूसरी छमाही के दौरान रुकावट आई क्योंकि उच्च उधारों¹ के कारण लिवरेज अनुपात (ऋण को आस्ति अनुपात द्वारा मापा गया) में वृद्धि हुई। वृद्धिशील उधारों का उपयोग वित्तीय आस्तियों (अनुषंगी / अन्य कंपनियों और वित्तीय निवेशों के लिए ऋण और अग्रिम) के निर्माण के लिए किया गया न कि पूंजीगत निर्माण व्यय (कैपेक्स) के लिए, क्योंकि मांग की स्थिति धीमी रही।

1.28 वर्ष 2015-19² के दौरान 3,760 सूचीबद्ध गैर-वित्तीय फर्मों (68 पीएसयू और 3692 गैर-पीएसयू) के नमूनों के विश्लेषण से पता चलता है कि गैर-पीएसयू कंपनियों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के सापेक्ष काफी अधिक डीलिवरेजिंग की स्थिति रही (चार्ट 1.14)। ऋण प्रोफाइल में इस सुधार के बावजूद, इस अवधि के दौरान बिक्री अनुपात की तुलना में स्थिर परिचालन लाभ चुनौतीपूर्ण कारोबारी माहौल को दर्शाते हैं। पीएसयू के लिए परिचालनगत लाभ की तुलना में ब्याज व्यय का अनुपात गैर-पीएसयू की तुलना में कम रहा। फिर भी, ब्याज दरों में काफी अधिक कमी के बावजूद, यह अनुपात पीएसयू और गैर-पीएसयू गैर-पीएसयू दोनों कंपनियों के लिए अस्थिर बना हुआ है, जो ब्याज लागत के प्रलंबित प्रभाव को दर्शाता है। ये दोनों समूह, जैसा कि वर्तमान अनुपात द्वारा मापा गया है, बिगड़ती चलनिधि स्थितियों को भी दर्शाते हैं (चार्ट 1.14)।

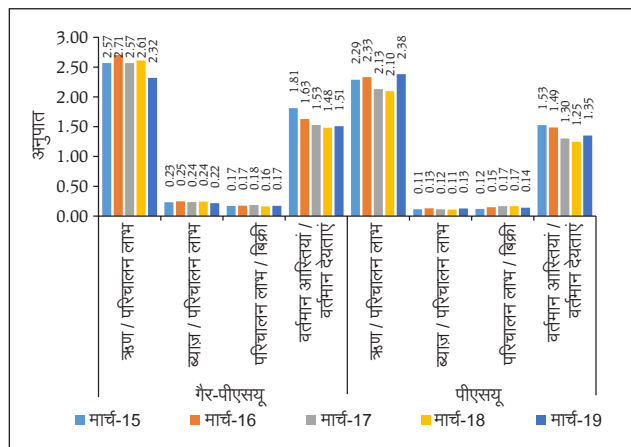
1.29 1,488 सूचीबद्ध गैर-पीएसयू और गैर-वित्तीय फर्मों (चार्ट 1.15) के स्थिर नमूनों का लीवरेज अनुपात दर्शाता है कि 'अन्य' श्रेणी में डिलीवरेजिंग विशेष रूप से मुखर रही जबकि चालू अनुपात में तदनुसूची मुखर गिरावट दिखी।

1.30 कॉर्पोरेट क्षेत्र की ऋण मांग मंद रही है। इसी कारण, एससीबी की ऋण वृद्धि आश्चर्यजनक रूप से मजबूत रही लेकिन सभी बैंक समूहों में खुदरा ऋण वृद्धि धीमी रही जबकि थोक ऋण वृद्धि में गिरावट आई (चार्ट 1.16)।

1.2.3 ऋण स्थगन और बैंक ऋण

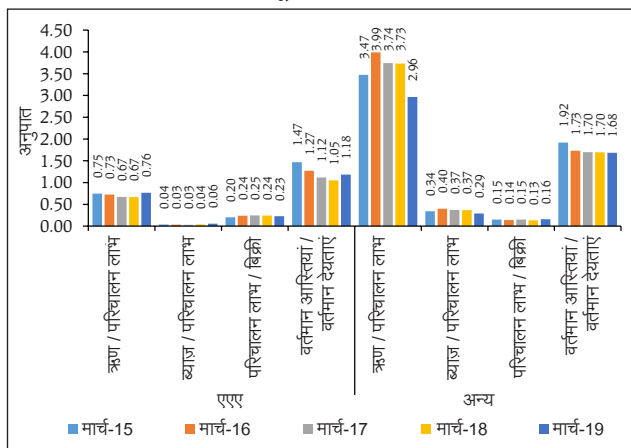
1.31 भारत में कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण, आरबीआई ने अन्य बातों के साथ-साथ ऋण चुकौती के भार

चार्ट 1.14: लीवरेज और लाभप्रदता – स्वामित्व द्वारा सूचीबद्ध गैर-वित्तीय फर्म



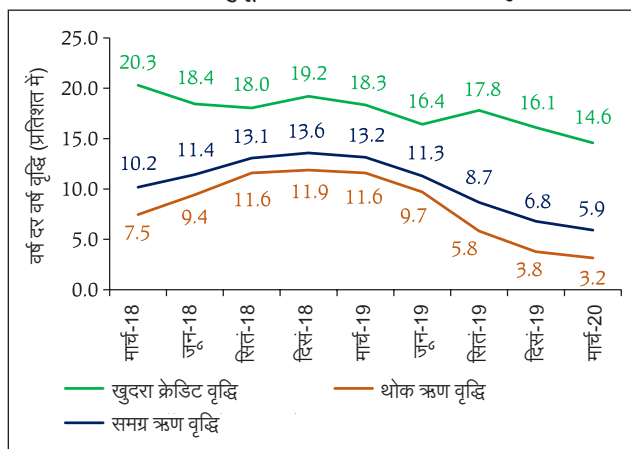
स्रोत : कैपिटलाइन

चार्ट 1.15: लीवरेज और लाभप्रदता – रेटिंग वाली सूचीबद्ध गैर-पीएसयू और गैर-वित्तीय फर्म



नोट: एएए के रूप में दिखाई गई कंपनियों की 2015-19 अवधि के दौरान 'एएए' रेटिंग रही।
स्रोत: कैपिटलाइन, प्राइम डाटाबेस।

चार्ट 1.16: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण वृद्धि



स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां और स्टाफ गणना।

¹ 967 गैर-पीएसयू गैर-वित्तीय सूचीबद्ध कंपनियों के बिना लेखा परीक्षा के अर्धवार्षिक परिणामों पर आधारित।

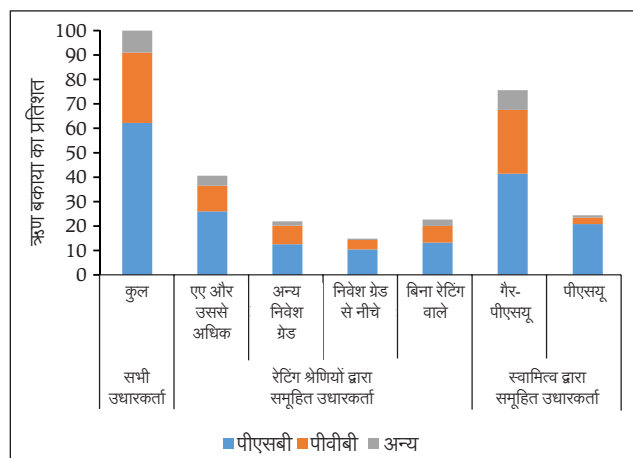
² वर्ष 2019-20 के वित्त नमूने में कंपनियों की थोड़ी संख्या के लिए उपलब्ध थे।

को कम करने और व्यवहार्य व्यवसायों तथा हाउसहोल्ड्स को निरंतरता प्रदान करने के लिए विनियामकीय और पर्यवेक्षी उपायों की घोषणा की। पर्यवेक्षी संस्थाओं (एसई) ने इन विनियामकीय राहत उपायों को बड़े पैमाने पर लागू किया है। लगभग आधे बकाया बैंक ऋणों में से लगभग आधे ग्राहकों ने राहत उपायों का लाभ उठाने का विकल्प चुना (सारणी 1.4)।

1.32 मार्च 2020 के अंत में थोक ऋण बकाया³ में 62 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) का हिस्सा था जबकि निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) की हिस्सेदारी लगभग 29 प्रतिशत थी। कुल बकाया ऋण का लगभग 63 प्रतिशत हिस्सा निवेश ग्रेड उधारकर्ताओं का था; गैर-सरकारी ऑब्लिगर्स का 76 प्रतिशत हिस्सा था (चार्ट 1.17)।

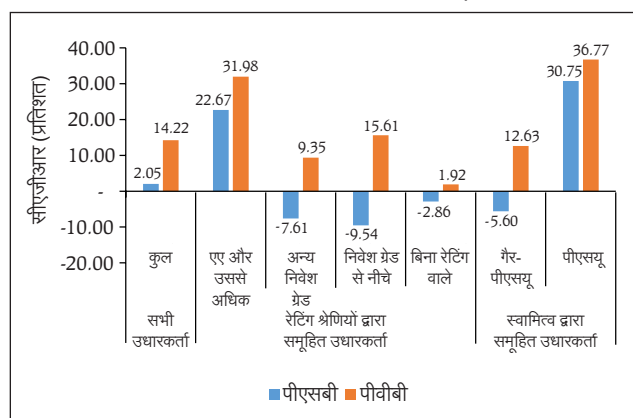
1.33 वर्ष 2019-20 में विभिन्न समूहों में क्रेडिट वृद्धि को रखने के परिप्रेक्ष्य में, पिछले 3 वर्षों के विभिन्न उधारकर्ता श्रेणियों के अंतर्गत थोक ऋण वृद्धि का विश्लेषण किया गया। पीएसबी के बीच गैर-पीएसयू ऑब्लिगर्स और 'एए और उससे अधिक' को छोड़कर, सभी रेटिंग श्रेणियों में तीव्र ऋण संकुचन रहा। इसके विपरीत, पीवीबी ने सभी रेटिंग श्रेणियों और पीएसयू व गैर-पीएसयू दोनों ऑब्लिगर्स में धनात्मक ऋण वृद्धि दर्ज की, जो पीएसबी की तुलना में समग्र कम जोखिम विमुखता की ओर संकेत करती है, इस स्थिति के बाद भी इसने अपनी जोखिम प्रबंधन कार्यप्रणालियों में सुधार करने की कोशिश जारी रखी है (चार्ट 1.18)। हालांकि, आगे के विश्लेषणों में पता

चार्ट 1.17 : उधारकर्ता श्रेणियों / उधारदाता समूहों का मार्च 2020 को थोक ऋण बकाया



स्रोत: बड़े ऋणों से संबंधित सूचना का केंद्रीय भंडार (सीआरआईएलसी), प्राइम डाटाबेस

चार्ट 1.18 : विभिन्न उधारकर्ता श्रेणियों में थोक ऋण बकाया (पिछले 3 वर्षों से अधिक के सीएजीआर पर आधारित)



स्रोत: सीआरआईएलसी, प्राइम डाटाबेस

सारणी 1.4: 30 अप्रैल 2020 तक लिए गए ऋण स्थगन का विश्लेषण

क्षेत्र	कॉर्पोरेट		एमएसएमई		वैयक्तिक		अन्य		कुल	
	कुल ग्राहकों का %	कुल बकाए का %	कुल ग्राहकों का %	कुल बकाए का %	कुल ग्राहकों का %	कुल बकाए का %	कुल ग्राहकों का %	कुल बकाए का %	कुल ग्राहकों का %	कुल बकाए का %
पीएसबी	28.8	58	73.9	81.5	80.3	80	48.8	63.7	66.6	67.9
पीवीबी	21.6	19.6	20.9	42.5	41.8	33.6	39.1	40.9	49.2	31.1
एफबी	32.6	7.7	73.3	50.4	8.4	21.1	75.8	4.8	21.4	11.5
एसएफबी	78.8	43.7	90.5	52.3	90.9	73.2	64.6	12.3	84.7	62.6
यूसीबी	63.4	69.3	66.5	65.5	56.8	62	35.6	59.2	56.5	64.5
एनबीएफसी	39.7	56.2	60.7	61.1	32.5	45.9	37.3	41.4	29	49
एससीबी	24.7	39.1	43.1	65.3	52.1	56.2	45.7	55.7	55.1	50
प्रणाली	30.8	41.9	45.8	65	50.4	55.3	45.7	54.6	48.6	50.1

स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां।

³ केवल वित्तपोषित बकाया राशि पर विचार किया गया है। केवल कंपनियों के लिए ऋण (जो थोक ऑब्लिगर्स के लिए कुल वित्तपोषित बकाया राशि का लगभग 88 प्रतिशत है) पर विचार किया गया है जिसे अन्य संगठनात्मक ढांचे जैसे सहकारी समितियों, सहभागिता, न्यास और सोसाइटी के ऋण के विपरीत माना गया है।

चलता है कि पिछली दो तिमाहियों में पीवीबी का व्यवहार पिछले तीन वर्षों में उनके व्यवहार के विपरीत रहा।

1.34 वर्ष 2019-20 के दौरान, पीवीबी प्रेरित समग्र ऋण वृद्धि धीमी रही, जो बढ़ी हुई जोखिम विमुखता के साथ-साथ सुस्त समष्टि आर्थिक स्थितियों में कम मांग को दर्शाती है (सारणी 1.5)।

1.35 स्वामित्व आधार पर ऋण प्रवाह के विश्लेषण से पता चलता है कि पीएसयू क्षेत्र प्रमुख प्राप्तकर्ता रहा। वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही में गैर-पीएसयू फ़र्मों के लिए तिमाही-दर-तिमाही ऋण प्रवाह पिछले वर्ष से तुलनीय था लेकिन पीएसबी ने एक वर्ष के पहले के विपरीत 2019-20 की चौथी तिमाही में ऋण प्रावधानों पर प्रभुत्व बनाए रखा (सारणी 1.6)।

1.36 गैर-पीएसयू ऑब्लिगर्स के लिए रेटिंग ग्रेड पर आधारित ऋण प्रवाह के विश्लेषण से पता चलता है कि 'ए और उससे अधिक' के रेटिंग समूह ने मुख्य रूप से 2019-20 की तीसरी और चौथी तिमाही के दौरान ऋण तक पहुँच बनाई। इस अवधि के दौरान ए और उससे कम रेटिंग वाले उधारकर्ताओं के लिए ऋण तक कम पहुँच के सापेक्ष पीएसबी और पीवीबी दोनों में समान स्थिति बनी रही। ए और इससे कम रेटिंग वाले समूह के संबंध में पीवीबी का व्यवहार 2018-19 में उनके ऋण के मामले में विशेषरूप से संवृद्धि प्रोफाइल विपरीत रहा (सारणी 1.7)।

1.37 कोविड-19 द्वारा प्रेरित ऋण वृद्धि पर हानियों के प्रभाव को समझने के लिए पिछले दिनों के बकाया (डीपीडी) के आधार पर विश्लेषण किया गया। पिछली टिप्पणियों के अनुरूप, पीवीबी इस विमूहन में जोखिम विमुखता के व्यवहार को दिखाते हैं, केवल समूह (कोहार्ट) ही ऐसे हैं जो दोनों तिमाहियों में गैर-हानि श्रेणी में धनात्मक ऋण वृद्धि दर्शाते हैं (सारणी 1.8)।

सारणी 1.5: भिन्न भिन्न थोक ऋण वृद्धि (तिमाही-दर-तिमाही जब तक अन्यथा उल्लेख नहीं किया गया) (प्रतिशत)

	विव-18-19	जून-19	सित -19	दिस-19	मार्च-20	विव-19-20
पीएसबी	2.61	-2.58	-0.33	-0.91	7.13	3.08
पीवीबी	23.79	-3.15	3.82	0.25	1.37	2.19
समग्र	8.52	-2.76	0.99	-0.54	5.24	2.79

स्रोत: सीआरआईएलसी

सारणी 1.6: स्वामित्व पर आधारित भिन्न भिन्न थोक ऋण वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) (प्रतिशत)

	दिस-18		मार्च-19		दिस-19		मार्च-20	
	गैर-पीएसयू	पीएसयू	गैर-पीएसयू	पीएसयू	गैर-पीएसयू	पीएसयू	गैर-पीएसयू	पीएसयू
पीएसबी	-0.96	7.35	-4.34	14.83	-2.03	1.84	1.38	20.78
पीवीबी	2.36	3.73	9.38	8.41	-0.70	14.17	-0.89	30.15
समग्र	0.17	6.97	0.45	14.18	-1.51	3.04	0.49	21.78

स्रोत: सीआरआईएलसी

सारणी 1.7: गैर-पीएसयू ऑब्लिगर्स में भिन्न भिन्न थोक ऋण वृद्धि (तिमाही-दर-तिमाही) (प्रतिशत)

	पीवीबी				पीएसबी			
	दिस-18	मार्च-19	दिस-19	मार्च-20	दिस-18	मार्च-19	दिस-19	मार्च-20
ए और उससे अधिक	3.83	6.57	-0.43	5.14	2.13	-0.92	0.67	7.91
ए और उससे कम बिना रेटिंग वाले	5.13	13.35	-0.56	-2.62	-1.94	-4.36	-3.35	-2.75
	-3.03	6.32	-1.23	-4.76	-2.28	-7.90	-2.67	1.41

स्रोत: सीआरआईएलसी, प्राइम डाटाबेस

सारणी 1.8 विभिन्न ट्रांजिशन ऋण समूहों में थोक ऋण वृद्धि (तिमाही दर तिमाही) (प्रतिशत)

	पीएसबी		पीवीबी	
	मार्च 2020 में एसएमए	मार्च 2020 में गैर-हानि	मार्च 2020 में एसएमए	मार्च 2020 में गैर-हानि
दिसंबर 2019 में एसएमए	4.7	3.2	-2.9	-3.7
दिसंबर 2020 में गैर-हानि	6.5	11.2	-1.4	2.4

टिप्पणी: कोई ऐसा ऑब्लिगर जिसका एक्सपोजर विशेष उल्लेखनीय खातों (एसएमए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है-दी गई एक अवधि में उधार देने वाले किसी बैंक में 1/2 को एसएमए जोखिम कहा जाता है। वैकल्पिक रूप से, एक्सपोजर को गैर-हानि के रूप में नामित किया गया कूपया एसएमए श्रेणियों के आगे के स्पष्टीकरण के लिए अध्याय II के फुटनोट 7 का संदर्भ लें।

स्रोत: सीआरआईएलसी

1.38 ऋण के क्षेत्रगत आबंटन का विश्लेषण दर्शाता है कि कम जोखिम ऋण भार वाले क्षेत्रों का सामान्य तौर पर ऋण वृद्धि पर वर्चस्व है। केंद्र और राज्य पीएसयू की नागरिक आपूर्तियों में ऋण वृद्धि प्रधान रही जबकि कृषि और इससे सबद्ध सेवाएं प्राथमिक क्षेत्र के संवितरण के लिए पसंद किए जा सकते हैं। जैसे बिजली उत्पादन / वितरण कुछ क्षेत्रों जहां पर अपेक्षाकृत कम जोखिम भार और कम ऋण वृद्धि रही, में मांग की गति धीमी रह सकती है, हालांकि, इनमें हाल में वृद्धि दिखाई देती प्रतीत हो रही है (सारणी 1.9)।

1.39 चयनित पीएसबी और शीर्ष 5 पीवीबी की अधिशेष चलनिधि (अधिशेष सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) / चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर)) का विश्लेषण यह दर्शाता है कि हाल में, सामान्य तौर पर, पीवीबी में चलनिधि की कमी नहीं रही लेकिन उनमें जोखिम विमुखता थी (चार्ट 1.19)।

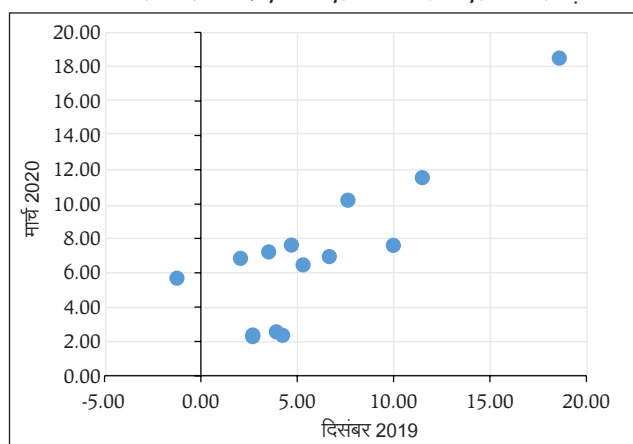
1.40 दीर्घकालिक रेटिंग गति (त्रैमासिक अपग्रेड बनाम डाउनग्रेड) 2018-19 की तीसरी तिमाही में शुरू हुए प्रतिकूल रेटिंग डाउनग्रेड गति को दर्शाते हैं (चार्ट 1.20)। पीएसबी और पीवीबी के अपने थोक ऋण एक्सपोजर औसत जोखिम भार में सुधार मार्च 2019 में 85 प्रतिशत से मार्च 2020 में 81.75 प्रतिशत हो गया, बावजूद इसकी रेटिंग गति में गिरावट देखी गई।

सारणी 1.9: क्षेत्रगत ऋण वृद्धि

Sector	पिछली तिमाही में वृद्धि दर (प्रतिशत)	वृद्धि दर - वित्त वर्ष 2019-20 (प्रतिशत)	औसत जोखिम भार (प्रतिशत) (मार्च 2020 के अनुसार)
ईंधन उत्पादों का विनिर्माण	49.49	29.14	47.18
थोक / रिटेल सेवाएँ	11.76	8.89	104.54
वित्तीय सेवाएँ	10.20	14.07	40.80
मूल धातु और धातु उत्पादों का विनिर्माण	5.27	-5.25	87.66
कृषि और सम्बद्ध	4.37	1.25	121.90
डाक, दूरसंचार और आईटी सेवाएँ	4.10	7.61	63.90
खनन /ओयल और गैस निकालना	3.31	-5.93	95.92
रसायन, रबड़ और सीसे का विनिर्माण	2.92	-0.03	88.35
विविध मदों का विनिर्माण	2.86	2.61	135.97
बिजली उत्पादन और / वितरण	2.84	-3.87	77.39

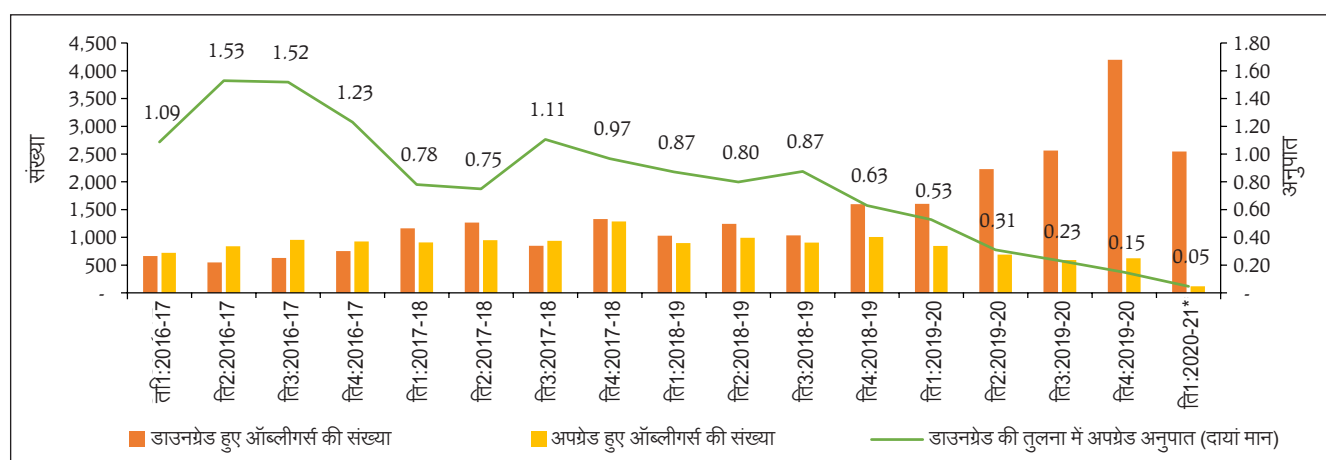
स्रोत : सीआरआईएलसी, प्राइम डाटाबेस

चार्ट 1.19: अधिशेष चलनिधि / एनडीटीएल - चयनित पीएसबी और बड़े पीवीबी



स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां और स्टाफ गणना

चार्ट 1.20: दीर्घकालिक रेटिंग गति और ऑब्लिगर्स की संख्या



टिप्पणी: *मई 2020 के अंत तक

स्रोत: प्राइम डाटाबेस

⁴ चूंकि 10 पीएसबी का 4 संस्थाओं में विलय 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी हुआ है, अतः 31 मार्च 2020 के अनुसार इन 10 पीएसबी के संबंध में एक एकल चलनिधि मूल्यांकन उचित नहीं होगा। इसलिए, इस विश्लेषण के प्रयोजन के लिए केवल वे पीएसबी, जो विलय के दायरे में नहीं हैं, पर विचार किया गया है।

1.41 ऑब्लिगर्स के एक निश्चित समूह को, जो अप्रैल-सितंबर 2019 के दौरान डाउनग्रेड हो गया था, उनकी ऋण पात्रता के मूल्यांकन को देखने के लिए एक निर्धारित अवधि में ट्रैक किया गया। इस समूह की वृद्धिशील चूक दर दिसंबर 2019 में तीव्र उर्ध्वगामी उतार-चढ़ाव को दर्शाती है, जिसका तात्पर्य यह है कि महामारी से पूर्व भी ऋण स्थितियां नरम रहीं (चार्ट 1.21)।

1.42 बैंकों के कार्यनिष्पादन पोर्टफोलियो की गुणवत्ता के ऋण प्रावधानों और वित्तीय स्थिरता के लिए भी मायने हैं (सारणी 1.10, 1.11 और 1.12)। स्थगन प्रभावों से अलग रहते हुए कार्यनिष्पादन पोर्टफोलियो में मानक आस्तियों की हिस्सेदारी (0 दिनों की अवधि वाली बकाया आस्ति और एसएमए-0 भुगतान की स्थिति) में 2017 और 2018 के सापेक्ष सुधार हुआ।

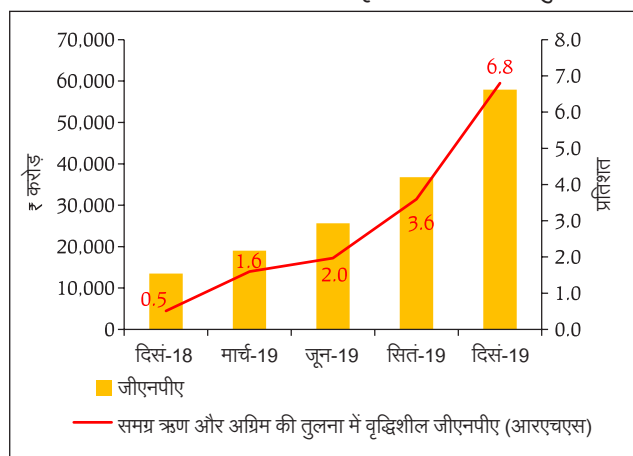
1.43 इसके अलावा, मानक आस्तियों की संरचना भी 'एए और उससे अधिक' रेटिंग की आस्तियों के अपेक्षाकृत ज्यादा हिस्सेदारी को दर्शाती है, जो आघातों के प्रति बढ़ती सहनीयता की ओर इंगित करती है। (सारणी 1.11)।

1.44 कार्यशील पोर्टफोलियो जो अतिसंवेदनशील (एसएमए 1 और एसएमए 2 श्रेणियाँ) है, का रेटिंग संवितरण 'एए और उससे अधिक' को सबसे बड़ी रेटिंग ग्रेड के रूप में दर्शाता है, इसका अर्थ है कि सभी उच्च रेटिंग वाले ऑब्लिगर्स आघातों / जोखिम विमुखता के प्रति अभेद्य नहीं हैं।

1.2.4 गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता में गतिविधियां

1.45 हाल के वर्षों में, म्यूचुअल फंड ने वित्तीय बचत के लिए एक वैकल्पिक अवसर के रूप में विशेष तौर से पारिवारिक इकाइयों के बीच मजबूत निवेशक की इच्छा पैदा की है, और यह झुकाव भारत में वित्तीय मध्यस्थता के परिदृश्य को आकार दे रहा है। भारत में ऋण /आय उन्मुख म्यूचुअल फंड योजनाओं के प्रबंधन (एयूएम) के तहत निवल आस्तियां 2015-2020 (5 वर्ष) के दौरान लगभग 70 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2020 के अंत तक 11.80 लाख करोड़ हो गईं। आस्ति प्रबंधन कंपनियां, जो वित्तीय प्रणाली के लिए निधियों की बड़ी निवल प्रदाता हैं, निधीयन बाज़ार को कुछ मात्रा में प्रभावित करती हैं। यह इस संदर्भ में है कि आरबीआई ने कोविड-19 के प्रभावों को कम करने और म्यूचुअल फंडों (एमएफ) को समग्र वित्तीय स्थिरता के हित में, ऋण जोखिम

चार्ट 1.21: डाउनग्रेडेड कंपनियों का वृद्धिशील जीएनपीए अनुपात



स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां और स्टाफ गणना।

सारणी 1.10: एससीबी के कार्यनिष्पादन पोर्टफोलियो और उनकी संरचना

	मार्च-17	मार्च-18	मार्च-19	जून-19	सितं-19	दिसं-19	मार्च-20
0 डीपीडी और एसएमए-0 के साथ मानक आस्ति	85.15	86.25	95.75	94.75	94.08	94.59	93.97
कार्य निष्पादन करने वाली लेकिन कमजोर (एसएमए ½)	14.85	13.75	4.25	5.25	5.92	5.41	6.03

स्रोत: सीआरआईएलसी

सारणी 1.11: एससीबी के मानक पोर्टफोलियो का रेटिंग संवितरण

(0 दिनों की अवधि के लिए बकाया और एसएमए-0) (पोर्टफोलियो के प्रतिशत के रूप में)

	मार्च-18	मार्च-19	जून-19	सितं-19	दिसं-19	मार्च-20
'एए' और उससे अधिक	39.04	45.27	45.38	46.11	45.39	47.46
रेटिंग ग्रेड 'ए' तक निवेश ग्रेड	28.55	27.41	27.23	26.49	27.17	26.04
उप-निवेश ग्रेड	8.77	6.78	7.22	6.55	6.92	7.34
रेटिंग रहित	23.64	20.54	20.17	20.85	20.52	19.16

स्रोत: सीआरआईएलसी, प्राइम डाटाबेस

सारणी 1.12: कार्यनिष्पादन का रेटिंग संवितरण लेकिन एससीबी के अतिसंवेदनशील पोर्टफोलियो (एसएमए-1/2)

	मार्च-18	मार्च-19	जून-19	सितं-19	दिसं-19	मार्च-20
'एए' और उससे अधिक	41.89	20.72	15.65	12.79	29.38	40.44
रेटिंग ग्रेड 'ए' तक निवेश ग्रेड	26.64	24.58	17.12	24.32	20.82	13.65
उप-निवेश ग्रेड	18.54	35.29	39.84	35.21	27.05	17.54
बिना रेटिंग वाले	12.92	19.41	27.39	27.69	22.76	28.37

स्रोत: सीआरआईएलसी, प्राइम डाटाबेस

सारणी 1.13: म्यूचुअल फंड्स द्वारा रिसोर्स मोबिलाइजेशन में रुझान (₹ करोड़ में)

विवरण	अक्तूबर- 19	नवंबर- 19	दिसंबर- 19	जनवरी- 20	फरवरी- 20	मार्च- 20	अप्रैल-जून 20
सकल मोबिलाइजेशन	14,93,175	8,82,234	11,50,581	11,51,675	8,82,288	13,12,136	26,47,640
मोचन	13,59,693	8,27,815	12,12,078	10,31,527	8,84,273	15,24,873	25,23,561
शुद्ध अंतर्वाह/बहिर्वाह	1,33,482	54,419	-61,497	1,20,149	-1,986	-2,12,737	1,24,079
अवधि के अंत में आस्तियाँ	26,32,824	27,04,699	26,54,075	27,85,804	27,22,937	22,26,203	25,48,848

स्रोत: भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी)

निधि मोचन दबावों के प्रभाव विस्तार से बचाने के लिए एक विशेष चलनिधि खिड़की बनाई।

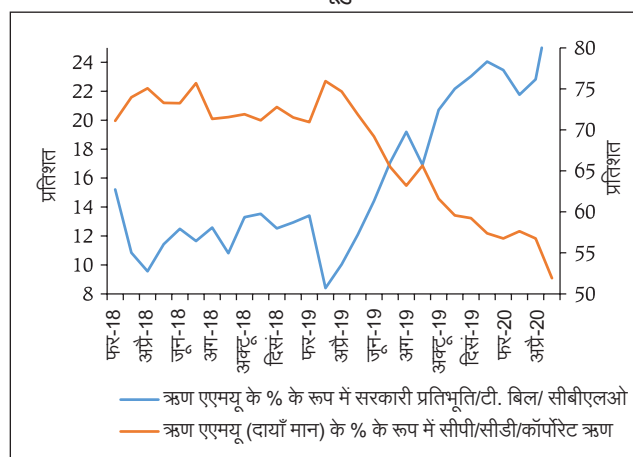
1.46 मार्च 2020 में दबावों के बढ़ने पर, वर्ष 2019-20 की दूसरी छमाही के दौरान म्यूचुअल फंड द्वारा संसाधनों के संग्रहण को कॉर्पोरेट चूक जैसे विशेष प्रवृत्तिगत आघात लगे (सारणी 1.13)। मार्च 2020 के दौरान असीमित अवधि वाली ऋण-उन्मुख योजनाओं का निवल बहिर्वाह ₹1,94,900 करोड़ था। इस महत्वपूर्ण अस्थिरता को देखते हुए, आय/ ऋण-उन्मुख योजनाओं में तरल प्रतिभूतियाँ प्रणालीगत महत्व की हैं।

1.47 मोचन दबाव के कारण मार्च 2020 में गिरावट के बावजूद, कुल ऋण एयूएम के अनुपात के रूप में सरकारी प्रतिभूतियों में ऋण एयूएम का परिनियोजन मार्च 2019 के बाद से बढ़ रहा है (चार्ट 1.22)। इसके अलावा, ऋण म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग में लिक्विड प्रतिभूतियों का अनुपात अप्रैल 2020 में सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो जोखिम विमुखता और तरलता भंडारण को दर्शाता है।

1.48 मार्च 2020 में ऋण फंड में आहरण द्वारा गिरावट के कारण तीन प्रतिनिधि योजनाओं की निवल परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) में अस्थिरता, आस्ति बाजार में अव्यवस्था को दर्शाती है (चार्ट 1.23)। यहाँ तक की दैनिक लाभांश योजनाएँ, जिन्हें अपेक्षाकृत जोखिममुक्त माना जाता है, लॉकडाउन से प्रभावित नहीं, जैसा कि एनएवी के उतार-चढ़ावों में परिलक्षित हुआ।

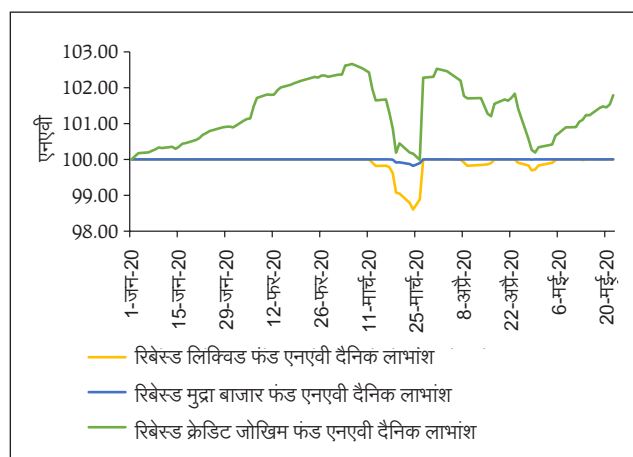
1.49 भारतीय ऋण आस्ति प्रबन्धन फंड की कुछ विशेष प्रवृत्तिगत विशेषताएँ हैं जो संभवतः ऐसे धन को परिचालन के लिए अतिसंवेदनशील बना सकता है। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) के दिसम्बर 2018 के अंक में ऋण फंड में गैर-खुदरा निवेशक के प्रभुत्व की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है (आईएल एंड एफएस संकट के मद्देनजर)। कॉर्पोरेट और उच्च मालियत व्यक्तियों के पास, ऋण निधियों के लिए प्रबंधन के तहत, कुल संपत्ति (एयूएम) की 90 प्रतिशत से अधिक की

चार्ट 1.22: सरकारी प्रतिभूति/टी. बिलों/ सीबीएलओ और स्प्रेड उत्पादों में म्यूचुअल फंड निवेश



टिप्पणी: सीबीएलओ- संपार्श्विक ऋण उधार दायित्व; सीपी- वाणिज्यिक पत्र; सीडी- जमा प्रमाणपत्र
स्रोत: सेबी

चार्ट 1.23: तीन योजनाओं के रिबेसड निवल आस्ति मूल्यों में प्रतिनिधि उतार-चढ़ाव



स्रोत: एसोसिएसन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया (एएमएफआई)

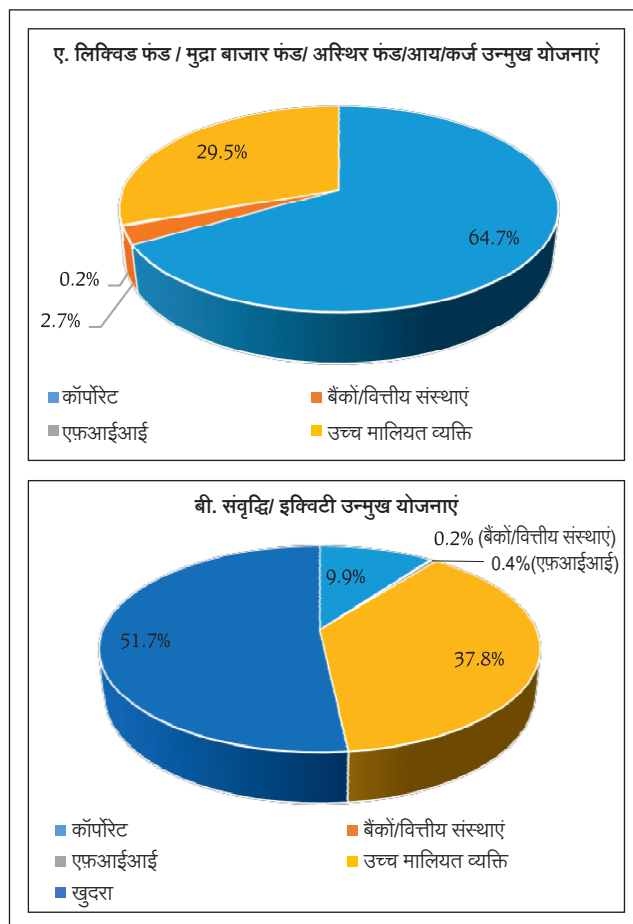
हिस्सेदारी है (चार्ट 1.24); इसके ठीक विपरीत, इक्विटी फंडों में उनकी 48 प्रतिशत की अधिक संतुलित हिस्सेदारी है।

1.50 यद्यपि व्यय अनुपात को विनियमावली के माध्यम से परिसीमित रखा जाता है, फिर भी, बड़े फंड गृहों को लागत प्रतिस्पर्धी होने के लिए एक बड़े एयूएम पर अपनी निश्चित लागतों के विस्तार का लाभ मिला है। इससे निवेश में कॉर्पोरेट प्रभुत्व से फंड प्रबंधन में संकेद्रण हो सकता है क्योंकि छोटे फंड गृह व्यय अनुपात प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हैं। मार्च 2019 और मार्च 2020 के बीच, कुल लिक्विड फंड कॉर्पोरेट में 5 शीर्ष फंडों की हिस्सेदारी 55 फीसदी से बढ़कर 61 फीसदी हो गई। इसके अलावा, एक बड़े फंड का आकार निवेशक के दृष्टिकोण से भी प्रोत्साहन सुसंगत है, क्योंकि इस तरह के फंड में महत्वपूर्ण प्रणालीगत स्पिल-ओवर होते हैं, जो संभावित रूप से बेलआउट की संभावनाओं में सुधार करते हैं।

1.51 सिद्धांत रूप में, बाहर निकलने की दृष्टि से कॉर्पोरेट की तेजी को यह सुनिश्चित करते हुए विविधाकृत किया जा सकता है कि कोई भी निवेशक एक निर्धारित आस्तित्व प्रबंधन कंपनी (एएमसी) की किसी योजना में निवेश का अनुपातहीन हिस्सा अंशदान नहीं कर सकता। मौजूदा विनियमावली में निवेशक आधार में विविधता लाने के लिए एकल निवेशक संकेद्रण मानदंडों को निर्दिष्ट किया गया है। हालांकि, जब निवेशक प्रोफाइल में जोखिम से बचने वाले निवेशकों का बाहुल्य रहता है, जैसा कि मुद्रा बाजार / ऋण म्यूचुअल फंडों के मामले में है तो इसकी प्रबल संभावना रहती है कि कुछ कॉर्पोरेट अपने अधिशेष को चार/पाँच फंड गृहों में बाँट रखने और दबाव के समय में बाहर निकल आएँ और इस प्रकार सम्मिलित रूप में दबाव का सामना करें।

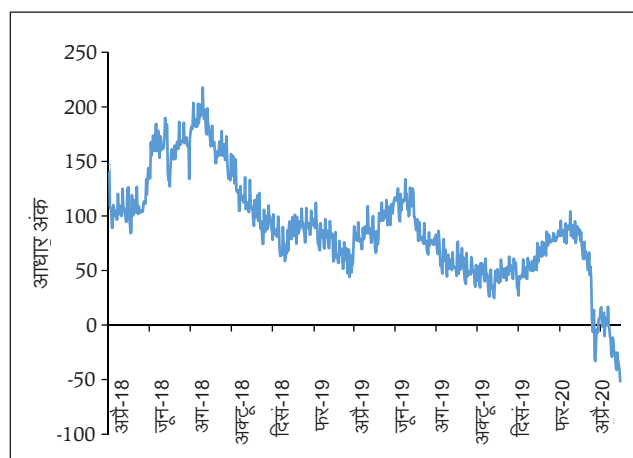
1.52 ऋण फंड प्रबंधन उद्योग अत्यन्त प्रतिस्पर्धी है और पोर्टफोलियो निष्पादन वृद्धिशील फंड प्रवाह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसी प्रकृति आम तौर पर गैर तरल प्रीमियम को अतिरिक्त रिटर्न शॉर्ट रन के रूप में प्रदर्शित करती है। अतिरिक्त रिटर्न, हालांकि काफी अधिक है परंतु यह कोविड -19 से संबंधित अव्यवस्थाओं के मद्देनजर नकारात्मक हो गया (चार्ट 1.25)। ऋण म्यूचुअल फंड्स में हालिया मंथन को देखते हुए, सेक्टर की जोखिम वहन क्षमता और परिणामस्वरूप निवेश आवंटन का महत्व बढ़ जाता है।

चार्ट 1.24 ऋण और इक्विटी फंड का निवेशक प्रोफाइल (31 दिसम्बर, 2019 को)



टिप्पणी: एफआईआई- वित्तीय संस्था, एफआईआई-विदेशी संस्थागत निवेशक
स्रोत: एएमएफआई

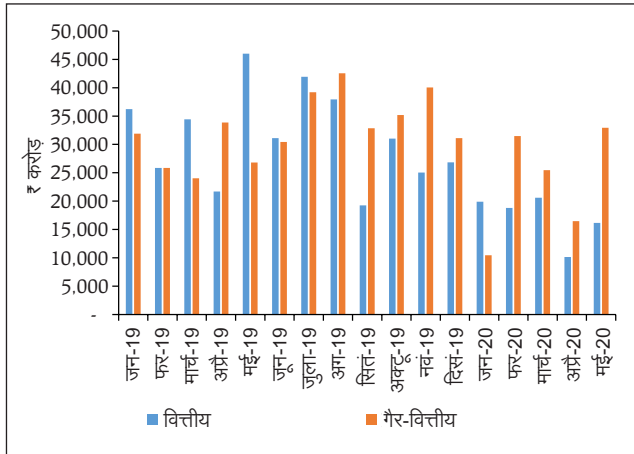
चार्ट 1.25: लिक्विड फंड में अतिरिक्त रिटर्न*



टिप्पणी: * क्रिसिल लिक्विड फंड इंडेक्स और 3 माह के स्थिर परिपक्वता वाले टी-बिल्स पोर्टफोलियो 5 के बीच के रिटर्न अंतर है।
स्रोत: ब्लूमबर्ग

⁵ स्थिर अवधि पोर्टफोलियो को 3 माह के लिए चुना गया क्योंकि लिक्विड फंड 91 दिनों तक अवशिष्ट परिपक्वता वाली लिखतों में निवेश कर सकते हैं।

चार्ट 1.26: सीपी निर्गमन: गैर- पीएसयू ऑब्लिगर्स



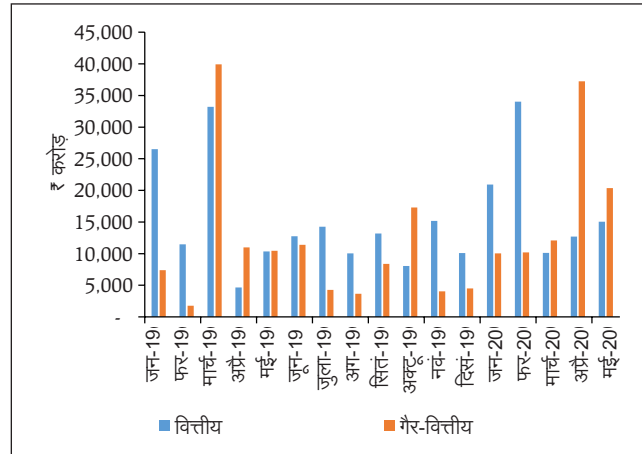
स्रोत: प्रमुख डाटाबेस

1.53 भारतीय रिज़र्व बैंक के चलनिधि उपायों के समर्थन से, कोविड-19 प्रेरित व्यवधानों के बावजूद गैर परिवर्तनशील डिबेंचर (एनसीडी) और वाणिज्यिक पत्र (सीपी) बाजार दोनों सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं (चार्ट 1.26 और 1.27)।

1.54 हालांकि वित्तीय कंपनियों द्वारा वाणिज्यिक पत्रों के निर्गमन में गिरावट की प्रवृत्ति दिख रही है लेकिन, हालिया निर्गमन में गैर वित्तीय संस्थाओं का वर्चस्व (चार्ट 1.26)।

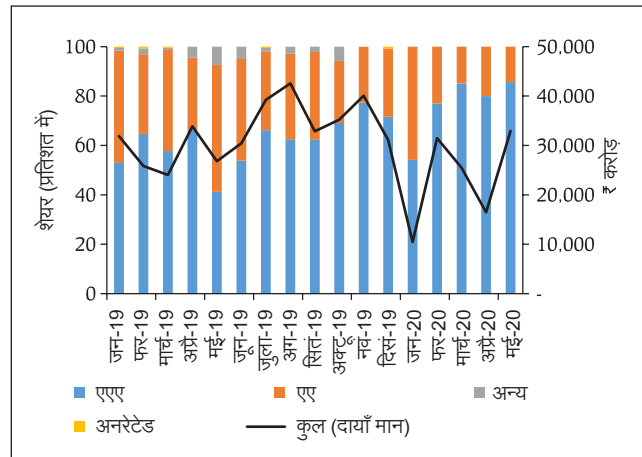
1.55 सीपी बनाम एनसीडी का रेटिंग विस्तार, एनसीडी के मामले में अधिक भिन्न रेटिंग प्रोफाइल को दर्शाता है, भले ही सापेक्षित रूप से उनके निवेश का अपेक्षाकृत लंबा कार्यकाल रहा हो जिसमें, 'एएए' / 'एए' रेटिंग ग्रेड का वर्चस्व हों (चार्ट 1.28 और 1.29)।

चार्ट 1.27: एनसीडी निर्गमन: गैर- पीएसयू ऑब्लिगर्स



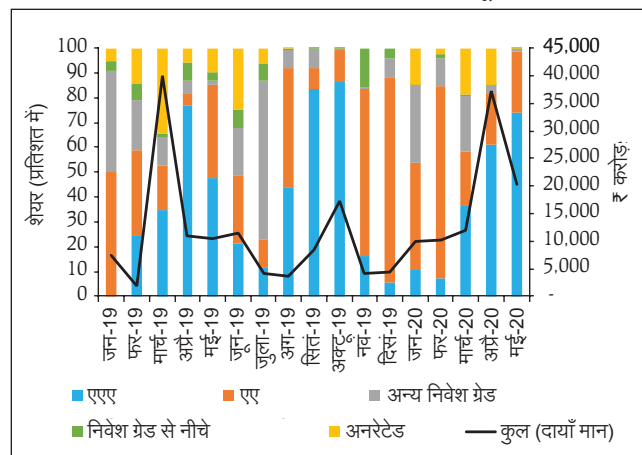
स्रोत: प्रमुख डाटाबेस

चार्ट 1.28: सीपी निर्गमन: गैर- वित्तीय गैर-पीएसयू ऑब्लिगर्स



स्रोत: प्रमुख डाटाबेस

चार्ट 1.29: एनसीडी निर्गमन: गैर- वित्तीय गैर-पीएसयू ऑब्लिगर्स



स्रोत: प्रमुख डाटाबेस

सारणी 1.14: गैर-वित्तीय गैर-पीएसयू ऑब्लिगर्स के सीपी और एनसीडी के निर्गम और निकट अवधि परिपक्वता

(₹ करोड़)

	निर्गमन			परिपक्वता						
	मार्च-20	अप्रैल-20	मई-20	मार्च-20	अप्रैल-20	मई-20	जून-20	जुलाई-20	अगस्त-20	सितंबर-20
'एएए'	26,100	35,865	43,310	28,044	2,732	20,225	21,840	13,820	23,354	7,026
'एए'	6,440	11,064	9,720	12,928	10,312	9,789	8,337	2,747	8,176	3,631
अन्य	5,015	6,801	272	9,898	12,560	3,261	7,723	6,713	1,853	6,594
कुल	37,555	53,730	53,302	50,870	25,604	33,275	37,901	23,279	33,383	17,251

स्रोत: प्राइम डाटाबेस

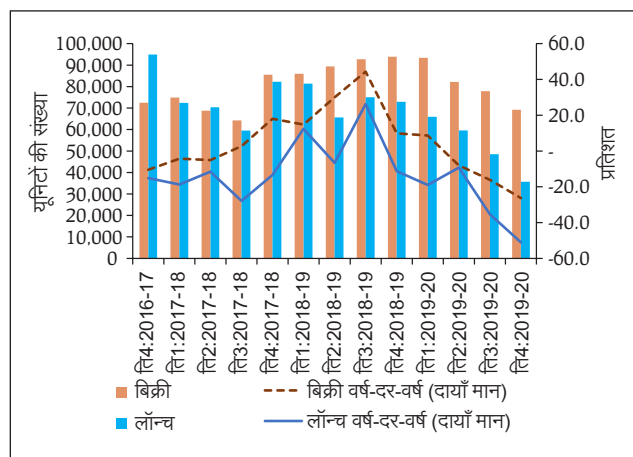
1.56 सीपी और एनसीडी के संदर्भ में, निकट अवधि की परिपक्वताएं रेटिंग ग्रेड में व्यापक विस्तार को दिखलाती हैं, यद्यपि उच्च रेटिंग की परिपक्वताएं हावी हैं (सारणी 1.14)।

1.2.5 आवास बाजार

1.57 कोविड-19 के प्रकोप के कारण, आवास क्षेत्र में मांग और तरलता में कमी बढ़ गई है। मकान की बिक्री और लॉन्च, जिसमें 2019-20 की तीसरी तिमाही के दौरान क्रमशः 16 प्रतिशत और 35 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की गिरावट आई थी, 2019-20 की चौथी तिमाही के दौरान क्रमशः लगभग 26 प्रतिशत और 51 प्रतिशत से नीचे आ गई (चार्ट 1.30)।

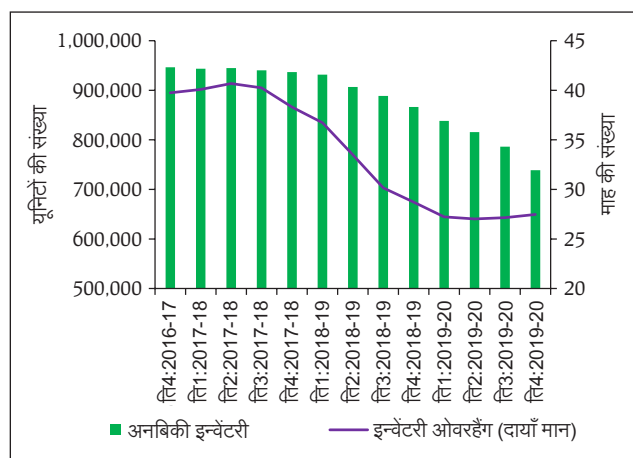
1.58 उपभोक्ता विश्वास में राष्ट्रव्यापी गिरावट ने पूर्ण रूप से तैयार घरों की खरीद की प्राथमिकता को बढ़ावा दिया, जिसने निर्माणाधीन घरों की बिक्री पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। नए लॉन्च मकानों में गिरावट आई, अनबिके घरों के स्टॉक में कमी आई और इन्वेन्ट्री ओवरहेंग (यानी एक घर बेचने के लिए महीनों की औसत संख्या) में गिरावट आई (चार्ट 1.31)।

चार्ट 1.30: मकान लॉन्च और बिक्री



स्रोत: प्रोप टाइगर डाटाबेस

चार्ट 1.31 अनबिके इन्वेन्टरी और इन्वेन्टरी ओवरहेंग



स्रोत: प्रोप टाइगर डाटाबेस

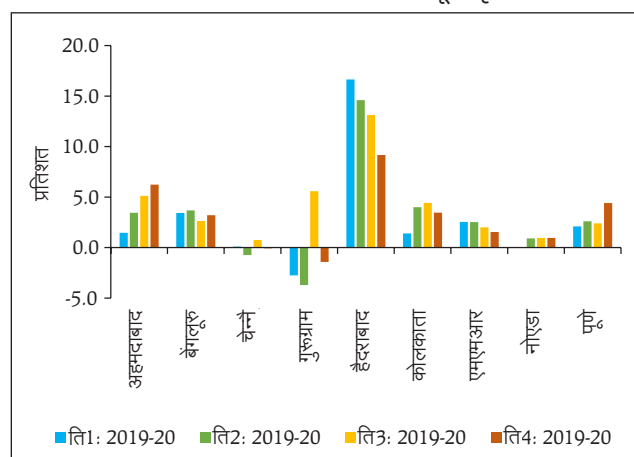
1.59 निर्माणाधीन परियोजनाओं में अनबिकी इन्वेंट्री का 70-80 फीसदी हिस्सा है। 2019-20 में अधिकांश शहरों में घरों के मूल्य में वृद्धि रुकी रही। मार्च के मध्य से देश भर में निर्माण गतिविधियों के निलंबित होने से, निर्माणाधीन परियोजनाओं के पूरा होने में देरी हो सकती है, जिससे नई मांग में बाधा आएगी (चार्ट 1.32)।

1.2.6 प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण⁶

1.60 हालिया प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण (एसआरएस) में सभी प्रमुख जोखिम समूहों जैसे; वैश्विक जोखिम, समष्टि आर्थिक स्थितियों पर जोखिम धारणा, वित्तीय बाजार जोखिम, और वित्तीय प्रणाली को प्रभावित करने वाली संस्थागत स्थिति को 'उच्च' माना गया था। समष्टि आर्थिक जोखिम समूह के अंतर्गत, घरेलू विकास के लिए जोखिम और राजकोषीय घाटे को 'बहुत उच्च' श्रेणी में माना गया था, जबकि एफआईआई में उलटफेर के कारण जोखिम, एफडीआई में मंदी, कॉर्पोरेट क्षेत्र की कमजोरियों, अचल संपत्ति की कीमतों और घरेलू बचत में कमी को 'उच्च जोखिम' श्रेणी माना गया था।

1.61 लगभग 56 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की संभावनाएं अगले एक वर्ष में काफी बिगड़ने वाली हैं, क्योंकि बैंकिंग उद्योग की कमाई धीमी रिकवरी, लॉकडाउन के बाद कम निवल ब्याज मार्जिन, उच्च आर्स्टि गुणवत्ता की चिंताओं और प्रावधान आवश्यकताओं में संभावित वृद्धि के कारण नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकती है। कोविड-19 महामारी से बुरी तरह से प्रभावित होने वाले शीर्ष तीन क्षेत्र हैं: (i) पर्यटन और आतिथ्य; (ii) निर्माण और अचल संपत्ति; और (सी) विमानना। इनके अगले छह महीनों में ठीक होने की संभावनाएं क्षीण दिखाई देती हैं। बहुसंख्यक उत्तरदाताओं ने इस बात का विरोध किया कि स्थानीयकरण पर अधिक जोर देने से वैश्वीकरण को वरीयता मिलेगी। और आगे जाकर, क्षेत्रीय व्यापार समझौतों को अधिक तरजीह दी जाएगी।

चार्ट 1.32: शहर-वार भारत औसत मूल्य वृद्धि



स्रोत: प्रोप टाइगर डाटाबेस

सारांश और दृष्टिकोण

1.62 कुल मिलाकर, वैश्विक संवृद्धि के बारे में एक अप्रत्याशित अनिश्चितता है, किन्तु अप्रत्याशित राजकोषीय और मौद्रिक प्रोत्साहनों के कारण वित्तीय बाजार में व्यापक रूप से स्थिरता है। भारत में राजकोषीय, मौद्रिक और विनियामक हस्तक्षेपों के संयोजन ने वित्तीय बाजारों को अनवरुद्ध रखा है और वित्तीय मध्यस्थ सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। बैंक ऋण जोखिम न लेने के स्पष्ट संकेत देता है। उथल पुथल का सामना करने के बाद, गैर-बैंक मध्यस्थ संस्थाएं समय पर और सोचे समझे नियामक हस्तक्षेपों के कारण स्थिर रही हैं। पूँजी के प्रवाह में अस्थायी रूप से वृद्धि हो रही है लेकिन बाहरी वित्तपोषण की जरूरतें पूरी नहीं हुई हैं। तेल को छोड़कर, पण्य बाजार के स्वीचओवर अवरुद्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार का पर्याप्त स्तर एक बफर प्रदान करता है। हालांकि, अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है, वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और मानकों को साथ लेकर वित्तीय क्षेत्र के सुधारों को फिर से शुरू करना होगा और साथ ही भविष्य में भारत की विकासात्मक रणनीति की विशिष्ट आवश्यकताओं के साथ समायोजन करना होगा।

⁶ प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण (एसआरएस) एक 10-बिंदु वाले पैमाने पर वित्तीय प्रणाली द्वारा सामना किए जा रहे प्रमुख जोखिमों पर विशेषज्ञों की धारणाओं को अभिव्यक्त करता है। विशेषज्ञों में बाजार सहभागी, शिक्षाविद और रेटिंग एजेंसियां शामिल हैं। एसआरएस छमाही आधार पर किया जाता है और एफएसआर (अनुबंध 1) में रिपोर्ट किया जाता है।

अध्याय II

वित्तीय संस्थाएं : सुदृढ़ता और समुत्थानशक्ति

वर्ष 2019-20 की दूसरी छमाही के दौरान बैंक ऋण वृद्धि घटक बैंक समूहों में कम रही। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का लाभप्रदता अनुपात, हालांकि वित्तीय वर्ष 2018-19 के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2019-20 में बेहतर रहा, वित्तीय वर्ष 2019-20 की दूसरी छमाही में गिर गया है और परिदृश्य ऋण वर्गीकरण के स्थगन के निहितार्थों के कारण धूमिल हो गया। ऋण जोखिम के लिए समष्टि तनाव के परीक्षण यह संकेत देते हैं कि बेसलाइन परिदृश्य के तहत, एससीबी की सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (जीएनपीए) अनुपात मार्च 2020 के 8.5 प्रतिशत से मार्च 2021 में बढ़कर 12.5 प्रतिशत (बहुत अधिक तनाव परिदृश्य की स्थिति में 14.7 प्रतिशत) हो सकती है, जबकि प्रणालीगत स्तर¹ जोखिम-भारित परिसंपत्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) मार्च 2020 के 14.6 प्रतिशत से मार्च 2021 में गिरकर 13.3 प्रतिशत (बहुत अधिक तनाव की स्थिति में परिदृश्य 11.8 प्रतिशत) तक हो सकती है। बैंकों का एनबीएफसी/एचएफसी में जोखिम बढ़ा है। उच्च पूंजीगत बफर्स और सिमटते अंतर-बैंक बाजार के कारण भी वित्तीय नेटवर्कों के माध्यम से संक्रामक जोखिम कम हो गए हैं।

परिचय

2.1 दिसंबर 2019 के एफएसआर के बाद से, वैश्विक और घरेलू स्तर पर, समष्टि आर्थिक और वित्तीय माहौल में गिरावट का, ऋण की मांग, परिसंपत्ति की गुणवत्ता, पूंजी पर्याप्तता और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, जो कोविड-19 के संपूर्ण प्रभाव का सामना कर रहे हैं, की लाभप्रदता पर असर पड़ा है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और सहकारी बैंकों का दबाव, जो 2019 में हुई ऋण घटनाओं के मद्देनजर बढ़ा है, बैंकों द्वारा जोखिम से बचने और सुरक्षा की तरफ पलायन के कारण बढ़ गया है, जिससे धन की कमी और बाजार तक पहुंच में अंतर पड़ गया है। काफी अधिक अनिश्चितता के कारण परिदृश्य अस्पष्ट हो गया है क्योंकि महामारी ने जान माल को काफी हानि पहुंचाई। हाल के नीतिगत उपायों के कारण वित्तीय बाजारों में स्थिरता आई है और कई वित्तीय मध्यस्थों द्वारा अनुभव किए गए चलनिधि दबाव कम हुए हैं।

2.2 इस पृष्ठभूमि के बावजूद, यह अध्याय बैंकों और एनबीएफसी की सुदृढ़ता और आघात सहनीयता का मूल्यांकन करता है। खंड II.1 एससीबी के ऋण प्रदर्शन, संपत्ति की गुणवत्ता, पूंजी पर्याप्तता और जोखिमों का मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। यह ऋण जोखिम के तनाव परीक्षण के माध्यम से समष्टि आर्थिक आघातों को सामने रखकर आघात सहनीयता

का भी मूल्यांकन करता है, जिसे (ए) ऋण, ब्याज दर, चलनिधि, संकेंद्रीकरण और इक्विटी मूल्य जोखिमों के बैंक स्तर के एकल कारक संवेदनशीलता विश्लेषण ; तथा (बी) पूंजी और चलनिधि के साथ-साथ डेरिवेटिव पोर्टफोलियो के उर्ध्वगामी तनाव परीक्षण से संपूरित किया गया है। खंड II.2 अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों (एसयूसीबी) के हालिया प्रदर्शन तथा ऋण और चलनिधि जोखिम के तनाव परीक्षण के परिणामों का परीक्षण करता है। खंड II.3 में एनबीएफसी के प्रमुख वित्तीय मापदंडों, सेक्टर के हालिया व्यवधानों और प्रणालीगत स्तर पर तनाव परीक्षण के परिणामों के साथ-साथ वैयक्तिक एनबीएफसी पर चर्चा की गई है। खंड II.4 में विशेष उल्लिखित खातों (एसएमए) की अंतर्निहित परिसंपत्तियों के रेटिंग वितरण का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। समापन खंड II.5 में भारतीय वित्तीय प्रणाली की नेटवर्क संरचना और कनेक्टिविटी का एक विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अंतर-बैंक बाजार, वित्तीय संस्थाओं के विभिन्न समूहों का/के प्रति एक्सपोजर और प्रतिकूल परिदृश्यों के संक्रामक विश्लेषण के परिणाम शामिल हैं।

II.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक²

2.3 हाल की अवधि को भारत के वाणिज्यिक बैंकिंग क्षेत्र के कार्य निष्पादन में एक संरचनात्मक बदलाव की दृष्टि से चिह्नित

¹ विश्लेषण आरबीआई की पर्यवेक्षी विवरणियों पर आधारित है, जिसमें एससीबी के केवल घरेलू परिचालन को कवर किया गया है, सिवाय बड़े कर्जदारों के आंकड़ों के मामले के, जो बैंकों के वैश्विक परिचालन पर आधारित हैं। सीआरएआर पूर्वानुमानों के लिए, बैंकिंग क्षेत्र की कुल संपत्ति के 98 प्रतिशत वाले 53 एससीबी (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी), निजी क्षेत्र के बैंक (पीवीबी) और विदेशी बैंक (एफबी) सहित) पर विचार किया गया है।

² अध्याय में किए गए विश्लेषण 10 जून 2020 तक नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित हैं, जो अनंतिम हैं। एससीबी में केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक और विदेशी बैंक शामिल हैं। वर्षों के दौरान आंकड़ों की तुलनात्मकता सुनिश्चित करने के लिए, आईडीबीआई बैंक को इस क्षेत्र में विश्लेषण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अंतर्गत शामिल किया गया है, हालांकि इसे 21 जनवरी, 2019 से विनियामकी प्रयोजनों के लिए एक निजी क्षेत्र का बैंक घोषित किया गया है।

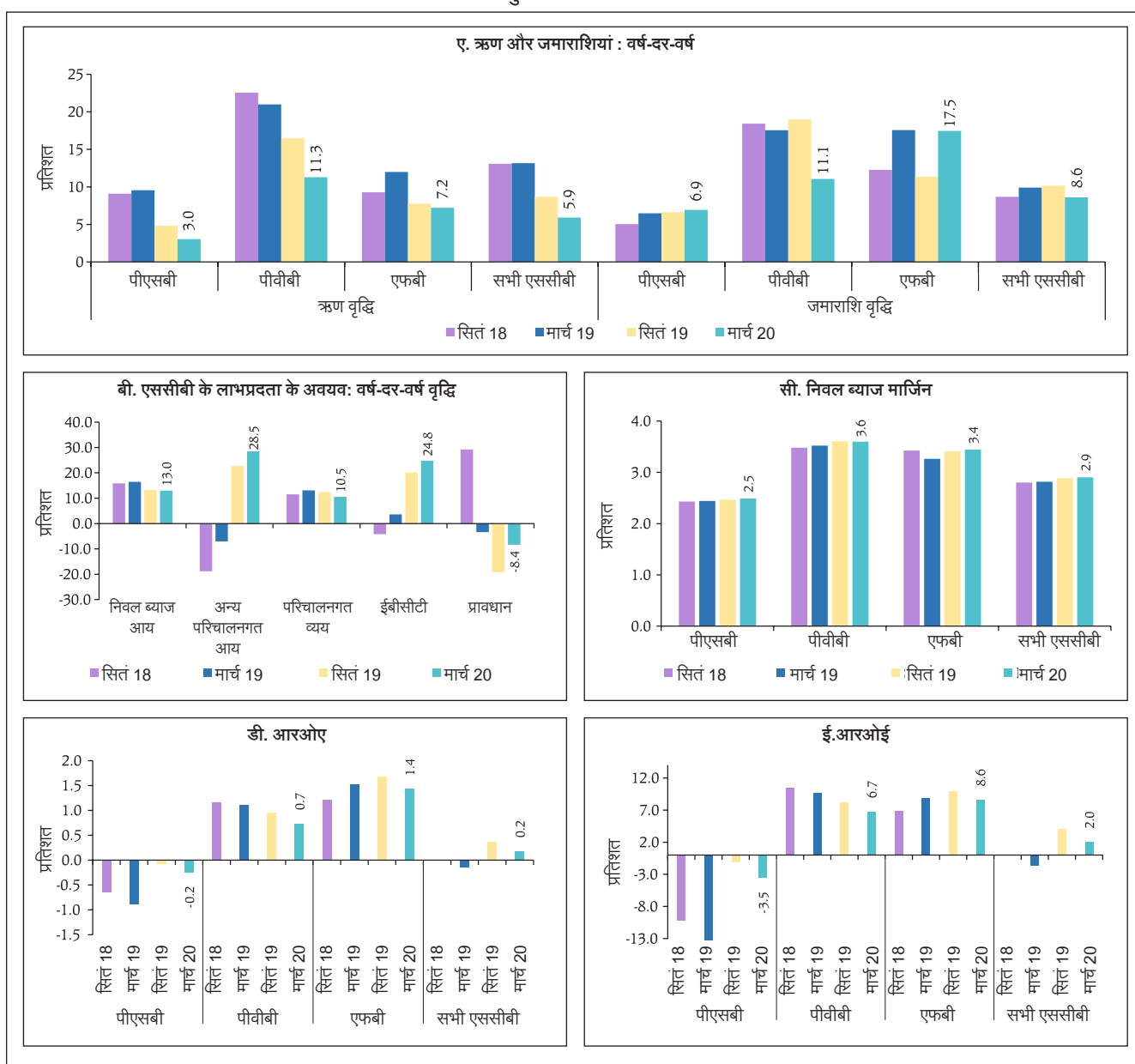
किया गया है। तनावग्रस्त आस्तियों के ओवर हैंग में कमी 2019-20 के शुरुआती हिस्से तक जारी रही, और वैश्विक और घरेलू संवृद्धि में लंबे समय तक जारी मंदी के बावजूद जिसने ऋण की मांग पर प्रभाव डाला, नई गिरावट में विराम लगा गया। वित्तीय वर्ष के अंत में, कोविड-19 के प्रकोप के कारण धीमी गति से हो रहे ये सुधार अभिभूत और ठप हो गए। महामारी के कारण विनियामकीय व्यवस्था के लिए

अनिवार्य हो गए ऋण किस्तों के स्थगन और ब्याज भुगतान के आस्थगन भविष्य में एससीबी के वित्तीय स्वास्थ्य के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं।

II.1.1 निष्पादन – परिसंपत्तियां और अर्जन

2.4 एससीबी की ऋण वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष), जो 2019-20 की पहली छमाही के दौरान काफी अधिक कमजोर हो गई थी, मार्च 2020 तक और गिरकर 5.9 प्रतिशत तक हो गई (चार्ट 2.1)

चार्ट 2.1: चुनिंदा कार्य निष्पादन संकेतक



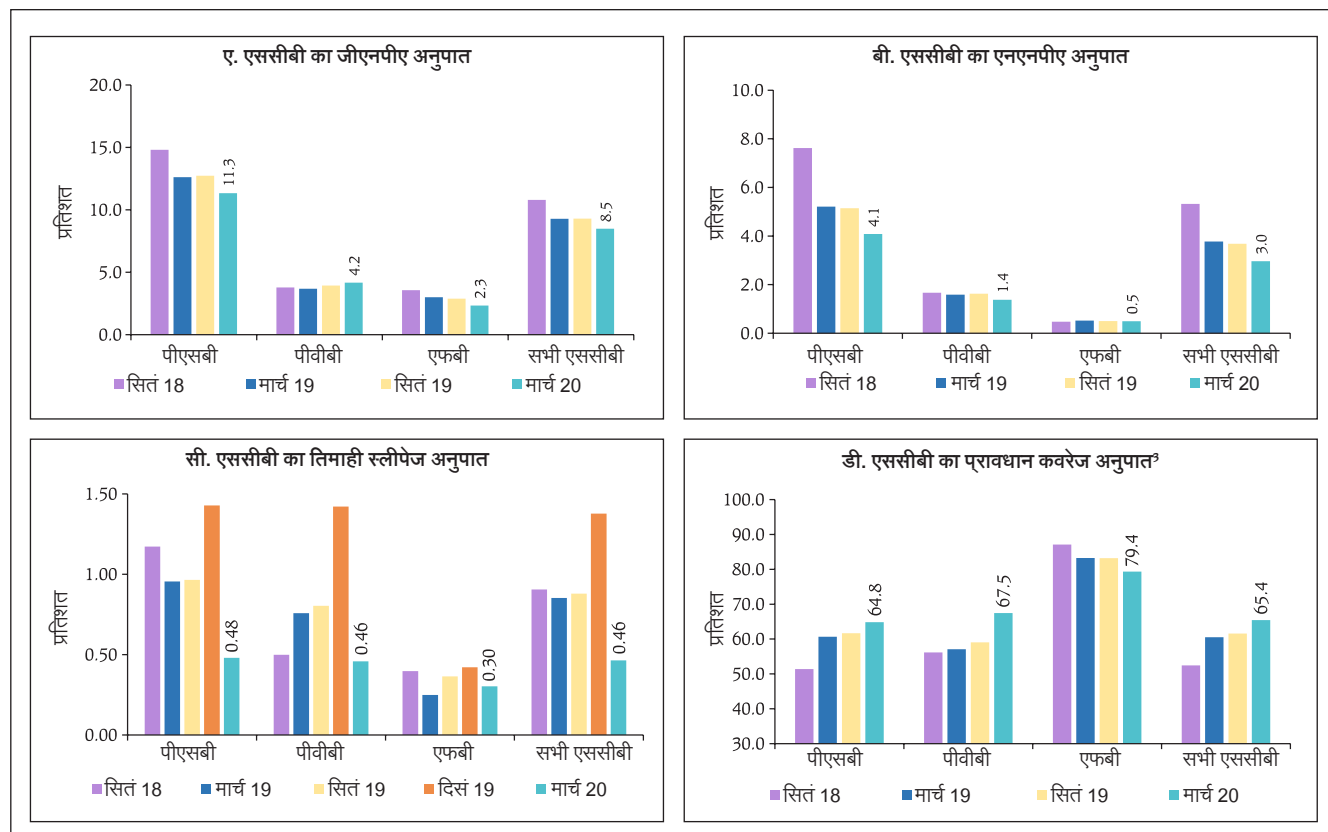
स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां और स्टाफ गणना

और जून 2020 की शुरुआत तक धीमी रही। यह कमी सभी बैंक समूहों में व्यापक रही। वर्ष-दर-वर्ष जमा वृद्धि भी 2019-20 की दूसरी छमाही के दौरान कम हुई, मुख्य रूप से पीवीबी के कारण थी (चार्ट 2.1 ए), हालांकि 2020-21 के शुरुआती महीनों में इसमें सुधार हुआ, जो कोविड-19 से संबंधित ऐहतियाती बचत व्यवहार को दर्शाता है। वाणिज्यिक बैंकों के प्रावधान और कर पूर्व मुनाफे (ईबीपीटी) को अन्य परिचालनगत आय (ओओआई) में वृद्धि और परिचालनगत व्यय की वृद्धि में कुछ कमी से समर्थन मिला (चार्ट 2.1 बी)। निवल ब्याज आय (एनआईआई) में मामूली कमी हुई जिसके कारण निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) सितंबर 2019 के स्तर तक आ गया (चार्ट 2.1 सी)। लाभप्रदता अनुपात, अर्थात्, परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (आरओए) और इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई), में वित्त वर्ष 2019-20 की दूसरी छमाही में सभी बैंक समूहों में गिरावट आई (चार्ट 2.1 डी और चार्ट 2.1 ई)।

II.1.2 परिसंपत्ति गुणवत्ता और पूंजी पर्याप्तता

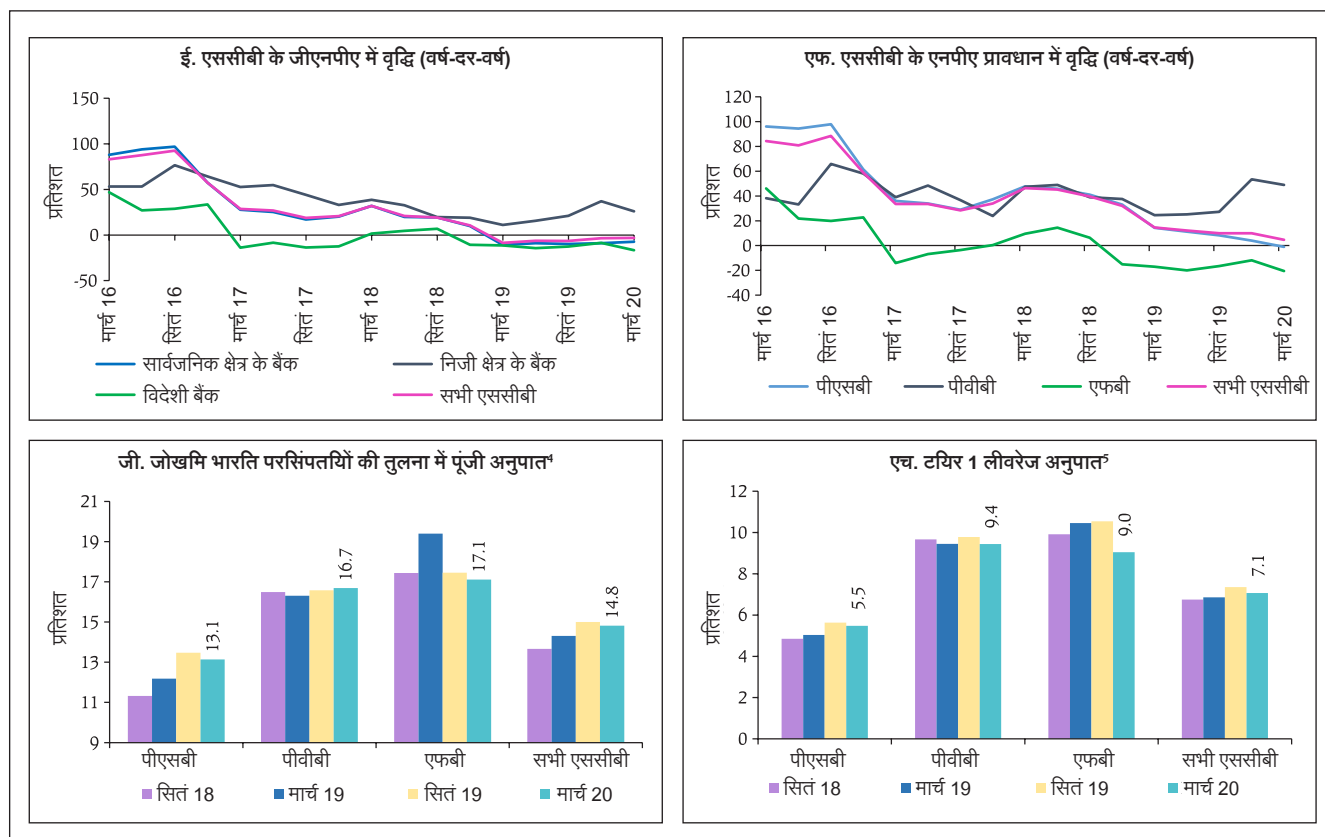
2.5 सभी एससीबी का सकल और निवल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (जीएनपीए और एनएनपीए) अनुपात जो सितंबर 2019 में 9.3 प्रतिशत और 3.7 प्रतिशत पर पहुंच गया था, मार्च 2020 में घटकर 8.5 प्रतिशत और 3.0 प्रतिशत पर आ गया (चार्ट 2.2 ए & बी)। यह सभी बैंक समूहों के गिरते तिमाही स्लीपेज अनुपात (तिमाही की शुरुआत में मानक अग्रिमों के अनुपात के रूप में तिमाही में एनपीए में नई अभिवृद्धि के रूप में गणना की गई) से स्पष्ट है (चार्ट 2.2 ग)। परिणामस्वरूप, एससीबी का प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) सितंबर 2019 में 61.6 प्रतिशत से मार्च 2020 में बढ़कर 65.4 प्रतिशत हो गया (चार्ट 2.2 डी)। मार्च 2019 के बाद से पीएसबी और एफबी के लिए एनपीए प्रावधान कम हो रहे हैं (चार्ट 2.2 एफ)।

चार्ट 2.2: चुनिंदा परिसंपत्ति गुणवत्ता संकेतक (जारी ...)



3 प्रावधान कवरेज अनुपात (राइट-ऑफ समायोजन के बिना) = एनपीए * 100/जीएनपीए के लिए धारित प्रावधान।

चार्ट 2.2: चुनिंदा परिसंपत्ति गुणवत्ता संकेतक (समाप्त)



स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां और स्टाफ गणना

2.6 एससीबी का जोखिम-भारित संपत्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) मार्च 2020 में घटकर 14.8 प्रतिशत हो गया, जिसका मुख्य कारण पीएसबी के सीआरएआर में कमी थी। उनका आरओए एक समूह के रूप में ऋणात्मक रहा, बावजूद धीमी ऋण वृद्धि और मामूली स्लीपेज के। बैंक समूहों के बीच, पीवीबी ने सीआरएआर में मामूली वृद्धि दर्ज की जबकि पीएसबी और एफबी के लिए अनुपात कम हो गया (चार्ट 2.2 जी)। मार्च 2020 में सभी बैंक समूहों के लिए टियर 1 लीवरेज अनुपात कम हो गया (चार्ट 2.2 एच)।

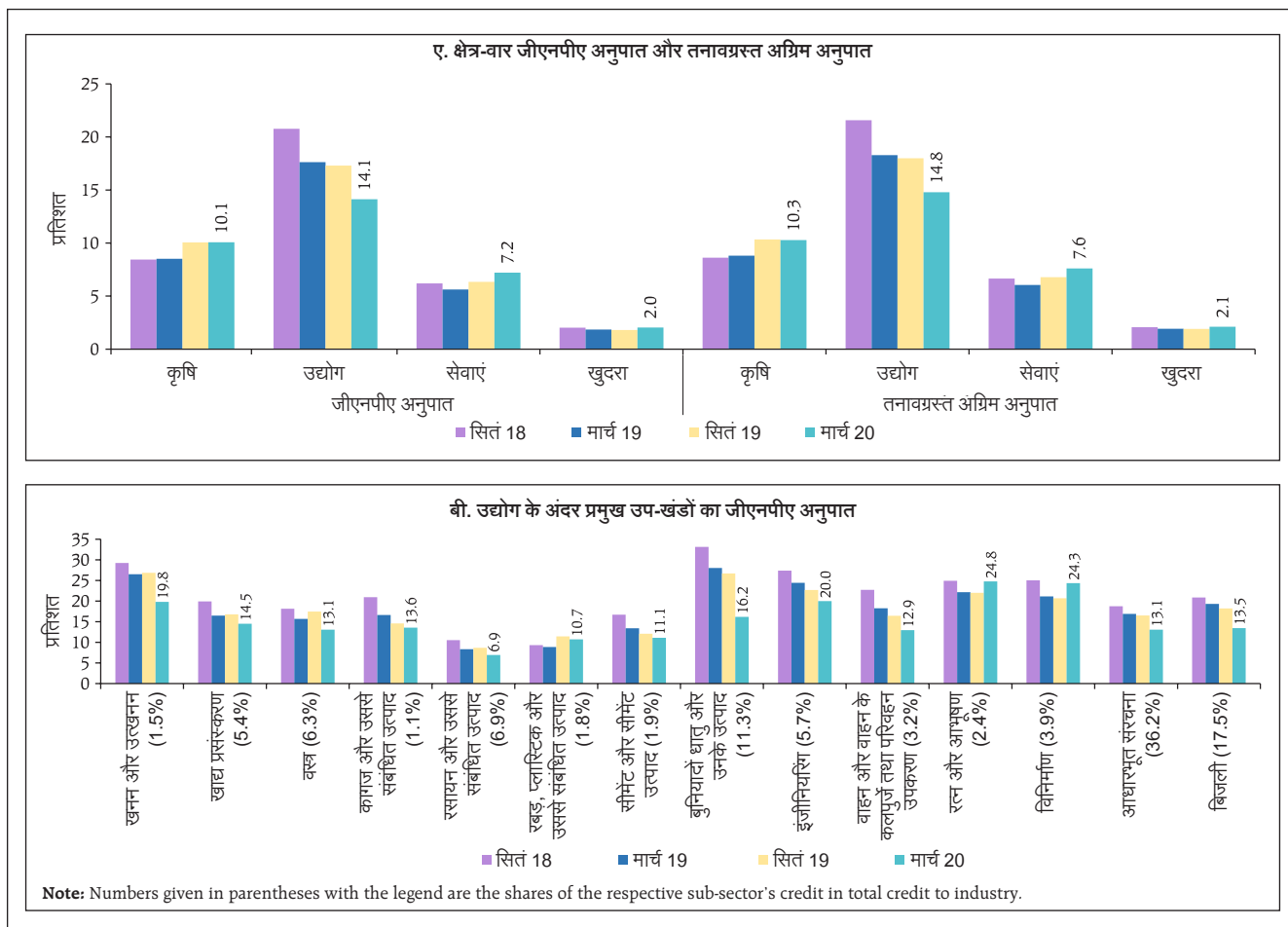
II.1.3 क्षेत्रवार परिसंपत्ति गुणवत्ता

2.7 क्षेत्रवार रूप से, मार्च 2020 में सेवा क्षेत्र में बैंक ऋणों की गुणवत्ता खराब हो गई। खुदरा ऋण क्षेत्र का जीएनपीए अनुपात भी बढ़ा (चार्ट 2.3 ए)। उद्योग के भीतर प्रमुख उप-क्षेत्रों में, निर्माण और रत्न तथा आभूषण क्षेत्र का जीएनपीए अनुपात मार्च 2020 में बढ़ गया (चार्ट 2.3 बी)। दूसरी ओर, बुनियादी ढांचा क्षेत्र (औद्योगिक क्षेत्र के बैंक ऋण में 36.2 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ), बुनियादी धातु (11.3 प्रतिशत) और बिजली (17.5 प्रतिशत) में जीएनपीए अनुपात

4 सीआरएआर सभी एससीबी से संबंधित है।

5 टियर 1 लीवरेज अनुपात कुल आस्तियों की तुलना में टियर 1 पूंजी का अनुपात है।

चार्ट 2.3: क्षेत्रवार परिसंपत्ति गुणवत्ता संकेतक



स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां और स्टाफ गणना

में एक स्पष्ट गिरावट दिखाई दी है। इसका बैंकिंग क्षेत्र की समग्र परिसंपत्ति गुणवत्ता में प्रभाव पड़ा है।

II.1.4 बड़े उधारकर्ताओं की ऋण गुणवत्ता

2.8 मार्च 2020 में एससीबी के बड़े उधारकर्ता⁶, क्रमशः 51.3 प्रतिशत और 78.3 प्रतिशत के समग्र ऋण पोर्टफोलियो और जीएनपीए के लिए जिम्मेदार हैं (चार्ट 2.4ए)। मार्च 2018 के बाद से इन दोनों के भागों में गिरावट आई है, इसका मतलब

है कि वृद्धिशील आधार पर, हाल कि अवधि में छोटे उधारकर्ता श्रेणी में ऋण और एनपीए में वृद्धि हो रही है। एसएमए⁷-0, एसएमए-1, एसएमए-2 और पुनर्गठित मानक ऋण श्रेणी तथा बड़े उधारकर्ताओं के एनपीए के तहत बकाया राशि मार्च 2020 को समाप्त तिमाही के दौरान कम हो गई (चार्ट 2.4 बी)। पीवीबी को छोड़कर सभी बैंकों में तिमाही के दौरान बड़े उधारकर्ताओं के जीएनपीए अनुपात में गिरावट आई (चार्ट 2.4 सी)। विदेशी बैंकों को छोड़कर सभी बैंक समूहों में बड़े उधारकर्ताओं के

⁶ एक बड़े उधारकर्ता को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके पास 5 करोड़ और उससे अधिक का निधि-आधारित और गैर-निधि-आधारित एक्सपोजर है यह विश्लेषण एससीबी के वैश्विक परिचालनों पर आधारित है।

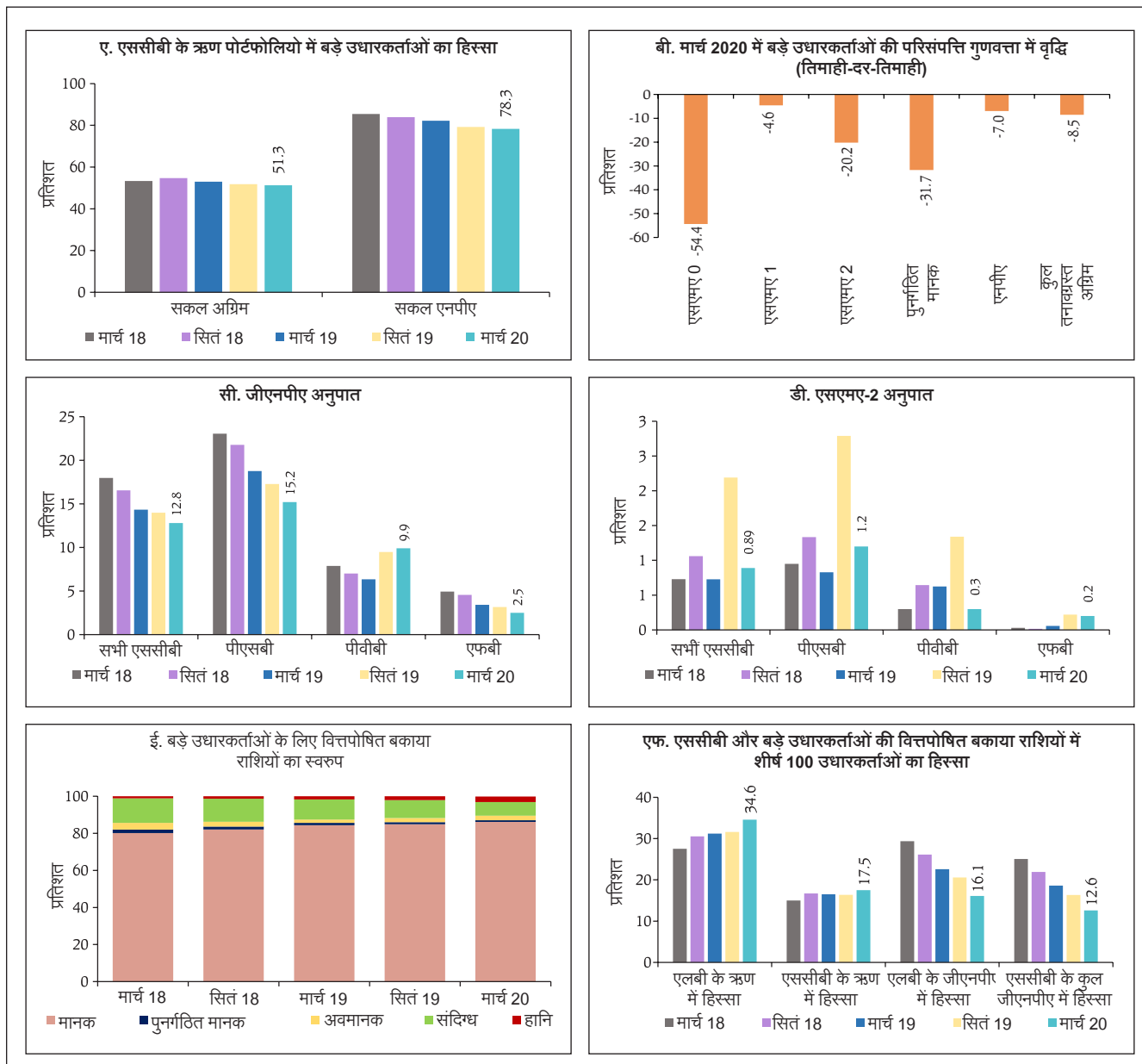
⁷ एसएमए-0, एसएमए-1 और एसएमए-2 श्रेणियां: मानक संपत्ति जो क्रमशः 1-30 दिन, 31-60 दिन और 60-90 दिन के लिए अतिदेय हैं।

एसएमए-2 अनुपात में गिरावट आई (चार्ट 2.4 डी)। इसी तरह, बड़े उधारकर्ताओं के लिए वित्तपोषित राशि में हानि परिसंपत्तियों का हिस्सा बढ़ रहा है (चार्ट 2.4 ई)।

2.9 शीर्ष 100 उधारकर्ता सकल अग्रिमों का 17.5 प्रतिशत हिस्सा हैं, लेकिन वे मार्च 2020 में एससीबी के जीएनपीए के

केवल 12.6 प्रतिशत हैं (चार्ट 2.4 एफ)। चूंकि कोविड-19 से संबंधित विनियामकी अधिस्थगन में एसएमए अनुपात एक कारक है, इसलिए रेटिंग वितरण की जांच के द्वारा एसएमए परिसंपत्तियों की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए एक अलग विश्लेषण खंड II.4 में प्रस्तुत किया गया है।

चार्ट 2.4: बड़े उधारकर्ताओं के चुनिंदा परिसंपत्ति गुणवत्ता संकेतक



स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां और स्टाफ गणना

II.1.5 जोखिम

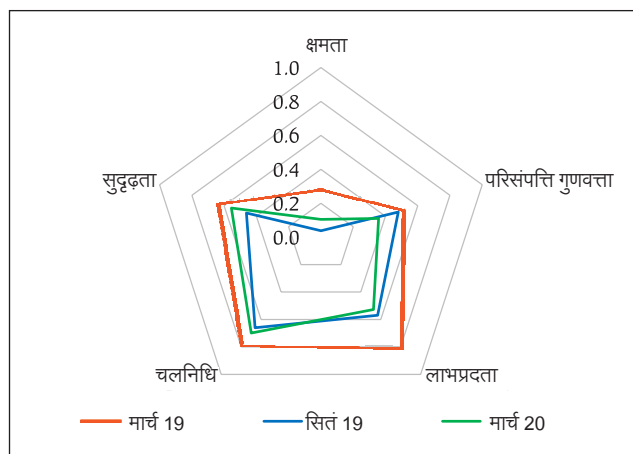
2.10 बैंकिंग स्थिरता संकेतक (बीएसआई)⁸ दिखाता है कि अंतर्निहित दशाओं और जोखिम कारकों में बदलावों के मूल्यांकन के लिए विचारित पांच आयामों में, एससीबी ने सितंबर 2018 की स्थिति की तुलना में मार्च 2020 में सुदृढ़ता, चलनिधि और दक्षता में गिरावट दर्ज की है, जबकि संपत्ति की गुणवत्ता और लाभप्रदता में मामूली सुधार हुआ है (चार्ट 2.5)। किंतु, इस मोर्चे पर किसी राहत की बात नहीं काही जा सकती क्योंकि कोविड-19 के दौरान बैंकों की आय में कोई नुकसान 2020-21 की पहली तिमाही से ही दिखाई देगा।

II.1.6 आघात सहनीयता – समष्टि दबाव परीक्षण

2.11 समष्टिआर्थिक आघातों को देखते हुए भारतीय बैंकिंग की आघात सहनीयता का परीक्षण समष्टि-दबाव परीक्षणों के माध्यम से किया गया, जो एससीबी के तुलन-पत्र पर संचयी आघात के प्रभाव का आकलन और एक वर्ष के दौरान बेसलाइन तीन प्रतिकूल⁹ (मध्यम, गंभीर और अति गंभीर) परिदृश्यों के अंतर्गत जीएनपीए अनुपात और सीआरआई का अनुमान लगाने का प्रयास है। बेसलाइन परिदृश्य समष्टिआर्थिक चरों¹⁰ के पूर्वानुमानित मूल्यों से लिया गया है। चूंकि मार्च 2020 में परिसंपत्ति वर्गीकरण कोविड-19 महामारी के कारण विनियामी अधिस्थगन से प्रभावित हो सकता है, इस अभ्यास के अनुमान जून 2011 से दिसंबर 2019 को समाप्त तिमाही (मार्च 2020 के बजाय) के आंकड़ों का उपयोग करके बनाए गए हैं। मध्यम, गंभीर और अति गंभीर परिदृश्य प्रत्येक समष्टि आर्थिक चरों के लिए क्रमशः 0.25 से एक मानक विचलन (एसडी) आघात, 1.25 से दो एसडी आघात और 2.25 से तीन एसडी आघात का उपयोग करके प्राप्त किया गया है, जिससे प्रत्येक परवर्ती अनुमान तिमाही में आघातों में 25 आधार अंक की वृद्धि हुई है (चार्ट 2.6)।

2.12 इस तथ्य को देखते हुए कि ऋण स्थगन का प्रभाव अभी भी अनिश्चित है और विकसित हो रहा है, बैंकिंग परिसंपत्तियों की गुणवत्ता पर इसका सही सही स्वरूप कैसा होगा, सटीक

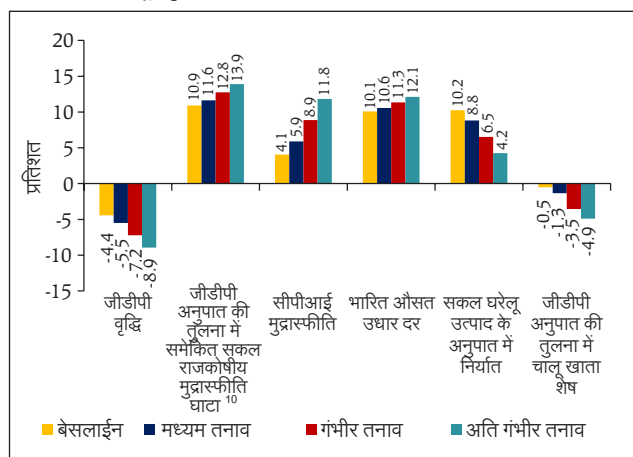
चार्ट 2.5: बैंकिंग स्थिरता मानचित्र



नोट: केंद्र से दूरी जोखिम में वृद्धि को दर्शाती है।

स्रोत : आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां और स्टाफ गणना।

चार्ट 2.6: समष्टि आर्थिक परिदृश्य मूल्यांकन
(कड़ी काल्पनिक प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियों के तहत आकलन को पूर्वानुमान के रूप में व्याख्या नहीं की जानी चाहिए)



8 विभिन्न बीएसआई आयामों के तहत उपयोग की जाने वाली विस्तृत कार्यप्रणाली और बुनियादी संकेतकों के लिए कृपया अनुबंध-2 देखें।

9 प्रतिकूल परिदृश्य काल्पनिक प्रतिकूल आर्थिक स्थितियों के तहत कड़े आकलन हैं और मॉडल परिणामों की पूर्वानुमान के रूप में व्याख्या नहीं किया जाना चाहिए।

10 जीडीपी विकास, संयुक्त सकल राजकोषीय घाटा और जीडीपी का अनुपात, सीपीआई मुद्रास्फीति, भारत औसत उधार दर, निर्यात और जीडीपी का अनुपात तथा चालू खाता शेष और जीडीपी का अनुपात। संयुक्त सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) केंद्र और राज्यों के समग्र राजकोषीय घाटे का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन पहले केंद्र के जीएफडी का प्रयोग किया जाता था।

तरीके से पता लगाना मुश्किल है। इसलिए, यह केवल समय बीतने के साथ पता लग पाएगा और समय-समय पर आरबीआई के आगामी प्रकाशनों में इसके परिणामों की जानकारी दी जाएगी।

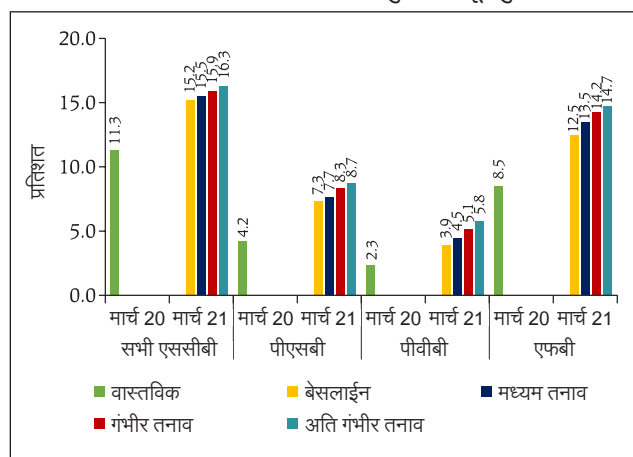
2.13 दबाव परीक्षणों से संकेत मिलता है कि बेसलाइन परिदृश्य के तहत सभी एससीबी का जीएनपीए अनुपात मार्च 2020 के 8.5 प्रतिशत से मार्च 2021 तक बढ़कर यह 12.5 प्रतिशत हो सकता है (चार्ट 2.7)। यदि समष्टि आर्थिक माहौल और बिगड़ता है, तो अनुपात बहुत गंभीर तनावग्रस्त परिदृश्य के तहत 14.7 प्रतिशत तक बढ़ सकता है।

2.14 बैंक समूहों में, बेसलाइन परिदृश्य के अंतर्गत पीएसबी का जीएनपीए अनुपात मार्च 2020 के 11.3 प्रतिशत से मार्च 2021 तक बढ़कर 15.2 प्रतिशत हो सकता है और इसी अवधि में पीवीबी और एफबी का जीएनपीए अनुपात 4.2 प्रतिशत और 2.3 प्रतिशत से क्रमशः बढ़कर 7.3 और 3.9 प्रतिशत हो सकता है।

2.15 बेसलाइन परिदृश्य के तहत प्रणाली स्तरीय सीआरएआर के मार्च 2020 के 14.6 प्रतिशत से मार्च 2021 में घटकर 13.3 प्रतिशत और बहुत गंभीर तनाव परिदृश्य के तहत 11.8 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है (चार्ट 2.8 ए)।

2.16 तनाव परीक्षण के परिणाम बताते हैं कि पांच बैंक मार्च 2021 तक बहुत गंभीर तनाव के परिदृश्य में न्यूनतम पूंजी स्तर को पूरा करने में विफल हो सकते हैं। हालांकि, इसमें विलय या

चार्ट 2.7: एससीबी के जीएनपीए अनुपात का पूर्वानुमान

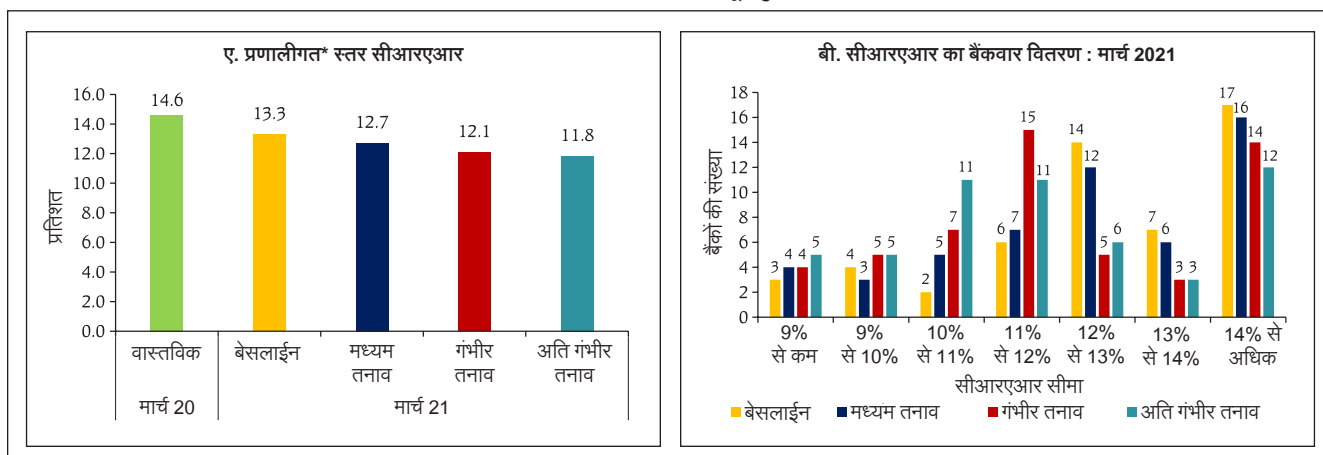


नोट: प्रणालीगत स्तर के जीएनपीए को तीन संपूरक और परिणामी जीएनपीए अनुपात का औसत अर्धमितीय मॉडल- मल्टीवेरेंट रियेशन, वेक्टर ऑटोरियेशन (वीएआर) और क्वांटाइल रियेशन का उपयोग करके अनुमानित किया जाता है। बैंक समूह स्तर के अनुमानों के लिए, मल्टीवेरिएट रियेशन और वीएआर परिणामों के औसत का उपयोग किया जाता है।
स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियाँ और स्टाफ गणना

किसी भावी पुनर्पूँजीकरण को ध्यान में नहीं रखा गया है, जिससे आगे प्रणालीगत आघात सहनीयता में वृद्धि होगी (चार्ट 2.8 बी)।

2.17 बेसलाइन परिदृश्य के तहत एससीबी का सामान्य इक्विटी टीयर I (सीईटी-1) पूंजी अनुपात मार्च 2020 में 11.7 प्रतिशत से घटकर 10.7 प्रतिशत और मार्च 2021 में अति गंभीर तनाव परिदृश्य के तहत 9.4 प्रतिशत हो सकता है (चार्ट 2.9)। इसके अलावा, इन शर्तों के तहत, तीन बैंक मार्च 2021 तक 5.5 प्रतिशत के न्यूनतम विनियामकी सीईटी 1 पूंजी अनुपात को पूरा करने में विफल हो सकते हैं (चार्ट 2.9 बी)।

चार्ट 2.8: सीआरएआर पूर्वानुमान

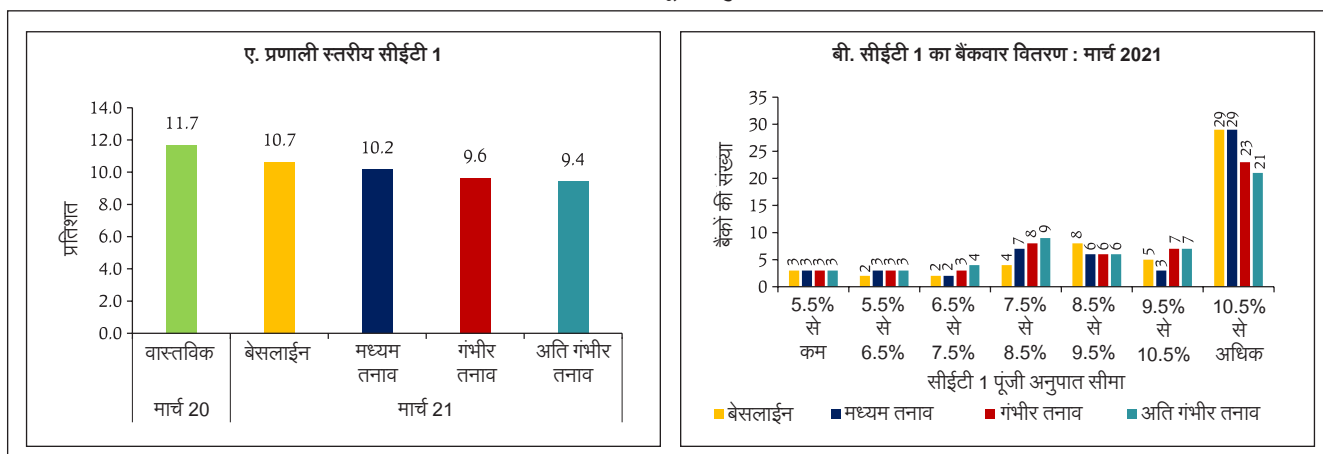


* नमूने के 53 चुनिंदा बैंक कुल बैंकिंग क्षेत्र की संपत्ति का 98 प्रतिशत हिस्सा हैं।

नोट: लाभ वाले एससीबी के लिए पूंजी अनुमान को पूंजीगत आरक्षित निधि में 25 प्रतिशत के न्यूनतम लाभ को हस्तांतरण करने की एक रूढ़िवादी धारणा के तहत निर्मित किया गया है। इसमें हितधारकों द्वारा किसी भी पूंजी को डालने की बात को ध्यान में नहीं रखा जाता है।

स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियाँ और स्टाफ गणना

चार्ट 2.9: सीईटी 1 पूंजी अनुपात की जांच



* नमूने के 53 चुनिंदा बैंक कुल बैंकिंग क्षेत्र की संपत्ति का 98 प्रतिशत हिस्सा हैं।

नोट: लाभ वाले एससीबी के लिए पूंजी अनुमान को पूंजीगत आरक्षित निधि में 25 प्रतिशत के न्यूनतम लाभ को हस्तांतरण करने की एक रूढ़िवादी धारणा के तहत निर्मित किया गया है। इसमें हितधारकों द्वारा किसी भी पूंजी को डालने की बात को ध्यान में नहीं रखा जाता है।

स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां और स्टाफ गणना

2.18 जबकि विनियामी ऋण अधिस्थगन कुछ तनाव को कम कर सकते हैं, पीएसबी और पीवीबी के अच्छी गुणवत्ता वाले ऋणों की उद्योग-वार संरचना (अर्थात्, मानक अग्रिम जो अभी तक एसएमए और एसएमए-0 ऋण में नहीं बदले हैं) बताती है कि ऐसे उद्योग, जिनकी बैंक समूहों में ऐसे ऋणों की अधिक हिस्सेदारी है, कोविड-19 संकट के कारण प्रभावित हो सकते हैं (तालिका 2.1)।

II.1.7 संवेदनशीलता विश्लेषण¹¹

2.19 विभिन्न परिदृश्यों¹² के तहत एससीबी की कमजोरियों का आकलन करने के लिए मार्च 2011 से मार्च 2020 तक तिमाही आंकड़ों के आधार पर कई एकल-फैक्टर संवेदनशीलता तनाव परिक्षण¹³ किए गए ताकि ऋण, ब्याज दर, इक्विटी की कीमतों और चलनिधि जोखिमों का अनुकरण किया जा सके और टॉप-डाउन¹⁴ संवेदनशीलता विश्लेषण के अंतर्गत मूल रूप दिया जा सके।

सारणी 2.1: अच्छी गुणवत्ता की परिसंपत्तियों के उच्च हिस्से वाले शीर्ष 10 उद्योग

सार्वजनिक बैंक		निजी बैंक	
उद्योग	मार्च 2020 तक कुल अच्छी गुणवत्ता वाले ऋणों के हिस्से के रूप में उद्योग के अच्छे गुणवत्ता वाले ऋणों का हिस्सा	उद्योग	मार्च 2020 तक कुल अच्छी गुणवत्ता वाले ऋणों के हिस्से के रूप में उद्योग के अच्छे गुणवत्ता वाले ऋणों का हिस्सा
एनबीएफसी- सामान्य प्रयोजन ऋण	10.4	एनबीएफसी- सामान्य प्रयोजन ऋण	7.9
बिजली का उत्पादन	9.8	बिजली का उत्पादन	6.0
एनबीएफसी- आवास क्षेत्र में	7.7	रियल एस्टेट गतिविधियाँ	5.5
विकासत्मक वित्तीय संस्थाएं	4.6	मूलभूत लौह और स्टील का उत्पादन	4.1
परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों का विनिर्माण	4.6	एनबीएफसी- आवास क्षेत्र में	3.6
मूलभूत लौह और स्टील का उत्पादन	4.4	सड़कों का निर्माण / रखरखाव	2.4
सड़कों का निर्माण / रखरखाव	3.9	आधारभूत संचार सेवाएं	2.4
ग्राहकों समितियों के माध्यम से जन उपयोग सुविधाएं	3.3	परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन	2.4
बिजली का संग्रहण और वितरण	2.5	आधारभूत अलौह धातुओं का उत्पादन	1.7
रियल एस्टेट गतिविधियाँ	2.3	सीमेंट, चूना और प्लास्टर का उत्पादन	1.7

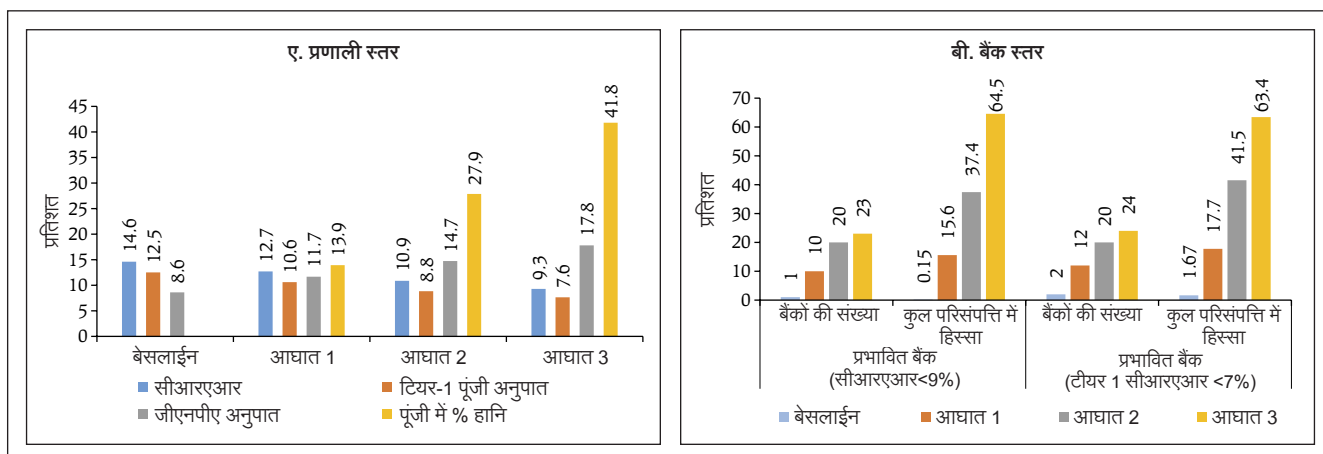
स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां और स्टाफ गणना

11 समष्टि तनाव परीक्षणों के तहत, आघात प्रतिकूल समष्टिआर्थिक स्थितियों में थे जबकि संवेदनशीलता विश्लेषण आघात एक समय में जीएनपीए, ब्याज दर, इक्विटी मूल्य, जमा आदि एकल कारकों पर लागू होते हैं। इसके अलावा, जीएनपीए अनुपात के लिए समष्टि तनाव परीक्षण प्रणाली और प्रमुख बैंक समूह स्तरों पर लागू किए गए थे, जबकि संवेदनशीलता का विश्लेषण प्रणाली और बैंक स्तरों पर किया गया।

12 एकल कारक संवेदनशीलता विश्लेषण तनाव परीक्षण कुल बैंकिंग क्षेत्र की परिसंपत्तियों के 98 प्रतिशत वाले 53 एससीबी के नमूने के लिए किए गए। विभिन्न काल्पनिक परिदृश्यों के तहत डिजाइन किए गए आघात चरम लेकिन विश्वसनीय हैं।

13 तनाव परीक्षणों के विवरण के लिए कृपया अनुबंध-2 देखें।

चार्ट 2.10: क्रेडिट जोखिम - आघात और परिणाम



आघात 1: जीएनपीए पर 1 एसडी आघात
 आघात 2: जीएनपीए पर 2 एसडी आघात
 आघात 3: जीएनपीए पर 3 एसडी आघात

नोट: चुनिंदा 53 एससीबी की प्रणाली।

स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां और स्टाफ गणना।

ए. ऋण जोखिम

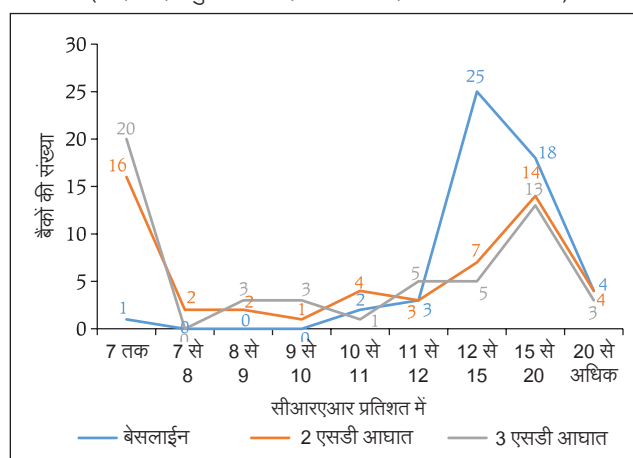
2.20 प्रणाली स्तरीय जीएनपीए के प्रति 3 एसडी¹⁵ के अति गंभीर आघात के तहत (अर्थात्, यदि 53 चुनिंदा एससीबी का जीएनपीए अनुपात 8.6 प्रतिशत से बढ़कर 17.8 प्रतिशत हो जाता है), प्रणाली स्तरीय सीआरएआर 14.6 प्रतिशत से घटकर 9.3 प्रतिशत और टियर-1 पूंजी अनुपात 12.5 प्रतिशत से घटकर 7.6 प्रतिशत हो जाएगा। इस प्रकार प्रणालीगत स्तर पर पूंजी में हानि लगभग 41.8 प्रतिशत हो सकती है। प्रतिकूल तनाव परीक्षण के परिणाम बताते हैं कि प्रणाली स्तर पर सीआरएआर को 9 प्रतिशत तक लाने के लिए 3.26 एसडी के आघात की आवश्यकता होती है।

2.21 बैंक-स्तरीय तनाव परीक्षण के परिणाम बताते हैं कि एससीबी की कुल परिसंपत्ति में 64.5 प्रतिशत की हिस्सेदारी वाले 23 बैंक¹⁶, जीआरपीए अनुपात के 3 एसडी आघात के परिदृश्य के तहत अपेक्षित सीआरएआर को बनाए रखने में विफल हो सकते हैं (चार्ट 2.10)। इस तरह के चरम आघात परिदृश्य में, सभी 18 पीएसबी के सीआरएआर के 9 प्रतिशत तक नीचे जाने की संभावना है।

2.22 जीएनपीए अनुपात के 3 एसडी आघात के परिदृश्य के तहत, 20 बैंकों के लिए सीआरएआर 7 प्रतिशत से नीचे गिर जाएगा (चार्ट 2.11), जो बैंकों की सूची पर हावी होकर बड़े पूंजी क्षरण का साक्षी होगा।

2.23 15 और 20 बैंक क्रमशः 2 एसडी और 3 एसडी आघात के तहत सीआरएआर में छह प्रतिशत से अधिक गिरावट दर्ज करेंगे (चार्ट 2.12)।

चार्ट 2.11: बैंकों का सीआरएआर-वार वितरण (जीएनपीए अनुपात पर 2 एसडी और 3 एसडी आघात के तहत)



नोट: चुनिंदा 53 एससीबी की प्रणाली।

स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां और स्टाफ गणना।

14 टॉप डाउन तनाव परीक्षण विशिष्ट परिदृश्यों और कुल बैंकवार डेटा पर आधारित थे जिससे विभिन्न बैंकों के तनाव का तुलनात्मक मूल्यांकन दिया जा सके।

15 जीएनपीए अनुपात के मानक विचलन (एसडी) को 2011 से तिमाही आंकड़ों का उपयोग करके अनुमानित किया गया है। एक एसडी आघात जीएनपीए के स्तर में 36 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाता है।

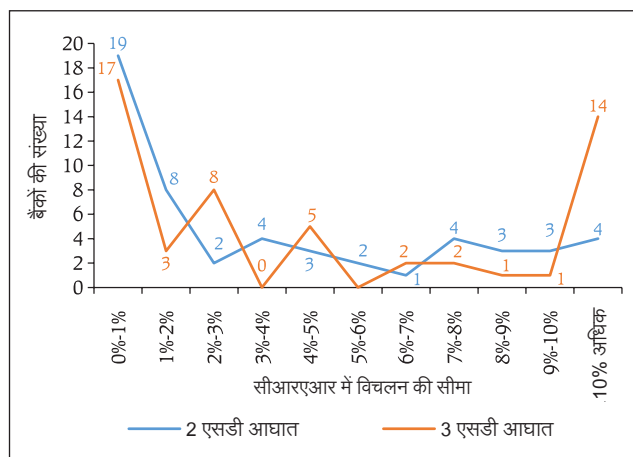
16 इन बैंकों में, आघातों के लागू होने से पहले एक बैंक का सीआरएआर 9 प्रतिशत से कम था।

ख. ऋण संकेंद्रण जोखिम

2.24 शीर्ष वैयक्तिक उधारकर्ताओं के दबावग्रस्त अग्रिमों के अनुसार बैंक के ऋण संकेंद्रण पर दबाव परीक्षण यह दर्शाता है कि शीर्ष तीन उधारकर्ताओं द्वारा चुकौती में चूक करने¹⁷ के चरम परिदृश्य में उन तीन बैंकों पर इसका प्रभाव काफी अधिक रहा जिनकी एससीबी की कुल आस्तियों में 2.7 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। शीर्ष 1, 2 और 3 दबावग्रस्त उधारकर्ताओं द्वारा चूक करने के कल्पित परिदृश्य में प्रणाली स्तर में सीआरएआर पर प्रभाव क्रमशः 34, 51 और 63 आधार अंक होगा (चार्ट 2.13)।

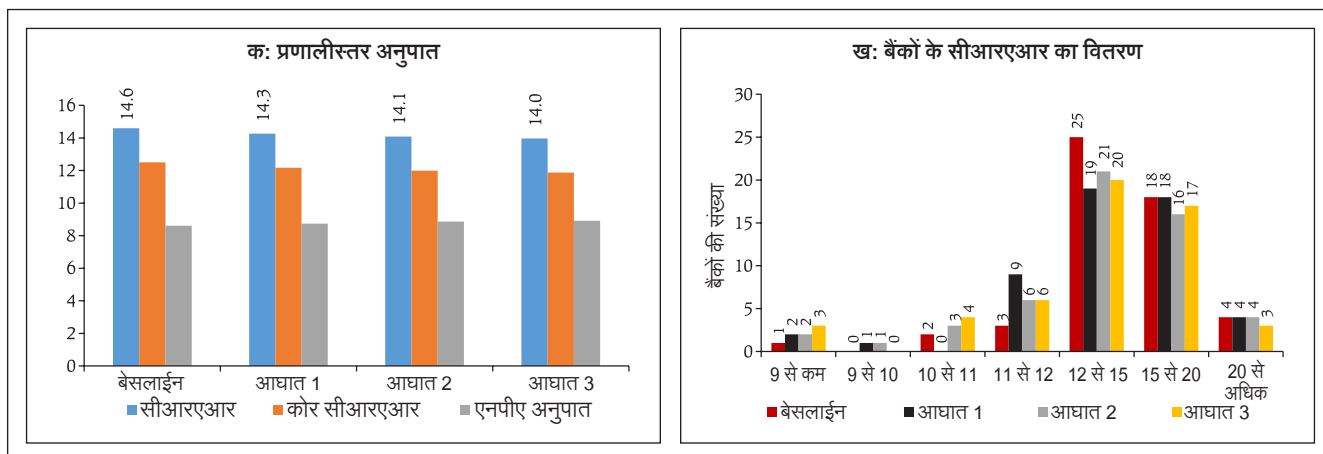
2.25 मानक एक्सपोजर के अनुसार शीर्ष वैयक्तिक उधारकर्ताओं पर विचार करने पर बैंक के ऋण संकेंद्रण पर दबाव परीक्षण दर्शाता है कि शीर्ष तीन वैयक्तिक उधारकर्ताओं द्वारा चुकौती में चूक करने¹⁸ के चरम परिदृश्य में, दो बैंकों पर इसका प्रभाव काफी अधिक था (चार्ट 2.14)। सभी शीर्ष तीन वैयक्तिक उधारकर्ताओं द्वारा चूक करने के कल्पित परिदृश्य के तहत प्रणाली स्तर पर सीआरएआर 140 आधार अंक नीचे गिर जाएगा।

चार्ट 2.12: सीआरएआर में बदलाव की सीमा (जीएनपीए अनुपात पर 2 एसडी और 3 एसडी आघात के तहत)



नोट: चुनिंदा 53 एससीबी की प्रणाली।
स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणी और स्टाफ गणना।

चार्ट 2.13: ऋण संकेंद्रण जोखिम: वैयक्तिक उधारकर्ता – दबावग्रस्त अग्रिम

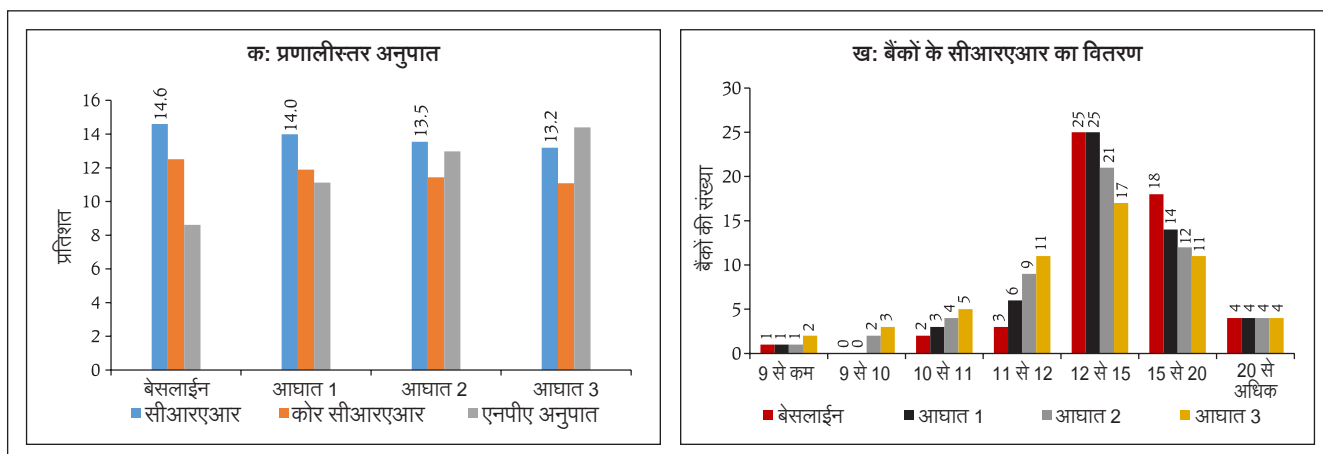


नोट: चयनित 53 एससीबी प्रणाली के लिए।
आघात 1: शीर्षस्थ दबावग्रस्त वैयक्तिक उधारकर्ता भुगतान करने की अपनी प्रतिबद्धता में विफल रहता है।
आघात 2: शीर्ष 2 दबावग्रस्त वैयक्तिक उधारकर्ता भुगतान करने की अपनी प्रतिबद्धता में विफल रहते हैं।
आघात 3: शीर्ष 3 दबावग्रस्त वैयक्तिक उधारकर्ता भुगतान करने की अपनी प्रतिबद्धता में विफल रहते हैं।
स्रोत: रिजर्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणी और स्टाफ आकलन।

¹⁷ चूक होने की स्थिति में यह मान लिया जाता है कि उधारकर्ता अवमानक या पुनर्संचित वर्ग से हानि वर्ग में आ गया है।

¹⁸ चूक होने की स्थिति में यह मान लिया जाता है कि उधारकर्ता मानक वर्ग से अवमानक वर्ग में आ गया है।

चार्ट 2.14: ऋण संकेंद्रण जोखिम: वैयक्तिक उधारकर्ता – एक्सपोजर



नोट: चयनित 53 एससीबी प्रणाली के लिए
 आघात 1: शीर्षस्थ दबावग्रस्त वैयक्तिक उधारकर्ता भुगतान करने की अपनी प्रतिबद्धता में विफल रहता है।
 आघात 2: शीर्ष 2 दबावग्रस्त वैयक्तिक उधारकर्ता भुगतान करने की अपनी प्रतिबद्धता में विफल रहते हैं।
 आघात 3: शीर्ष 3 दबावग्रस्त वैयक्तिक उधारकर्ता भुगतान करने की अपनी प्रतिबद्धता में विफल रहते हैं।
 स्रोत: रिजर्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणी और स्टाफ आकलन।

सारणी 2.2: ऋण संकेंद्रण जोखिम – समूह उधारकर्ता – एक्सपोजर

आघात	प्रणाली स्तर				बैंक स्तर	
	सीआरएआर	कोर सीआरएआर	एनपीए अनुपात	पूंजी की तुलना में हानि का %	प्रभावित बैंक (सीआरएआर < 9%)	एससीबी की कुल आस्तियों में हिस्सा (% में)
बेसलाइन (आघातपूर्व)	14.6	12.5	8.6	---	बैंकों की संख्या	एससीबी की कुल आस्तियों में हिस्सा (% में)
आघात 1	13.8	11.7	11.9	6.0	1	0.2
आघात 2	13.1	11.0	14.7	10.9	1	0.2
आघात 3	12.6	10.4	17.0	15.0	2	1.1

नोट: चयनित 53 एससीबी प्रणाली के लिए
 स्रोत: रिजर्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणी और स्टाफ आकलन।

2.26 बैंक के ऋण एक्सपोजर संकेंद्रण में समूह उधारकर्ताओं द्वारा चूक के परिदृश्य के तहत किए गए दबाव परीक्षण से ज्ञात होता है कि प्रणाली स्तर की पूंजी हानियाँ¹⁹ लगभग (क) यदि शीर्षस्थ समूह उधारकर्ता चूक करता है तो 6.0 प्रतिशत और (ख) यदि शीर्षस्थ दो समूह उधारकर्ता चूक करते हैं तो 10.9 प्रतिशत हो सकती हैं। यदि शीर्ष तीन समूह उधारकर्ता चूक करते हैं तो दो बैंक अपने सीआरएआर स्तर को बनाए रखने में सक्षम नहीं रहेंगे (सारणी 2.2)।

ग. क्षेत्रगत ऋण जोखिम

2.27 कतिपय उपक्षेत्रों (उपक्षेत्र-वार जीएनपीए अनुपात के ऐतिहासिक मानक विचलन पर आधारित आघात) में अपने एक्सपोजर के कारण बैंक-वार आघात सहनीयता का संवेदनशीलता विश्लेषण, विभिन्न उपक्षेत्रों में बैंकों के जीएनपीए अनुपात में विभिन्न आकार की बढ़त को दर्शाता है (सारणी 2.3)।

2.28 बैंकों की दबावग्रस्त सीआरएआर और जोखिम भारित आस्तियों की गणना करने के लिए बढ़े हुए प्रावधानों और घटी हुई आय के कारण हुई हानियों को हिसाब में लिया गया है।

सारणी 2.3: प्रणाली स्तर सीआरएआर में गिरावट (आधार अंक, घटते क्रम में)

	1 एसडी	2 एसडी	3 एसडी
इंफ्रास्ट्रक्चर – ऊर्जा (55%)	10	20	29
मूलभूत धातु और धातु उत्पाद (74%)	10	17	22
समस्त इंजीनियरिंग (38%)	3	5	7
इंफ्रास्ट्रक्चर – परिवहन (29%)	3	6	6
कपड़ा (29%)	2	4	5
इंफ्रास्ट्रक्चर – संचार (78%)	2	3	5
विनिर्माण (27%)	2	3	5
खाद्य प्रसंस्करण (25%)	1	3	4
वाहन, वाहनों के पुर्जों और परिवहन उपकरण (52%)	1	2	3
रत्न और आभूषण (24%)	1	1	2

नोट: चयनित 53 एससीबी प्रणाली के लिए
 नोट: कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े उपक्षेत्र जीएनपीए अनुपात में 1 एसडी आघात के कारण जीएनपीए में हुई वृद्धि को दर्शाते हैं।
 स्रोत: रिजर्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणी और स्टाफ आकलन।

¹⁹ चूक होने की स्थिति में यह मान लिया जाता है कि उधारकर्ता समूह अवमानक वर्ग में आ गया है।

इंफ्रास्ट्रक्चर – ऊर्जा खंड एवं मूलभूत धातु और धातु उत्पाद खंड में 2 एसडी आघात प्रणाली स्तर सीआरएआर को क्रमशः 20 बीपीएस और लगभग 17 बीपीएस घटा देंगे (सारणी 2.3)। हालांकि, विभिन्न क्षेत्रों में 3 एसडी आघात को भी सीमित ही देखा जा रहा है परंतु कुछ बैंकों के लिए संचयी प्रभाव काफी असरदार हो सकता है।

घ. ब्याज दर जोखिम

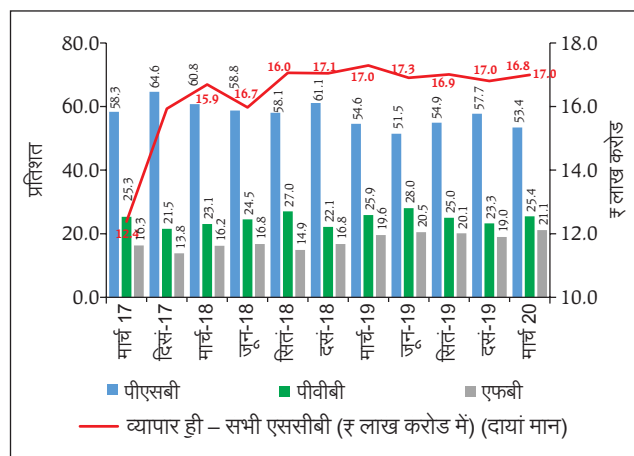
2.29 नमूने के तौर पर लिए गए 52 एससीबी का पोर्टफोलियो का बाजार मूल्य बशर्ते उचित मूल्यन किया गया हो, मार्च 2020 के अंत में ₹ 17 लाख करोड़ हो गया जो बैंकिंग प्रणाली की कुल आस्तियों का 98 प्रतिशत होता है (चार्ट 2.15)। उचित मूल्य के शर्ताधीन निवेश के लगभग 91.7 प्रतिशत को, बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) रूप में वर्गीकृत किया गया था।

2.30 पीएसबी और पीवीबी के एएफएस पोर्टफोलियो की संवेदनशीलता (पीवी01²⁰) में दिसंबर 2019 की स्थिति के मुकाबले गिरावट हुई जबकि एफबी के मामले में इसमें मामूली बढ़ोतरी हुई। पीवी01 वक्र स्थिति के संदर्भ में, अवधि वार वितरण से पता चलता है कि 5-10 वर्ष की अवधि के पक्ष में पीएसबी का पूर्वाग्रह रहा और 1-5 वर्ष की अवधि में पीवी01 के अनुपात में मामूली गिरावट हुई, साथ ही समतुल्य रूप में दीर्घावधिक परिपक्वता अवधि में, मामूली बढ़ोतरी हुई। हालांकि, पीवीबी और एफबी ने 1-5 वर्ष की अवधि में अपना दांव लगाना जारी रखा तथापि इस मामले में पीवीबी का अनुपात अपेक्षाकृत कम रहा (सारणी 2.4)।

2.31 ब्याज दरों में नरमी और उसके अवधियों के प्रतिफल वक्र उतार-चढ़ाव पर परिणामी प्रभावों के कारण बैंकों की मुनाफा वसूली में वृद्धि हुई (चार्ट 2.16)। प्रतिभूति कारोबार में पीएसबी और पीवीबी की मुनाफा वसूली मार्च 2020 को समाप्त तिमाही तक जारी रही जबकि, इसके पहले की तिमाही में एफबी ने हानियों को पलटा था (सारणी 2.5)।

2.32 पीवीबी और एफबी का, उनके एएफएस बहियों के सापेक्ष में कारोबार के लिए उपलब्ध (एचएफटी) पोर्टफोलियो में, काफी अधिक ब्याज दर एक्सपोजर बना रहा। पीवीबी के लिए पीवी01

चार्ट 2.15: व्यापार बही पोर्टफोलियो: बैंक समूहवार



स्रोत: वैयक्तिक बैंक प्रस्तुतियां और स्टाफ आकलन।

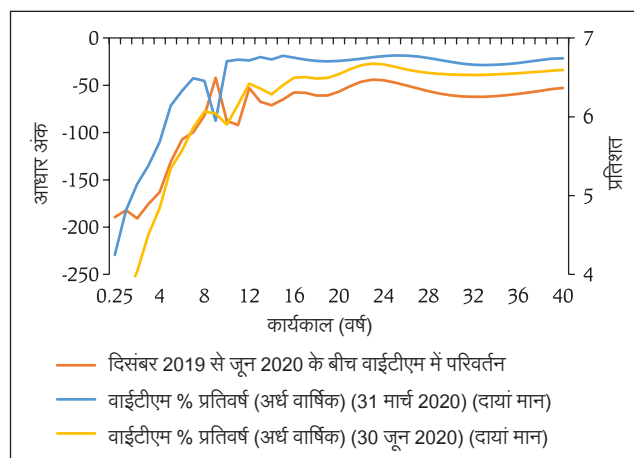
सारणी 2.4: एएफएस पोर्टफोलियो का अवधिवार पीवी01 वितरण (प्रतिशत में)

	कुल (₹ करोड़ में)	<1 वर्ष	1 वर्ष-5 वर्ष	5 वर्ष-10 वर्ष	>10 वर्ष
पीएसबी	212.4 (255.8)	6.4 (5.8)	25.4 (29.3)	54.4 (51.8)	13.9 (13.1)
पीवीबी	43.7 (46.4)	20.0 (18.2)	49.2 (51.7)	25.0 (25.2)	5.7 (5.0)
एफबी	43.9 (41.1)	6.4 (8.3)	64.2 (60.5)	10.1 (9.9)	19.4 (21.3)

नोट: कोष्ठक में दिए गए भाव दिसंबर 2019 के आंकड़े दर्शाते हैं।

स्रोत: वैयक्तिक बैंक प्रस्तुतियां और स्टाफ आकलन।

चार्ट 2.16: प्रतिफल वक्र (जी-सेक) और दिसंबर 2019 से अवधियों के प्रतिफलों में परिवर्तन



नोट: 30 जून 2020 को वर्तमान स्थिति।

स्रोत: फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (फिम्मडा)।

²⁰ पीवी01 ब्याज दर में एक आधार अंक परिवर्तन से पोर्टफोलियो के संपूर्ण मूल्य में संवेदनशीलता का एक माप है।

अवधि-वार वितरण, एएफएस पोर्जिशनिंग के समान, 1 से 5 वर्ष की अवधि में प्रबल को एक्सपोजर दर्शाता है जबकि एफबी की पीवी01 संवेदनशीलता 5-10 वर्ष की अवधि में बढ़ी हुई दिखाई देती है (सारणी 2.6)।

2.33 ब्याज दरों में किसी भी प्रकार की वृद्धि एएफएस और एचएफटी श्रेणियों के अंतर्गत निवेश आय को कम करेगी (प्रत्यक्ष प्रभाव)। प्रतिलाभ वक्र में 2.5 प्रतिशत अंकों का समानांतर ऊर्ध्वगामी परिवर्तन प्रणाली स्तर पर सीआरएआर को लगभग 69 आधार अंक गिरा देगा जबकि यह प्रणाली स्तर की पूंजी को 5.5 प्रतिशत घटा देगा (सारणी 2.7)

इक्विटी कीमत जोखिम

2.34 बैंक की पूंजी और लाभ पर इक्विटी कीमतों में गिरावट से पडने वाले प्रभाव का विश्लेषण दर्शाता है कि इक्विटी कीमतों में 55 प्रतिशत गिरावट के तहत बेसलाइन में प्रणाली स्तर की सीआरएआर 57 आधार अंक गिर जाएगी (चार्ट 2.17)। समग्र प्रणाली पर इक्विटी कीमतों में गिरावट से होनेवाला प्रभाव सीमित है क्योंकि विनियामकीय सीमाओं के कारण बैंकों का आम तौर पर उनके तुलनपत्र पर पूंजी बाजार एक्सपोजर का कम अनुपात होता है।

च. चलनिधि जोखिम: जमाराशि की निकासी का प्रभाव

2.35 चलनिधि जोखिम विश्लेषण का लक्ष्य है - जमाराशियों की संभावित निकासी और स्वीकृत/प्रतिबद्ध/गारंटीकृत क्रेडिट लाइन के अप्रयुक्त हिस्से की बढ़ती हुई मांग के प्रभाव को ज्ञात करना। बैंक सामान्य तौर पर अपनी उच्च कोटि की तरल आस्तियों (एचक्यूएलए)²¹ की सहायता से चलनिधि आघातों को सहन करने की स्थिति में हो सकते हैं।

सारणी 2.5: अन्य परिचालन आय (ओओआई) – प्रतिभूत कारोबार की लाभ/ (हानि) (₹ करोड़ में)

	30-जून-19	30-सितं-19	31-दिसं-19	31-मार्च-20
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	3912.66	8993.73	4184.28	8375.85
निजी क्षेत्र के बैंक	2545.25	2590.44	2291.46	4110.63
विदेशी बैंक समूह	225.21	926.75	-58.74	223.53

स्रोत: रिजर्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणी और स्टाफ आकलन।

सारणी 2.6: एचएफटी पोर्टफोलियो का अवधिवार पीवी01 वितरण (प्रतिशत में)

	कुल (₹ करोड़ में)	<1 वर्ष	1 वर्ष-5 वर्ष	5 वर्ष-10 वर्ष	>10 वर्ष
पीएसबी	0.2 (1.2)	4.8 (1.1)	17.8 (43.4)	71.0 (49.9)	6.5 (5.6)
पीवीबी	11.0 (7.7)	11.3 (6.7)	64.9 (77.8)	19.3 (0.4)	4.5 (15.0)
एफबी	18.7 (10.2)	3.7 (4.7)	33.2 (48.0)	33.6 (23.6)	29.5 (23.7)

नोट: कोष्ठक में दिए गए भाव दिसंबर 2019 के आंकड़े दर्शाते हैं।

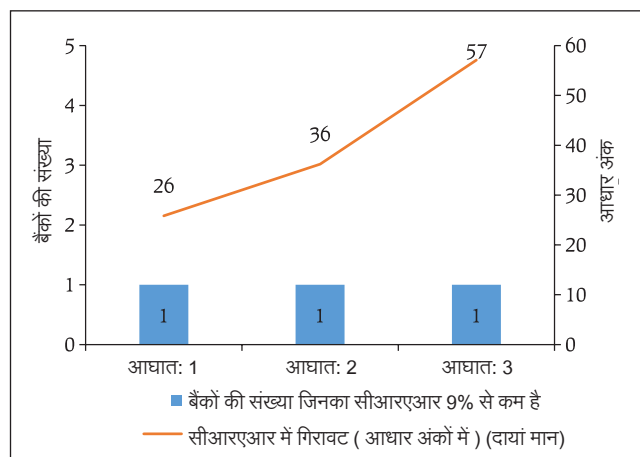
स्रोत: वैयक्तिक बैंक प्रस्तुतियां और स्टाफ आकलन।

सारणी 2.7: ब्याज दर जोखिम- बैंक समूह – आघात और प्रभाव (250 आधार अंक के आघात के अंतर्गत भारतीय रुपया प्रतिफल वक्र में समानांतर ऊर्ध्वगामी परिवर्तन)

	सरकारी क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के बैंक		विदेशी बैंक		सभी एससीबी	
	एएफएस	एचएफटी	एएफएस	एचएफटी	एएफएस	एचएफटी	एएफएस	एचएफटी
संशोधित अवधि	2.3	2.7	1.2	1.5	1.5	2.9	1.9	2.1
सीआरएआर में कमी (बीपीएस)	82		32		138		69	

स्रोत: वैयक्तिक बैंक प्रस्तुतियां और स्टाफ आकलन।

चार्ट 2.17: इक्विटी कीमत जोखिम



नोट: चयनित 53 एससीबी प्रणाली के लिए

आघात लगाने से पहले एक बैंक का सीआरएआर 9 प्रतिशत से कम था।

आघात-1 : इक्विटी कीमत 25 प्रतिशत तक गिरने पर

आघात-2 : इक्विटी कीमत 35 प्रतिशत तक गिरने पर

आघात-3 : इक्विटी कीमत 55 प्रतिशत तक गिरने पर

स्रोत: रिजर्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणी और स्टाफ आकलन।

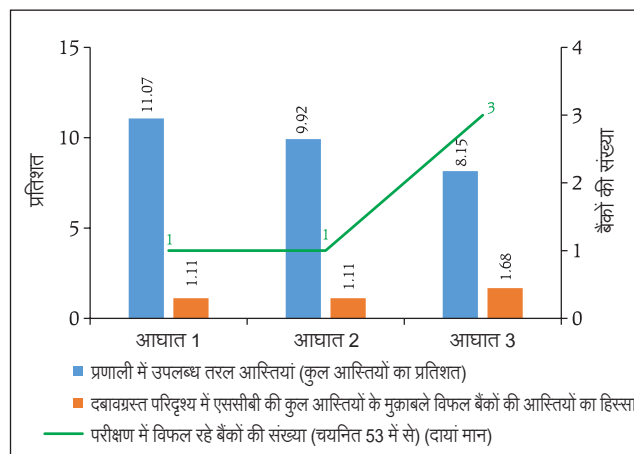
21 भारत में 01 जनवरी, 2015 से चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) को लागू किए जाने के मद्देनजर, दबाव परीक्षण हेतु चलनिधि आस्तियों की परिभाषा को संशोधित किया गया। एचक्यूएलए की गणना अपेक्षित सीआरएआर से अधिक नकदी रिजर्व, अतिरिक्त एसएलआर निवेश, एनडीटीएल (एमएसएफ के तहत) के 2 प्रतिशत तक एसएलआर निवेश और एनडीटीएल के 14.5 प्रतिशत के अतिरिक्त एसएलआर निवेश के रूप में की गई (27 सितंबर 2018 के परिपत्र डीबीआर.बीपी.बीसी. सं. 4/21.04.098/2018-19 और 4 अप्रैल 2019 की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति 2019-20 के अनुसरण में)।

2.36 कल्पित स्थितियों में, बीमा-रहित जमाराशियों²² की निकासी बढ़ेगी और स्वीकृत कार्यशील पूंजी सीमाओं के अप्रयुक्त भाग का प्रयोग बढ़ेगा तथा साथ ही साथ बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को दी गई क्रेडिट प्रतिबद्धताओं और गारंटियों का उपयोग भी बढ़ जाएगा। दैनिक चलनिधि जरूरतों को पूरा करने के लिए अपेक्षित एचक्यूएलए का प्रयोग करते हुए, इस नमूने के 53 में से 50 बैंक ऐसे हैं जो अपनी प्रतिबद्ध क्रेडिट सुविधाओं के 75 प्रतिशत भाग का उपयोग किए जाने के साथ-साथ अपनी जमाराशियों में से लगभग 10 प्रतिशत की अचानक और अप्रत्याशित निकासी की स्थिति के आघात को सहन कर लेंगे (चार्ट 2.18)।

II.1.8 ऊर्ध्वमुखी दबाव परीक्षण (बॉटम-अप टेस्ट) – क्रेडिट, बाजार और चलनिधि जोखिम

2.37 चुनिंदा बैंकों²³ (संवेदनशीलता विश्लेषण) पर उपरिगामी दबाव परीक्षण (संवेदनशीलता विश्लेषण) किए गए इसकी संदर्भ तारीख 31 मार्च 2020 रखी गई, इसने विभिन्न प्रकार के आघातों के प्रति बैंकों की सामान्य आघात सहनीयता का भी परीक्षण किया। सामान्य रूप से निम्नगामी दबाव परीक्षण परिणामों की पुष्टि करते हुए उपरिगामी दबाव परीक्षण दर्शाते हैं कि पीएसबी के बेहतर पूंजीकृत होने के कारण औसत सीआरएआर 9 प्रतिशत से ऊपर रहता है हालांकि कुछ बैंकों को सीआरएआर के 9 प्रतिशत के विनियमाकीय न्यूनतम से नीचे रहने की दबावग्रस्त स्थितियों से जूझना पड़ सकता है (चार्ट 2.19)।

चार्ट 2.18: चलनिधि जोखिम- आघात और परिणाम

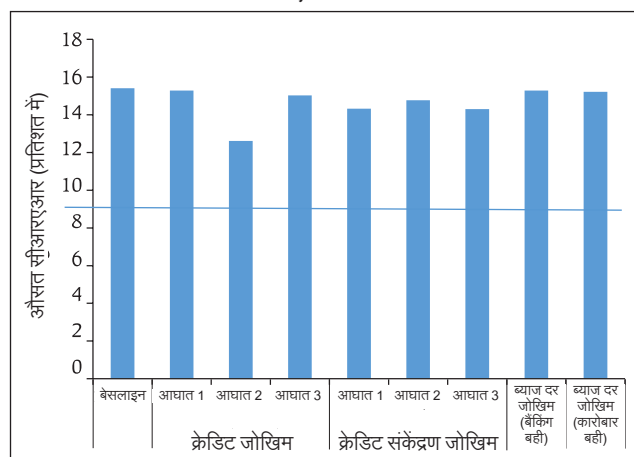


नोट : 1. एक बैंक परीक्षण में विफल तब माना गया जब वह दबावग्रस्त परिदृश्य के अंतर्गत अपनी तरल आस्तियों की सहायता से अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में असफल रहा - दबावग्रस्त स्थितियों के तहत तरल आस्तियों का स्टॉक नकारात्मक हो गया।
2. चलनिधि आघातों में 75 प्रतिशत प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइन की मांग शामिल है (स्वीकृत कार्यशील पूंजी सीमाओं के अप्रयुक्त भाग और उनके ग्राहकों के लिए ऋण प्रतिबद्धताएं) और नीचे दी गई बीमा-रहित जमाराशियों के एक हिस्से के आहरण को भी शामिल किया गया है:

आघात	आघात 1	आघात 2	आघात 3
बीमा-रहित जमाराशियों के आहरण का प्रतिशत	10	12	15

स्रोत: रिजर्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणी और स्टाफ आकलन

चार्ट 2.19: उपरिगामी दबाव परीक्षण – क्रेडिट और बाजार जोखिम – सीआरएआर पर प्रभाव



क्रेडिट जोखिम: सकल क्रेडिट	आघात 1 आघात 2 आघात 3	एनपीए 50 प्रतिशत बढ़ जाता है पुनर्संचित आस्तियों का 30 प्रतिशत एनपीए हो जाता है प्रत्येक शीर्ष 5 क्षेत्र/उद्योग में एनपीए 5 प्रतिशतता अंक बढ़ जाता है
क्रेडिट जोखिम: संकेंद्रण	आघात 1 आघात 2 आघात 3	शीर्ष तीन वैयक्तिक उधारकर्ता चूक करते हैं शीर्ष सबसे बड़ा समूह चूक करता है शीर्ष पांच उद्योगों/क्षेत्रों में प्रत्येक का सबसे बड़ा उधारकर्ता चूक करता है
ब्याज दर जोखिम (बैंकिंग बही)	आघात	आईएनआर प्रतिफल वक्र में 2.5 प्रतिशतता अंकों का समानांतर उर्ध्वगामी शिफ्ट
ब्याज दर जोखिम (कारोबार बही)	आघात	आईएनआर प्रतिफल वक्र में 2.5 प्रतिशतता अंकों का समानांतर उर्ध्वगामी शिफ्ट

स्रोत: चयनित बैंक (उपरिगामी दबाव परीक्षण)।

²² कुल जमाराशियों में से लगभग लगभग 72 प्रतिशत जमाराशियां बीमा-रहित हैं (स्रोत: डीआईसीजीसी की 2018-19 की वार्षिक रिपोर्ट)।

²³ चयनित 19 बैंकों के नमूनों पर दबाव परीक्षण किया गया। आघातों के उसी सेट को निम्नगामी और उपरिगामी दबाव परीक्षणों के लिए प्रयोग किया गया (अनुबंध 2)।

2.38 कुछ परिदृश्यों में, चुनिंदा बैंकों के तरल आस्ति अनुपातों²⁴ पर चलनिधि आघात प्रभावों के उपरिगामी दबाव परीक्षण दर्शाते हैं कि नमूने में से एचक्यूएलए सक्षम बैंक, जमाकर्ताओं द्वारा जमाराशियों के अचानक और अप्रत्याशित आहरण से उत्पन्न दबावों को झेल सकते हैं (चार्ट 2.20)। औसत आधार पर, बैंकों के पास मार्च 2019 में तरल आस्तियों पर किए गए परीक्षण के मुकाबले तरल आस्ति अनुपात उच्च रहा।

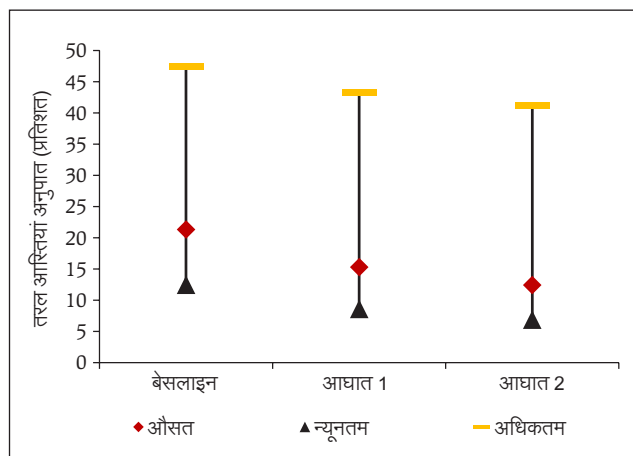
II.1.9 उपरिगामी दबाव परीक्षण : डेरिवेटिव पोर्टफोलियो

2.39 चुनिंदा बैंकों²⁵ के डेरिवेटिव पोर्टफोलियो पर उपरिगामी दबाव परीक्षणों (संवेदनशीलता विश्लेषण) की एक श्रृंखला का संचालन किया गया जिसकी संदर्भ तारीख 31 मार्च 2020 रखी गई। इस नमूने में शामिल बैंक, ब्याज और विदेशी मुद्रा विनिमय दरों पर चार अलग-अलग आघातों के विषयाधीन थे, जहां ब्याज दरों पर आघात का दायरा 100 से 250 आधार अंकों के बीच था, वहीं विदेशी मुद्रा विनिमय दरों के लिए 20 प्रतिशत मूल्यवृद्धि / मूल्यहास के आघात को माना गया। वैयक्तिक आघातों के लिए दबाव परीक्षण किए गए।

2.40 सीईटी 1 पूंजी (चार्ट 2.21) के अनुपात के रूप में मार्क-टू-मार्केट (एमटीएम) मूल्यन में परिलक्षित तीव्र उतार-चढ़ावों का प्रभाव अधिकांश वैयक्तिक बैंकों, विशेष रूप से पीसीबी और पीवीबी के मामले में मूक दिखा। चूंकि जोखिमों को केवल हस्तांतरित किया जा सकता है, खत्म नहीं इसलिए आगे कॉर्पोरेट के हेजिंग प्रोफाइल, जैसा कि प्रकटीकरण में दिया गया है, का संपूर्ण मूल्यांकन जोखिमों को सही तरीके से समझने में मदद करेगा।

2.41 ब्याज दर और विनिमय दर आघातों का औसत निवल प्रभाव कुल पूंजी निधियों के 2.5 प्रतिशत की सीमा में है और विपरीत आघातों में हानि और लाभ (पीएंडएल) प्रभाव भी लगभग एक समान स्थिति में है। घरेलू ब्याज दरें बढ़ने से पीएंडएल में लाभ होता है और घरेलू ब्याज दर घटने से इसके उलट होता है, जिसका अर्थ यह है कि ब्याज दर पोजीशन प्रकृति में नेट शार्ट होती है। इसी तरह आईएनआर मूल्यहास के रूप में विनिमय दर आघातों से पीएंडएल में लाभ होता है और आईएनआर मूल्यवृद्धि से इसके उलट होता है जिसका अर्थ यह है कि विदेशी मुद्रा विनिमय बही की पोजीशन इस तरह होगी कि आईएनआर मूल्यहास से लाभ होगा (चार्ट 2.22)।

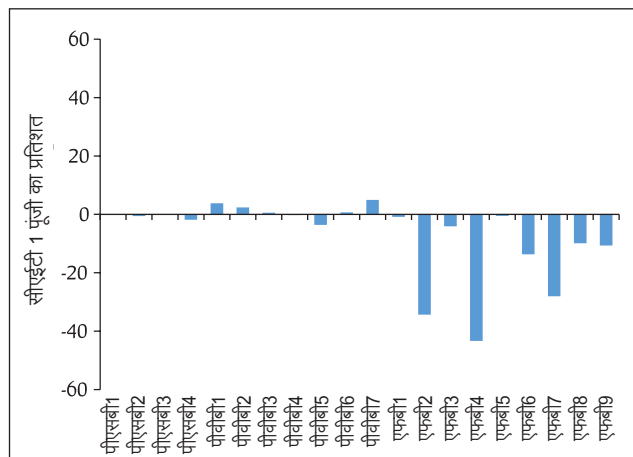
चार्ट 2.20: उपरिगामी दबाव परीक्षण – चलनिधि जोखिम



तरल आस्तियों की परिभाषा	
1	चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) दिशा-निर्देशों के अनुसार उच्च कोटि तरल आस्तियां (एचक्यूएलए)
चलनिधि आघात	
आघात 1	अल्पावधि के दौरान (अर्थात 1 या 2 दिन) के दौरान 10 प्रतिशत जमाराशियों का आहरण (संचयी)
आघात 2	5 दिनों के भीतर 3 प्रतिशत जमाराशियों का आहरण (प्रति दिन)

स्रोत: चयनित बैंक (उपरिगामी दबाव परीक्षण)

चार्ट 2.21: कुल डेरिवेटिव पोर्टफोलियो का निवल एमटीएम – चुनिंदा बैंक, मार्च 2020



नोट : पीएसबी : सरकारी बैंक, पीवीबी : निजी बैंक, एफबी : विदेशी बैंक
स्रोत : नमूना बैंक (डेरिवेटिव पोर्टफोलियो पर उपरिगामी दबाव परीक्षण)

²⁴ नकद आस्तियां अनुपात = नकद आस्तियां X 100/कुल आस्तियां। आघात परिदृश्यों के अंतर्गत, ऋणात्मक तरल आस्ति अनुपात अपेक्षित जमाराशियों के आहरण की कमी के प्रतिशत को दर्शाता है।

²⁵ चुनिंदा 20 बैंकों के नमूनों, जिसमें प्रमुख सक्रिय प्राधिकृत डीलर और ब्याज दर स्वैप प्रतिपक्षी शामिल हैं, के डेरिवेटिव पोर्टफोलियो पर दबाव परीक्षण किए गए।

2.42 किए गए अनेक दबाव परीक्षण प्रणाली स्तर के साथ-साथ बैंक के वैयक्तिक स्तर पर बैंकों के तुलन पत्र पर कोविड-19 के प्रभाव को दर्शाते हैं। इस संदर्भ में, आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए वे उनके तुलन पत्र, आस्ति गुणवत्ता, चलनिधि, लाभप्रदता और पूंजी पर्याप्तता पर गहन परंतु सत्याभासी परिदृश्यों के तहत कोविड -19 के प्रभाव का आकलन करें। बैंकों को यह भी सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि उक्त विश्लेषण, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को निर्बाध क्रेडिट आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य के साथ-साथ पूंजी और चलनिधि की योजना सहित जोखिम कम करने के संभावित उपायों से अनुपूरित हों।

II.2 अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक

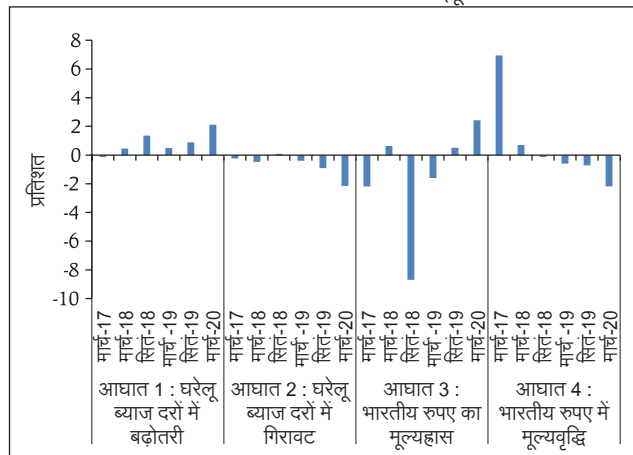
2.43 अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों (एसयूसीबी) का सितंबर 2019 से मार्च 2020 के बीच निष्पादन मौटे तौर पर स्थिर बना रहा। प्रणाली स्तर²⁶ पर एसयूसीबी का सीआरएआर दोनों तिमाहियों के लिए 9.8 प्रतिशत बना रहा। इस अवधि के दौरान के उनका जीएनपीए सकल ऋणों और अग्रिमों के 10.5 प्रतिशत से घटकर 9.9 प्रतिशत हो गया और उनका प्रावधान कवरेज अनुपात²⁷ 40.9 प्रतिशत से बढ़कर 61.4 प्रतिशत हो गया। एसयूसीबी के आरओए में सुधार हुआ परंतु सितंबर 2019 में -3.6 प्रतिशत के मुकाबले मार्च 2020 में -1.8 प्रतिशत होने के कारण यह ऋणात्मक बना रहा जबकि चलनिधि अनुपात²⁸ 34.0 प्रतिशत पर स्थिर बना रहा।

II.2.1 दबाव परीक्षण – क्रेडिट जोखिम

2.44 एसयूसीबी के सीआरएआर पर क्रेडिट जोखिम आघातों का प्रभाव चार अलग-अलग परिदृश्यों²⁹ में देखा गया। परिणाम दर्शाते हैं कि (i) हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत जीएनपीए में 1 एसडी आघात के तहत, प्रणाली स्तर पर सीआरएआर गिरकर 9.1 प्रतिशत होगा और दो एसयूसीबी न्यूनतम सीआरएआर संबंधी अपेक्षाओं को हासिल करने में विफल रहेंगे,

चार्ट 2.22: दबाव परीक्षण – चुनिंदा बैंकों के डेरिवेटिव पोर्टफोलियो पर आघातों का प्रभाव – (आघात की स्थिति में निवल एमटीएम में बदलाव)

(पूंजी निधियों का प्रतिशत)



नोट : आघात की स्थिति में बेसलाइन के सापेक्ष निवल एमटीएम में बदलाव
स्रोत : नमूना बैंक (डेरिवेटिव पोर्टफोलियो पर उपरिगामी दबाव परीक्षण)

इसके अलावा 3 ऐसे थे जिनका सीआरएआर आघात के पहले ही 9 प्रतिशत से कम था। (ii) अवमानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत जीएनपीए में 2 एसडी आघात के तहत, एक अतिरिक्त एसयूसीबी 9 प्रतिशत न्यूनतम सीआरएआर को हासिल करने में विफल रहेगा; और (iii) हानि अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत जीएनपीए में 2 एसडी आघात के तहत, प्रणाली स्तर पर सीआरएआर 8.1 प्रतिशत तक गिर जाएगा है तथा आठ और यूसीबी न्यूनतम सीआरएआर अपेक्षाओं को बनाए रखने में विफल रहेंगे।

II.2.2 दबाव परीक्षण – चलनिधि जोखिम

2.45 i) 50 प्रतिशत और ii) 100 प्रतिशत की 1-28 दिवसीय समयावधि (टाइम बकेट) में नकदी बहिर्वाह में दो अलग-अलग परिदृश्यों का उपयोग करते हुए चलनिधि पर एक दबाव परीक्षण किया गया जिसमें नकदी अंतर्वाह अपरिवर्तित रहा है। दोनों ही परिदृश्यों के तहत, क्रमशः 20 बैंक और 34 बैंक चलनिधि दबाव³⁰ का सामना करेंगे।

²⁶ 54 एसयूसीबी शामिल हैं।

²⁷ प्रावधान कवरेज अनुपात = (एनपीए हेतु धारित प्रावधान) / 100/जीएनपीए

²⁸ चलनिधि अनुपात = (नकदी + बैंकों से प्राप्त + अन्य संस्थानों से प्राप्त + एसएलआर निवेश) / 100/कुल आस्तियां

²⁹ चारों परिदृश्य हैं: i) जीएनपीए में 1 एसडी आघात (अवमानक अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत), ii) जीएनपीए में 2 एसडी आघात (अवमानक अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत), iii) जीएनपीए में 1 एसडी आघात (हानि अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत), और iv) जीएनपीए में 2 एसडी आघात (हानि अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत)। एसडी का अनुमान 10 वर्षों के आंकड़ों का प्रयोग करते हुए लगाया गया (अनुबंध-2)।

³⁰ आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, 1 से 28 दिवसीय समयावधि में विसंगति [ऋणात्मक अंतराल अर्थात नकद अंतर्वाह से नकद बहिर्वाह को घटाकर] बहिर्वाहों के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। आघात के बाद वे एसयूसीबी जिनमें विसंगति 20 प्रतिशत से अधिक है, बहुत कम चलनिधि मार्जिन के तहत कार्य कर रहे हैं।

II.3 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

2.46 मार्च 2020 अंत तक भारतीय रिजर्व बैंक के पास 9,601 एनबीएफसी पंजीकृत थीं, जिनमें से 66 जमा स्वीकार करने वाली (एनबीएफसी-डी) थीं और 278 प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमा स्वीकार नहीं करने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-एनडी-एसआई) थीं। सरकार के स्वामित्व वाली एनबीएफसी सहित सभी एनबीएफसी-डी और एनबीएफसी-एनडी-एसआई रिपोर्टिंग की अपेक्षाओं के साथ ही पूंजी पर्याप्तता अपेक्षाओं तथा प्रावधानीकरण मानदंडों जैसे विवेकपूर्ण विनियमों के अधीन हैं। हालांकि एनबीएफसी के संयुक्त तुलन पत्र का आकार एससीबी के आकार का लगभग पांचवां हिस्सा है परंतु ये इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये अंतिम छोर तक क्रेडिट आपूर्ति करती हैं और भारतीय वित्तीय व्यवस्था के निचले क्षेत्र तक सहायता पहुंचाती हैं।

II.3.1 आस्तित्व-गुणवत्ता और पूंजी पर्याप्तता

2.47 एनबीएफसी क्षेत्र के जीएनपीए अनुपात में दिसंबर 2019 तक लगातार तिमाहियों के दौरान गिरावट रही हालांकि मार्च 2020 तिमाही में बढ़त हुई। निवल एनपीए अनुपात मार्च 2020 की तिमाही में पिछले वर्ष की तुलना में मामूली रूप से कम रहा। इस क्षेत्र का सीआरएआर मार्च 2020 में 19.6 प्रतिशत पर रहा, जो इसके एक साल पहले के स्तर से कम था (सारणी 2.8)।

II.3.2 कोविड-19 के बाद की प्रतिक्रिया

2.48 एनबीएफसी क्षेत्र की कुल बाह्य देयताओं का 70 प्रतिशत से अधिक हिस्सा बैंक और बाजार उधारियों का है। बाजार में घटते विश्वास के साथ ही, एनबीएफसी क्षेत्र की कुल उधारियों में से दीर्घावधिक बाजार कर्ज [अर्थात् अपरिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी)] का हिस्सा गिरकर दिसंबर 2019 अंत में 40.8 प्रतिशत हो गया जो मार्च 2017 अंत में 49.1 प्रतिशत था। तदवर्ती निधीयन अंतराल को बैंक उधारियों के द्वारा भरा गया जिससे कुल उधारियां इस अवधि के दौरान 23.1 प्रतिशत से बढ़कर 28.9 प्रतिशत हो गईं।

2.49 एनबीएफसी के लिए बाजार निधीयन का घटता हिस्सा एक चिंता का विषय है क्योंकि इसमें एनबीएफसी के साथ-साथ वित्तीय प्रणाली की चलनिधि जोखिम बढ़ाने की क्षमता है। लघु / मध्यम आकार और एए या लोवर रेटेड / अनरेटेड एनबीएफसी से बैंक और बाजार दोनों ही बचते रहे जिससे एनबीएफसी को बढ़ते चलनिधि तनावों का सामना करना पड़ा, जो लक्षित दीर्घावधि रेपो परिचालनों 2.0 (टीएलटीआरओ 2.0) के प्रति फीकी प्रतिक्रिया से भी प्रदर्शित हुआ।

2.50 आईएल एंड एफएस संकट के बाद एनबीएफसी को बाजार में पहुंच और वित्तीय स्थितियों संबंधी भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें केवल उच्च श्रेणी की संस्थाएं ही निधि जुटाने में सक्षम हैं। उन्होंने उच्च लागत के बावजूद, दो से तीन महीने के चलनिधि कवर को बनाए रखना शुरू कर दिया है। कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में इस क्षेत्र के जोखिम और फलस्वरूप प्रणालीगत जोखिम बढ़ सकते हैं। इंडएएस लेखांकन तुलन पत्र जोखिमों विशेष रूप से आस्तित्व गुणवत्ता और प्रावधानन; एनबीएफसी-एमएफआई के वित्तों; मोचन दबावों और ग्राहक विश्वास के कारण म्युचुअल फंडों के संक्रमण को प्रभावित कर सकता है।

सारणी 2.8 : एनबीएफसी की आस्तित्व गुणवत्ता³¹ और सीआरएआर³² (प्रतिशत में)

	जीएनपीए अनुपात	एनएनपीए अनुपात	सीआरएआर
मार्च 2015	4.1	2.5	26.2
मार्च 2016	4.5	2.5	24.3
मार्च 2017	6.1	4.4	22.1
मार्च 2018	5.8	3.8	22.8
मार्च 2019	6.1	3.3	20.1
सित 2019	5.6	2.9	19.9
दिस 2019	5.9	3.1	19.5
मार्च 2020*	6.4	3.2	19.6

*: अंतिम
स्रोत: रिजर्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणी।

31 एनबीएफसी क्षेत्र में मंथन को देखते हुए, कंपनियों के एक सामान्य समूह पर आधारित नहीं है : चूंकि विवेकपूर्ण मानदंडों को 2015 से उत्तरोत्तर कड़ा कर दिया गया है, इसलिए जीएनपीए अनुपात सामान्य मानदंडों पर आधारित नहीं हो सकता है।

32 बासेल 1 पूंजी फ्रेमवर्क पर आधारित है जो एकसमान क्रेडिट जोखिम पर पूंजी प्रदान करता है।

II.3.3 दबाव परीक्षण

2.51 दिसंबर 2019 को समाप्त तिमाही के लिए एनबीएफसी क्षेत्र के समग्र क्रेडिट जोखिम हेतु प्रणाली स्तर पर दबाव परीक्षण तीन परिदृश्यों के तहत किए गए: अर्थात् जीएनपीए में (i) 1 एसडी (ii) 2 एसडी और (iii) 3 एसडी, वृद्धि पहले मूल्यांकन में यह पाया गया कि क्षेत्र का सीआरएआर 19.4 प्रतिशत से गिरकर 17.2 प्रतिशत हो जाएगा, दूसरे परिदृश्य में यह 16.4 प्रतिशत और तीसरे परिदृश्य में यह 15.2 प्रतिशत रह जाएगा।

2.52 वैयक्तिक एनबीएफसी पर किए गए दबाव परीक्षण के परिणाम यह दर्शाते हैं कि उपर्युक्त तीनों परिदृश्यों में 11.2 प्रतिशत, 14.0 प्रतिशत और 19.5 प्रतिशत वाली कंपनियां 15

प्रतिशत की न्यूनतम विनियामकीय पूंजीगत अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाएंगी।

II.4 एसएमए अनुपात विश्लेषण

2.53 विशेष रूप से गैर-पीएसयू ऑब्लिगेंस, जो जोखिम से बचने के प्रति अत्यधिक संवेदनशील समूह हैं, पर एक विशेष उल्लेख खाता वाली (एसएमए) आस्तियों की रेटिंग मैपिंग की गई है ताकि विनियामक अधिस्थगन के मद्देनजर कॉर्पोरेटों की आघात सहनीयता की जांच की जा सके। मार्च 2020 को गैर-पीएसयू ऑब्लिगेंस के लिए एए और उससे ऊपर की रेटिंग वाली एसएमए³³ श्रेणी का समग्र हिस्सा मानक श्रेणी³⁴ में उनकी विद्यमानता के सापेक्ष कम रहा है (सारणी 2.9 और 2.10)। गैर-वित्तीय ऑब्लिगेंस के बजाय समग्र ऑब्लिगेंस पर एसएमए

सारणी 2.9: गैर-पीएसयू ऑब्लिगेंस को दिए गए ऋणों में एसएमए (एसएमए 1 और 2) रेटिंग श्रेणी का हिस्सा

(प्रतिशत)

	मार्च-17	जून-17	सितं-17	दिसं-17	मार्च-18	जून-18	सितं-18	दिसं-18	मार्च-19	जून-19	सितं-19	दिसं-19	मार्च-20
एएए	0.0	4.2	0.0	0.2	14.7	21.5	0.0	2.1	0.0	0.0	0.7	0.0	1.8
एए	6.9	8.6	6.4	18.3	16.3	16.6	18.8	11.1	2.8	0.2	1.2	1.9	0.2
एए और उससे ऊपर	6.9	12.8	6.5	18.6	31.0	38.1	18.8	13.1	2.8	0.2	1.9	1.9	1.9
ए	17.4	12.5	15.4	14.6	15.5	5.2	2.3	9.1	14.6	7.8	3.8	5.6	13.4
बीबीबी	17.1	16.5	11.3	14.1	16.4	16.6	16.0	15.6	16.5	13.2	16.4	15.0	18.8
बीबी	12.3	11.3	16.3	12.8	12.0	13.2	18.4	17.1	12.8	18.0	15.8	18.1	9.3
बी	4.3	5.5	5.1	3.8	4.2	3.3	6.1	7.2	5.5	6.6	6.5	9.7	6.9
सी	2.1	1.7	1.0	1.3	0.2	0.7	5.1	1.2	1.1	3.1	0.5	0.8	1.7
डी	20.6	18.9	26.4	18.4	10.0	10.8	17.1	20.5	23.9	26.9	30.5	19.1	24.0
अनरेटेड	19.3	20.9	18.0	16.5	10.6	12.1	16.2	16.1	22.8	24.2	24.7	29.7	24.0

स्रोत: प्रमुख डेटाबेस, रिजर्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणी और स्टाफ आकलन।

सारणी 2.10: रेटिंग श्रेणी का हिस्सा – गैर-पीएसयू गैर वित्तीय ऑब्लिगेंस को मानक ऋण (0 दिवसीय पूर्व देयक और एसएमए-0)

(प्रतिशत)

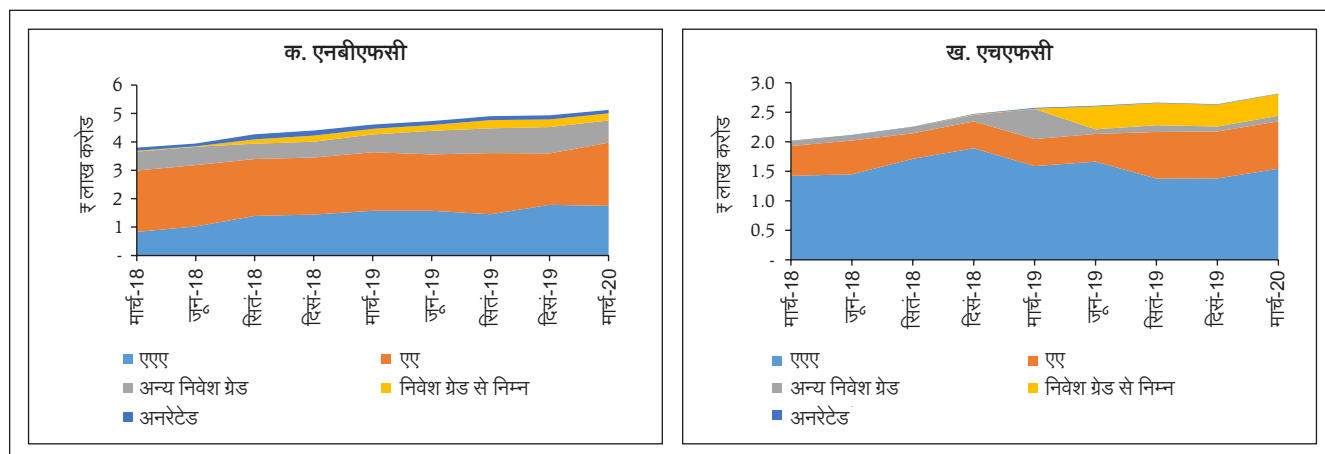
	मार्च-17	जून-17	सितं-17	दिसं-17	मार्च-18	जून-18	सितं-18	दिसं-18	मार्च-19	जून-19	सितं-19	दिसं-19	मार्च-20
एएए	3.4	3.6	4.4	4.2	3.4	2.3	4.3	4.3	5.7	5.7	6.3	6.1	6.4
एए	16.2	16.5	16.3	17.8	19.4	21.2	21.2	21.1	19.9	19.9	20.4	20.4	20.6
एए और उससे ऊपर	19.6	20.0	20.7	22.0	22.8	23.5	25.5	25.4	25.6	25.6	26.7	26.5	27.0
ए	19.2	20.5	19.9	19.5	18.4	18.5	17.6	19.5	20.3	20.2	19.8	19.3	18.9
बीबीबी	18.8	18.5	18.6	16.8	16.9	18.1	17.3	17.1	15.8	16.3	15.3	17.1	15.9
बीबी	7.9	7.1	7.3	8.5	8.6	7.7	8.7	7.4	7.8	7.3	6.8	6.4	7.2
बी	3.2	3.2	2.9	3.0	2.8	2.8	2.9	2.8	2.7	2.6	2.8	2.8	3.8
सी	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3
अनरेटेड	31.1	30.6	30.2	30.1	30.3	29.2	27.6	27.6	27.8	27.8	28.5	27.5	26.8

स्रोत: प्रमुख डेटाबेस, रिजर्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणी और स्टाफ आकलन।

33 एक ऑब्लिगेंस को बैंकिंग क्षेत्र में एसएमए के रूप में तब माना जाता है यदि उसे किसी बैंक द्वारा दी गई तिमाही में एसएमए 1 या एसएमए 2 के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

34 कोई आस्ति, जो 0 दिवसीय पूर्व देय या एसएमए-0 श्रेणी में है, उसे मानक आस्ति के रूप में पारिभाषित की गई है।

चार्ट 2.23: गैर-पीएसयू एनबीएफसी/एचएफसी – निधीकृत राशि जो बैंकों पर बकाया है



स्रोत: क्रिकिक, प्रमुख डेटाबेस।

विश्लेषण का संचालन किया गया क्योंकि क्योंकि एसएमए श्रेणी में वित्तीय ऑब्लिगॉर्स की उपस्थिति आमतौर पर विरल ही रही है। फिर भी, अनरेटेड समूह में दोनों ही मानक और एसएमए आस्ति श्रेणियों ने बृहद व तुलनीय उपस्थिति दर्शाई है। इसके अलावा, जैसा कि अध्याय 1 में उल्लेख किया गया है, कोविड-19 के फैलने के साथ विशेष रूप से पीवीबी से 2019-20 की चौथी तिमाही में ग्रेड ए और उससे निम्न रेटिंग वाले गैर-पीएसयू ऑब्लिगॉर्स के लिए क्रेडिट प्रवाह को कुछ हद तक नियंत्रित किया गया है। अतएव इस समूह का वित्तीय स्वास्थ्य प्रणालीगत स्थिरता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

2.54 क्रेडिट क्षेत्र में गैर-बैंकिंग वित्तीय अंतर्मध्यस्थता और बैंकिंग चैनलों के माध्यम से उच्च निधीयन (चार्ट 2.23) को दिए गए महत्व को देखते हुए, निर्धारित रेटिंग ग्रेडों के लिए हानि स्पेक्ट्रम के मध्य एनबीएफसी और एचएफसी का प्रसार, अधिस्थगन के पहले एनबीएफसी के अच्छे भुगतान रिकार्ड को दर्शाता है (सारणी 2.11 एवं 2.12)। निजी एनबीएफसी/

एचएफसी पर अधिस्थगन का प्रभाव काफी अधिक हो सकता है क्योंकि अंतर्निहित आस्तियों के आधार पर एनबीएफसी के लिए अधिस्थगन के तहत आस्तियों का अनुपात औसतन 39-65 प्रतिशत है, जिसमें अप्रैल 2020 की समाप्ति पर अधिस्थगन के अंतर्गत कुल आस्तियां लगभग 50 प्रतिशत हैं। एनबीएफसी/एचएफसी द्वारा किए गए प्रकटीकरण के आधार पर, अधिस्थगन के तहत आस्तियों पर थोक ग्राहक और रियल एस्टेट डेवलपर हावी हैं, हालांकि सूक्ष्म-ऋण व ऑटो ऋण खंड के खुदरा पोर्टफोलियो भी प्रभावित हुए हैं। एनबीएफसी/एचएफसी की पूंजी बाजार तक पहुंच, कर्ज और इक्विटी दोनों, क्षेत्र के लिए काफी अधिक महत्वपूर्ण हैं।

2.55 कोविड-19 द्वारा प्रेरित नकद प्रवाह संबंधी अनिश्चितताओं को देखते हुए, गैर-पीएसयू एनबीएफसी/एचएफसी की बाजार देयताओं की अल्पावधिक परिपक्वताएं प्रासंगिक हो गई हैं। सभी रेटिंग ग्रेडों में काफी अधिक निकट अवधि की परिपक्वताएं हैं (सारणी 2.13)। आंशिक क्रेडिट

सारणी 2.11: गैर-पीएसयू एनबीएफसी को दिए गए बैंक ऋणों की आस्ति हानि स्थिति, मार्च 2020 (प्रतिशत)

गैर-पीएसयू एनबीएफसी	मानक (0 दिवसीय पूर्व देय या एसएमए-0)	एसएमए (एसएमए 1/एसएमए 2)	अनर्जक
एए	99.1	0.9	0.0
ए	100.0	0.0	0.0
अन्य निवेश ग्रेड	88.6	11.4	0.0
निवेश ग्रेड से निम्न	5.2	1.4	93.4
अनरेटेड	96.2	0.1	3.7

स्रोत: प्रमुख डेटाबेस, रिजर्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणी और स्टाफ आकलन।

सारणी 2.12: गैर-पीएसयू एचएफसी को दिए गए बैंक ऋणों की आस्ति हानि स्थिति, मार्च 2020 (प्रतिशत)

गैर-पीएसयू एचएफसी	मानक (0 दिवसीय पूर्व देय या एसएमए-0)	एसएमए (एसएमए 1/एसएमए 2)	अनर्जक
एए	100.0	0.0	0.0
ए	100.0	0.0	0.0
अन्य निवेश ग्रेड	100.0	0.0	0.0
निवेश ग्रेड से निम्न	1.1	0.0	98.9
अनरेटेड	93.4	0.0	6.6

स्रोत: प्रमुख डेटाबेस, रिजर्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणी और स्टाफ आकलन।

सारणी 2.13: गैर-पीएसयू एनबीएफसी/एचएफसी के सीपी और एनएसडी के निर्गम और निकट अवधि परिपक्वता

(₹ करोड़ में)

	निर्गम			परिपक्वता						
	मार्च-20	अप्रै-20	मई-20	मार्च-20	अप्रै-20	मई-20	जून-20	जुला-20	अग-20	सितं-20
एए	21,885	17,465	22,980	34,680	8,363	19,454	27,645	15,735	24,792	11,802
ए	7,427	3,351	7,377	19,520	6,517	7,142	8,815	4,622	5,790	4,389
अन्य	937	694	138	2,885	3,413	4,037	1,658	1,887	3,589	2,559
कुल	30,249	21,510	30,495	57,084	18,293	30,633	38,117	22,243	34,171	18,750

स्रोत: प्रमुख डेटाबेस, रिजर्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणी और स्टाफ आकलन।

गारंटी योजना जिसमें सरकार पहली हानि का 20 प्रतिशत तक अवशोषित करेगी, इस संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है।

II.5 अंतर्संबद्धता

II.5.1 वित्तीय प्रणाली का नेटवर्क^{35 36}

2.56 वित्तीय प्रणाली की कल्पना एक नेटवर्क के रूप में की जा सकती है जिसमें वित्तीय संस्थानों को नोड और द्विपक्षीय

एक्सपोजर को इन नोड्स को जोड़ने वाले लिंक के रूप में रखा जा सकता है। हालांकि, ये लिंक दक्षता लाभ और जोखिमों के विविधीकरण को सक्षम करते हैं, वे संकट की स्थिति में जोखिम संचरण के वाहक बन सकते हैं। नेटवर्क के माध्यम से जोखिम प्रसार में सूक्ष्म बातों को समझना वित्तीय और समष्टि आर्थिक स्थिरता की सुरक्षा हेतु उपयुक्त नीति की प्रतिसाद तैयार करने के लिए उपयोगी है (बॉक्स 2.1)।

बॉक्स 2.1: महामारी से वित्तीय संकट – नेटवर्क और संक्रमण को समझने की महत्ता

वित्तीय नेटवर्क विश्लेषण वित्तीय प्रणाली की बढ़ती अंतर्संबद्धता के तर्कों से संबंधित इन प्रश्नों को सुलझाता है; क्या संबद्धता प्रणालीगत आघातों को बढ़ाने या कम करने में सहायक है; और क्या नेटवर्क की संरचना मायने रखती है। यह नीति निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक संरचनात्मक विशेषताओं की पहचान करने में मदद करती है (ग्लासरमैन एंड यंग, 2016)। इसके अलावा, यह समझने की कोशिश की गई कि नेटवर्क संरचना कैसे संक्रमण के अन्य संभावित स्रोतों के साथ संपर्क करती है। वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) के दौरान सुस्पष्ट रूप से एक यह पहलू सामने आया है कि वैयक्तिक वित्तीय संस्थानों का स्वास्थ्य समग्र रूप से वित्तीय प्रणाली के स्वास्थ्य को सुनिश्चित नहीं कर सकता। अंतर्संबद्धता को देखते हुए, चरम दबाव बाजारों के सामान्य कामकाज को बाधित कर सकता है और आर्स्टि बाजार अतरलता से ऋण-शोधन क्षमता के मामले हो सकते हैं और अंत में यह संक्रमण में परिणत होगी – जो ऐसे वायरस के सदृश होगा कि यह संपर्क के विभिन्न रूपों के माध्यम से वायरस संक्रमितों से सेहतमंदों में फैलता है। जीएफसी के चरण में, लीवरेज स्तर में

बढ़ती हुई, अल्पावधिक निधीयन पर निर्भरता अधिक रही और कुछ बैंकों के पूंजी बफर अत्यंत कम रहे। ये सभी कारक वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करते हैं। मुख्य मुद्दा यह है कि बाध्यताओं के नेटवर्क का संक्रमण के संभावित स्रोतों के साथ कैसा संबंध है और क्या यह उन्हें बढ़ाने या कम करने का कार्य करता है। निवेश, जोखिम विविधीकरण और चलनिधि प्रबंधन को अवसर प्रदान करने से नेटवर्क कनेक्शन वित्तीय प्रणाली के लिए निवल सकारात्मक हो सकता है। उसी समय चैनल बनाने के माध्यम से नेटवर्क कनेक्शन के नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं जिनसे आघात फैल सकते हैं और इस प्रकार संक्रमण फैल सकता है।

हालांकि, वित्तीय संक्रमण का अंदाजा लगाना एक चुनौती है, जहां एक ओर वित्तीय नेटवर्क के दक्षता प्रेरित पहलुओं को संतुलित करना और दूसरी ओर मिथ्या चेतावनियों पर प्रतिक्रिया न देना शामिल है। महामारी डोमेन में वित्तीय नेटवर्किंग संबंधी अवधारणाओं के अनुप्रयोग के लिए अनुकूलन की आवश्यकता होती है। जबकि श्रृंखला के किसी भी एक तत्व में चूक होने पर

(जारी)

35 विश्लेषण में उपयोग किए गए नेटवर्क मॉडल का विकास प्रोफेसर शेरी मार्कोस (यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स) और डॉ सिमोन गियानसांटे (बाथ यूनिवर्सिटी) ने वित्तीय स्थिरता इकाई, भारतीय रिजर्व बैंक के सहयोग से किया है।

36 यहां पर और अगले भाग में प्रस्तुत विश्लेषण आगे दिए गए आठ क्षेत्रों की 199 संस्थाओं के डेटा पर आधारित है: एससीबी, अनुसूचित यूसीबी (एसयूसीबी), एएमसी-एमएफ, एनबीएफसी, एचएफसी, बीमा कंपनियां, पेंशन फंड और एआईएफआई। कवर की गई 199 संस्थाओं में शामिल हैं - 78 एससीबी, 20 एसयूसीबी, 22 एएमसी-एमएफ (जो म्यूचुअल फंड क्षेत्र के 90 प्रतिशत से अधिक एयूएम को कवर करते हैं), 32 एनबीएफसी (जमाराशि स्वीकार करने वाली और जमाराशि स्वीकार न करने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, जो एनबीएफसी आस्तियों के लगभग 60 प्रतिशत भाग का प्रतिनिधित्व करती हैं), 21 बीमा कंपनियां (जो इस क्षेत्र की 90 प्रतिशत से ज्यादा आस्तियों को कवर करती हैं), 15 एचएफसी (जो एचएफसी की कुल आस्तियों के 90 प्रतिशत से अधिक भाग का प्रतिनिधित्व करती हैं), 7 पीएफ और 4 एआईएफआई (नाबार्ड, एक्जिम, एनएचबी और सिडबी)।

नेटवर्क वाली संस्थाएं अनिवार्य रूप से प्रभावित होती हैं, महामारी के प्रसार की संभाव्यता है जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति के संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से उसके संक्रमित होने की एक निश्चित संभावना होगी। इस तरह के संभाव्य संबंधों का अर्थ यह है कि संक्रामक प्रभाव का सही तरीके से अनुमान मामले दर मामले की बजाय पूलित पद्धति से लगाया जाए। इस संबंध में, यह कुछ हद तक व्यवहारगत वित्त में आस्ति मूल्य "बुलबुले" के मॉडलिंग के समान है, जिसमें आस्ति मूल्यों का उतार-चढ़ाव दूसरों में संभाव्य रूप से मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा करता है न कि निर्धारणात्मक रूप से।

महामारी और वित्तीय संकट के बीच की समानता तब से है जब पहली बार 'एशियाई फ्लू' के कारण एशियाई वित्तीय संकट हुआ था। वैश्विक वित्तीय संकट से पहले वित्तीय बाजारों में संकट के लिए संक्रामक शब्द का उपयोग शायद ही कभी हुआ हो।

शहरी समुदाय (या नेटवर्क), जो वर्तमान में खुद कोविड-19 महामारी के प्रसार के केंद्र बन गए हैं, की उपयोगिता छानबीन के अंतर्गत आ गई है। शहरी समुदाय, संबद्ध नेटवर्क प्रभावों के साथ,

लागत में किरायाती हैं, जो अर्थव्यवस्था को पैमाने पर ले जा रहे हैं। ऐसे तत्व जो सामान्य कारोबार में एक डोमेन से दूसरे संबंधित डोमेन में विशेषज्ञता और रचनात्मक इनपुट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देते हैं, महामारी के संदर्भ में संक्रमण के प्रसार की कड़ी बन जाते हैं।

संदर्भ

एंड्रयू जी हेल्डेन (2009)। "रिथिंकिंग द फाइनेंशियल नेटवर्क" कार्यकारी निदेशक का भाषण, वित्तीय स्थिरता, बैंक ऑफ इंग्लैंड, एम्स्टर्डम के वित्तीय छात्र संगठन, एम्स्टर्डम में (28 अप्रैल 2009)।

ग्लासमैन एंड यंग (2016)। कंटेजियन इन फाइनेंशियल नेटवर्क्स, जर्नल ऑफ इकॉनॉमिक लिटरेचर। 54 (3), 779-831।

रॉबर्ट पेकहम (2013)। इकॉनॉमीज ऑफ कंटेजियन: फाइनेंशियल क्राइसिस एंड पेंडेमिक, इकॉनामी एंड सोसाइटी। 42:2, 226-248।

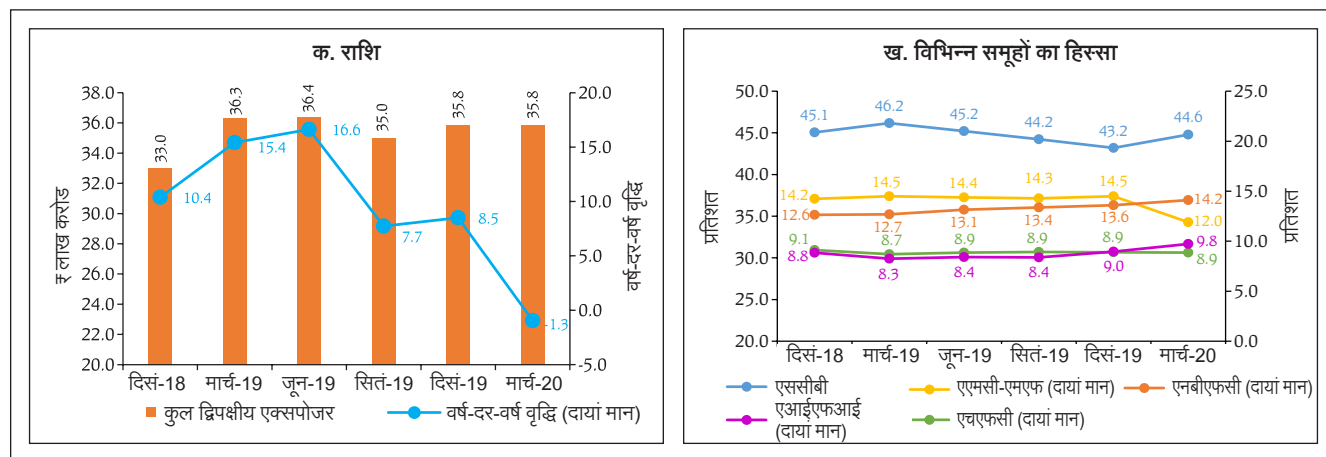
उलरिक बेक, स्कॉट लैश, ब्रायन वेन (1992), रिस्क सोसाइटी - टुवर्ड्स ए न्यू मॉडर्निटी, सेज पब्लिकेशन्स।

2.57 वित्तीय प्रणाली में संस्थाओं के बीच कुल बकाया द्विपक्षीय एक्सपोजर³⁷ वर्ष 2019-20 के दौरान मामूली रूप से घट गए (चार्ट 2.24 क)।

2.58 हिस्से में एक निरपेक्ष गिरावट के बावजूद मार्च 2020 में भारतीय वित्तीय प्रणाली में एससीबी का सबसे अधिक द्विपक्षीय

एक्सपोजर था। अन्य संस्थाओं (अन्य एससीबी सहित) को एससीबी द्वारा दिया गया ऋण और लिया गया उधार, प्रणाली के कुल ऋण और उधार का 44.6 प्रतिशत रहा है (चार्ट 2.24 ख)। बैंक समूहों के बीच, जहां पूरे वित्तीय क्षेत्र के मुकाबले में पीएसबी की निवल प्राप्य की स्थिति रही वहीं पीवीबी की निवल देय की

चार्ट 2.24: वित्तीय प्रणाली में संस्थाओं के बीच द्विपक्षीय एक्सपोजर



स्रोत: रिजर्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणी और स्टाफ आकलन।

37 समान क्षेत्र की संस्थाओं के बीच एक्सपोजर शामिल हैं।

स्थिति रही और एफबी समान रूप से संतुलित रहे (चार्ट 2.25 और 2.26)।

2.59 एएमसी-एमएफ अपनी प्रवृत्ति के अनुरूप निष्पादन से दूर रहे तथा वर्ष 2019-20 के दौरान उनके शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई, जबकि इनके एयूएम में कमी आई। दूसरी तरफ, वर्ष के दौरान एआईएफआई के शेयर, एससीबी से जमाराशियों, एएमसी-एफएम से उधारों तथा पीवीबी एवं एचएफसी के पुनर्वित्तपोषण में बढ़ोतरी हुई। वर्ष 2019-20 के दौरान एनबीएफसी, एचएफसी, बीमा कंपनियों तथा पेंशन फंडों के शेयरों में भी बढ़ोतरी हुई और ये मार्च 2020 में क्रमशः 14.2 प्रतिशत, 8.9 प्रतिशत, 8.8 प्रतिशत एवं 1.6 प्रतिशत पर कायम रहे (चार्ट 2.24 बी)।

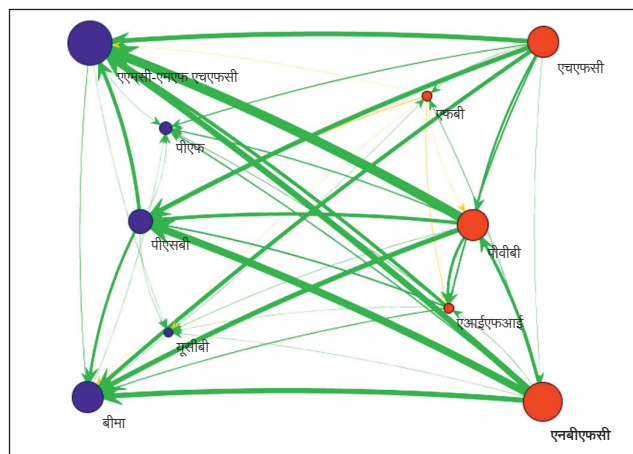
2.60 अंतर-क्षेत्रवार³⁸ एक्सपोजर के अनुसार एएमसी-एमएफ, जिनके बाद बीमा कंपनियों का स्थान है, ने सिस्टम को सबसे अधिक निधि उपलब्ध कराई, जबकि एनबीएफसी, जिसके बाद एचएफसी का स्थान है, को सबसे अधिक निधियों की प्राप्ति हुई। वित्तीय प्रणाली से जिन संस्थाओं को निधियों की प्राप्ति हुई, उनमें से पीवीबी ने 22 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की, जबकि एनबीएफसी तथा एचएफसी की देयताओं में सीमांत रूप से बढ़ोतरी हुई (चार्ट 2.26)।

2.61 वित्तीय प्रणाली को निधि उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं में एएमसी-एमएफ ने वित्तीय प्रणाली से अपनी प्राप्य राशियों में तेज गिरावट दर्ज की, जबकि इस मामले में पीएसबी और बीमा कंपनियों ने बढ़ोतरी दर्ज की (चार्ट 2.26)।

ए. अंतर-बैंक बाज़ार

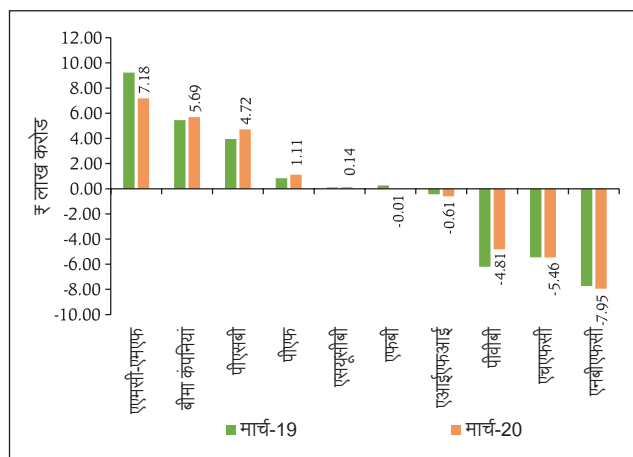
2.62 अंतर-बैंक बाज़ार (निधि-आधारित³⁹ और गैर-निधि आधारित⁴⁰ दोनों) का आकार विगत कुछ वर्षों से लगातार कम हो रहा है। बैंकिंग प्रणाली की कुल आस्तियों के हिस्से के रूप में निधि-आधारित अंतर-बैंक एक्सपोजर वर्ष के दौरान बैंकिंग प्रणाली में अधिशेष चलनिधि के साथ-साथ एलसीआर मानदंडों के प्रभाव के कारण, जो रक्षित अंतर-बैंक बाज़ार के निधियन की

चार्ट 2.25: वित्तीय प्रणाली का नेटवर्क प्लॉट, मार्च 2020



नोट: प्राप्य और देय में उसी समूह की संस्थाओं के बीच के लेनेदेन शामिल नहीं हैं। लाल रंग के गोले निवल देय वाली संस्थाएं हैं और नीले निवल प्राप्य वाली संस्थाएं हैं।
स्रोत: रिज़र्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणी और स्टाफ आकलन।

चार्ट 2.26: संस्थानों के निवल प्राप्य राशियों (सकारात्मक) / देय राशियों (-)



स्रोत: रिज़र्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणी और स्टाफ आकलन।

³⁸ अंतर क्षेत्रीय एक्सपोजर में वित्तीय प्रणाली में शामिल एक ही क्षेत्र की संस्थाओं के बीच के लेनेदेन शामिल नहीं हैं।

³⁹ निधि-आधारित एक्सपोजर में अल्पावधि और दीर्घावधि दोनों तरह के एक्सपोजर शामिल हैं। अल्पावधि एक्सपोजर पर डेटा सात श्रेणियों, अर्थात रेपो (नन-सेंट्रली क्लियर्ड), कॉल/नोटिस/टर्म मनी, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाण पत्र, अल्पावधि ऋण, अल्पावधि जमा और अन्य अल्पावधि एक्सपोजरों, में एकत्र किया जाता है। दीर्घावधि एक्सपोजर पर डेटा पांच श्रेणियों, अर्थात इक्विटी, दीर्घावधि कर्ज, दीर्घावधि ऋण, दीर्घावधि जमाराशियों और अन्य दीर्घावधि देयताओं, में एकत्र किया जाता है।

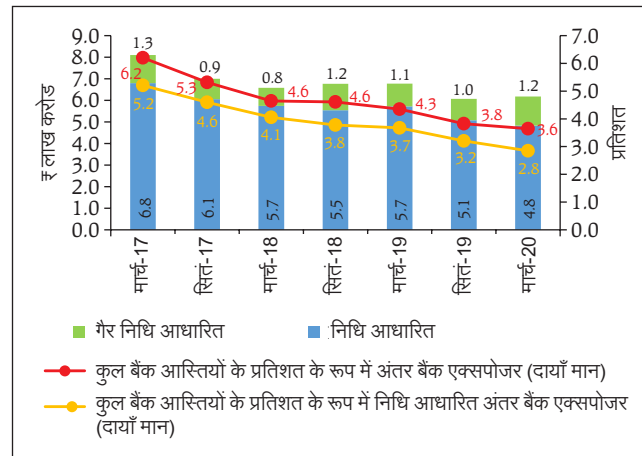
⁴⁰ गैर-निधि आधारित एक्सपोजर में, बकाया बैंक गारंटी, बकाया साख पत्र और डेरिवेटिव बाज़ार में घनात्मक मार्क-टू-मार्केट पोজीशन (उन एक्सपोजर को छोड़कर जिनके लिए सीसीआईएल द्वारा निपटान की गारंटी है) शामिल है।

तुलना में रक्षित निधियन को प्रोत्साहित करता है, और अधिक नरम हुआ (चार्ट 2.27)।

2.63 वर्ष 2020 के मार्च-अंत में अंतर-बैंक बाज़ार में पीएसबी हावी रहे जिनके बाद पीवीबी एवं एफबी का स्थान आता है (चार्ट 2.28)।

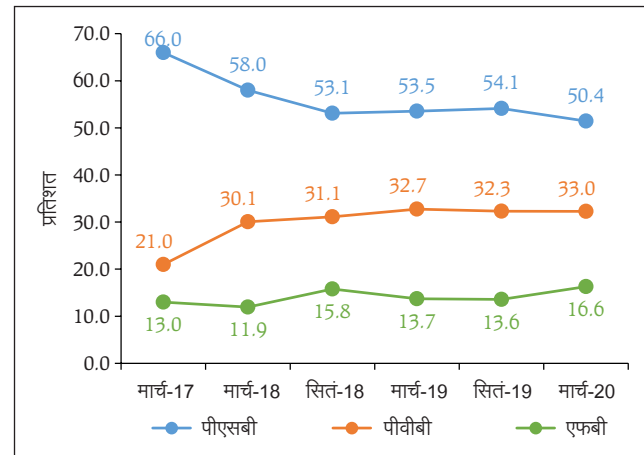
2.64 निधि-आधारित अंतर-बैंक बाज़ार के लगभग 70 प्रतिशत हिस्से की प्रकृति अल्पकालिक थी जिसमें एसटी जमाराशियों का हिस्सा सबसे अधिक था तथा उनके बाद एसटी ऋणों का स्थान था। निधि-आधारित अंतर-बैंक दीर्घावधि (एलटी) एक्सपोजर की संरचना यह दर्शाती है कि एलटी एक्सपोजर में आधे से थोड़ी अधिक की हिस्सेदारी एलटी ऋणों की थी जिनके बाद एलटी जमाराशियों का स्थान है (चार्ट 2.29)।

चार्ट 2.27: अंतर-बैंक बाज़ार



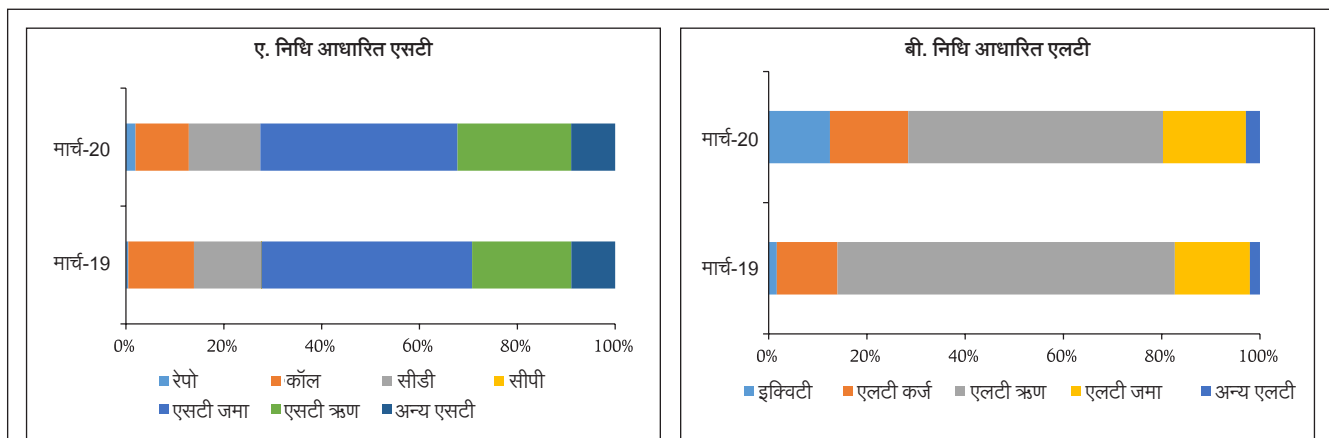
स्रोत: आरबीआई की पर्यवेक्षी विवरणियाँ एवं स्टाफ द्वारा गणना।

चार्ट 2.28: अंतर-बैंक बाजार में विभिन्न बैंक समूह



स्रोत: आरबीआई की पर्यवेक्षी विवरणियाँ एवं स्टाफ द्वारा गणना।

चार्ट 2.29: निधि आधारित अंतर-बैंक बाजार की संरचना



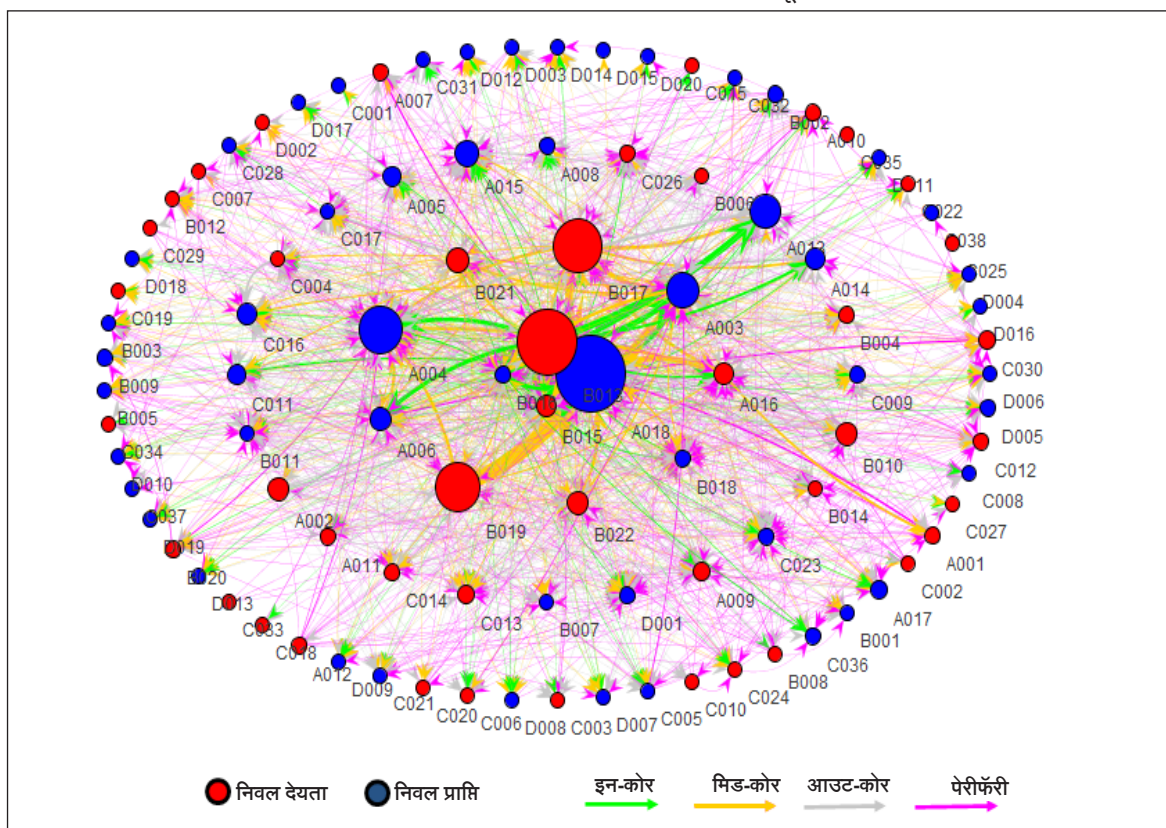
स्रोत: आरबीआई की पर्यवेक्षी विवरणियाँ एवं स्टाफ द्वारा गणना।

2.65 अंतर-बैंक बाज़ार के पास एक विशिष्ट कोर-पेरीफ़ेरी नेटवर्क स्ट्रक्चर^{41 42} है। वर्ष 2020 के मार्च-अंत में, परिधि के सबसे भीतरी कोर में 4 बैंक थे तथा इसके मिड-कोर में 9 बैंक थे। यह पिछले 5 वर्षों के दौरान देखी गई प्रवृत्ति के अनुरूप है, जब इस परिधि के सबसे भीतरी कोर में बैंकों की संख्या 2 से 5 के बीच थी। ये प्रायः सबसे बड़े पीएसबी अथवा पीवीबी होते हैं। अधिकतर विदेशी बैंक तथा लगभग सभी पुराने निजी बैंक प्रायः इस परिधि के सबसे बाहरी भाग में रहते हैं जो इनको भारत में सबसे कम जुड़ाव वाला बैंक बनाता है। शेष पीएसबी

तथा पीवीबी, कुछ बड़े एफबी सहित, इस परिधि के मध्य एवं बाहरी कोर का निर्माण करते हैं। अप्रैल 2020 से कुछ पीएसबी का विलयन इसके मध्य-कोर तथा बाहरी-कोर को प्रभावित करेगा (चार्ट 2.30)।

2.66 बैंकिंग प्रणाली (एससीबी) में अंतर-संबद्धता के स्तर में, जैसा कि संबद्धता अनुपात⁴³ द्वारा मापा गया है, पिछले कुछ वर्षों में धीरे-धीरे गिरावट होती रही है। जैसा कि पहले बताया गया है, यह संकुचित हो रहे अंतर-बैंक बाज़ार के अनुरूप है। क्लस्टर गुणांक⁴⁴, जो स्थानीय अंतर-संबद्धता को परिभाषित करता है

चार्ट 2.30: भारतीय बैंकिंग प्रणाली का नेटवर्क ढांचा (एससीबी + एसयूसीबी) – मार्च 2020



स्रोत: आरबीआई की पर्यवेक्षी विवरणियाँ एवं स्टाफ द्वारा गणना।

41 बैंकिंग प्रणाली के नेटवर्क का आरेखात्मक प्रतिनिधित्व एक ऐसी टियर वाली संरचना है, जहां नेटवर्क में एक-दूसरे के साथ विभिन्न बैंकों में विभिन्न परिमाण अथवा स्तर की संयोजकता है। सबसे ज्यादा कनेक्टेड बैंक इनर मोस्ट कोर (नेटवर्क आरेख के केंद्र में) में हैं। बैंकों को बाद में उनके सापेक्ष संयोजकता के स्तर के आधार पर मिड कोर, आउटर कोर और पेरीफ़ेरी (आरेख में केंद्र के आसपास संकेंद्रित वृत्तों) में रखा गया है। टायर नेटवर्क आरेख में लिंक का रंग कोडिंग नेटवर्क में विभिन्न स्तरों से उधार का प्रतिनिधित्व करता है (उदाहरण के लिए, हरा लिंक आंतरिक कोर में बैंकों से उधार का प्रतिनिधित्व करता है)। प्रत्येक बॉल एक बैंक का प्रतिनिधित्व करती है और प्रणाली में अन्य सभी बैंकों की तुलना में उनके निवल स्थितियों के अनुसार उन्हें भारित किया गया है। प्रत्येक बैंक को जोड़ने वाली लाइनों को बकाया एक्सपोजरों के आधार पर भारित किया गया है।

42 इस विश्लेषण के लिए 78 एससीबी और 20 एसयूसीबी पर विचार किया गया है।

43 संयोजकता अनुपात संपूर्ण नेटवर्क में सभी संभावित लिंक के सापेक्ष नोड्स के बीच लिंक की वास्तविक संख्या को मापता है। कृपया अनुबंध 2 देखें।

44 क्लस्टर गुणांक : नेटवर्क में क्लस्टरिंग यह मापता है कि प्रत्येक नोड आपस में कैसे जुड़ा हुआ है। विशेष रूप से, इसकी बहुत अधिक संभावना बढ़ जाती है कि (वित्तीय नेटवर्क के मामलों में बैंकों के समकक्ष) एक नोड के समीप दो नोड आपस में भी समीप हों। नेटवर्क के लिए एक उच्च क्लस्टर गुणांक प्रणाली में प्रचलित उच्च स्थानीय अंतरसम्बन्ध के साथ मेल खाता है। पद्धति के लिए अनुबंध 2 देखें।

(अर्थात्, क्लस्टर होने की प्रवृत्ति), पिछले 5 वर्षों की अवधि में अधिकतर स्थिर रहा है (चार्ट 2.31)।

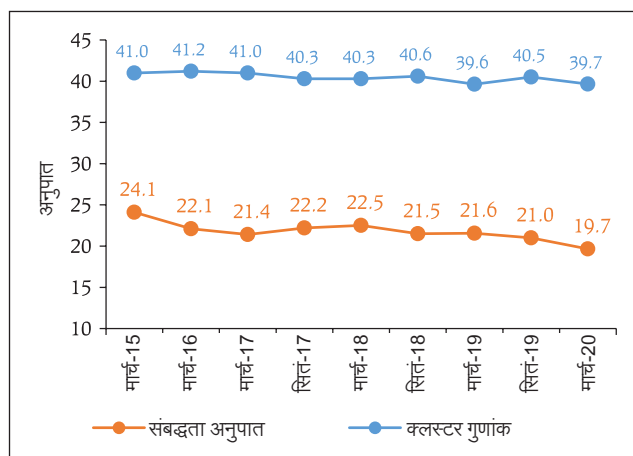
बी. एएमसी-एमएफ का एक्सपोजर

2.67 एयूएम में हाल की गिरावट के बावजूद, एएमसी-एमएफ की सकल प्राप्य राशियाँ लगभग ₹7.86 लाख करोड़ (उनके औसत एयूएम का 29.5 प्रतिशत) थीं, जबकि वर्ष 2020 के मार्च-अंत में उनकी सकल देयताएं लगभग ₹0.68 लाख करोड़ थीं।

2.68 उनके निधीयन के शीर्ष प्राप्तकर्ता एससीबी थे जिनके बाद एनबीएफसी, एचएफसी और एआईएफआई का स्थान आता है। वर्ष 2018-19 में एससीबी से उनकी प्राप्य राशियों में, जिनमें तेजी से बढ़ोतरी हो गई थी, वर्ष 2019-20 में गिरावट आई। तथापि, मात्रा की दृष्टि से एससीबी, एनबीएफसी और एचएफसी सभी ने एएमसी-एमएफ को अपनी देय राशियों में गिरावट दर्ज की है। इसके विपरीत, अन्य वित्तीय संस्थाओं के वित्तपोषण में बढ़ोतरी करने के कारण एएमसी-एमएफ पर एआईएफआई का भरोसा बढ़ गया। एएमसी-एमएफ से निधीयन कर्ज तथा एआईएफआई द्वारा जारी सीडी के लिए अभिदान का बड़ा साधन था (चार्ट 2.32 ए)।

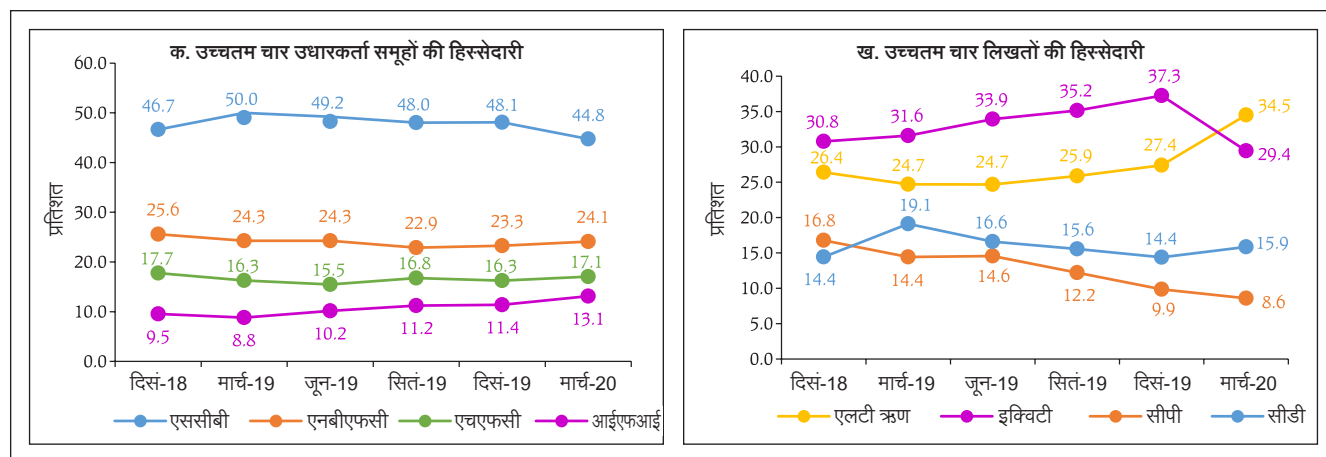
2.69 लिखतवार, एएमसी-एमएफ प्राप्य राशियों ने मुख्यतः हाल की तिमाहियों में इक्विटी निधीयन के शेयर में तेज बढ़ोतरी दर्ज की। यह वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही में पूर्व की स्थिति में वापस आ गई, परंतु कर्ज निधीयन में बढ़ोतरी द्वारा इसकी क्षतिपूर्ति की गई। एएमसी-एमएफ ने सीपी की तुलना में सीडी को वरीयता देना जारी रखा (चार्ट 2.32 बी)।

चार्ट 2.31: बैंकिंग प्रणाली (एससीबी) की संयोजकता सांख्यिकी



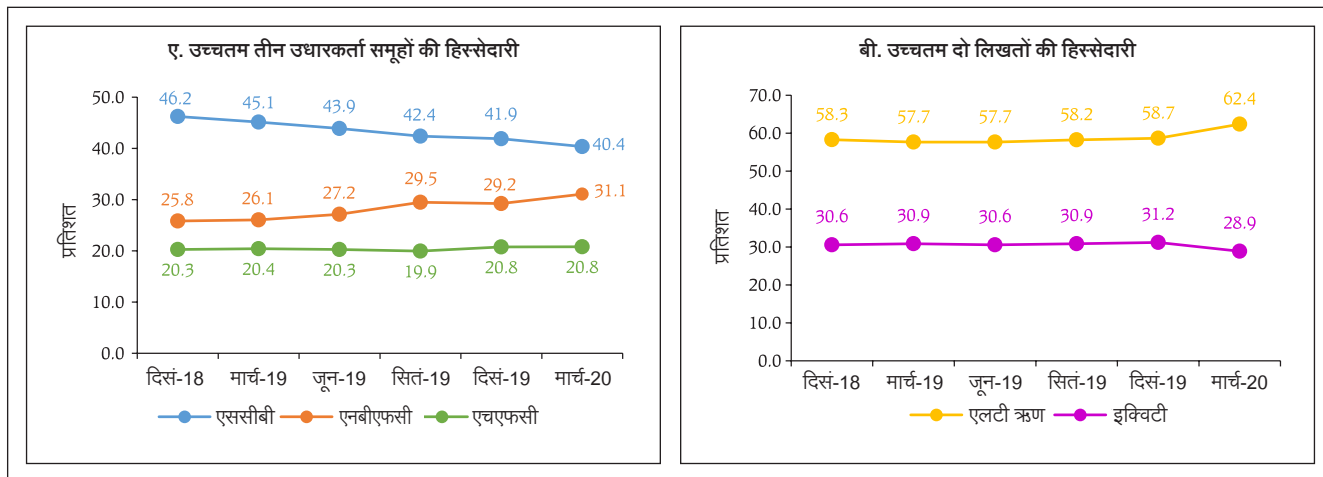
स्रोत: आरबीआई की पर्यवेक्षी विवरणियाँ एवं स्टाफ द्वारा गणना।

चार्ट 2.32: वित्तीय प्रणाली से एएमसी-एमएफ की सकल प्राप्तियाँ



स्रोत: आरबीआई की पर्यवेक्षी विवरणियाँ एवं स्टाफ द्वारा गणना।

चार्ट 2.33: वित्तीय प्रणाली से एआईएफआई की सकल प्राप्तियाँ



स्रोत: आरबीआई की पर्यवेक्षी विवरणियाँ एवं स्टाफ द्वारा गणना।

सी. बीमा कंपनियों का एक्सपोजर

2.70 वित्तीय प्रणाली को सबसे अधिक निवल निधियां उपलब्ध कराने में बीमा कंपनियों का दूसरा स्थान (मार्च 2020 में सकल प्राप्य राशियाँ ₹5.93 लाख करोड़ तथा सकल देयताएं ₹0.24 लाख करोड़ थीं) है।

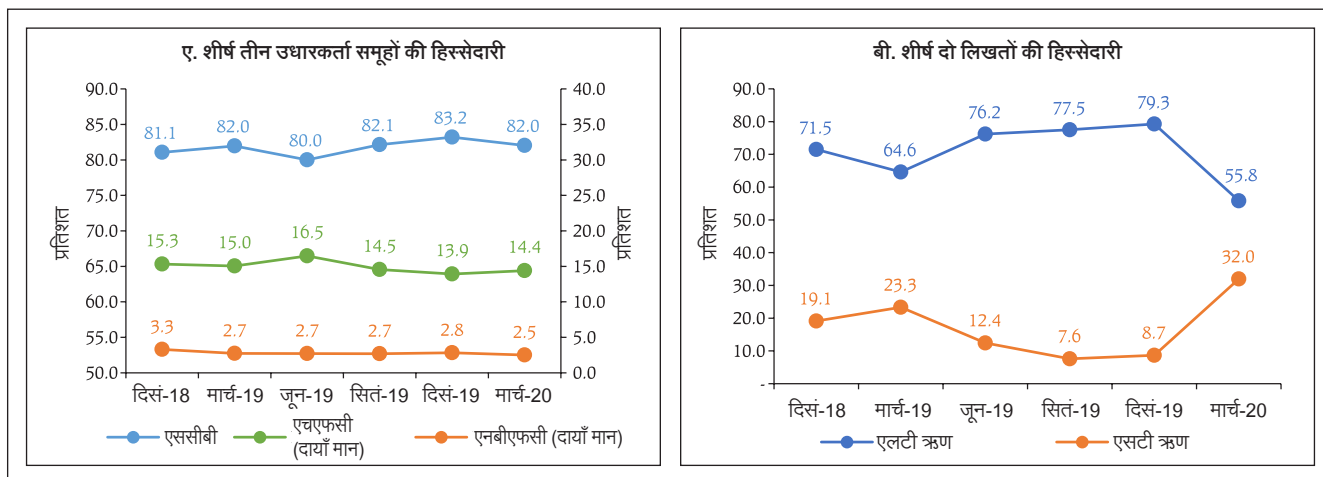
2.71 उनकी निधियों के सबसे बड़े प्राप्तकर्ता एससीबी थे जिनके बाद एनबीएफसी और एचएफसी का स्थान आता है। बीमा कंपनियों की लगभग संपूर्ण प्राप्य राशियों के लिए दीर्घावधि कर्ज और इक्विटी साधन बने, जिनका अल्पावधि लिखतों के प्रति केवल सीमित एक्सपोजर था। दीर्घावधि कर्ज के शेयर ने, जिसमें गिरावट हो रही थी, एनबीएफसी और एआईएफआई द्वारा दिए जा रहे कर्ज को लेने के लिए इन कंपनियों की सहमति के

परिणामस्वरूप वर्ष 2019-20 में धीरे-धीरे वापसी की (चार्ट 2.33 ए एवं बी)।

डी. एआईएफआई का एक्सपोजर

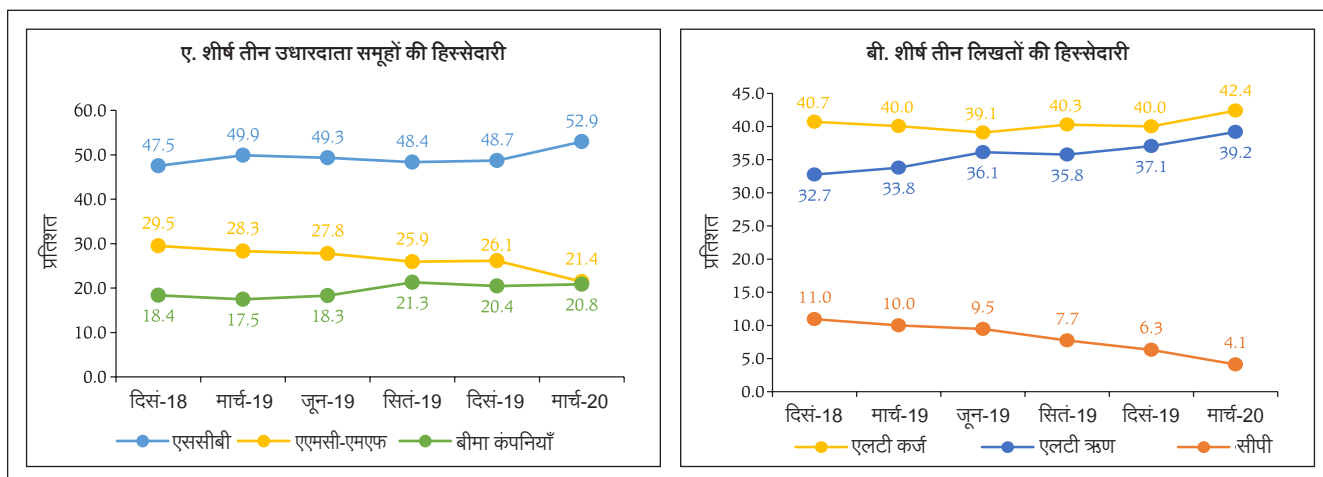
2.72 वर्ष-दर-वर्ष की स्थिति के अनुसार वर्ष 2020 के मार्च-अंत में एआईएफआई की सकल प्राप्य राशियां लगभग 16 प्रतिशत तक बढ़कर ₹3.18 लाख करोड़ हो गईं। उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों के शीर्ष प्राप्तकर्ता एससीबी (प्राथमिक रूप से पीवीबी) थे, जिनके बाद एचएफसी और एनबीएफसी का स्थान है। लिखतवार, इन निधियों ने प्राथमिक रूप से ऋणों – एलटी और एसटी दोनों के वित्तपोषण के उद्देश्य से ऋण-का रूप ले लिया (चार्ट 2.34 ए और बी)।

चार्ट 2.34: वित्तीय प्रणाली से एआईएफआई की सकल प्राप्तियाँ



स्रोत: आरबीआई की पर्यवेक्षी विवरणियाँ एवं स्टाफ द्वारा गणना।

चार्ट 2.35: वित्तीय प्रणाली को एनबीएफसी की सकल देयताएं



स्रोत: आरबीआई की पर्यवेक्षी विवरणियाँ एवं स्टाफ द्वारा गणना।

ई. एनबीएफसी का एक्सपोजर

2.73 वित्तीय प्रणाली से निधियों के सबसे बड़े निवल उधारकर्ता एनबीएफसी थे, जिनकी वर्ष 2020 के मार्च-अंत में सकल देयताएं ₹8.84 लाख करोड़ और सकल प्राप्य राशियाँ ₹0.89 लाख करोड़ थीं। एससीबी द्वारा दी गई निधियों में से आधा से अधिक एनबीएफसी ने प्राप्त किया, जिनके बाद एमसी-एमएफ और बीमा कंपनियों का स्थान आता है (चार्ट 2.35 ए)।

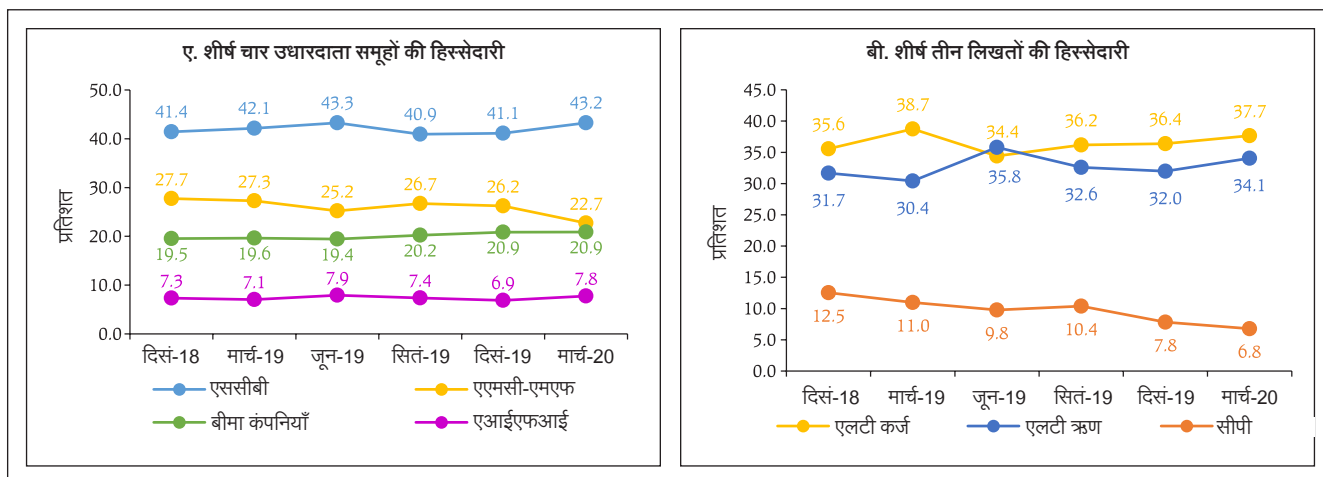
2.74 एनबीएफसी फंडिंग मिक्स में लिखतों का चयन एलटी ऋणों (एससीबी और एआईएफआई द्वारा सब्सक्राइव किया गया) और एसटी कर्ज (बीमा कंपनियों और एमसी-एमएफ द्वारा धारित) की बढ़ती भूमिका तथा सीपी (एमसी-एमएफ और एससीबी द्वारा अभिदत्त) के शेयर में हो रही गिरावट को दर्शाता है (चार्ट 2.35 बी)।

एफ. एचएफसी के प्रति एक्सपोजर

2.75 वित्तीय प्रणाली से निधियों के दूसरे सबसे बड़े उधारकर्ता एचएफसी थे जिनकी वर्ष 2020 के मार्च-अंत में सकल देयताएं लगभग ₹5.91 लाख करोड़ और सकल प्राप्य राशियाँ ₹0.45 लाख करोड़ थीं। एचएफसी का उधार प्रोफाइल, एचएफसी को निधियां उपलब्ध कराने में एआईएफआई की महत्वपूर्ण भूमिका को छोड़कर, एनबीएफसी के उधार प्रोफाइल के समान था। अंतिम तिमाही में एमसी-एमएफ द्वारा एचएफसी के निधीयन के शेयर में तेजी से कमी आई। इसके विपरीत, एससीबी का शेयर बढ़ गया है (चार्ट 2.36 ए)।

2.76 एनबीएफसी की तरह एलटी कर्ज, एसटी ऋण तथा सीपी जैसे तीन शीर्ष लिखत थे जिनके माध्यम से एचएफसी द्वारा

चार्ट 2.36: वित्तीय प्रणाली को एचएफसी की सकल देयताएं



स्रोत: आरबीआई की पर्यवेक्षी विवरणियाँ एवं स्टाफ द्वारा गणना।

वित्तीय प्रणाली से निधियां जुटाई गईं। हालांकि, उनका फंडिंग मिक्स पिछली छह तिमाहियों में बदलता रहा है। सीपी (एमसी-एमएफ तथा, कुछ हद तक, एससीबी द्वारा सबस्क्राइब किया गया) पर भरोसा पिछली छह तिमाहियों में लगातार कम हुआ है। एलटी ऋण (बैंकों और एआईएफआई से) और एलटी कर्ज के शेयर द्वारा इसकी क्षतिपूर्ति की गई (चार्ट 2.36 बी)।

2.77 पीएसबी द्वारा दबावग्रस्त एनबीएफसी/एचएफसी के लिए कुल निधीयन में बढ़ोतरी हो रही है (सारणी 2.14 एवं चार्ट 2.26)। एनबीएफसी/एचएफसी क्रेडिट पोर्टफोलियो में पक्षपातपूर्ण चयन वाली प्रतिकूल परिस्थिति विद्यमान हो तो इसका परिणाम संक्रामक होगा। साथ ही, बैंक द्वारा निधीयन पर अधिक भरोसा कई अन्य वित्तीय उत्पादों, मुख्यतः उन मामलों में जहां इस क्षेत्र को बैंकों से प्रतिस्पर्धा है, के मुकाबले एनबीएफसी को अप्रतिस्पर्धी बना देता है। इसके परिणामस्वरूप एनबीएफसी पोर्टफोलियो के लिए पसंदीदा विकल्प का चुनाव पक्षपातपूर्ण⁴⁵ चयन वाली प्रतिकूल परिस्थिति पैदा कर सकता है।

II.5.2 संक्रमण विश्लेषण⁴⁶

2.78 संक्रमण विश्लेषण विभिन्न बैंकों के प्रणालीगत महत्व का आकलन करने के लिए नेटवर्क तकनीक का प्रयोग करता है। प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण किसी बैंक की विफलता का परिणाम बैंकिंग प्रणाली के लिए बड़ी ऋण-शोधन क्षमता और

चलनिधि हानियों के रूप में होता है जो, बदले में, बैंकों की प्रारंभिक पूंजी और चलनिधि की स्थिति सहित विफल बैंक का शेष बैंकिंग प्रणाली से आपसी जुड़ाव की संख्या, प्रकृति (चाहे यह एक उधारदाता हो अथवा उधारकर्ता) तथा परिमाण पर निर्भर करता है।

ए. संयुक्त ऋण-शोधन क्षमता⁴⁷ – बैंक की विफलता के कारण एससीबी के लिए चलनिधि⁴⁸ संक्रमण वाली हानियाँ

2.79 इन विश्लेषण में बैंकिंग प्रणाली पर विभिन्न आघातों के प्रभाव को घटित हुई बैंक विफलताओं की संख्या तथा वहन की गई ऋण-शोधन क्षमता एवं चलनिधि हानियों की राशि को ध्यान में रखते हुए देखा जाता है।

2.80 वर्ष 2020 के मार्च-अंत की स्थिति पर आधारित बैंकिंग नेटवर्क⁴⁹ का संक्रमण विश्लेषण यह इंगित करता है कि संक्रमण हानियों को अधिकतम उत्पन्न करने की क्षमता वाले बैंक के विफल होने की स्थिति पैदा होने के कारण एससीबी के कुल टियर I पूंजी का 4.30 प्रतिशत ऋण-शोधन क्षमता हानि तथा बैंकिंग प्रणाली के उच्च गुणवत्ता वाली कुल चलनिधि आस्तियों (एचक्यूएलए) के 0.30 प्रतिशत के बराबर की चलनिधि हानि होगी। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2020 के मार्च-अंत में अपेक्षाकृत कम हानियाँ एक बेहतर पूंजीगत सरकारी क्षेत्र की

सारणी 2.14: वित्तीय प्रणाली से वित्तीय मध्यस्थों के चुनिंदा वर्गों को निवल निधीयन के स्रोत

(₹ करोड़ में)

		सितंबर-19				मार्च-20			
		निधियों के उपयोगकर्ता							
		पीएसबी	पीवीबी	एनबीएफसी	एचएफसी	पीएसबी	पीवीबी	एनबीएफसी	एचएफसी
निधियों के स्रोत	एआईएफआई	-54,249	1,35,195	8,063	42,956	-84,353	97,172	7,904	45,555
	पीएसबी	-	1,22,443	2,50,694	1,53,810	-	1,33,892	3,02,375	1,67,220
	पीवीबी	-1,22,443	-	84,518	55,889	-1,33,892	-	90,529	44,442
	एमसी	1,03,736	3,33,158	2,06,488	1,51,440	91,248	2,37,978	1,74,517	1,29,605

स्रोत: आरबीआई की पर्यवेक्षी विवरणियाँ एवं स्टाफ द्वारा गणना।

⁴⁵ जून 2019 की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट।

⁴⁶ पद्धति के लिए अनुबंध 2 देखें।

⁴⁷ ऋण-शोधन संक्रमण विश्लेषण में, एक अथवा एक से अधिक उधारकर्ता बैंक के विफल होने के कारण बैंकिंग प्रणाली को दूरगामी प्रभाव वाली हुई सकल हानि का पता लगाया जाता है। संक्रमण विश्लेषण के लिए विफलता के मानदंड को टियर-I पूंजी का 7 प्रतिशत से नीचे गिर जाने के रूप में लिया जाता है।

⁴⁸ तरलता संक्रमण विश्लेषण में, एक बैंक को विफल तब माना जाता है, जब उसकी तरल परिसंपत्तियाँ एक बड़े निवल ऋणदाता की विफलता के कारण होने वाले तरलता तनाव की झेलने के लिए पर्याप्त नहीं होती हैं। तरल परिसंपत्तियों को इस प्रकार मापा जाता है: एनडीटीएल का 16 प्रतिशत + अधिशेष एसएलआर + अधिशेष सीआरआर।

⁴⁹ संक्रमण के शुरु होने से पहले प्रारम्भ में ही ऋण-शोधन क्षमता मानदंड पर खरा नहीं उतरने वाले एससीबी को इस अभ्यास में शामिल नहीं किया गया है।

बैंकिंग प्रणाली एवं एक संकुचित हो रहे अंतर-बैंक बाज़ार को दर्शाती है (सारणी 2.15)।

बी. एनबीएफसी/एचएफसी की विफलता के कारण एससीबी के लिए संक्रामक ऋण-शोधन क्षमता हानियाँ

2.81 एनबीएफसी एवं एचएफसी, जैसा कि पहले टिप्पणी की गई है, वित्तीय प्रणाली से निधियों के सबसे बड़े उधारकर्ता हैं। इस निधीयन का एक बड़ा भाग बैंकों से आता है। इसलिए, एनबीएफसी और एचएफसी की विफलता उनके उधारदाताओं के लिए एक ऋण-शोधन क्षमता आघात के रूप में कार्य करेगा, जो संक्रमण द्वारा प्रसारित हो सकता है।

2.82 किसी एनबीएफसी की विशिष्ट प्रकृति की विफलता के कारण बैंकिंग प्रणाली की संभावित ऋण-शोधन क्षमता संक्रमण वाली हानियों⁵⁰ का विश्लेषण यह इंगित करता है कि वर्ष 2020 के मार्च-अंत में शीर्ष तीन पीएसयू एनबीएफसी की विफलता के कारण संक्रामक हानियाँ बैंकिंग प्रणाली के टियर-1 पूंजी के 4.3 प्रतिशत से 5 प्रतिशत के बीच रहीं। आगे, बैंकिंग प्रणाली के लिए ऋण-शोधन हानियाँ पैदा करने की अधिकतम क्षमता वाले गैर-पीएसयू एनबीएफसी बाद वाले की कुल टियर 1 पूंजी को 2.7 प्रतिशत धराशायी कर सकता है, लेकिन इससे कोई भी बैंक विफल नहीं हो सकता है (सारणी 2.16)।

2.83 बैंकिंग प्रणाली के लिए ऋण-शोधन हानियाँ पैदा करने की अधिकतम क्षमता वाले एचएफसी बिना किसी बैंक की विफलता का करना बनते हुए बाद वाली कुल टियर 1 पूंजी के 6.77 प्रतिशत को धराशायी कर सकता है (सारणी 2.17)।

2.84 हालांकि, एससीबी द्वारा एनबीएफसी एवं एचएफसी को दिए जा रहे ऋण, जैसा की ऊपर टिप्पणी की गई है (चार्ट 2.35 एवं 2.36), में बढ़ोतरी हुई है, वर्ष 2020 के मार्च-अंत में हानियाँ एक वर्ष पूर्व की तुलना में कम थीं जिसका कारण बेहतर पूंजीगत सरकारी क्षेत्र एवं संकुचित हो रहे अंतर-बैंक बाज़ार थे।

सारणी 2.15: बैंक की विफलता के कारण संक्रामक हानियाँ – मार्च 2020

ट्रिगर	बैंकिंग प्रणाली के टियर 1 कैपिटल का %	एचक्यूएलए का %	ऋण-शोधन क्षमता हानियों के कारण चूक करने वाले बैंकों की संख्या	चलनिधि हानियों के कारण चूक करने वाले बैंकों की संख्या
बैंक 1	4.30	0.30	1	0
बैंक 2	3.23	0.35	1	0
बैंक 3	1.87	2.47	0	2
बैंक 4	1.74	1.65	0	4
बैंक 5	1.72	1.01	0	0

टिप्पणी: बैंकिंग प्रणाली को हुई ऋण-शोधन हानियों के आधार पर शीर्ष 5 "ट्रिगर बैंकों" का चयन किया गया है।

स्रोत: आरबीआई की पर्यवेक्षी विवरणियाँ एवं स्टाफ द्वारा गणना।

सारणी 2.16: गैर-पीएसयू एनबीएफसी की विफलता के कारण संक्रामक हानियाँ – मार्च 2020

ट्रिगर	बैंकिंग प्रणाली के टियर 1 कैपिटल के % के रूप में ऋण-शोधन क्षमता हानियाँ	ऋण-शोधन क्षमता हानियों के कारण चूक करने वाले बैंकों की संख्या
एनबीएफसी 1	2.71	0
एनबीएफसी 2	2.17	0
एनबीएफसी 3	1.88	0
एनबीएफसी 4	1.57	0
एनबीएफसी 5	1.29	0

टिप्पणी: बैंकिंग प्रणाली को हुई ऋण-शोधन हानियों के आधार पर शीर्ष 5 "ट्रिगर बैंकों" का चयन किया गया है।

स्रोत: आरबीआई की पर्यवेक्षी विवरणियाँ एवं स्टाफ द्वारा गणना।

सारणी 2.17: एचएफसी की विफलता के कारण संक्रमण हानियाँ – मार्च 2020

ट्रिगर	बैंकिंग प्रणाली के टियर 1 कैपिटल के % के रूप में ऋण-शोधन क्षमता हानियाँ	ऋण-शोधन क्षमता हानियों के कारण चूक करने वाले बैंकों की संख्या
एचएफसी 1	6.77	0
एचएफसी 2	3.64	0
एचएफसी 3	1.65	0
एचएफसी 4	1.63	0
एचएफसी 5	1.20	0

टिप्पणी: बैंकिंग प्रणाली को हुए ऋण-शोधन हानि के आधार पर शीर्ष 5 "ट्रिगर बैंकों" का चयन किया गया है।

स्रोत: आरबीआई की पर्यवेक्षी विवरणियाँ एवं स्टाफ द्वारा गणना।

⁵⁰ संक्रमण के प्रारंभ होने से पहले ऋण-शोधन क्षमता मानदंड (टियर 1 सीआरएआर – 7 प्रतिशत के बराबर अथवा इससे कम) पर दो एससीबी खरा नहीं उतरे। इन दो बैंकों को इस अभ्यास में शामिल नहीं किया गया है।

सी. समष्टि-आर्थिक आघातों के कारण एससीबी के लिए ऋण-शोधन क्षमता संक्रमण हानियाँ⁵¹

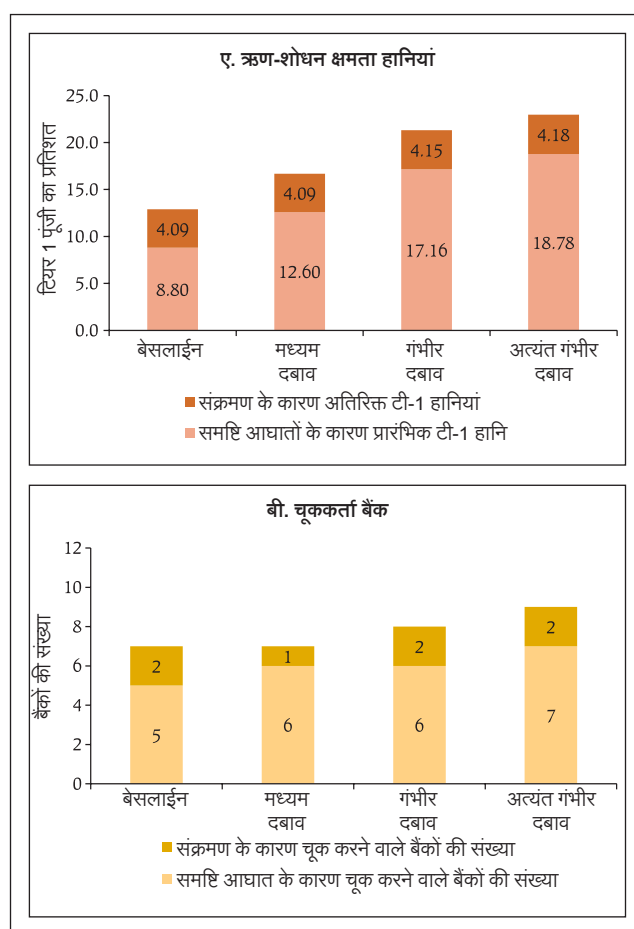
2.85 अर्थव्यवस्था में सामान्यीकृत गिरावट की स्थिति में बैंकिंग प्रणाली में समष्टि-आर्थिक आघातों के कारण विपदा वाली स्थिति होने पर किसी बैंक की विफलता के संक्रामक प्रभाव में इजाफा हो सकता है। समष्टि-आर्थिक आघात कुछ एससीबी के लिए ऋण-शोधन क्षमता मानक पर खरा उतरने में विफल कर सकते हैं जो आगे की ऋण-शोधन क्षमता हानियों के लिए ट्रिगर का काम कर सकते हैं। पिछली पुनरावृत्ति में संस्था पर आघात किया गया जिसके कारण अधिकतम ऋण-शोधन क्षमता संक्रमण हानियाँ पैदा हो सकती है। इस पुनरावृत्ति में, तथापि, एक विशिष्ट बैंक की पूंजी पर समष्टि-आर्थिक आघातों का आरंभिक प्रभाव समष्टि-दबाव परीक्षणों से लिया गया जिसमें मार्च 2021⁵² के लिए बेसलाइन, तीन (मध्यम, गंभीर और बहुत गंभीर) प्रतिकूल परिदृश्य लिए गए थे।

2.86 समष्टि-आर्थिक आघात के कारण बेसलाइन, मध्यम, गंभीर और अत्यंत गंभीर दबाव परिदृश्यों के लिए आरंभिक पूंजीगत हानि टियर। पूंजी का क्रमशः 8.80 प्रतिशत, 12.60 प्रतिशत, 17.16 प्रतिशत और 18.78 प्रतिशत रही। समष्टि-आर्थिक आघातों के कारण 7 प्रतिशत की टियर। पर्याप्तता अनुपात बनाए रखने में विफल बैंकों की संख्या बेसलाइन में 5, मध्यम और गंभीर दबाव परिदृश्यों में 6 एवं अत्यंत गंभीर दबाव परिदृश्य में 7 है। वर्ष 2020 के मार्च-अंत में इन बैंकों की टियर। पूंजी कम (या तो पहले से 7 प्रतिशत के नीचे अथवा सीमांत रूप से अधिक) थी।

2.87 संक्रमण (समष्टि आघातों के कारण आरंभिक हानि से अधिक एवं ऊपर) के कारण बैंकिंग प्रणाली को हुई अतिरिक्त ऋण-शोधन क्षमता हानियाँ, बैंकिंग प्रणाली के टियर। पूंजी के रूप में, क्रमशः बेसलाइन और मध्यम दबाव परिदृश्यों के मामले में 4.09 प्रतिशत तथा गंभीर एवं अत्यंत गंभीर दबाव के मामले में क्रमशः 4.15 और 4.18 प्रतिशत हैं। वैसी परिस्थितियों में, बेसलाइन परिदृश्य, गंभीर व अत्यंत गंभीर दबाव परिदृश्यों में

संक्रमण के कारण दो अतिरिक्त बैंक विफल होते हैं, जबकि मध्यम दबाव परिदृश्य में एक अतिरिक्त बैंक विफल होता है। इन बैंकों के अपेक्षकृत छोटा होने के साथ-साथ अंतर-बैंक बाजार में सीमित उधार लेने तथा अन्य बैंकों के बेहतर रूप से पूंजीगत होने के कारण भी संक्रमण का प्रभाव निम्न है। आगे, दो विफल हो रहे बैंकों का मजबूत बैंकों के साथ विलयन (जो 01 अप्रैल 2020 से लागू हो गया) प्रणालीगत समुत्थान शक्ति को आगे बेहतर बनाएगा (चार्ट 2.37)।

चार्ट 2.37: समष्टि आर्थिक आघातों के बाद संक्रामक हानियाँ



टिप्पणी: मार्च 2021 में अनुमानित पूंजी में हितधारकों द्वारा प्रवाहित कि गई किसी पूंजी को गणना में नहीं शामिल किया गया है। इसने पूंजीगत रिजर्व में 25 प्रतिशत न्यूनतम लाभ अतिरिक्त करने की रूढ़िवादी धारणा को अपनाया है।

स्रोत: रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियाँ एवं स्टाफ द्वारा गणना।

51 पीएसबी और पीवीबी दोनों के लिए विफलता का मानदंड टियर-1 सीआरएआर का 7 प्रतिशत से नीचे गिर जाने के रूप में लिया गया है।

52 समष्टि-दबाव परीक्षणों के परिणामों का प्रयोग संक्रमण विश्लेषण द्वारा किया गया और निम्नलिखित धारणाएं बनाई गईं:

ए) समष्टि-परिदृश्य के तहत अनुमानित हानियाँ (मार्च 2020 की इसकी वास्तविक राशि की तुलना में मार्च 2021 में प्रतिशत रूप में अनुमानित टियर-1 सीआरएआर में कमी के रूप में आकलित किया गया) मार्च 2020 की पूंजी स्थिति पर लागू किए गए थे, यह मानते हुए कि मार्च 2020 और मार्च 2021 दोनों के लिए तुलना पत्र का खाका आनुपातिक रूप से समान है।

बी) वित्तीय संस्थाओं के बीच द्विपक्षीय एक्सपोजर को मार्च 2020 और मार्च 2021 के लिए समान माना गया।

2.88 संक्षेप में, कोविड-19 महामारी से उत्प्रेरित व्यवधानों के आलोक में विनियामक अधिकार-क्षेत्र में विनियामक छूट का उद्देश्य सम्पूर्ण प्रणाली की ऋण-शोधन क्षमता को बचाने के प्रयास करते हुए जोखिमों को न्यूनतम करना है। परिणामस्वरूप, वित्तीय प्रणाली पर निश्चित रूप से अधिक अतिरिक्त दबाव रहेगा। समस्त प्रणाली का निरंतर रूप से चलते रहने की बात करें तो नीतिगत उपायों ने वित्तीय प्रणाली में समुत्थान शक्ति सुनिश्चित किया है।

2.89 बैंकिंग प्रणाली अपनी पूंजी को बढ़ाएगा जिससे कि कोविड-19 के बाद अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में मदद मिल सके। संकुचित हो रहे अंतर-बैंक बाजार सहित उच्च पूंजीकरण ने अंतर-बैंक संक्रमण जोखिमों को कम किया है। जबकि एनबीएफसी/एचएफसी के प्रति म्युच्यूल फंड के एक्सपोजर कम हुए हैं, बैंकों के मामले में समान एक्सपोजर बढ़े हैं। म्युच्यूल फंड को अपने चलनिधि ढांचे में सुधार करना होगा जिससे कि प्रभाव-विस्तार को रोका जा सके।

अध्याय III

वित्तीय क्षेत्र में विनियामकीय पहल

वैश्विक महामारी कोविड-19 की प्रतिक्रिया स्वरूप घटती मांग परिस्थितियों, क्षेत्र विशेष में उत्पन्न चलनिधि के दबाव और वित्तीय स्थिरता तथा अन्य चिंताओं के निवारण हेतु केंद्रीय बैंक और अन्य विनियामकों के साथ ही साथ मानक तय करने वाले निकायों ने वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) के दौरान किए गए उपायों से भी आगे बढ़कर कदम उठाए हैं। तात्कालिक परिस्थितियों में इस तरह की नीतिगत कार्रवाइयों को उचित ठहराया जा सकता है, किंतु पारदर्शिता सहित वित्तीय प्रणाली की दीर्घावधिक स्थिरता सुनिश्चित करने वाले विनियामकीय और पर्यवेक्षण संबंधी सिद्धांतों से इनका संतुलन भी आवश्यक है। घरेलू मोर्चे पर देखा जाए तो भारत सरकार और वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों ने वैश्विक महामारी-जन्य बाधाओं से निपटने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) तथा उसकी उप-समिति (एफएसडीसी-एससी) उभरती चुनौतियों प्रति चौकन्नी रही हैं।

3.1 कोविड-19 ने बहुत बड़ी संख्या में जान एवं आजीविका की तिलांजलि ले ली है और यह वैश्विक वित्तीय स्थिरता के लिए प्रलयकारी चुनौती बन गई है। वर्ष 2020 की पहली तिमाही के दौरान, व्यापक स्तर पर चूक के साथ उधार लेने की लागत में तेजी से बढ़ोतरी होने की आशंकाओं के साथ जोखिमपूर्ण आस्तियों की कीमत में भारी गिरावट आई, और बाजार में घटबढ़ तीव्र हो गई है। संकट की अभूतपूर्व प्रकृति को देखते हुए, केंद्रीय बैंकों को पुनः अग्रिम पंक्ति में खड़ा कर दिया गया है, और इन्होंने सुरक्षा के अभूतपूर्व उपाय किए हैं। वित्तीय बाजारों और वित्तीय मध्यस्थों को क्रियाशील बनाए रखने, तथा वैश्विक वित्तीय स्थिरता कायम रखने के लिए इन उपायों में पारंपरिक और गैर-पारंपरिक –दोनों तरह के उपाय शामिल हैं – ब्याज दर में कटौती; चलनिधि और बाजार में चलनिधि के विस्तार के निधीयन की व्यवस्था करना; आस्तियों की खरीद; ऋण को सुगम बनाना; समष्टिगत विवेकपूर्ण नीतियां; तथा स्वैप लाइन्स। उन उपायों¹ के परिणामस्वरूप, इक्विटी बाजार अपने गर्त से उभरे, ऋण विस्तार में उसके उच्च स्तर से कमी आई, निवेशकों का भरोसा बढ़ा और जोखिम लेने की चाहत भी तीव्र हुई।

III.1 मौद्रिक नीति

3.2 कोविड-19 का जैसे ही वैश्विक महामारी के रूप में विष्फोट हुआ, केंद्रीय बैंकों ने प्रथम सुरक्षा उपाय के रूप में नीतिगत ब्याज दरों को घटाया ताकि उधार लेने की लागत और वित्तीय दबाव में कमी आए। प्रणालीगत महत्वपूर्ण केंद्रीय बैंकों के मध्य, अमेरिकी फेडरल रिजर्व (यूएस फेड) ने दो सप्ताहों से

भी कम की अवधि में फेडरल निधि दर के अपने लक्ष्य में 150 आधारभूत अंकों की कटौती कर 0 से 0.25 के स्तर पर लाया। बैंक ऑफ इंग्लैंड (बीओई) ने एक सप्ताह से थोड़ी अधिक अवधि में अपनी नीतिगत दर में 65 आधारभूत अंकों की कटौती कर 0.1 प्रतिशत के स्तर पर लाया। अन्य उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय बैंकों के बास बहुत कम मोहलत उपलब्ध थी क्योंकि उनकी ब्याज दरें पहले ही शून्य के करीब थीं, या फिर वे ऋणात्मक थीं, जैसा कि यूरोपीय केंद्रीय बैंक (ईसीबी) एवं बैंक ऑफ जापान (बीओजे) के मामले में हुआ। इनमें से बाद वाले अर्थात् बैंक ऑफ जापान ने अपनी प्रतिफल वक्र नियंत्रण नीति के तहत 10-वर्षीय जेजीबी प्रतिफलों को 0 प्रतिशत के आसपास बनाए रखा।

3.3 विकासशील देशों के केंद्रीय बैंकों ने भी अपनी नीतिगत दरों में उनके स्वयं के इतिहास की तुलना में काफी कटौती किया। उभरते बाजारों वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के मध्य, बैंको सेंट्रल डो ब्राजिल ने अपनी नीतिगत दरों में 75 आधारभूत अंकों की कटौती की; दक्षिण अफ्रीकी केंद्रीय बैंक ने अपनी नीतिगत दर में 100 आधारभूत अंकों की कटौती की; तुर्की गणराज्य के केंद्रीय बैंक ने अपनी नीतिगत दर में 100 आधारभूत अंकों की कटौती की तथा बैंक इंडोनेशिया ने अपनी नीतिगत दरों में 50 आधारभूत अंकों की कमी की। केंद्रीय बैंकों ने नीतिगत दरों की भविष्य की राह के संबंध में अग्रगामी मार्गदर्शन भी किया, जिसके तहत आगे चलकर अत्यधिक समायोजनकारी नीतिगत रुझान होने का संकेत दिया गया है।

1 अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की वैश्विक अद्यतन वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, जून 2020.

III.2 निधीयन एवं बाजार में चलनिधि

3.4 वैश्विक महामारी के मद्देनजर, विकसित एवं विकासशील देशों –दोनों के केंद्रीय बैंकों ने भी चलनिधि के असाधारण अंतर्वेशन का सहारा लिया। एक दिवसीय रिपो में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2-सप्ताह की रिपो में 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने वाले यूएस फेड ने इस सुविधा का विस्तार किया और प्रतिदिन एक दिवसीय रिपो में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, एक माह के रिपो में 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 3-माह के रिपो में 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान किए। इसके अलावा, इसने सुविधाओं की एक शृंखला स्थापित किया – कुछ मामलों में पुनर्स्थापित किया – जिसका उद्देश्य वित्तीय बाजारों के सुचारु संचालन और अर्थव्यवस्था में ऋण प्रवाह को बनाए रखने के लिए निधीयन हेतु चलनिधि उपलब्ध कराना या बाजार में चलनिधि के हालात में सुधार लाना था। अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं, विकसित एवं उभरती अर्थव्यवस्थाओं –दोनों के केंद्रीय बैंकों ने भी चलनिधि उपलब्ध कराने के लिए बहुत से

उपाय किए। इनमें से बहुतों ने देश-विशेष के संदर्भ में अपनी जरूरत के अनुसार उपाय किए (सारणी 3.1)। ये मौद्रिक प्राधिकार इन सुविधाओं को उनके आकार, समायोधि एवं स्वीकार किए जाने वाले संपार्श्विकों की दृष्टि से लगातार पुनर्समायोजित कर रहे हैं। इसी प्रकार से, विकासशील देशों के केंद्रीय बैंकों ने भी चलनिधि उपलब्ध कराने और आर्थिक गतिविधियों को सहारा प्रदान करने हेतु सुविधाएं प्रदान किया है। ये सुविधाएं उनकी वित्तीय प्रणालियों के विकास की अवस्था में उपलब्ध गुंजाइश के अनुरूप हैं। उभरते बाजारों वाली अर्थव्यवस्थाओं (ईएम) में भी केंद्रीय बैंकों ने अचानक होने वाले दिवालियापन को रोकने के लिए अग्रसक्रिय होकर चलनिधि का अंतर्वेशन किया है और इस प्रकार से वित्तीय स्थिरता को सहारा प्रदान किया है। भारत में, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वित्त मंत्रालय एवं वित्तीय क्षेत्र के अन्य विनियामकों के साथ मिलकर वैश्विक महामारी के प्रभाव को समाप्त करने के लिए मजबूत कदम उठाया है, जिनका विस्तृत ब्योरा 'घरेलू गतिविधियां' के खंड के अंतर्गत बाद में दिया गया है।

सारणी 3.1 : कोविड-19 चलनिधि की सुविधाएं

केंद्रीय बैंक	नीतिगत कार्रवाई के विवरण
बैंक ऑफ इंग्लैंड	लघु एवं मध्यम आकार वाले उद्यमों (टीएफएसएमई) के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहनों के साथ नई मीयादी निधीयन योजना, जिसका वित्तीय केंद्रीय बैंक की आरक्षित निधियों के निर्गमन के माध्यम से किया गया।
	कोविड कॉर्पोरेट वित्तीय सुविधा की स्थापना, जो फर्मों द्वारा एक वर्ष तक की परिपक्वता वाले वाणिज्यिक पत्रों की खरीद के माध्यम से कारोबारियों को निधीयन उपलब्ध कराएगी जिससे यूके की अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त होगा।
	आकस्मिक मीयादी रिपो सुविधा (सीटीआरएफ) को सक्रिय करना – इसकी स्टर्लिंग चलनिधि बीमा सुविधा का अस्थायी रूप से बढ़ाया जाना।
	लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों के लिए मीयादी निधीयन योजना (टीएफएसएमई)। टीएफएसएमई के तहत पात्र बैंकों एवं बिल्डिंग सोसायटियों को बैंक दर के करीब दर पर 4-वर्षीय निधीयन प्राप्त करने की अनुमति दी जाती है।
	सरकार को अल्पावधिक चलनिधि उपलब्ध कराने के माध्यम से सरकार की लंबे समय से स्थापित अर्थोपाय अग्रिम (डब्लू एंड एम) सुविधा के उपयोग को बढ़ाया गया।
बैंक ऑफ जापान	ईटीएफ में 12 ट्रिलियन येन और जे-आरईआईटी में 180 बिलियन येन तक की खरीद करने के लिए प्रतिबद्ध।
	वाणिज्यिक पत्रों में 3.2 ट्रिलियन येन और कॉर्पोरेट बॉण्डों में 4.2 ट्रिलियन येन की खरीद करने के लिए प्रतिबद्ध।
	वाणिज्यिक पत्रों और कॉर्पोरेट बॉण्डों की अतिरिक्त खरीद की अधिकतम राशि को बढ़ाया और कुल मिलाकर लगभग 20 ट्रिलियन येन की बकाया राशि की ऊपरी सीमा के साथ खरीद किया। प्रत्येक आस्ति के लिए, वाणिज्यिक पत्रों तथा कॉर्पोरेट बॉण्डों की अतिरिक्त खरीद की अधिकतम राशि को 1 ट्रिलियन येन से बढ़ाकर 7.5 ट्रिलियन येन किया जाएगा। अतिरिक्त खरीद के अलावा, वाणिज्यिक पत्रों तथा कॉर्पोरेट बॉण्डों की वर्तमान में बकाया राशियों को क्रमशः लगभग 2 ट्रिलियन येन और लगभग 3 ट्रिलियन येन के स्तर पर कायम रखा जाएगा।
यूरोपीय केंद्रीय बैंक	कॉर्पोरेट क्षेत्र के वित्तीय से संबंधित दावों को शामिल करने के लिए संपार्श्विकों से संबंधित ढांचे के मुख्य जोखिम मानकों को समायोजित करने तथा अतिरिक्त ऋण दावों (एसीसी) के दायरे को विस्तारित करने के माध्यम से संपार्श्विकों के मानकों को सुगम बनाया।
	गैर-वित्तीय वाणिज्यिक पत्रों की तुलना में कॉर्पोरेट क्षेत्र के खरीद कार्यक्रम (सीएसपीपी) के तहत पात्र आस्तियों के दायरे को बढ़ाया गया, जिसमें पर्याप्त ऋण गुणवत्ता वाले वाणिज्यिक पत्रों को सीएसपीपी के तहत खरीद किए जाने के लिए पात्र बनाया गया; एलटीआरओ एवं टीएलटीआरओ के तहत कार्रवाई की गई।
	यूरोपीय संघ (ईयू) के सदस्य राज्यों से यथाअनुपात आधार पर मुद्रा की उगाही किए जाने के माध्यम से 25 बिलियन यूरो मूल्य की गारंटी निधि के सृजन को अनुमोदन दिया गया।
	वैश्विक महामारी आपातकाल से संबंधित दीर्घावधिक पुनर्वित्तीय परिचालनों (पीईएलटीआरओ) के तहत नई शृंखला के अंतर्गत सात परिचालन करने का निर्णय लिया गया।

सारणी 3.1 : कोविड-19 चलनिधि की सुविधाएं (जारी)

बैंको सेंट्रल डो ब्राज़िल	विशेष अस्थायी चलनिधि पथ (लिक्विडिटी लाइन) शुरू किया।
	फेडरल सरकारी प्रतिभूतियों से समर्थन प्राप्त एक वर्ष तक की अवधि के साथ खरीद (परिचालन) करना।
बैंक इंडोनेशिया	बैंकों और कॉर्पोरेट संस्थाओं को एक वर्ष तक की अवधि वाली मीयादी-रिपो व्यवस्था के साथ मौद्रिक परिचालनों का विस्तार किया।
	पर्याप्त चलनिधि होना सुनिश्चित करने के लिए 1, 3, 6 और 12-महीनों की अवधि से संबंधित एफएक्स स्वैप नीलामियों की बारंबारता को एक सप्ताह में तीन बार से बढ़ाकर दैनिक कर दिया गया।
सेंट्रल बैंक ऑफ द रिपब्लिक ऑफ टर्की	आस्तित्व-समर्थित प्रतिभूतियों और रहन-समर्थित प्रतिभूतियों को संपादकों के समूह में शामिल करने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ द रिपब्लिक ऑफ टर्की (सीबीआरटी) में होने वाले तुर्की लीरा और विदेशी मुद्रा विनमय परिचालनों को बदल दिया।
	91 दिनों तक की परिपक्वता और 150 आधार अंकों की ब्याज दर, जो एक-सप्ताह के लिए रिपो दर की अपेक्षा कम है, पर रिपो नीलामियों के माध्यम से चलनिधि उपलब्ध कराई गई।
बैंक ऑफ रसिया	प्रणालीगत दृष्टि से महत्वपूर्ण ऋण देने वाले संस्थानों के लिए अप्रतिबंधनीय ऋण पथों (इरिवोकेबल क्रेडिट लाइन्स) के तहत अधिकतम समग्र सीमा को 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 की अवधि के लिए 1.5 से बढ़ाकर 5 ट्रिलियन रूबल कर दिया गया।
	'आज' की परिपक्वता तारीख के साथ 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक अमेरिकी डॉलर उपलब्ध कराने के लिए अपने एफएक्स स्वैप परिचालनों की सीमा बढ़ाया।
पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना	मध्यावधिक ऋण प्रदान करने की सुविधा के माध्यम से 100 बिलियन आरएमबी का अंतर्वेशन किया।
साउथ अफ्रीकन रिज़र्व बैंक	स्थायी सुविधा (एसएफ) के तहत उधार लेने, वह दर जिस पर एसएआरबी चलनिधि को अवशोषित करता है, को समायोजित कर रिपो दर से 200 आधार अंक कम किया। पहले, उधार लेने की दर रिपो दर से 100 आधार अंक कम थी।
	अंतःदिवसीय एकदिवसीय पूरक खरीद परिचालनों (आईओएसआरओ) की सुविधा वाले समाशोधन बैंकों को अंतःदिवसीय चलनिधि सहारा प्रदान किया।

स्रोत : कोविड-19 फाइनेंसियल रिपोर्ट ट्रेकर, याले प्रोग्राम ऑन फाइनेंसियल स्टैबिलिटी (वाईपीएफएस)।

III.3 आस्तित्व खरीद

3.5 कई केंद्रीय बैंकों ने बड़े पैमाने पर आस्तित्व खरीद या 'मात्रात्मक सुगमता' (क्यूई) को पुनः प्रारंभ किया, जो शून्य के करीब दरों से निपटने के लिए वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) की प्रतिक्रिया में प्रयुक्त प्रमुख उपाय था। इसका प्रयोग अधिकांश उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (ईई) के केंद्रीय बैंकों ने किया है। वित्तीय बाजार के सुचारु कामकाज को सहारा प्रदान करने के लिए अमेरिकी फेड ने खजाना प्रतिभूतियों और ऐजेंसियों की रहन-समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) की धारिता क्रमशः 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने के अपने इरादों की घोषणा कर दिया है। इसके पश्चात, फेड ने बाजार के सुचारु संचालन और मौद्रिक नीति के व्यापक वित्तीय परिस्थितियों तथा अर्थव्यवस्था में प्रभावी संचरण खुली-सीमा खरीद किया और खरीद का दायरा भी बढ़ाया ताकि वाणिज्यिक रहन-समर्थित प्रतिभूतियों को इसमें शामिल किया जा सके। बाद में बाजार की गतिविधियों में सुधार हुआ, और फेड ने अप्रैल और मई के दौरान अपनी खरीद को नियंत्रित किया। हालांकि, 10 जून को फेड ने यह संकेत दिया कि वह इस नियंत्रण पर रोक लगाएगा और अगली सूचना दिए जाने तक प्रत्येक माह में खजाने में कम से कम 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर और आवासीय तथा वाणिज्यिक रहन-समर्थित

प्रतिभूतियों में 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर की खरीद करेगा। मार्च के मध्य और जून के मध्य के बीच फेड के पोर्टफोलियो में सीधे तौर पर धारित प्रतिभूतियां 3.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 6.1 ट्रिलियन हो गईं। इसी प्रकार से, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने यूके सरकार तथा स्टर्लिंग गैर-वित्तीय निवेश श्रेणी के कॉर्पोरेट बॉण्डों की धारित में 200 बिलियन पौंड की वृद्धि की। बैंक ऑफ जापान ने निर्णय लिया कि – (क) उनके निर्णम को सहारा प्रदान करने के लिए ईटीएफ एवं जापान रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (जे-आरईआईटी) की सक्रियतापूर्वक खरीद करेगा, और (ख) बॉण्ड बाजार में स्थिरता बनाए रखने तथा संपूर्ण प्रतिफल वक्र को निम्न स्तर पर बनाए रखने के लिए जेजीबी एवं टी-बिलों –दोनों की सक्रिय खरीद आगे जारी रखेगा। यूरोपीय केंद्रीय बैंक (ईसीबी) ने नए अस्थायी आस्तित्व खरीद कार्यक्रम – द पैडेमिक इमर्जेंसी पर्चेज प्रोग्राम (पीईपीपी) की शुरुआत किया, जिसका उद्देश्य 750 बिलियन तक की निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की प्रतिभूतियों की खरीद करना है। इसने वर्तमान आस्तित्व खरीद कार्यक्रम (एपीपी) के साथ ही 2020 के अंत तक 120 बिलियन यूरो की अतिरिक्त निवल आस्तित्व खरीद के रूप में अस्थायी खरीद भी करने की शुरुआत किया। विकासशील देशों के केंद्रीय बैंकों ने वित्तीय बाजारों के कामकाज को सहारा प्रदान करने के लिए व्यापक रूप से संबंधित सरकारी प्रतिभूतियों की पारंपरिक खुले बाजार परिचालनों (ओएमओ)

के माध्यम से खरीद किया, और उनमें से कुछ असाधारण परिस्थितियों की प्रतिक्रिया में चलन में रहे अपारंपरिक चलनिधि उपायों का उपयोग किया।

III.4 ऋण सुविधा

3.6 मात्रात्मक सुगमता (क्यूई) कार्यक्रम के प्रभाव के अपने चरम पर पहुंच जाने से समग्ररूप से उधार लेने की लागत कम हुई, जोखिम विमुख वित्तीय मध्यस्था और बाजारों ने ऋण जोखिम वक्र में नीचे अवस्थित संस्थानों से भेदभाव जारी रखा, किंतु केंद्रीय बैंकों ने उत्पादक क्षेत्रों में ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किया। बड़े निगमों, छोटे व्यापारों और नगरपालिकाओं को सहारा प्रदान करने के लिए अमेरिकी फेड ने नई सुविधा स्थापित किया, और अप्रत्याशित कदम उठाते हुए 2.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण के रूप में प्रदान करने का निर्णय लिया। हालांकि, विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत उपयोगिता का स्तर उनके प्रावधानों की तुलना में बहुत कम रहा है। ईसीबी ने लक्षित उधार देने के परिचालनों को पुनःसमायोजित किया है, जिसके अंतर्गत स्वीकार्य संपार्श्विकों के दायरे को बढ़ाते

हुए अपने पुनर्वित्तीयन परिचालनों के लिए हेयरकट को कम किया है, और पेंडेमिक इमर्जेसी लॉगर टर्म रिफाइनेंसिंग ऑपरेशन्स (पीईएलटीआरओ) की भी शुरुआत किया है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने बैंकों के लिए 4-वर्षीय रियायती निधीयन सुविधा प्रारंभ किया है, जिसमें छोटे और मझोले आकार वाले उद्यमों को ऋण देने के लिए अतिरिक्त निधीयन के प्रावधान किए गए हैं।

3.7 ऋण को आसान बनाने वाले इन उपायों ने हड़बड़ी में की जाने वाली बिक्री को कम करने और घोषणाओं के होने वाले प्रभावों सहित बाजार की परिस्थितियों को स्थिर बनाने में मदद किया। अमेरिका में, कॉर्पोरेट बॉण्ड मूल्यों में सभी श्रेणी के अंतर्गत तेजी रही है, जिसके कारण नए कॉर्पोरेट बॉण्डों की बिक्री में रिकॉर्ड तेजी आई, जिसे 3 जून तक कॉर्पोरेट कर्ज खरीद के लिए फेड के 750 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बजट प्रावधान में से 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की खरीद से भी मदद मिली। यह नोट करने योग्य है कि लांछन की धारणाओं के चलते बाजारों पर मजबूत निगरानी वाले क्षेत्राधिकारों और कॉर्पोरेट अभिशासन के अंतर्गत कंपनियां इन सुविधाओं का उपयोग करने के प्रति अनिच्छुक हैं (सारणी 3.2)।

सारणी 3.2 : ऋण सहायता संबंधी हस्तक्षेप

देश	कार्यक्रम का नाम	कुल निधीयन	व्याप्ति अनुपात	कार्यक्रम का विवरण
आस्ट्रेलिया	कोरोना वायरस एसएमई गारंटी स्कीम	40 बिलियन आस्ट्रेलियाई डॉलर (27.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर)	50%	गैर-जमानती ऋणों पर दी गई गारंटी को कार्यशील पूंजी के रूप में प्रयोग किया जाना 50 मिलियन आस्ट्रेलियाई डॉलर तक के राजस्व वाली एसएमई पात्र हैं। ऋण का अधिकतम कुल आकार 250,000 आस्ट्रेलियाई डॉलर है। तीन वर्ष की अवधि प्रारंभिक 6 महीनों में चुकौती से छूट। सरकार ऋणदाताओं को यह सुविधा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है कि एसएमई को आहरण की, यदि जरूरत हो तभी आहरण करें (अर्थात एसएमई को सिर्फ उस राशि पर ब्याज लगेगा, जितना उन्होंने आहरण किया होगा)। अप्रैल 2020 में प्रारंभ होता है और 30 सितंबर 2020 तक उपलब्ध है।
आस्ट्रिया	ब्रिज-फाइनेंस गारंटीज ड्यूटी द कोरोना वायरस क्राइसिस (आस्ट्रिया की विचक्रॉफ्ट सर्विस एडब्ल्यूएस द्वारा परिचालित)	9 बिलियन ईयूआर	500,000 ईयूआर तक 100%; 27.7 मिलियन ईयूआर तक 90% (पूर्व में 1.5 मिलियन ईयूआर तक 80% दिया जाता था)	ईयू द्वारा अस्थायी ढांचे में संशोधन के बाद प्रारंभिक कार्यक्रम को अद्यतन किया। 500के ईयूआर तक के ऋणों के लिए 3-माह के यूरिबोर + 75 आधार अंक ब्याज के साथ 100% गारंटी, किंतु 2 वर्ष ब्याज मुक्त होंगे। कोई गारंटी शुल्क नहीं लगेगा। 1.5 मिलियन ईयूआर तक 90% की व्याप्ति के साथ गारंटी से संयोजित किया जा सकता है। 27.7 मिलियन ईयूआर तक के ऋणों के लिए 1% ब्याज और 0.25% तथा 1% के बीच गारंटी शुल्क। ऋण की अवधि 5 वर्ष।
	एनओबीईजी	20 मिलियन ईयूआर	80%	सिर्फ आस्ट्रिया की निचले भाग में, पर्यटन और व्यापार तथा चेंबर ऑफ कॉमर्स में सदस्यता वाली एसएमई। अधिकतम 500के ईयूआर का कार्यशील पूंजी ऋण, 5 वर्ष की अवधि संसाधन शुल्क और गारंटी कमीशन सरकार अदा करती है।
ब्राजील	ऑपरेशन गारंटी फंड	15.9 बिलियन बीआरएल (3 बिलियन यूएसडी)	100%	10 जून को प्रारंभ हुआ सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (प्रोनेपी) से संबंधित राष्ट्रीय सहायता कार्यक्रम में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋण गारंटी देता है। पोर्टफोलियो के 85% तक गारंटी दी जा सकती है।

सारणी 3.2 : ऋण सहायता संबंधी हस्तक्षेप (जारी)

देश	कार्यक्रम का नाम	कुल निधीयन	व्याप्ति अनुपात	कार्यक्रम का विवरण
				2019 के सकल राजस्व के 30% की सीमा 8 महीनों की अनुग्रह अवधि के साथ 36 महीनों की अवधि अंतिम किश्त प्राप्त करने के बाद ऋण अनुबंध करने से 60 दिनों तक कर्मचारियों की संख्या बनाए रखने के लिए आवश्यक रूप से प्रतिबद्ध होना।
बुल्गारिया	प्रोग्राम फॉर लिक्विडिटी सपोर्ट थ्रु पोर्टफोलियो गारंटीज फॉर माइक्रो एंड एसएमईज सफरिंग फ्रॉम डिक्लेयर्ड इमरजेंसी एंड कोविड-19 आउटब्रेक	संभावित पोर्टफोलियो 1.6 बिलियन बीजीएन (919 मिलियन यूएसडी)	80%	300के बीजीएन का अधिकतम ऋण आकार बैंक ऋण पोर्टफोलियो का 80% तक गारंटी दे सकता है 5 वर्ष की अवधि मूलधन एवं ब्याज के लिए 36 महीनों की अनुग्रह अवधि संपार्श्विकों की आवश्यकताओं को घटाकर अधिकतम 20% तय किया
चिली	एफओजीएपीई	3 बिलियन यूएसडी (24 बिलियन यूएसडी जुटाने हेतु)	पूर्वनिर्धारित नहीं है, गारंटी के अधिकारों की नीलामी की जा सकती है	ऋण का आकार 3 महीनों की बिक्री के तुल्य है 6 महीनों की अनुग्रह अवधि के साथ 24 से 48 महीनों की अवधि बैंचमार्क से ऊपर अधिकतम 300 आधार अंकों का ब्याज बिक्री में 25,000 यूएफ में से कार्यक्रम के लिए पात्र राशि को घटाकर बैंकों को नीलामी की गारंटी, पहला प्रस्ताव मई में आया और इसका अधिकार मूल्य 30 मिलियन यूएफ या 1 बिलियन यूएसडी था
डेनमार्क	गैरान्टिओर्डिंग फॉर यूडान टिल स्मा-ऑग मेल्लेम्सटोर विक्सोम्हेडेर	1 बिलियन डीकेके (151 मिलियन यूएसडी)	70%	सिर्फ उन एसएमई के लिए जिनके राजस्व में 30% की कमी हो रही है अधिकतम 7 वर्षों की अवधि
ईयू	इन्नोवफिन एसएमई गारंटी एंड कॉस्मे लोन गारंटी फैसिलिटी	1 बिलियन ईयूआर (8 बिलियन ईयूआर जुटाने के लिए)	80% (50% से बढ़ाकर)	100,000 एसएमई के लिए विशेष गारंटी जारी करने हेतु ईआईएफ को अनुमति देते हुए ईएफएसआई बजट से ईआईएफ की गारंटी देने के लिए ईसी ने 1 बिलियन ईयूआर अनलॉक किया। रुचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से बाजार को ईआईएफ के माध्यम से गारंटी दी गई
फिनलैंड	फिन्नेर्वा स्टार्ट गारंटी	2 बिलियन ईयूआर के पैकेज का हिस्सा	80%	अधिकतम 3 वर्षों के लिए परिचालन करने वाली कंपनियों के लिए व्याप्ति अनुपात 80% तक का है गारंटी शुल्क अधिकतम 1.75% सेवा शुल्क को घटाकर 0.1% कर दिया गया ऋण का न्यूनतम आकार 10,000 इयूआर और अधिकतम 80,000 इयूआर की होगी कोई एक फर्म दूसरी गारंटी ले सकती है किंतु बीच में 2 महीनों का अंतराल होना चाहिए। प्रति फर्म कुल गारंटी 160,000 इयूआर है।
	फिन्नेर्वा एसएमई गारंटी	2 बिलियन ईयूआर के पैकेज का हिस्सा	80%	3 वर्षों से अधिक से परिचालन करने वाली कंपनियां ऋण का अधिकतम आकार 150,000 इयूआर है निवेश और कार्यशील पूंजी, किंतु वर्तमान कर्ज की चुकौती नहीं न्यूनतम 10,000 इयूआर कोई एक फर्म दूसरी गारंटी ले सकती है किंतु बीच में 2 महीनों का अंतराल होना चाहिए। प्रति फर्म कुल गारंटी 240,000 इयूआर है (गारंटी का आकार ऋण के आकार से भिन्न है)। किसी संपार्श्विक की आवश्यकता नहीं है। गारंटी शुल्क सुओमून असिंकारिस्टेटो द्वारा कंपनी को दी गई रेटिंग पर आधारित है (एएए या एए+ के लिए 0.95% और एए, एए+ , ए एवं बी के लिए 1.75%)
फ्रांस	स्टेट गारंटी लोन	300 बिलियन इयूआर	5000 से कम कर्मचारियों वाली फर्मों के संबंध में ऋण के लिए 90%; 5000 कर्मचारियों वाली फर्मों अथवा 1.5 बिलियन इयूआर के टर्नओवर वाली फर्मों के लिए 80%	16 मार्च को कोविड प्रतिक्रिया के तहत आकस्मिक सहायता

सारणी 3.2 : ऋण सहायता संबंधी हस्तक्षेप (समाप्त)

देश	कार्यक्रम का नाम	कुल निधीयन	व्याप्ति अनुपात	कार्यक्रम का विवरण
				2019 के तीन महीनों तक के टर्नओवर या जनवरी 2019 के बाद बनाई गई कंपनियों के लिए 2 वर्षों के पेरॉल के साथ सभी छोटी-बड़ी कंपनियों टियर वाली प्रणाली
जर्मनी	ईआरपी – ग्रंडरक्रेडिट-यूनिवर्सल	लागू नहीं	एसएमई के लिए 90%; बड़े उद्यमों के लिए 80%; पूर्व निर्धारित नहीं, गारंटी अधिकारों की नीलामी की जाती है	1-2.12% के बीच ब्याज उद्यम ऋण अग्रिग्रहण, परिचालन लागत, और सामानों तथा वस्तुओं के वेयरहाउस के लिए 800के ईयूआर तक के ऋणों की अवधि 10 वर्ष, 800के से अधिक के लिए 6 वर्ष है
	केएफडब्लू स्केनेलक्रेडिट (क्विक लोन 2020)	लागू नहीं	100%	100% गारंटीशुदा ऋणों से कम से शुरुआत के बाद प्रारंभ की गई नई योजना मंद रही 800,000 ईयूआर तक 3% ब्याज 10 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियां शुरुआती 2 वर्षों तक कोई चुकौती नहीं पुनर्वित्तीयन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता "सीमारहित "
	केएफडब्लू – अनटर्नहोरक्रेडिट	लागू नहीं	90%	प्रारंभ में 80% गारंटी, किंतु इसका विस्तार 90% तक किया गया 100 मिलियन ईयूआर तक और 2 वर्षों तक कोई चुकौती नहीं 1-2.12% के बीच ब्याज उद्यम ऋण
ग्रीस	कोविड-19 बिजनेस गारंटी फंड विदिन द हेल्लेनिक डेवलपमेंट बैंक	2.25 बिलियन ईयूआर	80%	नई निधि की शुरुआत 30 अप्रैल को की गई 1-5 वर्ष की अवधि सिर्फ नए ऋणों के लिए एसएमई और स्वरोजगारियों के लिए वित्तीय मध्यस्थों के कुल पोर्टफोलियो से संबंधित निधि हानि की सीमा 40% है और बड़े उद्यमों के लिए 30% है
आईलैंड	गारंटी स्कीम इन रिस्पांस टु द पैनडेमिक	50 बिलियन आईएसके (361 मिलियन यूएसडी)	70%	गारंटीशुदा ऋण का अधिकतम आकार 1.2 बिलियन क्रोना है अधिकतम अवधि 18 महीने
आयरलैंड	डीबीईआई एसएमई क्रेडिट गारंटी स्कीम	N/A	80%	ऋण गारंटी योजना देश के प्रमुख बैंकों के सहयोग से उपलब्ध है (अल्स्टर बैंक, बैंक ऑफ आयरलैंड, एवं एआईबी) 10,000 ई एवं 1 मिलियन ई के बीच बैंक ऋण दर ही ब्याज दर है। प्रारंभ में गारंटी शुल्क 0.5% तय किया गया है। पुनर्वित्तीयन को शामिल किया गया है
जापान	पार्ट ऑफ इकोनॉमिक पैकेज इन रिस्पांस टु कोरोना वायरस : "सेफ्टी नेट्स फॉर फाइनेंसिंग गारंटी"	N/A	100%	जापान फेडरेशन ऑफ क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (जेएफजी) इस तरह की एसएमई के पूरे ऋण की गारंटी सामान्य वित्तीयन गारंटी से भिन्न एक अलग ढांचे के तहत देगा। अनुमोदन के मानदंड शिथिल किए गए ताकि 1 वर्ष से कम से परिचालनरत कंपनियां भी आवेदन कर सकें।

स्रोत : याले सिस्टेमिक रिस्क ब्लॉग (15 अप्रैल 2020 को देखी गई)।

III.5 समष्टिगत विवेकसम्मत नीतियां

3.8 कोविड-19 के हानिकारक प्रभावों से निपटने और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए समष्टिगत विवेकसम्मत हस्तक्षेपों (उदा. – लेखांकन नियमों में सुधार अथवा उन्हें

अधिक लचीला बनाना; संकट से प्रभावित हुए बैंक एक्सपोजरों के वर्गीकरण और उनकी माप के लिए विवेकसम्मत मानदंड) का भी व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया है (सारणी 3.3)। जनवरी 2020² के पश्च भाग से, 56 देश 700 से अधिक समष्टिगत विवेकसम्मत नीतियों को लागू कर चुके हैं। इस तरह के कदम

2 स्रोत : याले सिस्टेमिक रिस्क ब्लॉग (15 अप्रैल 2020 को देखी गई)।

सारणी 3.3 : बैंकिंग क्षेत्र के लिए चुनिंदा विनियामकीय नीतिगत उपाय

क्षेत्राधिकार	सरकारी गारंटी	पूँजी संबंधी अपेक्षाएं	आस्ति वर्गीकरण	संभावित हानि के लिए प्रावधान	लाभांश एवं अन्य भुगतान
आस्ट्रेलिया	हां	बफर का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहन	नया मार्गदर्शन	नया मार्गदर्शन, संक्रमणकारी व्यवस्थाओं की शुरुआत	सीमाओं की छूट
कनाडा	हां	अपेक्षाकृत कम घरेलू स्थिरता बफर, बफर का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहन			रुकने वाली वृद्धियों की छूट
ईयू/एसएसएम	हां (*)	सीसीवाईबी जारी करना, बफर का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहन		नया मार्गदर्शन	रुकने की छूट
जापान	हां	बफर का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहन	विशिष्ट ऋणों का भारत जोखिम समायोजित करना	-	-
यूनाइटेड किंगडम	हां	सीसीवाईबी जारी करना, बफर का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहन	नया मार्गदर्शन	नया मार्गदर्शन	रुकने की छूट
अमेरिका	हां	बफर का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहन, पूरक लीवरेज अनुपात का समायोजन	नया मार्गदर्शन, पुनर्चित कर्ज की परिभाषा	संक्रमणकारी व्यवस्थाओं की वैकल्पिक रोक, बढ़ाया जाना	विवेकपूर्ण निर्णयों की छूट, स्वचालित पाबंदियों को सहज बनाना

(*): सदस्य देशों के बीच शर्तों में भिन्नता है।

स्रोत : बोरिओ, सी एवं फर्नांडो रेस्टॉय (2020), " रिफ्लेक्सन्स ऑन रेग्युलेटरी रिस्पॉन्सेज टु द कोविड-19 पैनेडेमिक ", फाइनेंसियल स्टेबिलिटी इंस्टीट्यूट (एफएसआई) ब्रीफ्स, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, अप्रैल। <https://www.bis.org/fsi/sibriefs1.htm>

पूँजी और अन्य विनियामकीय अपेक्षाओं और/अथवा अपेक्षाकृत कम कठोर विनियामकीय रुख को प्रभावी ढंग से हल्का बनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय मानक निर्धारकों {उदा.- बैंकिंग पर्यवेक्षण संबंधी बासेल समिति (बीसीबीएस)} ने भी नए मानक लागू किए जाने को स्थगित कर दिया है और राष्ट्रीय/बहुराष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के कदमों का सार्वजनिक रूप से समर्थन भी किया है [20 का समूह (जी20); वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी)]।

III.5.1 संकटपूर्ण आस्ति वर्गीकरण में लचीलेपन के लिए नीतियां

3.9 जिन उधार लेने वालों पर वैश्विक महामारी का विपरीत असर पड़ा है उनकी सहायता के लिए वैश्विक स्तर पर सरकारों और विनियामकों ने ऋण संशोधन/पुनर्चना लागत कम करने के लिए कदम उठाया है। इन पहलों से विद्यमान लेखांकन मानकों के तहत बढ़े हुए जोखिम के एवज में अतिरिक्त पूँजी अपेक्षा में भी कमी आई है। बीसीबीएस ने इन कार्यनीतियों का तब तक समर्थन करने की बात कही है जब तक कि पर्यवेक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि बैंक उनका विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग करेंगे और उचित ढंग से उन्हें प्रकट करेंगे, ताकि बाजार के प्रतिभागी उनके औचित्य और इस तरह की कार्रवाई के बैंकों पर पड़ने वाले असर का आकलन कर सकें।

III.5.2 आजीवन संभावित हानि के लेखांकन के प्रभाव को कम करने के लिए नीतियां

3.10 नवीनतम लेखांकन मानकों में ऋण दाताओं से यह अपेक्षित होता है कि वे प्रत्येक आस्ति के जीवन चक्र के दौरान

प्रत्याशित ऋण हानि (ईसीएल) का सकारात्मक ढंग से मूल्यांकन करें। चूंकि प्रत्याशित ऋण मॉडल बैंकों को यदाकदा होने वाली अप्रत्याशित घटनाओं (उदा.- कोविड-19) के लिए तैयार नहीं कर सकते हैं, यह मान लेना विवेकपूर्ण होगा कि बैंक पूँजी पर कोविड-19 का संभावित प्रभाव उस स्थिति की तुलना में अधिक होगा, जितना हुई-हानि मॉडल अथवा पूर्व के लेखांकन उपागमों के अनुसार हो सकते थे।

III.5.3 बीमा उद्योग को राहत

3.11 कोविड-19 का बीमा व्यापार पर तगड़ा असर हुआ है, जो बीमा दावों के तेजी से बढ़ने के लिए तैयारी कर रहा है। विस्थापन के कारण दावों की प्रस्तुति में विलंब को भांपते हुए व्यापार बाधा कवर भी इसमें शामिल है। इस संदर्भ में, बीमा प्राधिकारियों ने बीमाकर्ताओं को विलंबित करके, कम करके या फिर लाभांश वितरण को रद्द करके और हिस्सेदारी की पुनर्खरीदों और/अथवा परिवर्तनशील मेहनताना नीतियों की समीक्षा करके एवं आहरणों के विलंबन के माध्यम से पूँजी संरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया है अथवा निदेशित किया है। बीमा पर्यवेक्षकों के अंतरराष्ट्रीय संघ (आईएआईएस) ने अपने बीमा के मूल सिद्धांत (2019) के माध्यम से यह कहा है कि जोखिम-आधारित विनियामकीय पूँजीगत ढांचा तैयार करते समय बीमा पर्यवेक्षकों से अनुचक्रीय निवेश बर्ताव को ध्यान में रखें। इसके अलावा, कई बीमा

विनियामकों³ ने बीमाकर्ताओं को परिचालनगत राहत प्रदान करने के लिए कार्रवाई किया है ताकि वे संसाधनों के विपरिनियोजन, कारोबारी निरंतरता बरकरार रखने और कोविड-19 में वित्तीय एक्सपोजर संबंधी निगरानी को तेज कर सकें।

III.5.4 प्रतिभूति बाजार

3.12 अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन (आईओएससीओ) ने 29 मई 2020 को एक सार्वजनिक वक्तव्य जारी किया जिसमें प्रतिभूति निर्गमकर्ताओं के परिचालनगत कार्यनिष्पादन, वित्तीय स्थिति एवं संभावनाओं पर कोविड-19 के हुए प्रभाव के बारे में समय पर और उच्च गुणवत्ता-युक्त जानकारी के महत्व को विशिष्ट रूप से दर्शाया है। वित्तीय रिपोर्टिंग एवं लेखांकन के संबंध में वैश्विक महामारी के महत्वपूर्ण प्रभावों, निर्गमकर्ताओं के प्रकटीकरण सहित, की सूचना निवेश निर्णयों में दी जानी चाहिए। आईओएससीओ ने इन बातों को विशेषरूप से रेखांकित किया है:

- क. वित्तीय विवरणियों में स्वीकृत, मापित एवं दर्शाई गई राशि पर कोविड के प्रभाव का प्रकटीकरण।
- ख. लेखांकन संबंधी प्रमुख मुद्दों की रिपोर्टिंग और इस तरह के मामलों में लेखापरीक्षकों द्वारा अपनाए जाने वाले उपागम; तथा

- ग. समय पर समग्र वित्तीय सूचना उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी के साथ वित्तीय सूचना फाइल करने के लिए समयावधि को बढ़ाए जाने के लिए विनियामकों द्वारा दिया जाने वाला संतुलनकारी लचीलापन।

III.5.5 निकासी योजना की जरूरत

3.13 वैश्विक महामारी से उत्पन्न बड़ी चुनौतियों के कारण विनियामकों तथा नीति निर्माताओं द्वारा साहसी एवं असाधारण उपागमों, उपायों तथा तरीकों का प्रयोग अपेक्षित हो गया है। तथापि, इस तरह की विनियामकीय और पर्यवेक्षण संबंधी प्रतिक्रियाओं के कारण वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और पारदर्शिता से समझौता नहीं किया जाना चाहिए और अंतर-पीढ़ी स्थिरता को खतरे में नहीं डाला जाना चाहिए। विनियामकीय छूट की प्रतिपूर्ति ऋण-योग्यता एवं पर्यवेक्षकीय निगरानी संबंधी पर्याप्त और अपेक्षित प्रकटीकरणों के माध्यम से की जानी चाहिए। सभी हितधारकों को आश्वस्त करने के लिए छूट के दौर से निकासी की स्पष्ट रूप से घोषित योजना होने की बहुत अधिक आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, वैश्विक महामारी के तात्कालिक प्रभावों से निपटने के लिए उठाए गए बहुत से उपायों ने बैंकों की आस्तियों और देनदारियों को प्रभावित किया है, किंतु बैंकिंग के शेयरों के बारे में सभी क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत बाजारों में भिन्न-भिन्न प्रतिक्रिया देखी गई है (बॉक्स 3.1)।

बॉक्स 3.1 : कोविड-19 : प्रमुख क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत जी-एसआईबी का पुनरावलोकन

वैश्विक रूप से, बैंकों – विशेषरूप से वैश्विक प्रणालीगत दृष्टि से महत्वपूर्ण बैंक या जी-एसआईबी- से अपेक्षित है कि संभावित ऋण हानि (ईसीएल) उपागम के आधार पर हो सकने वाली हानि के लिए प्रावधान करें। हालांकि, वैश्विक महामारी से सामना होने के कारण विनियामकों ने हानि के प्रावधानों की व्याख्या में लचीलेपन, विनियामकीय पूंजी से संबंधित नए नियमों के प्रभाव को अस्थायी रूप से निष्प्रभावी बनाने और बैंकों पर नए मानक लगाए जाने को अस्थायी रूप से स्थगित करने की अनुमति प्रदान की है। ये उपाय विनियामकीय छूट की प्रकृति वाले हैं, किंतु ऋण हानि प्रावधानों तथा बैंकिंग क्षेत्र के लचीलेपन के बीच के पेचीदे संबंध को देखते हुए यह रोचक हो सकता है कि इस तरह की परिवर्तनशील नीतियों का सभी क्षेत्राधिकारों में ऋण हानि प्रावधानों पर बाजार की कैसी प्रतिक्रिया होती है। बाजार की इस तरह की प्रतिक्रियाओं को बैंकों के कर्ज मूल्यन {क्रेडिट डिफाल्ट स्वैप (सीडीएस) के माध्यम से} में घटबढ़ के साथ ही इक्विटी मूल्य की घटबढ़ से भी मापा जा सकता है।

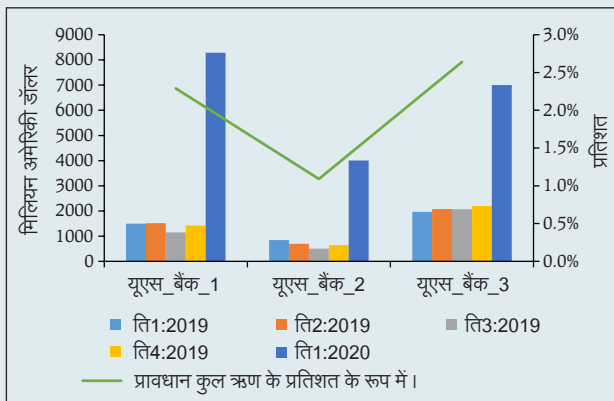
इस बात के मद्देनजर कि 2020 की प्रथम तिमाही में अमेरिका एवं यूरोप के प्रमुख वैश्विक प्रणालीगत दृष्टि से महत्वपूर्ण बैंकों (जी-एसआईबी) के ऋण हानि प्रावधान एक समान नहीं रहे हैं, ईसीएल मूल्यांकन में परिवर्तनशीलता की संभावना है, जो एकसमान आस्ति श्रेणियों के लिए गैर-महत्वपूर्ण नहीं हो सकती है। वस्तुतः, बकाया ऋण हानि प्रावधानों में एक ही क्षेत्राधिकार के अंतर्गत भी महत्वपूर्ण परिवर्तनशीलता देखी गई है (चार्ट 1 एवं 2)। इस तरह की परिवर्तनशीलता पर्यवेक्षकीय निगरानी के लिए चुनौती प्रस्तुत करती है।

अमेरिकी एवं यूरोपीय बैंकों के इक्विटी मूल्यों में वैश्विक महामारी के कारण तीव्र गिरावट हुई (चार्ट 3), जबकि अमेरिका और यूरोप –दोनों में बैंकों के सीडीएस स्प्रेड का स्तर इस वर्ष के प्रारंभ के स्तर पर स्थिर रहा (चार्ट 4 एवं 5)। इक्विटी मूल्य एवं सीडीएस स्प्रेड में वर्तमान देयताओं के संबंध में आस्ति कवर की किसी भी प्रकार की संभावित कमी की जानकारी समाहित होती है।

(जारी ...)

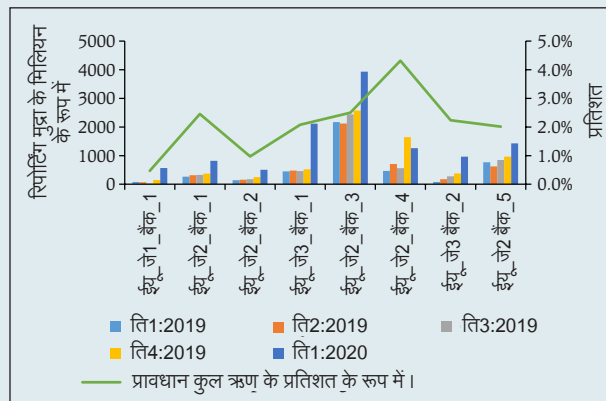
3 भारत सहित दुनिया भर के 32 बीमा विनियामकों द्वारा बीमाकर्ताओं के लिए परिचालनगत राहत से संबंधित एफएसआई द्वारा नोट की गई कार्रवाईयां।

चार्ट 1 : ऋण हानि प्रावधान – अमेरिकी बैंक



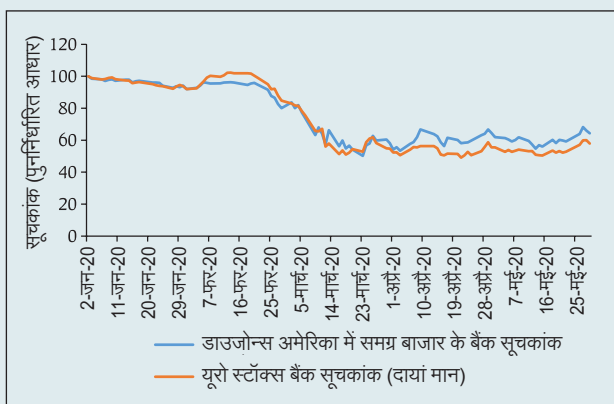
स्रोत : ब्लूमबर्ग।

चार्ट 2 : ऋण हानि प्रावधान – यूरोपीय बैंक



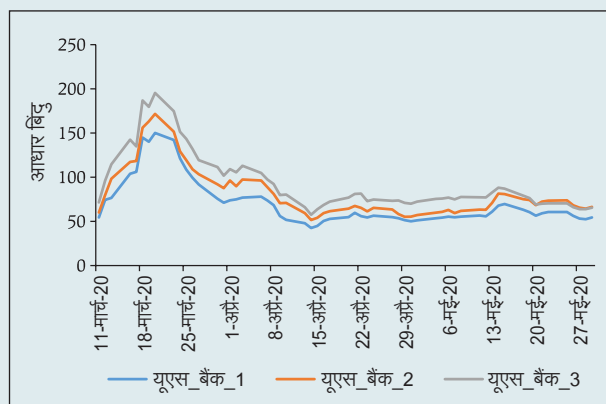
स्रोत : ब्लूमबर्ग।

चार्ट 3 : यूएस और यूरोप के बैंक की सूचियों में घटबढ़ (पुनर्निर्धारित आधार)



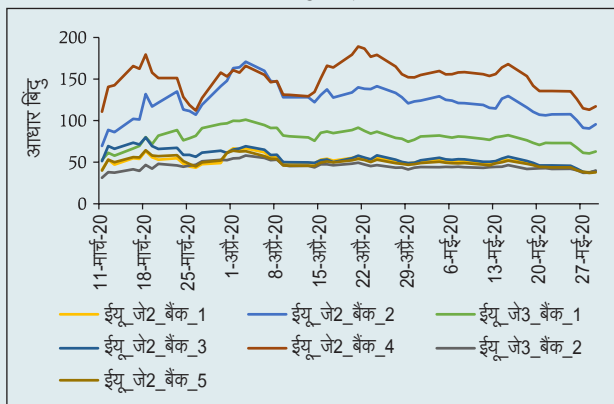
स्रोत : ब्लूमबर्ग एवं रिज़र्व बैंक स्टाफ की गणना।

चार्ट 4 : अमेरिका के जी-एसआईबी का सीडीएस स्प्रेड



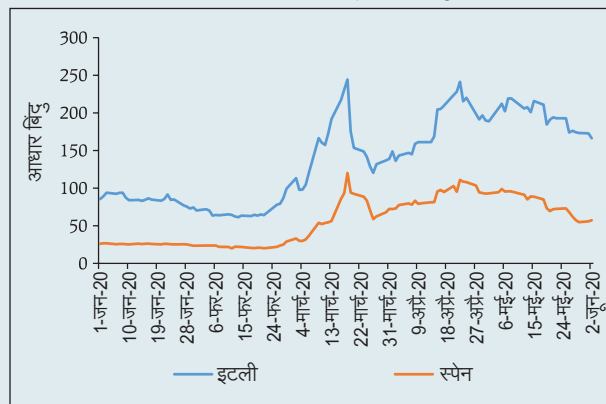
स्रोत : ब्लूमबर्ग।

चार्ट 5 : सीडीएस स्प्रेड – प्रमुख यूरोपीय बैंक जी-एसआईबी



स्रोत : ब्लूमबर्ग।

चार्ट 6 : सरकारी सीडीएस – यूरोजोन के चुनिंदा देश



स्रोत : ब्लूमबर्ग।

इसके अलावा, इक्विटी मूल्यों के भविष्य के नकदी प्रवाहों का बड़ाकृत वर्तमान मूल्य होने से उनमें अर्थव्यवस्था में संवृद्धि के प्रगतिशील अवसरों की सूचना भी समाहित होती है। इसके विपरीत बैंकों के सीडीएस मूल्यों से उनके कर्ज के बीमा किए जाने से संबंधित कीमत का पता चलता है और इसलिए इससे चूक की

संभावना, अर्थात अंतर्निहित बैंकों की ऋणशोधन क्षमता संबंधी बाजार के अनुमानों का पता चलता है।

यूरोप की दो सर्वाधिक प्रभावित अर्थव्यवस्थाएं – इटली और स्पेन में सरकारी सीडीएस बढ़ता पाया गया है, जो चूक के वर्धित जोखिम की ओर संकेत करता है (चार्ट 6)।

III.6 घरेलू गतिविधियां

3.14 दिसंबर 2019 में पिछली वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का प्रकाशन किए जाने के समय से, वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद (एफएसडीसी) तथा इसकी उप-समिति (एफएसडीसी-एससी) औपचारिक और अनौपचारिक संपर्कों के माध्यम से उभरती परिस्थितियों की निरंतर निगरानी कर रही हैं। दिनांक 28 मई 2020 को वित्त मंत्री की अध्यक्षता में हुई समिति की 22वीं बैठक में वर्तमान वैश्विक तथा घरेलू समष्टिगत आर्थिक परिस्थितियों, वित्तीय कमजोरियों, एनबीएफसी एवं क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (सीआरए) से संबंधित मुद्दों, समाधान ढांचे को मजबूत बनाने और वित्तीय क्षेत्र की साइबर सुरक्षा की समीक्षा की गई। परिषद ने यह नोट किया कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के रूप में वैश्विक वित्तीय प्रणाली की स्थिरता के लिए गंभीर चुनौती उत्पन्न हो गई है। यह भी नोट किया गया कि असंदिग्ध मौद्रिक और राजकोषीय नीतिगत कार्रवाईयों ने अल्पावधि में निवेशकों के मनोभावों को स्थिरता प्रदान किया है, किंतु इस बात की जरूरत है कि सारे प्रयास वित्तीय बाजारों से विस्थापन को टालने पर केंद्रित रखने के बावजूद सरकार और सभी विनियामक वित्तीय कमजोरियों पर निरंतर नजर बनाए रखें।

3.15 18 जून 2020 को हुई एफएसडीसी-एससी की 24वीं बैठक में वैश्विक और घरेलू अर्थव्यवस्थाओं और वित्तीय बाजारों की प्रमुख गतिविधियों की समीक्षा की गई। उप-समिति में फिनटेक से संबंधित अंतर-विनियामकीय तकनीकी समूह (आईआरटीजी-फिनटेक); संपूर्ण वित्तीय प्रणाली में साइबर सुरक्षा के महत्व; और वित्तीय शिक्षा से संबंधित राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफई) 2020-2025 के गठन किए जाने पर भी चर्चा की। समिति में दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता कोड (आईबीसी), 2016 की स्थिति एवं गतिविधियों तथा क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर भी विमर्श किया गया। समग्ररूप से, विद्यमान असाधारण परिस्थितियों के मद्देनजर उप-समिति ने सर्वसम्मति से यह संकल्प लिया कि - (क) प्रत्येक सहभागी विनियामक और मंत्रालय उभरती चुनौतियों के प्रति सतर्क रहेंगे और निगरानी करेंगे; (ख) औपचारिक और अनौपचारिक –दोनों रूप से आपसी और सामूहिक संपर्क की बारंबारता बढ़ाएंगे; तथा (ग) अर्थव्यवस्था के पुनरुज्जीवित करने और वित्तीय स्थिरता कायम रखने के लिए जो भी आवश्यक होगा वह कार्य करेंगे।

III.6.1 विनियामकों की ओर से की गई पहल

3.16 कोविड-19 के प्रभाव के कारण होने वाले विस्थापन को कम करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक, वित्तीय क्षेत्र के अन्य विनियामकों और भारत सरकार ने बहुत से कदम उठाए हैं। वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों ने कोविड-19 के प्रभाव के प्रतिसंतुलन के लिए मौद्रिक प्रोत्साहन और विनियामकीय दौरे तक की बहुत सी पहल की हैं। कोविड-19 जन्य लॉकडाउन के कारण उन्पन्न हुई परिचालनात्मक बाधाओं को सहज बनाने के अलावा बाजार की प्रतिबद्धता और बाजार के प्रतिभागियों की तीव्र जोखिम विमुखता के कारण आघात सहनीयता बरकरार रखने के लिए विनियामकों ने महत्वपूर्ण कार्रवाई की है (अनुबंध3)।

3.17 भारत सरकार ने अपनी ओर से सरकारी प्रतिभूति आधारित योजनाओं, सीधे राजकोष से होने वाले व्यय और अपेक्षाकृत दीर्घावधिक संरचनात्मक नीतिगत सुधारों के विवेकपूर्ण मिश्रण के माध्यम से सहायता पैकेज तैयार किया है। इस पैकेज में पांच चरणों वाला समग्र 'आत्म निर्भर' पैकेज समाहित है, जिसमें ग्रामीण रोजगार सृजन, आधारभूत संरचना, एमएसएमई क्षेत्र को सहायता, और समर्थनकारी कारोबारी माहौल तैयार करना शामिल हैं। अन्य उपायों के अंतर्गत, कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को यथास्थिति रखने के साथ ही साथ समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को मुफ्त (अनाजों की मुफ्त आपूर्ति) और नकदी (सीधे लाभांतरण – डीबीटी) –दोनों जैसे व्यय नियंत्रण उपाय किए गए हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि के लिए किए गए विभिन्न उपायों सहित सभी को एक साथ मिलाकर देखा जाए तो समग्र पैकेज जीडीपी के 10 प्रतिशत के तुल्य है। इसके अलावा, राज्य सरकारों की उधार लेने की सीमा को राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

3.18 भारत सरकार के नीतिगत पैकेज प्रमुख घटक हैं : (i) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) में इक्विटी डालने के लिए निधियों की निधि, मानक एमएसएमई के लिए संपार्श्विक रहित ऋण, दबावग्रस्त या एनपीए घोषित एमएसएमई के लिए अधीनस्थ कर्ज का प्रावधान; (ii) अगस्त 2020 तक नियोजित

और कर्मचारियों को ईपीएफ अंशदानों के भुगतान के माध्यम से पात्र स्थापनाओं को कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) सहायता; (iii) चलनिधि अंतर्वेशित करने के लिए एनबीएफसी/एचएफसी/एमएफआई के लिए विशेष चलनिधि योजना और एनबीएफसी/एचएफआई/एमएफआई के लिए आंशिक ऋण गारंटी योजना 2.0; (iv) 2020-21 की शेष अवधि के लिए स्रोत पर काटे गए कर (टीडीएस) एवं स्रोत पर एकत्र किए गए कर्ज (टीसीएस) में वर्तमान दरों से 25 प्रतिशत की कमी की गई; (v) ग्रामीण सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की फसल ऋण संबंधी आवश्यकताओं के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के माध्यम से पुनर्वित्तीयन की अतिरिक्त सहायता; (vi) पीएम-किसान के हितग्राहियों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के जरिए रियायती ऋण; एवं (vii) मुद्रा शिशु ऋणग्राहियों को 2 प्रतिशत की ब्याज छूट; तथा (viii) सड़कों पर ठेला लगाने वालों को अपना कारोबार पुनः प्रारंभ करने के लिए ऋण की सुलभता उपलब्ध कराने की योजना।

111.7 साइबर सुरक्षा

3.19 वर्षों के दौरान, वित्तीय क्षेत्र में साइबर जोखिम चिंता के प्रमुख क्षेत्र के रूप में उभरा है, ऐसा विशेषरूप से बैंकिंग परिचालनों के संदर्भ में हुआ है, जिनमें महत्वपूर्ण भुगतान प्रणाली की आधारभूत संरचनाएं शामिल होती हैं। साइबर जोखिम प्रबंधन और इस तरह के खतरों के प्रति आघातसहनीयता विकसित करने के क्षेत्र में बहुत से पड़ाव पार कर लिए गए हैं। साइबर सुरक्षा की तैयारी के लिए विभिन्न प्रतिभागियों के निरंतर और समकालिक प्रयासों की आवश्यकता है, जिनमें साइबर सुरक्षा की तैयारी के स्तर भिन्न-भिन्न होते हैं। हाल के कुछ उपायों में ये शामिल हैं :

(क) सभी पर्यवेक्षित संस्थाओं के लिए साइबर सुरक्षा पहलू से संबंधित विनियामकीय और पर्यवेक्षीय कार्यों का पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक के सीएसआईटीई (साइबर सुरक्षा एवं सूचना प्रौद्योगिकी जोखिम) समूह के साथ केंद्रीकरण किया जाना (यूसीबी के लिए समग्र साइबर सुरक्षा ढांचे को दिसंबर 2019 में जारी किया गया, जिसमें यूसीबी द्वारा अपनाई जाने वाली डिजिटल सघनता के आधार पर नियंत्रण अनिवार्य किए गए थे)।

(ख) बैंकिंग क्षेत्र के महत्वपूर्ण भुगतान सेवा प्रदाताओं के लिए प्रारंभ में, रिजर्व बैंक की विनियमित संस्थाओं द्वारा आधार स्तरीय अपेक्षाओं को अनिवार्य बनाने के लिए अनुदेश जारी किए गए, जिसके अंतर्गत तृतीय पक्ष के एटीएम एपलीकेशन स्विच सेवा प्रदाताओं के लिए आधार स्तरीय साइबर सुरक्षा के नियंत्रण अनिवार्य किए गए।

3.20 साइबर आक्रमण के लिए बैंकिंग उद्योग एक पसंदीदा लक्ष्य है। कोविड-19 के बाद के लॉकडाउन में साइबर खतरे की घटनाओं में वृद्धि हुई है। लॉकडाउन के कारण जरूरी हो गए गैर-पारंपरिक, दूरस्थ कार्य की परिस्थितियों तथा अन्य प्रथाओं/प्रक्रियाओं को अपनाए जाने के कारण पर्यवेक्षित संस्थाओं में वर्तमान साइबर सुरक्षा और डेटा संरक्षण के लिए किए गए नियंत्रण में छूट नहीं दी जा सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बहुत से उपाय किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कोविड-19 को 11 मार्च 2020 को वैश्विक महामारी घोषित किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने 13 मार्च 2020 को परामर्श जारी कर अपनी सभी विनियमित/पर्यवेक्षित संस्थाओं को *अन्य बातों के अलावा* यह सुनिश्चित करने को कहा कि प्रणालियों की पहुंच सुरक्षित हो तथा ग्राहकों को उपलब्ध कराई जाने वाली महत्वपूर्ण सेवाएं बाधा-रहित हों। मार्च 2020 से, भारतीय रिजर्व बैंक ने पर्यवेक्षित संस्थाओं को विभिन्न प्रकार के साइबर खतरों तथा अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में 10 से अधिक सलाह/चेतावनी जारी किया है। उनमें से कुछ भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सीईआरटी-आईएन) के साथ करीबी समन्वय के अंतर्गत जारी की गईं। पर्यवेक्षित संस्थाओं के शीर्ष प्रबंध-तंत्र को साइबर सुरक्षा की तैयारी और व्यापक साइबर/आईटी खतरों के बारे में अग्रसक्रिय रूप से जागरूक बनाने के लिए मई 2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठकों की शृंखला आयोजित की गई।

3.21 वित्तीय क्षेत्र के लिए, सीईआरटी-आईएन अग्रसक्रिय होकर नवीनतम साइबर खतरों की पहचान करता है, विविध स्रोतों से प्राप्त होने वाली खतरों की खुफिया जानकारी का विश्लेषण करता है और मुख्या सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) को सलाह एवं स्वचालित चेतावनियां जारी करता है, जिनमें संबंधित विवरण समाहित होते हैं ताकि वित्तीय संस्थाएं संबंधित साइबर आघातसहनीयता को महबूत कर सकें एवं साइबर सुरक्षा संबंधी घटनाओं से निपटने और

उनसे उबरने के लिए प्रभावी प्रथाएं विकसित कर सकें। सीईआरटी-आईएन वित्तीय क्षेत्र को कार्यशालाएं आयोजित करने के साथ ही साथ समर्पित साइबर सुरक्षा अभ्यास तथा भारतीय रिज़र्व बैंक और आईडीआरबीटी के साथ संयुक्त साइबर सुरक्षा अभ्यासों के माध्यम से साइबर आक्रमणों से निपटने के लिए समर्थ बनाता है। सीईआरटी-आईएन ने वित्तीय क्षेत्र के लिए आज तक 13 अभ्यासों का आयोजन किया है।

III.8 भुगतान एवं निपटान प्रणालियां

3.22 भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्तमान भुगतान एवं निपटान प्रणालियों में सुधार लाने तथा इस तरह की वैश्विक महामारी की परिस्थितियों के संदर्भ में विस्तारित अवधि के लिए कारोबारी निरंतरता सुनिश्चित करने के प्रयास जारी रखा है। दिसंबर 2019 से प्रारंभ करते हुए भुगतान एवं निपटान प्रणालियों से संबंधित प्रमुख गतिविधियों का ब्योरा नीचे दिया जा रहा है।

III.8.1 24x7x365 एनईएफटी की शुरुआत

3.23 रिज़र्व बैंक के भुगतान एवं निपटान प्रणालियों के विजन 2021 में दक्ष एवं बाधा रहित उपलब्धता सुनिश्चित करने की महत्वाकांक्षा व्यक्त की गई है, जो निरापद, सुरक्षित, सुलभ एवं वहनीय हों। भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिसंबर 2019 में दिन के चौबीसों घंटे निधि अंतरण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) प्रणाली उपलब्ध कराया। इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया जो दिन के चौबीसों घंटे निधि अंतरण की सुविधा प्रदान करते हैं, ऐसे अन्य देश हांगकांग, यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और चीन हैं। इसके साथ ही, आम जनता दिन/रात में किसी भी समय वर्ष के सभी दिनों में निधि अंतरण करने, वस्तुओं/सेवाओं की खरीद करने और उपयोगिता (यूटिलिटी) बिलों के भुगतान हेतु एनईएफटी प्रणाली का प्रयोग कर सकते हैं।

III.8.2 भुगतान प्रणालियों की कारोबारी निरंतरता

3.24 कोविड-19 महामारी और उसके परिणामस्वरूप होने वाले लॉकडाउन ने प्रणालगत दृष्टि से महत्वपूर्ण भुगतान

प्रणालियों के सुचारु संचालन हेतु कारोबारी निरंतरता योजनाओं की शुरुआत करना जरूरी हो गया। तत्काल सकल भुगतान (आरटीजीएस) एवं एनईएफटी प्रणालियों के रोजमर्रा के परिचालन प्राइमरी डेटा केंद्र को संरक्षित माहौल में परिचालन के लिए सौंपे गए। मुद्रा बाजार, सरकारी प्रतिभूतियों तथा विदेशी मुद्रा निपटान के क्षेत्र में कार्य करने वाले भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड ने अपने अधिकांश कर्मचारियों के लिए घर-से-कार्य करने की व्यवस्था की और प्राथमिक स्थल (प्राइमरी साइट) में गतिविधियों के बाधित होने की दशा में न्यूनतम स्टाफ के साथ कार्य-स्थल पर एवं दूरस्थ आपदा बहाली स्थलों से कार्य करने को भी तैयार रखा।

III.8.3 भुगतान संबंधी आधारभूत संरचना विकास निधि की स्थापना करना

3.25 भारतीय रिज़र्व बैंक के भुगतान प्रणाली विजन 2019-20 में बिक्री केंद्र (पीओएस) स्वीकृति संबंधी आधारभूत संरचना को छूट प्रदान करने के लिए स्वीकृति विकास निधि [अब इसे भुगतान संबंधी आधारभूत संरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) का नया नाम दिया गया है] सृजित करने की परिकल्पना की गई है। पीआईडीएफ के अंतर्गत देश भर में स्वीकृति आधारभूत संरचना (भौतिक एवं डिजिटल –दोनों मोड में) को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें टिअर III एवं IV केंद्रों एवं देश के उत्तर-पूर्वी भागों में अधिक जोर दिया गया है। पीआईडीएफ की राशि में भारतीय रिज़र्व बैंक ने ₹250 करोड़ का प्रारंभिक योगदान किया है, जो इस राशि के आधे हिस्से को कवर करता है। शेष अंशदान कार्ड जारी करने वाले बैंकों, और देश में परिचालनरत कार्ड नेटवर्कों की ओर से किया जाएगा। पीआईडीएफ का अभिशासन सलाहकार परिषद द्वारा किया जाएगा और इसका प्रबंधन तथा प्रशासन भारतीय रिज़र्व बैंक संभालेगा।

III.9 समाधान और वसूली

3.26 01 दिसंबर 2016 से कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के प्रावधान लागू किए जाने से मार्च 2020 तक

सारणी 3.4 : कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी)

(संख्या)

तिमाही	तिमाही की शुरुआत में सीआईआरपी	स्वीकृत	तक बंद किया गया				तिमाही के अंत में सीआईआरपी
			अपील/समीक्षा/निपटान किया गया	धार 12ए के तहत वापसी	समाधान योजना का अनुमोदन	परिसमापन की शुरुआत	
जन-मार्च, 2017	0	37	1	0	0	0	36
अप्रैल-जून, 2017	36	130	8	0	0	0	158
जुलाई-सितं, 2017	158	235	18	0	2	8	365
अक्तू-दिसं, 2017	365	144	40	0	7	24	438
जन-मार्च, 2018	438	196	23	0	11	59	541
अप्रैल-जून, 2018	541	249	22	1	14	51	702
जुला-सितं, 2018	702	242	33	27	29	86	769
अक्तू-दिसं, 2018	769	276	13	38	18	82	894
जन-मार्च, 2019	894	382	50	21	20	86	1,099
अप्रैल-जून, 2019	1,099	301	26	26	26	95	1,227
जुला-सितं, 2019	1,227	582	28	21	32	153	1,575
अक्तू-दिसं, 2019	1,575	613	27	11	35	149	1,966
जन-मार्च, 2020	1,966	387	23	12	27	121	2,170
कुल	NA	3,774*	312	157	221**	914	2,170

* इन सीआईआरपी का संबंध 3706 कॉर्पोरेट कर्जदारों (सीडी) से है।

** एक सीडी को छोड़कर, जो बीआईएफआर से सीधे समाधान के अंतर्गत चला गया है।

स्रोत : आंकड़ों का समेकन एनसीएलटी की वेबसाइट का प्रयोग करते हुए किया गया।

लगभग 3800 सीआईआरपी की शुरुआत की जा चुकी है (सारणी 3.4 एवं 3.5)।

सारणी 3.5 : सीआईआरपी के तहत सीडी का क्षेत्रवार वितरण

क्षेत्र	सीआईआरपी की संख्या (31 मार्च 2020)		
	बंद	चालू	कुल
विनिर्माण	676	851	1527
खाद्य, पेय पदार्थ एवं तंबाखू के उत्पाद	76	120	196
रसायन एवं रासायनिक उत्पाद	69	85	154
बिजली से चलने वाली मशीनरी एवं यंत्र	61	51	112
विनिर्मित धात्विक उत्पाद	39	46	85
मशीनरी एवं उपकरण	74	94	168
टेक्सटाइल, चमड़ा एवं पोशाक संबंधी उत्पाद	125	136	261
लकड़ी, रबड़, प्लास्टिक एवं कागजी उत्पाद	66	114	180
मूलभूत धातुएं	119	147	266
अन्य	47	58	105
स्थावर संपदा, किराये में देना एवं कारोबारी गतिविधियां	307	450	757
स्थावर संपदा की गतिविधियां	56	127	183
कंप्यूटर और संबंधित गतिविधियां	43	66	109
अनुसंधान एवं विकास	3	2	5
अन्य कारोबारी गतिविधियां	205	255	460
निर्माण	147	261	408
थोक एवं खुदरा व्यापार	168	210	378
होटल एवं रेस्त्रां	42	46	88
बिजली एवं अन्य	30	87	117
यातायात, भंडारण एवं संचार	57	55	112
अन्य	177	210	387
कुल	1,604	2,170	3,774

टिप्पणी : वितरण सीडी के सीआईएन पर आधारित है और राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनआईसी 2004) के अनुसार है।

स्रोत : भारतीय दिवाला एवं धनशोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई)।

3.27 सीआईआरपी में से 49.65 प्रतिशत की शुरुआत परिचालनगत ऋणदाताओं (ओसी) से हुई, उसके बाद 43.61 प्रतिशत के साथ वित्तीय ऋणदाताओं और शेष हिस्सा कॉर्पोरेट कर्जदारों (सीडी) के नाम रहा (सारणी 3.6)।

3.28 सीआईआरपी की स्थिति के बारे में देखा जाए तो चल रही सीआईआरपी में से 34 प्रतिशत 270 दिनों से अधिक विलंबित थीं (सारणी 3.7)।

सारणी 3.6 : कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया की शुरुआत

तिमाही	इनके द्वारा शुरु की गई सीआईआरपी			
	परिचालनगत ऋणदाता	वित्तीय ऋणदाता	कॉर्पोरेट कर्जदार	कुल
जन-मार्च, 2017	7	8	22	37
अप्रैल-जून, 2017	58	37	35	130
जुला-सितं, 2017	98	99	38	235
अक्तू-दिसं, 2017	65	65	14	144
जन-मार्च, 2018	89	85	22	196
अप्रैल-जून, 2018	129	102	18	249
जुला-सितं, 2018	126	100	16	242
अक्तू-दिसं, 2018	146	114	16	276
जन-मार्च, 2019	164	197	21	382
अप्रैल-जून, 2019	154	130	17	301
जुला-सितं, 2019	294	279	9	582
अक्तू-दिसं, 2019	329	267	17	613
जन-मार्च, 2020	215	163	9	387
कुल	1,874	1,646	254	3,774

स्रोत : आईबीबीआई।

3.29 बंद हो चुकी सीआईआरपी में से लगभग 56 प्रतिशत की समाप्ति परिसमापन के साथ हुई और 14 प्रतिशत समाधान योजना के साथ समाप्त हुई। तथापि, यह नोट किया जाना महत्वपूर्ण है कि परिसमापन के साथ समाप्त होने वाली 73 प्रतिशत सीआईआरपी (879 में से 637, जिनके आंकड़े उपलब्ध हैं) पूर्व में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्चना बोर्ड (बीआईएफआर) के पास थीं अथवा निष्क्रिय अवस्था में थीं, और उनके सीआईआरपी के तहत स्वीकृत किए जाने के पहले ही इनमें से अधिकांश कॉर्पोरेट कर्जदारों का आर्थिक मूल्य घट चुका था (सारणी 3.8)।

III.10 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

3.30 अर्थव्यवस्था में ऋण वितरण के मामले में एनबीएफसी बैंकों की पूरक होती हैं और वे अंतिम छोर में ऋण की आवश्यकताओं को पूरा करने में पहिले का महत्वपूर्ण हिस्सा (दांता) होती हैं। 30 सितंबर 2019 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकृत एनबीएफसी की संख्या 9543 थी (एचएफसी को छोड़कर), जिनमें से 82 जमा स्वीकार करने वाली⁴ (एनबीएफसी-डी) और 274 प्रणालीगत दृष्टि से महत्वपूर्ण जमा स्वीकार नहीं करने वाली (एनबीएफसी-एनडी-एसआई) थीं। दिनांक 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार, एनबीएफसी और एचएफसी की कुल आस्तियां ₹44.4 लाख करोड़ (एनबीएफसी : 70 प्रतिशत; एचएफसी : 30 प्रतिशत) थीं, जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के आस्तित्व आकार (₹166 लाख करोड़) के करीब-करीब एक चौथाई के तुल्य हैं (सारणी 3.9 एवं 3.10)।

सारणी 3.9 : एनबीएफसी के तुलन-पत्र

(राशि ₹ करोड़ में)

मदें	एनबीएफसी			एनबीएफसी-एनडी-एसआई			एनबीएफसी-डी		
	मार्च-18	मार्च-19	सितं-19	मार्च-18	मार्च-19	सितं-19	मार्च-18	मार्च-19	सितं-19
शेयर पूंजी एवं आरक्षित निधियां	6.10,383	6,95,807	7,73,163	5,56,043	6,28,603	6,99,301	54,339	67,204	73,862
जनता की जमाराशि	30,439	40,058	47,710	-	-	-	30,439	40,058	47,710
डिबेंचर	8,90,105	9,05,833	9,27,557	8,06,667	8,06,663	8,32,048	83,437	9,170	95,509
बैंक की उधारियां	4,18,902	6,07,037	6,30,786	3,47,546	5,00,803	5,13,205	71,356	1,06,235	1,17,581
वाणिज्यिक पत्र	1,47,742	1,54,469	1,23,440	1,29,569	1,36,357	1,04,477	18,173	18,112	18,964
अन्य	5,20,219	6,82,276	7,54,986	4,36,806	5,91,162	6,54,606	83,414	91,114	1,00,380
कुल देयताएं/आस्तियां	26,17,790	30,85,480	32,57,642	22,76,631	26,63,588	8,03,637	3,41,159	4,21,892	4,54,006

स्रोत : आरबीआई की पर्यवेक्षीय विवरणियां।

सारणी 3.7 : 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार सीआईआरपी की अवस्था

सीआईआरपी की अवस्था	सीआईआरपी की संख्या
स्वीकृत	3774
अपील/समीक्षा/समाधान/अन्य से समाप्त हुए	312
धारा 12ए के तहत वापसी से समाप्त हुए	157
समाधान होने से समाप्त हुए	221
परिसमापन से समाप्त हुए	914
चल रही सीआईआरपी	2170
> 270 दिन	738
> 180 दिन ≤ 270 दिन	494
> 90 दिन ≤ 180 दिन	561
≤ 90 दिन	377

टिप्पणी : 1. दिनों की संख्या स्वीकार किए जाने की तारीख से है।
2. दिनों की संख्या में ट्रिब्यूनलों द्वारा अलग रखे गए समय, यदि कोई हो, को शामिल किया गया है।

स्रोत : आईबीबीआई।

सारणी 3.8 : परिसमापन के आदेश के साथ सीआईआरपी की समाप्ति होना

सीआईआरपी की शुरुआत में सीटी की स्थिति	इनके द्वारा प्रारंभ की गई सीआईआरपी की संख्या			
	एफसी	ओसी	सीडी	कुल
या तो बीआईएफआर के अंतर्गत या फिर निष्क्रिय अथवा दोनों	251	285	101	637
समाधान का मूल्य ≤ परिसमापन का मूल्य	308	340	107	755
समाधान का मूल्य > परिसमापन का मूल्य	63	35	26	124

टिप्पणी: 1. 55 सीआईआरपी ऐसी थीं, जहां पर सीडी बीआईएफआर के अधीन थीं अथवा निष्क्रिय थीं, किंतु उनके समाधान का मूल्य परिसमापन के मूल्य से अधिक था।
2. जहां पर परिसमापन के मूल्य की गणना नहीं की गई थी, उसे '0' माना गया है।
3. 35 सीआईआरपी से आंकड़े अभी प्रतीक्षित हैं।

स्रोत : आईबीबीआई।

4 सिर्फ 22 एनबीएफसी को जमा राशियां स्वीकार करने की अनुमति दी गई, क्योंकि उन्हें निवेश श्रेणी की रेटिंग दी गई है।

सारणी 3.10 : एनबीएफसी क्षेत्र की देयता संरचना – दिसंबर 2019

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	₹ 5000 करोड़ से अधिक आस्ति आकार वाली एनबीएफसी (ए)		₹ 500 करोड़ से अधिक, किंतु ₹ 5000 करोड़ से कम आस्ति आकार वाली एनबीएफसी (बी)		₹ 500 करोड़ से कम आस्ति आकार वाली एनबीएफसी (सी)		कुल (ए+बी+सी)	
	₹ 5000 करोड़ से अधिक आस्ति आकार वाली एनबीएफसी (ए)	बाहरी देयताओं का %	₹ 500 करोड़ से अधिक, किंतु ₹ 5000 करोड़ से कम आस्ति आकार वाली एनबीएफसी (बी)	बाहरी देयताओं का %	₹ 500 करोड़ से कम आस्ति आकार वाली एनबीएफसी (सी)	बाहरी देयताओं का %	कुल (ए+बी+सी)	बाहरी देयताओं का %
एनबीएफसी की संख्या	102		220		9,289		9,611	
बाहरी देयता	23,58,207		188,941		252,794		27,99,942	
बैंक की उधारियां	578,193	24.5	64,451	34.1	103,914	41.1	746,558	26.7
डिबेंचर	872,748	37.0	34,661	18.3	56,302	22.3	963,711	34.4
अंतर कॉर्पोरेट उधारियां	91,846	3.9	12,213	6.5			104,059	3.7
सीपी	95,116	4.0	8,535	4.5	13,603	5.4	117,254	4.2
अन्य बाहरी देयताएं	720,304	30.5	69,082	36.6	78,974	31.2	868,360	31.0
कुल देयताएं	29,81,471		361,395		377,868		37,20,734	

स्रोत : आरबीआई की पर्यवेक्षीय विवरणियां।

3.31 2019 की ऋण संबंधी घटनाओं के बाद, सख्त सरकारी मानदंडों और आघातसह परिचालन व्यवहारों वाले एनबीएफसी, बाजार-पहुँच के साथ परिचालन करते रहे; तथापि छोटे एनबीएफसी और एमएफआई बाधाओं और नकदी की कमी का सामना करते रहे, जो प्रणालीगत नकदी की कमी के बजाय अंतर्निहित कमजोरियों को दर्शा रहे थे। वित्तीय बाजार सुदृढ़ एनबीएफसी और कमजोर एनबीएफसी के बीच भेदभाव करते रहे हैं। इन गतिविधियों ने बाजार अनुशासन और आस्ति-गुणवत्ता पर और अधिक फोकस बढ़ाया है।

3.32 आरबीआई ने 2020-21 से एनबीएफसी द्वारा इंड-एएस कार्यान्वयन पर विनियामक दिशानिर्देश जारी किए हैं। एनबीएफसी/एआरसी के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित उन नीतियों का अनुपालन करना बाध्यकारी है जो उनके कारोबारी मॉडलों और पोर्टफोलियो, हरेक पोर्टफोलियो को संभालने के लिए उद्देश्यों, और प्रत्याशित ऋण हानियों (ईसीएल) की गणना करने के लिए टोस पद्धतियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित और लिपिबद्ध करते हैं। बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) को उन खातों के

वर्गीकरण को अनुमोदित करना चाहिए जो 90 दिनों के बाद भी बकाया हैं लेकिन उन्हें हासित/क्षत नहीं माना गया है और ऐसा करने के औचित्य को स्पष्टतः लिपिबद्ध करना चाहिए। साथ ही, वित्तीय विवरणियों की टिप्पणियों में ऐसे खातों की संख्या और कुल बकाया राशि तथा विलंबित बकाया राशि का खुलासा करना चाहिए। एनबीएफसी/एआरसी को आय पहचान, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानिकरण (आईआरएसीपी) के मौजूदा विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार आस्ति-वर्गीकरण और प्रावधानों की गणना करने की भी आवश्यकता है।

III.11 म्यूचुअल फंड

3.33 म्यूचुअल फंड उद्योग की प्रबंधनाधीन आस्तियों (एयूएम) में सितंबर 2019 के अंत की तुलना में मार्च 2020 के अंत में 9.2 प्रतिशत की गिरावट आयी। इसमें शीर्ष-30 (टी-30) और निम्नतम-30 (बी-30) शहरों के बीच इक्विटी-उन्मुख स्कीमों की एयूएम में उनके ऋण-प्रतिरूपों के मुकाबले ज्यादा गिरावट आयी (सारणी 3.11)।

सारणी 3.11 अवधि के अंत में आस्तियाँ – बी-30 बनाम टी-30 शहर

(करोड़ रुपए)

की स्थितिनुसार	बी30 एयूएम			टी30 एयूएम			उद्योग एयूएम		
	इक्विटी	गैर-इक्विटी	कुल	इक्विटी	गैर-इक्विटी	कुल	इक्विटी	गैर-इक्विटी	कुल
31 मार्च-20	1,73,686	1,74,481	3,48,167	5,62,389	13,15,646	18,78,036	7,36,076	14,90,127	22,26,203
30 सितंबर-19	2,12,722	1,90,016	4,02,738	7,18,742	13,29,307	20,48,049	9,31,464	15,19,323	24,50,787
30 अप्रैल-20	1,99,130	1,87,259	3,86,389	6,35,609	13,71,488	20,07,097	8,34,739	15,58,746	23,93,486

स्रोत: भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी)

सारणी 3.12 2019-20 में एसआईपी (01 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020)

श्रेणी	अवधि के आरंभ में विद्यमान (एसटीपी को छोड़कर)	अवधि के दौरान पंजीकृत	अवधि के दौरान परिपक्व	अवधि के दौरान परिपक्वता-पूर्व निरस्त	अवधि के अंत में एसआईपी की अंतिम संख्या	अवधि के आरंभ में एयूएम	अवधि के अंत में एयूएम
	(लाख)				(करोड़ रुपए)		
शहर टी-30	151.48	32.75	6.07	11.66	166.49	1,98,055	1,60,618
शहर बी-30	133.48	26.61	3.31	11.04	145.74	94,265	79,098
कुल	284.96	59.36	9.38	22.70	312.23	2,92,320	2,39,716

स्रोत: सेबी

सारणी 3.13: 2019-20 में एसआईपी (अप्रैल 2020)

श्रेणी	अवधि के आरंभ में विद्यमान (एसटीपी को छोड़कर)	अवधि के दौरान पंजीकृत	अवधि के दौरान परिपक्व	अवधि के दौरान परिपक्वता-पूर्व निरस्त	अवधि के अंत में एसआईपी की अंतिम संख्या	अवधि के आरंभ में एयूएम	अवधि के अंत में एयूएम
	(लाख)				(करोड़ रुपए)		
शहर टी-30	166.19	4.12	1.23	1.93	165.22	1,60,618	1,84,286
शहर बी-30	145.68	3.38	0.68	1.57	148.76	79,098	91,552
कुल	311.87	7.50	1.91	3.50	313.98	2,39,716	2,75,838

स्रोत: सेबी

3.34 सुनियोजित निवेश योजनाओं (एसआईपी) को निवेशकों द्वारा पसंद किया गया है (सारणी 3.12)।

3.35 अप्रैल 2020 के अंत में, एसआईपी के जरिये फोलियो की संख्या मार्च 2020 के मुकाबले बढ़ गई (सारणी 3.13)।

3.36 दूसरी तरफ, 31 मार्च 2020 तक गैर-एसआईपी निवेश से 7,384 करोड़ रुपए का निवल बहिर्वाह था। अप्रैल 2020 में एसआईपी और गैर-एसआईपी दोनों निवेशों ने अंतर्वाह दर्ज किए (सारणी 3.14)।

III.11.1 निम्नवर्गीकृत कॉर्पोरेट बॉन्ड में एमएफ का जोखिम

3.37 यद्यपि कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश उच्चतर प्रतिलाभ देते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार में मौजूदा बढ़े हुए जोखिम के कारण जोखिम प्रीमियम अनुकूल नहीं हो सकते हैं। ऋण-उन्मुख म्यूचुअल फंड स्कीमों का कॉर्पोरेट बॉन्ड में जोखिम, सितंबर 2019 के अंत में रहे इन स्कीमों के कुल एयूएम के 42.9 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2020 के अंत तक 46.9 प्रतिशत हो गया। ऋण-उन्मुख म्यूचुअल फंड स्कीमों के निम्नवर्गीकृत कॉर्पोरेट बॉन्ड में जोखिमों में पिछले छह महीनों में लगातार स्थिर गिरावट देखने को मिली। यह जोखिम सितंबर 2019 के अंत में 2.37 प्रतिशत

सारणी 3.14 एसआईपी बनाम गैर-एसआईपी निवल अंतर्वाह

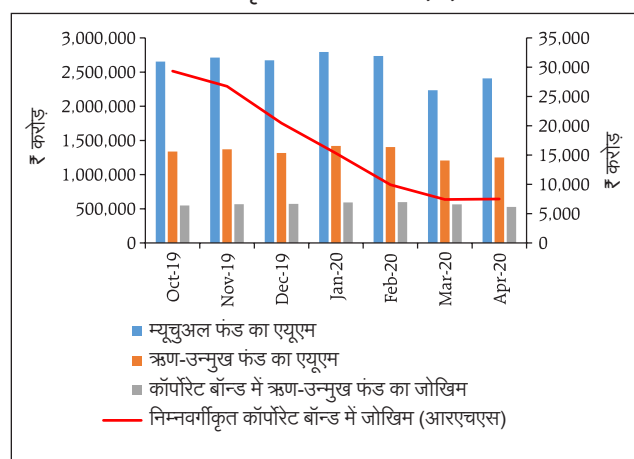
(करोड़ रुपए)

श्रेणी	... की स्थिति के अनुसार निवल अंतर्वाह		
	30 सितंबर 2019	31 मार्च 2020	30 अप्रैल 2020
एसआईपी	32,625	39,214	7,160
गैर-एसआईपी	22,846	-7,384	38,840
कुल	55,471	31,830	46,000

स्रोत: सेबी

था जो घटकर मार्च 2020 में 0.61 प्रतिशत और अप्रैल 2020 में 0.6 प्रतिशत हो गया (चार्ट 3.1)।

चार्ट 3.1 : निम्नवर्गीकृत कॉर्पोरेट बॉन्ड में एमएफ का जोखिम



स्रोत: सेबी

III.11.2 म्यूचुअल फंड द्वारा संसाधनों का अभिनियोजन

3.38 कोविड-19 से उत्पन्न चरम अनिश्चितता से इक्विटी के मूल्य में गिरावट के कारण, इक्विटी बाजार में म्यूचुअल फंड का कुल अभिनियोजन अक्टूबर 2019 (11,775,65 करोड़ रुपए) के मुकाबले मार्च 2020 (89,98,472 करोड़ रुपए) में अच्छा-खासा कम था। तथापि अप्रैल 2020 में बाजार के हालात और रुख में सुधार आया और इक्विटी बाजार के मूल्य में 10,14,909 करोड़ रुपये के कुल अभिनियोजन के साथ वृद्धि हुई। ऋण खंड में, 90-दिन और इससे कम की परिपक्वता वाले लिखतों – अधिकतर वाणिज्यिक पत्रों में एमएफ़ के निवेश में अक्टूबर 2019 से कमी आती गई और मार्च 2020 में निम्नतम स्तर को

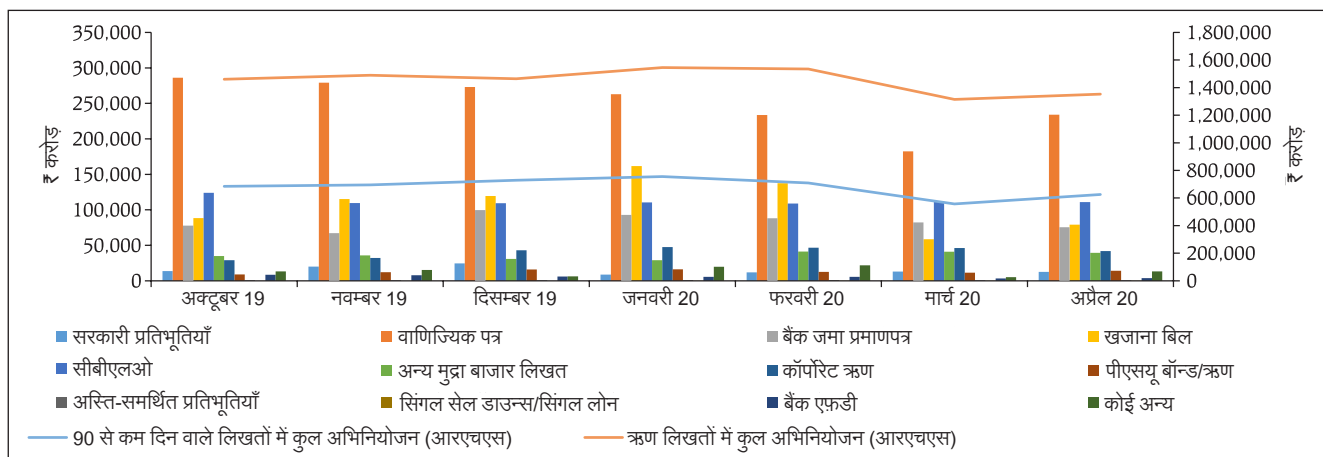
छू गई। तथापि अप्रैल 2020 में इसमें बदलाव आने लगा (चार्ट 3.2)।

3.39 मध्यम और दीर्घावधि लिखतों (90-दिन से अधिक की परिपक्वता वाले)- कॉर्पोरेट बॉन्ड सबसे पसंदीदा हैं और इसके बाद पीएसयू बॉन्ड पसंद किए जाते हैं- में निवेश कमोबेश स्थिर रहा। तथापि सरकारी प्रतिभूतियों में धीमी लेकिन निरंतर वृद्धि होती रही (चार्ट 3.3)।

III.12 पूँजी संग्रहण: इक्विटी और कॉर्पोरेट बॉन्ड

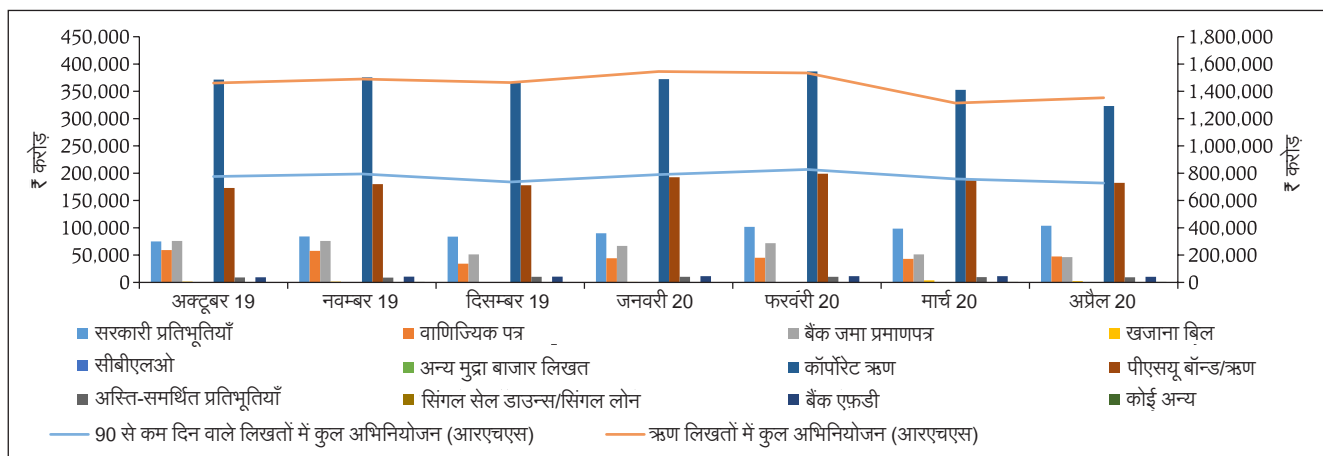
3.40 प्राथमिक बाजार में 2019-20 के दौरान कुल पूँजी संग्रहण में वर्षानुवर्ष 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई और अस्थिर बाजार परिस्थितियों के बावजूद, जनवरी-मार्च 2020 के दौरान

चार्ट 3.2 : 90 से कम दिन वाले लिखतों में निधियों का अभिनियोजन



स्रोत: सेबी

चार्ट 3.3 : 90 से अधिक दिन वाले लिखतों में निधियों का अभिनियोजन



स्रोत: सेबी

इक्विटी और ऋण निर्गमों दोनों के जरिये 3.34 लाख करोड़ रुपये की पूँजी जुटायी गयी (चार्ट 3.4)।

3.41 वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान पूँजी बाजारों में जुटाये गए कुल फंड में से, इक्विटी निर्गमों के जरिये जुटायी गयी राशि में 29.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह मुख्यतः सार्वजनिक निर्गमों, अधिकार निर्गमों और अहर्ता-प्राप्त संस्थागत स्थाननों (क्यूआईपी) से जुटायी गयी अधिक राशि के कारण हुआ। वहीं ऋण निर्गमों से जुटायी गयी पूँजी 7 प्रतिशत बढ़ी (चार्ट 3.5 ए और बी)।

3.42 तथापि अप्रैल 2020 में इक्विटी और ऋण निर्गमों, दोनों में संख्या और राशि की दृष्टि से एक वर्ष पहले के मुकाबले उल्लेखनीय गिरावट आई (सारणी 3.15)।

3.43 वर्ष के दौरान, बॉन्ड बाजार में सार्वजनिक निर्गमों के जरिये 14,984 करोड़ रुपये जुटाये गए थे। कॉर्पोरेट बॉन्ड के निजी स्थाननों के जरिये 6.75 लाख करोड़ रुपये जुटाये गए थे (चार्ट 3.5बी)। निगमित निकाय और एनबीएफ़सी प्रमुख निर्गमकर्ता थे, जिन्होंने वर्ष के दौरान कुल निर्गमों के लगभग 55 प्रतिशत हिस्से का योगदान किया था (चार्ट 3.6 ए)। बैंक और

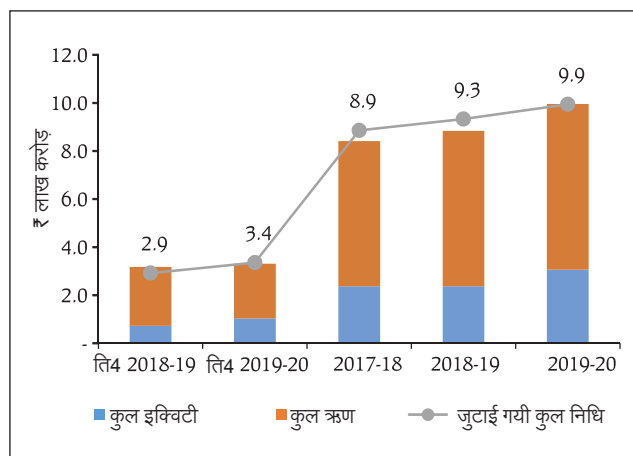
सारणी 3.15 : अप्रैल 2020 में प्राथमिक बाजार में जुटाई गयी निधि

मद	अप्रैल 2020		अप्रैल 2019	
	संख्या	राशि (करोड़ रुपए)	संख्या	राशि (करोड़ रुपए)
पब्लिक इशू (इक्विटी)	3	14	8	3,221
राइट्स इशू (इक्विटी)	0	0	2	25,012
क्यूआईपी & आईपीपी	0	0	1	3,173
प्रिफरेंशियल अलोटमेंट्स	23	1,108	23	35,828
कुल इक्विटी	26	1,122	34	67,234
पब्लिक इशू (ऋण)	0	0	5	2,191
कॉर्पोरेट बॉन्ड का निजी स्थानन	70	54,639	224	70,064
कुल ऋण	70	54,639	229	72,255
जुटाई गयी कुल निधि	96	55,761	263	1,39,489

स्रोत: सेबी

चार्ट 3.4 : पूँजी बाजारों में पूँजी उगाही

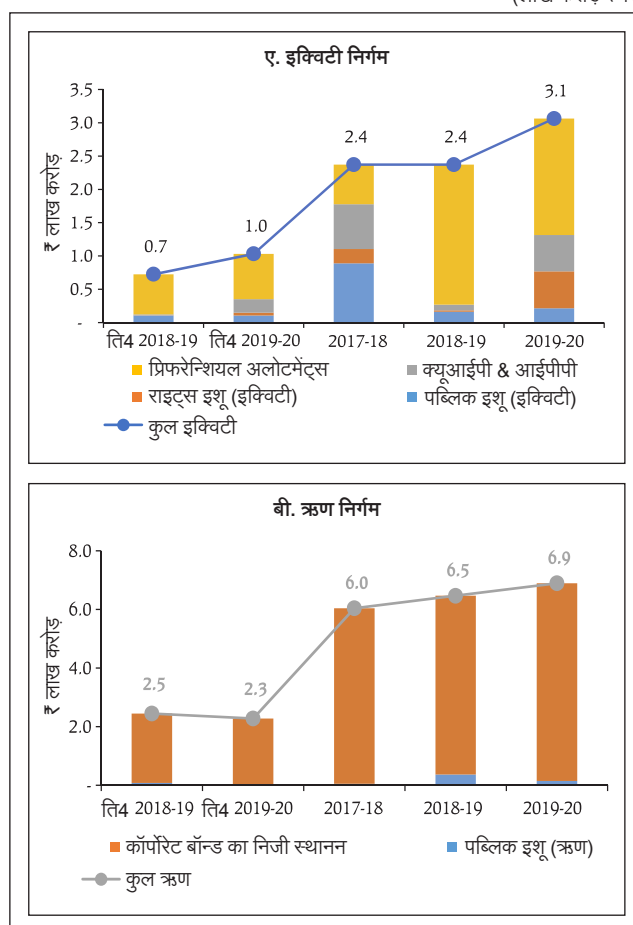
(लाख करोड़ रुपए)



स्रोत: सेबी (इशू बंद होने की तारीख के आधार पर तैयार आंकड़े)

चार्ट 3.5 : इक्विटी और ऋण निर्गमों के माध्यम से पूँजी उगाही

(लाख करोड़ रुपए)



स्रोत: सेबी (इशू बंद होने की तारीख के आधार पर तैयार आंकड़े)

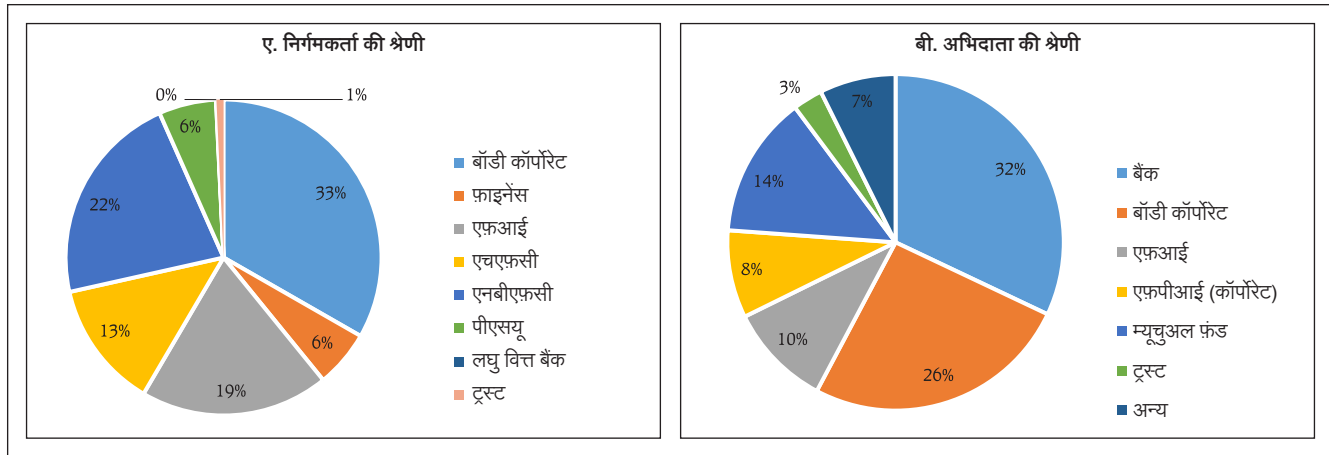
निगमित निकाय इस अवधि के दौरान प्रमुख अभिदाता थे (चार्ट 3.6बी और चार्ट 3.7)।

III.13 क्रेडिट रेटिंग (अक्तूबर 2019-मार्च 2020)

3.44 समग्र आधार पर दिसंबर, 2019 और मार्च 2020 को समाप्त तिमाहियों के दौरान निम्नवर्गीकृत/निलंबित सूचीबद्ध

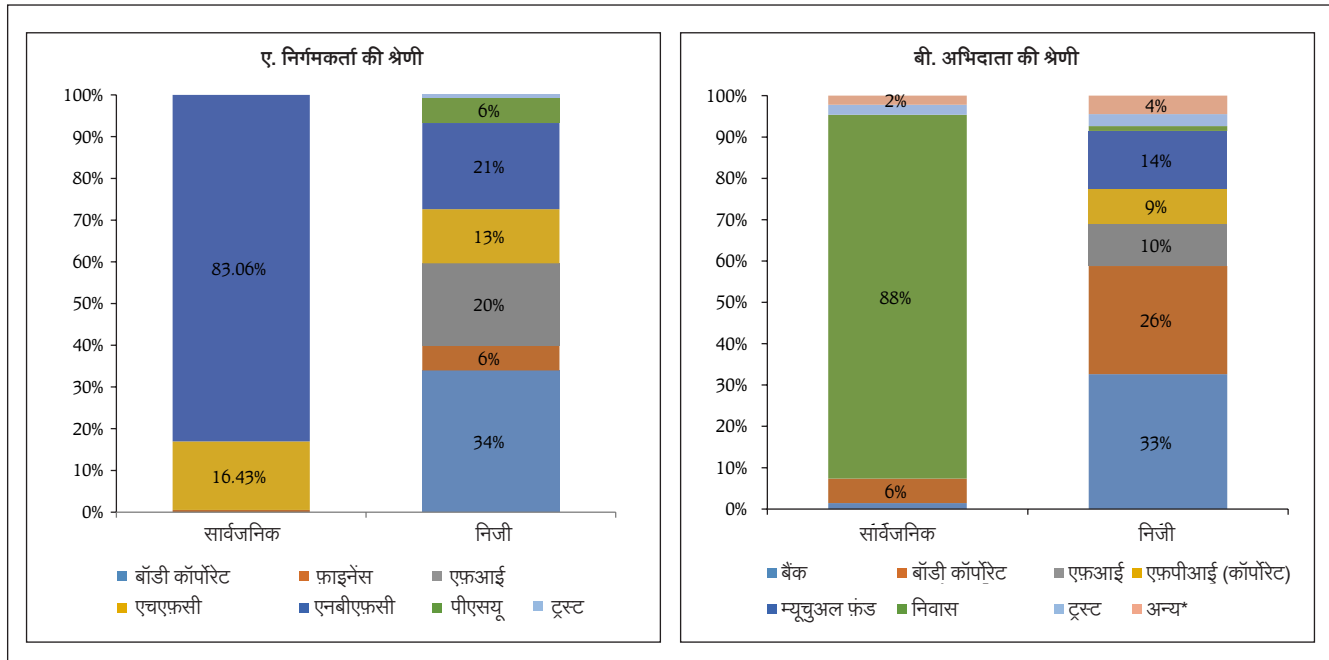
कंपनियों के शेयर में वर्षानुवर्ष वृद्धि थी। मार्च 2020 को समाप्त तिमाही के दौरान सूचीबद्ध कंपनियों के निम्नवर्गीकृत/निलंबित केयर-रेटेड ऋण निर्गमों में कुल रेटिंग एक्शन की 22 प्रतिशत वृद्धि हुई, जो पिछले तीन वर्षों में सबसे अधिक थी। क्रिसिल-रेटेड निम्नवर्गीकृत/निलंबित दिसंबर 2019 तिमाही में बढ़कर 17 प्रतिशत तक पहुँच गए। लेकिन

चार्ट 3.6 : कॉर्पोरेट बॉन्ड के श्रेणी-वार निर्गमकर्ता और अभिदाता



नोट: *अन्य में एआईएफ, सीएम, एफआईआई, एनआरआई, निवासी, एचयूएफ और क्यूआईबी शामिल हैं।
स्रोत: सेबी

चार्ट 3.7 : श्रेणी-वार निर्गमकर्ता और अभिदाता (सार्वजनिक और निजी)



नोट: *अन्य में एआईएफ, सीएम, एफआईआई, एनआरआई, निवासी, एचयूएफ और क्यूआईबी शामिल हैं।
स्रोत: सेबी

मार्च 2020 तिमाही में लुढ़ककर 9 प्रतिशत पर आ गए (चार्ट 3.8)।

III.14 पण्य डेरिवेटिव बाजार

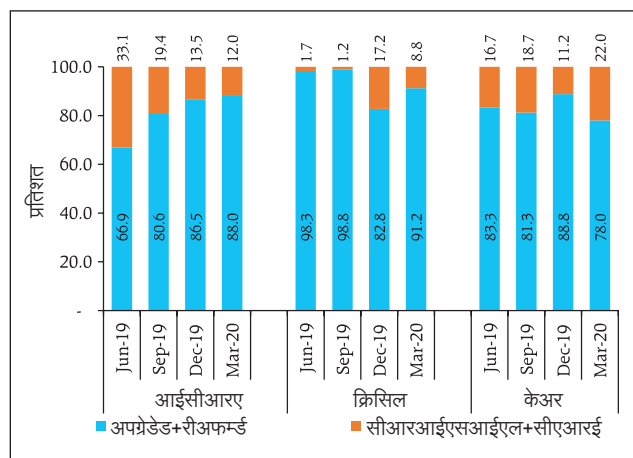
3.45 कोविड-19 से 2020 में पण्य कीमतों में गिरावट आने की संभावना है और अबतक ईंधन की कीमतें सर्वाधिक प्रभावित हुई हैं। अप्रैल 2020 में कच्चे तेल की कीमतों ने ऐतिहासिक रूप से निम्नतम स्तर को छू लिया और पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस द्वारा उत्पादन में कटौती की घोषणा के बावजूद, आपूर्ति की प्रचुरता और तेल ईटीएफ की तकनीकी पोजीशनिंग के कारण कच्चे तेल के अप्रैल वायदे अपनी समाप्ति के एक दिन पहले ही ऋणात्मक स्तर पर जा पहुंचे।

3.46 मांग में लंबे ठहराव से वैश्विक विनिर्माण नीचे धकेले जाने के कारण, वैश्विक आधारभूत धातुओं की कीमतें भी, भले अपेक्षाकृत कम पैमाने पर, गिरी हैं। आर्थिक गतिविधियों में मंदी (खासकर चीन में) और पूरे विश्व में खानों और रिफाइनरियों के बंद हो जाने से 2020 की पहली तिमाही में आपूर्ति शृंखला बाधित हो गई। वैश्विक अनिश्चितताओं और सुरक्षित-निवेश की ओर प्रवाह ने 2020 में सोने की कीमतों को चढ़ा दिया, जिसमें मार्च में कुछ नरमी आई (चार्ट 3.9)। 2019 के मुकाबले 2020 में पण्य कीमतों के नरम रहने की संभावना है। इसका परिदृश्य महामारी के प्रभावी नियंत्रण और सामाजिक दूरी संबंधी उपायों में रियायत पर निर्भर करेगा।

III.14.1 घरेलू पण्य डेरिवेटिव बाजार

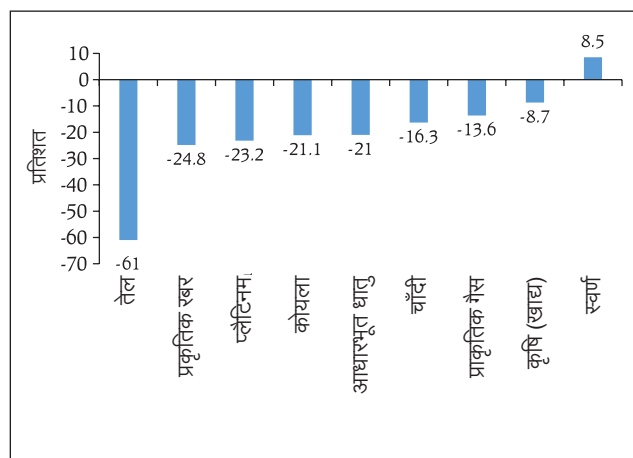
3.47 20 मार्च के बाद पूरे देश में अधिकांश भौतिक बाजार बंद कर दिये गए थे। यद्यपि अधिकांश स्थानों पर अप्रैल के अंत तक आर्थिक गतिविधियां चालू हो गयी थीं, रबी फसलों की भौतिक बाजार आपूर्ति के सर्वाधिक चरम समय (मार्च-मई) में इनकी आमद पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। गेहूं, जो रबी की सबसे बड़ी मौसमी फसल है, की मंडियों में आमद में अप्रैल 2020 के दौरान अखिल-भारतीय स्तर पर 65 प्रतिशत की वर्षानुवर्ष गिरावट देखी गई। सरसों (-68 प्रतिशत), धनिया (-75 प्रतिशत), रेड़ी (-78 प्रतिशत), चना (-82 प्रतिशत) और जीरा (-83 प्रतिशत) पर भी असर पड़ा। बाजारों की बंदी ने एक्सचेंज-कारोबार और माल-गोदामों में भंडारण जैसे अनुषंगी कार्यों को भी बुरी तरह प्रभावित किया। लॉकडाउन के बाद, सभी प्रमुख पण्यों के

चार्ट 3.8 : सूचीबद्ध कंपनियों के ऋण निर्गम-रेटिंग कार्रवाई के अनुसार-सीआरए-वार



स्रोत : विभिन्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां

चार्ट 3.9 : प्रतिशत में वैश्विक पण्य कीमतों में परिवर्तन (20 जनवरी 2020-21 अप्रैल 2020)



स्रोत : विश्व बैंक

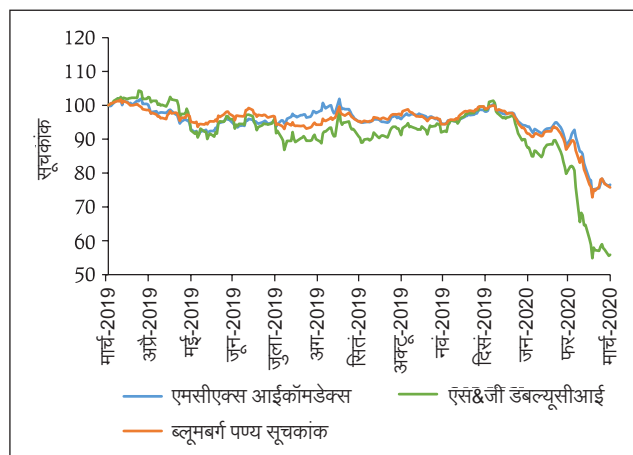
व्यपारित मूल्यों में 40-60 प्रतिशत तक की तीखी गिरावट आयी।

3.48 2019-20 में बेंचमार्क पण्य डेरिवेटिव सूचकांकों में तीखी गिरावट आयी। एमसीएक्स आईकॉमडेक्स संयुक्त सूचकांक में 22.9 प्रतिशत गिरावट आयी जबकि एन-कृषि सूचकांक में 6.9 प्रतिशत की गिरावट आयी। 2019-20 की अंतिम तिमाही में सूचकांकों में सबसे तीखी गिरावट थी। जनवरी-मार्च 2020 के दौरान आईकॉमडेक्स बुलियन सूचकांक में 2.6 प्रतिशत का मामूली सुधार हुआ, आईकॉमडेक्स कच्चा तेल सूचकांक में 63.3 प्रतिशत और आईकॉमडेक्स आधारभूत धातु सूचकांक में 16.0 प्रतिशत की गिरावट आयी। 2019-20 के दौरान घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पण्य वायदा सूचकांकों में उतार-चढ़ाव चार्ट 3.10 में दर्शाये गए हैं।

3.49 एक्सचेंजों के पण्य डेरिवेटिव खंड में ट्रेडिंग गतिविधियों ने वर्ष के दौरान व्यापारित डेरिवेटिव संविदाओं की कुल संख्या (23.3 प्रतिशत) और सभी एक्सचेंजों के कुल टर्नओवर (25.0 प्रतिशत) की दृष्टि से बढ़त दर्ज की। वायदा संविदाओं के टर्नओवर में 24.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि 'ऑप्शन ऑन फ्युचर्स' संविदाओं के टर्नओवर में 61.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ऊर्जा और बुलियन खंडों के कारण कुल टर्नओवर में मजबूती आयी थी (सारणी 3.16)।

3.50 तथापि एनसीडीईएक्स (कृषि-डेरिवेटिव का अग्रणी एक्सचेंज) में, औसत दैनिक टर्नओवर मार्च 2020 से पहले के मुकाबले 20 मार्च 2020 के बाद की अवधि में 1,488 करोड़ रुपए से गिरकर 682 करोड़ रुपए हो गया। 20 मार्च 2020 के बाद एनसीडीईएक्स प्लैटफॉर्म पर खुली संविदाएं 7.73 लाख इकाइयों से गिरकर 4.73 लाख इकाइयां (लगभग 40 प्रतिशत) हो गईं। एमसीएक्स, जो गैर-कृषि पण्य डेरिवेटिव का अग्रणी एक्सचेंज है, में भी टर्नओवर में इसी पैमाने में गिरावट (55 प्रतिशत तक) देखी गई, तथापि खुली संविदाओं में 7 प्रतिशत की गिरावट एनसीडीईएक्स की तुलना में कम थी। भारत में लॉकडाउन लागू होने के बाद से सभी खंडों के टर्नओवर में भयंकर गिरावट (माह-दर-माह) देखने को मिली है। अप्रैल 2020 में ऊर्जा खंड में अखिल-भारतीय टर्नओवर में 70 प्रतिशत और बुलियन तथा धातु खंडों में क्रमशः 63.1 प्रतिशत तथा 58.2

चार्ट 3.10 : घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पण्य वायदा सूचकांकों की गति



स्रोत : ब्लूमबर्ग

सारणी 3.16 : पण्य डेरिवेटिव में खंड-वार टर्नओवर

अवधि/टर्नओवर (बिलियन रुपये)	कृषि	धातु	बुलियन	ऊर्जा	रत्न एवं कीमती पत्थर	कुल
पहली छमाही-अप्रैल 2019 - सितंबर 2019	3,251	9,180	14,010	17,402	120	43,962
दूसरी छमाही-अक्टूबर 2019 - मार्च 2020	2,595	6,601	16,938	21,995	157	48,286
परिवर्तन (%)	-20.2	-28.1	20.9	26.4	30.5	9.8
शेयर (%) (पहली + दूसरी छमाही)	6.3	17.1	33.5	42.7	0.3	100.0

स्रोत: सेबी

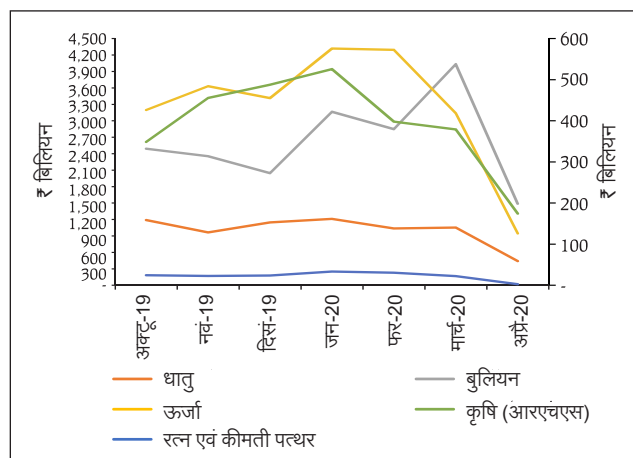
प्रतिशत और कृषि-डेरिवेटिव खंड में 54 प्रतिशत की गिरावट आयी है (चार्ट 3.11)।

III.15 बीमा

3.51 बीमा क्षेत्र पर कोविड-19 का प्रभाव जीवन और स्वास्थ्य बीमा दावों में वृद्धि, बाजार में अस्थिरता के कारण बीमाकर्ताओं की शोधन-क्षमता की चिंता, आस्ति-देयता बेमेल और धीमा प्रीमियम और राजस्व संग्रह के रूप में पड़ सकता है। भारतीय बीमा क्षेत्र में विवेकपूर्ण विनियामक फ्रेमवर्क, संतुलित निवेश नीतियों और आस्ति आकलन पद्धतियों के जरिये निवेश पर ज्यादा पर्यवेक्षी निगरानी ने इन कुछेक अधोगामी जोखिमों को सीमित किया। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) का एक आरंभिक अध्ययन दर्शाता है कि सभी बीमाकर्ता 31 मार्च 2020 तक शोधन-क्षमता मार्जिन को पूरा कर लेंगे। आईआरडीएआई ने सभी बीमाकर्ताओं को दिशानिर्देश जारी किए हैं कि कोविड-19 संबंधी घटनाओं, साथ ही कंपनियों के जोखिम और वित्त पर इसके प्रभाव पर बारीकी से निगरानी रखने और संभावित कारोबार बाधाओं का समय रहते ही आकलन करने तथा कारोबार निरंतरता प्रणालियों को सक्रिय करने के लिए प्रभावी प्रणालियाँ तैयार रखी जाएँ।

3.52 बीमाकर्ताओं को यह भी निर्देश दिया है कि वास्तविक समयाधार पर स्थिति पर निगरानी रखने और कारोबारी बाधाओं को कम से कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए कारोबार निरंतरता योजनाएँ (बीसीपी) और संकट प्रबंधन समितियाँ बनाकर तैयार रखी जाएँ। संकट प्रबंधन समितियों को

चार्ट 3.11: शेयर बाजार में पण्य डेरिवेटिव टर्नओवर की एक झलक



स्रोत: विभिन्न शेयर बाजार

बीमाकर्ताओं के जोखिम प्रबंधन समितियों को नियमित इनपुट प्रदान करनी है। ये समितियाँ रणनीतिक, परिचालनगत, चलनिधि, ऋण, प्रतिष्ठागत, बाजार और विदेशी मुद्रा जोखिमों, साथ ही, नए कारोबार, नवीनीकरण की कमी, पूंजी-हास और दावों के कारण उभरते खतरों का आकलन करेंगी और विनियामक प्राधिकरण को तत्काल सूचित करेंगी। सभी बीमाकर्ताओं को 2019-20 के लिए लाभांश भुगतान की व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है ताकि बीमाधरकों के हितों के रक्षार्थ उनके पास पर्याप्त पूंजी और संसाधन उपलब्ध हों।

3.53 कोविड-19 महामारी ने कारोबार शोधन-क्षमता पर बीमा कवर के प्रभाव पर फिर से ध्यान केन्द्रित कर दिया है (बॉक्स 3.2)।

बॉक्स 3.2 : विपत्ति जोखिम बीमा

वैश्विक कोविड-19 महामारी ने समुचित तरीके से बीमा कवर और बीमाकर्ताओं की मृत्यु, अस्पताल में भर्ती, आयोजन-निरस्तीकरण और कारोबार बाधाओं से संबन्धित संभावित दावों को संभालने की क्षमता पर दुबारा ध्यान केन्द्रित कर दिया है। विपत्तियों की लागत वैश्विक स्तर पर 1980 के दशक के यूएसडी 30 बिलियन/ प्रति वर्ष से बढ़कर 2019 में यूएसडी 232 बिलियन हो गयी है। औसतन, विपत्तियों से हानियों का लगभग 30 प्रतिशत मात्र ही बीमा से कवर किया जाता है जबकि शेष को प्रभावित व्यक्तियों,

प्रतिष्ठानों और सरकारों द्वारा वहन किया जाता है। क्या बीमा इनमें से कुछ हानियों को कम कर सकता है?

बीमा संविदाओं का कीमत-निर्धारण अपेक्षित हानि अनुमानों पर आधारित होता है; तथापि बीमा कीमत-निर्धारण के एक जटिल दृष्टिकोण में बीमाकृत के पक्ष से रणनीतिक कार्रवाइयों को भी ध्यान में रखना होता है। दो प्रकार की रणनीतिक कार्रवाइयों की पहचान की गई है- गुप्त कार्रवाई और गुप्त जानकारी। गुप्त कार्रवाई

(जारी ...)

नैतिक नुकसान की प्रकृति का प्रोत्साहन पैदा करती है- बीमा पॉलिसी के खरीददार अपेक्षित स्तर की सावधानी नहीं बरतेंगे। गुप्त जानकारी के परिणामस्वरूप प्रतिकूल चयन हो सकता है जिसमें बीमाकृत पक्ष को बीमाकर्ता की तुलना में बीमा चुकौती के बारे में ज्यादा निजी जानकारी होती है। रणनीतिक कार्रवाई के बिना भी, बीमा चुकौती को सहसंबद्ध किया जा सकता है- एक संक्रामक वैश्विक महामारी में, किसी व्यक्ति के विषाणु से संक्रमित होने की संभावना अन्य बातों के साथ-साथ उस व्यक्ति के किसी अन्य संक्रामक व्यक्ति के संपर्क में आने पर भी निर्भर करती है, अर्थात् संक्रमण की ऐसी घटनाएँ अयादृच्छक (नॉन-रैंडम) हैं। यह विपत्ति बीमा के लिए भी सही है, जहां भौगोलिक निकटता बीमा दावों को प्रेरित कर सकती है। अंत में, निवेशकों के दृष्टिकोण से, बीमा संविदाओं से लैस वित्तीय लिखतों में निवेश यह देखने की मांग करते हैं कि ऐसे प्रतिलाभ पोर्टफोलियो के समग्र प्रतिलाभ से कैसे सहसंबद्ध होते हैं।

सामान्यतः विपत्तिकारक घटनाओं के भुगतान अन्य वित्तीय आस्तियों से असंबद्ध होते हैं, जो उन्हें जोखिम को विविधिकृत करने के लिए आदर्श निवेश माध्यम बनाते हैं। तथापि, जैसा कि कोविड-19 महामारी दर्शाता है, ऐसी बीमा संविदाएं हो सकती हैं, जिनके लिए तब भुगतान किए जाने की व्यवस्था की जा सकती है, जब शेष सभी निवेशयोग्य आस्तियां पहले से ही कीमत-निर्धारण के दबाव में हों। ऐसे सहसंबंध बीमा से लैस आस्तियों को निवेशकों के लिए अनाकर्षक बना देते हैं। सरकारी हस्तक्षेप के बिना, सूचना विषमता और सहसंबद्ध भुगतान व्यापक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए बीमा के स्तर को अधिकतम से नीचे रखना सुनिश्चित करेंगे, जिसका आशय यह है कि व्यक्तियों/ कारोबारों द्वारा वहाँ लिए गए जोखिम अधिक होंगे। फलतः, उनके उपभोग प्रवाह/ परिणाम आकस्मिक एवं विषम आघातों के प्रति सुभेद्य हो जाते हैं, जिसके कल्याणकारी और वित्तीय स्थिरता संबंधी अनुवर्ती निहितार्थ हैं। इसलिए एक दक्ष बीमा बाजार उपभोग आघातों को दूर करने और सामान्य कल्याणकारी और वित्तीय स्थिरता को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

हैती और न्यूजीलैंड में 2010 में आए भूकंप इसके सबसे ज्वलंत उदाहरण हैं। दोनों देशों द्वारा झेले गए आर्थिक परिणामों में अंतर था: हैती में 2010 में ही वास्तविक वृद्धि 3.5 प्रतिशत से गिरकर (-) 5.1 प्रतिशत हो गई, निर्यात में भी गिरावट आ गई और महामारी भी फैल गई। इसके उलट, न्यूजीलैंड में क्षतिग्रस्त अवसंरचनाओं के पुनर्निर्माण से जीडीपी में 50 आधार अंकों की वृद्धि हुई। परिणामों के इस अंतर का कारण बीमा कवरेज था: न्यूजीलैंड में

81 प्रतिशत प्रत्यक्ष हानियाँ बीमाकृत थीं जबकि हैती में सिर्फ 1 प्रतिशत बीमा कवरेज था।

भारतीय परिप्रेक्ष्य

प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाओं वाले भारत के लिए, ऐसी प्रतिकूल घटनाओं के नकारात्मक वित्तीय परिणामों को कम करने के लिए बीमा कवर बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यह अब भी सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा ही संचालित है और अपेक्षाकृत कम विकसित है, जो राज्य के सीमित संसाधनों पर एक संभावित वित्तीय दबाव है। हरेक राज्य के लिए एक आपदा राहत कोष बनाया गया है जिसमें 75:25 के अनुपात में केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा अंशदान किया जाता है और यह पिछले 10 वर्षों के दौरान प्राकृतिक आपदाओं पर किए गए अधिकतम व्यय के औसत पर आधारित होता है। सरकार भी अपनी वार्षिक योजनाओं में आपदा-शमन के लिए संसाधनों के आबंटन पर बल दे रही है। सरकार की आपदा प्रबंधन नीति में सरकारी संसाधनों से बचाव, शमन, तैयारी, त्वरित कार्रवाई, पुनर्धार, पुनर्निर्माण और पुनर्वास शामिल हैं लेकिन बीमा को वित्तीय शामक के रूप में शामिल नहीं किया गया है।

भारत में क्रयशक्ति की कमी, बीमा में रुचि का अभाव और बीमा कवर की उपलब्धता के बारे में अज्ञानता को देखते हुए, जनकल्याण बीमा नीतियाँ आवश्यक हो जाती हैं। प्रभावी जोखिम स्थानांतरण समाधानों के माध्यम से सरकार पर बोझ कम करने के लिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)-फसल बीमा, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा और प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई)-जीवन बीमा जैसी पहलों को सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक सशक्तिकरण के उपायों के रूप में उपयोग किया जा रहा है। तथापि, इसके अनुभव अपेक्षित से कम ही रहे हैं। आईआरडीए विपत्ति बीमा के लिए कतिपय उत्पाद-रूपों की सिफारिश करता है जो प्रभावी हो सकते हैं, लेकिन अंतिम विश्लेषण में सरकारी वित्त-पोषण ही सर्वोत्तम समाधान प्रतीत होता है (आईआरडीए, 2019)। प्राकृतिक आपदाओं (एनएटी सीएटी) के इर्दगिर्द प्रचंड अनिश्चितताओं को देखते हुए, यह सरकार द्वारा हानियों के वित्तपोषण और इसके बदले, पुनर्बीमा समाधान खरीदने की वकालत करती है। तथापि, हाल के अनुभवों ने पुनर्बीमा समाधानों में भरोसे को कमजोर किया है। वैश्विक स्तर पर, सरकारी मदद (गवर्नमेंट बैकस्टॉप) के साथ समूहित जोखिम निधि (रिस्क पूल) 'बीमा नहीं करने लायक' महामारी सहित चरम जोखिम घटनाओं का बीमा करने के लिए पसंदीदा प्रणाली बनती जा रही है।

विभिन्न जोखिम-स्तरों वाला दृष्टिकोण (रिस्क-लेयर्ड अप्रोच), जिसमें सरकार, बैंक और बीमाकर्ता विभिन्न जोखिमों को उनके आकार और आवृत्ति के आधार पर वित्तपोषित करें, भविष्य का सर्वोत्तम मार्ग हो सकता है।

(जारी ...)

संदर्भ:

1. स्विस् रे रिपोर्ट (2018) “क्लोजिंग दी प्रोटेक्शन गैप डिजास्टर रिस्क फ़ाइनेंसिंग : स्मार्ट सोल्यूशंस फॉर दी पब्लिक सैक्टर”, स्विस् रे
2. गोएट्ज वॉन पीटर, एवं अन्य (2012), अनमिटीगेटेड डिजास्टरस? न्यू एविडेन्स ऑन दी मैक्रोइकनॉमिक कॉस्ट ऑफ नैचुरल कैटस्ट्रोफेज”, बीआईएस वर्किंग पेपर नं.394 (दिसम्बर)
3. मार्टिन मेलेक्की एंड क्लौडिओ रद्दाट्ज (2015), “फ़ाइनेंसियल डेव्लपमेंट कैन बूस्ट फिसकल रेस्पॉस आफ्टर

- डिजास्टरस : इंस्योरेंस मोर एफ़िसिएंट दैन डेट मार्केट डेव्लपमेंट”, वर्ल्ड बैंक ब्लॉग- ऑल अबाउट फ़ाइनेंस, (मई)
4. दिमिट्रिस करापीपिरिस (2017), नैचुरल कैटस्ट्रोफेज, इंस्योरेंस एंड आल्टरनेटिव रिस्क ट्रान्सफर”, सेंटर फॉर इंस्योरेंस एंड पॉलिसी रिसर्च (सीआईपीआर) न्यूजलेटर, नवम्बर
5. आईआरडीए (2019), रिपोर्ट ऑफ आईआरडीए वर्किंग ग्रुप ऑन प्रॉडक्ट स्ट्रक्चर फॉर इवेल्लिंग्स, ऑफिसेज, होटेल्स, शॉप्स ईटीसी एंड एमएसएमई फॉर कवर अगेन्स्ट फायर एंड अलाइड पेरिल्स” (पी 48-51), मई, 2019

III.16 पेंशन फ़ंड

3.54 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) एक स्वैच्छिक, परिभाषित अंशदान वाली सेवानिवृत्ति बचत योजना है, जो अभिदाताओं को उनके कार्यशील जीवन के दौरान सुनियोजित बचत के जरिये अपने भविष्य के बारे में इष्टतम निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। कार्यशील जीवन के दौरान संचित निधि एनपीएस अभिदाताओं के वृद्धावस्था आय के रूप में इस्तेमाल की जाती है। कोविड-19 की प्रतिक्रियास्वरूप, पीएफ़आरडीए ने अभिदाताओं और मध्यस्थों की मदद के लिए कई उपाय किए हैं।

3.55 प्राधिकरण ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से आंशिक निकासी के लिए गंभीर बीमारियों में कोविड-19 को भी मान्य बीमारी के रूप में शामिल कर लिया है। स्वयं/अभिदाता, उसकी विधिवत विवाहित पत्नी/पति, संतान (विधिवत गोद लिए गए बच्चे सहित) या यथानियमानुसार आश्रित माता-पिता के इलाज के लिए आंशिक निकासी हेतु अभिदाता द्वारा दिये गए आवेदन पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

3.56 अटल पेंशन योजना (एपीवाई) एक परिभाषित लाभ स्वैच्छिक पेंशन योजना है, जिसके अभिदाता मुख्यतः समाज के असंगठित क्षेत्रों से आते हैं और जो लॉकडाउन के दौरान और लॉकडाउन के बाद सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। एपीवाई योजना के अंतर्गत अभिदाता के बचत बैंक खाते से मासिक/तिमाही/छमाही आधार पर अंशदान स्वतः डेबिट होकर अभिदाता के पेंशन खाते में चला जाता है। कोविड-19 के दौरान इस योजना में नियमित अंशदान करने में अभिदाताओं को हो रही कठिनाइयों

का प्राधिकरण ने संज्ञान लिया। इसलिए बचत खाते से ऑटो-डेबिट को जून, 2020 तक स्थगित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही, यदि अभिदाता 1 जुलाई, 2020 से 30 सितंबर, 2020 के बीच डेबिट नहीं किए गए एपीवाई अंशदान के साथ नियमित एपीवाई अंशदान जमा कर अपने एपीवाई खाते को नियमित कराते हैं तो उनपर कोई दंडात्मक ब्याज नहीं लगाया जाएगा।

3.57 इसके अलावा, प्राधिकरण ने लॉकडाउन द्वारा पैदा हुई परिचालनगत बाधाओं को दूर करने के लिए परिचालनगत रियायतें भी दी हैं, जो निम्नानुसार हैं:

- i) पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) को अनुपालन रिपोर्ट (1 मार्च 2020 से 30 जून 2020 के बीच बकाया) सामान्य नियत तारीख से 30 दिन के अंदर ईमेल से प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई थी;
- ii) 1 मार्च 2020 से 30 अप्रैल 2020 तक की अवधि के लिए दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित टीएटी में विलंब के कारण अभिदाताओं को दिये जाने वाले हर्जाने की माफी;
- iii) यह निर्णय लिया गया कि भौतिक सत्यापन के बजाय, नियोक्ताओं/कॉर्पोरेटों को उनके कर्मचारियों द्वारा ईमेल से प्रस्तुत किए गए एनपीएस अभिदाता पंजीकरण फॉर्मों को प्राधिकृत करने की अनुमति दी जाए; और
- iv) इ-एनपीएस के माध्यम से खोले गए खातों को छोड़कर, जून तिमाही में खोले गए सभी पीआरएएन को सीआरए में दस्तावेज़ पूरा करने के लिए 30 जुलाई 2020 तक की समयसीमा दे दी गई है।

3.58 राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) ने अभिदाताओं की कुल संख्या और प्रबंधनाधीन आस्तियों (एयूएम) के मामले में वृद्धि दर्शाई है। एनपीएस और एपीवाई के अभिदाताओं की संख्या क्रमशः 1.34 करोड़ और 2.11 करोड़ पहुँच गई है। एनपीएस और एपीवाई के अंतर्गत प्रबंधनाधीन आस्तियां भी क्रमशः 4,06,953 करोड़ रुपये और 10,526 करोड़ रुपए तक पहुँच गई हैं (सारणी 3.17)।

3.59 पीएफ़आरडीए ने एपीवाई के अंतर्गत कवरेज को विस्तार देते हुए असंगठित क्षेत्र और निम्न-आय समूहों के वित्तीय समावेशन की दिशा में कार्य करना जारी रखा। 31 मार्च 2020 तक एपीवाई के अंतर्गत 403 बैंक पंजीकृत किए गए थे और अधिक से अधिक नागरिकों को पेंशन के दायरे में लाने का लक्ष्य रखा गया था।

3.60 समग्रतः, नीति प्राधिकरणों ने कोविड-19 महामारी के समय, जहां एक तरफ वित्तीय प्रणाली को कार्यरत और सुचारु रखने के लिए और वहीं दूसरी तरफ कारोबारों और परिवारों को अर्थक्षम और शोधक्षम बनाए रखने के लिए सभी मौद्रिक,

सारणी 3.17: अभिदाता और एयूएम : एनपीएस और एपीवाई

क्षेत्र	एयूएम		अभिदाता	
	मार्च 2019 (करोड़ रु.)	मार्च 2020 (करोड़ रु.)	मार्च 2019 (लाख में सं.)	मार्च 2020 (लाख में सं.)
केंद्रीय सरकार	1,09,010	1,38,046	19.85	21.02
राज्य सरकार	1,58,492	2,11,023	43.21	47.54
कॉर्पोरेट	30,875	41,243	8.03	9.74
ऑल सिटिजन मॉडल	9,569	12,913	9.30	12.52
एनपीएस लाइट	3,409	3,728	43.63	43.32
एपीवाई	6,860	10,526	149.53	211.42
कुल	3,18,214	4,17,479	273.55	345.55

स्रोत: पीएफ़आरडीए

चलनिधि, राजकोषीय और वित्तीय क्षेत्रों में तत्परता से कार्य किया। तथापि, समाज के बड़े तबके, खासकर उन लोगों को जो औपचारिक वित्तीय मध्यस्थता में बाहर ही छूट जाते हैं, को इस महामारी से अप्रभावित रखने, बाजार को अस्थिर किए बिना, सुविचारित तरीके से स्टिमुलस और सहायता पैकेज देने और विवेकपूर्ण मानदंडों को महामारी-पूर्व स्थिति में पुनर्स्थापित करने की चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

अनुलग्नक 1

प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण

वित्तीय प्रणाली के समक्ष प्रमुख जोखिमों के संबंध में बाजार के प्रतिभागियों सहित विशेषज्ञों की राय जानने के लिए अप्रैल-मई 2020 में प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण (एसआरएस) किया गया, जो इस श्रृंखला का अठारहवां सर्वेक्षण है। सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार सभी प्रमुख जोखिम समूह अर्थात वैश्विक जोखिम, व्यापक आर्थिक स्थितियों पर जोखिम धारणा, वित्तीय बाजार जोखिम और संस्थागत स्थितियों को वित्तीय प्रणाली को प्रभावित करने वाले 'उच्च' जोखिम के रूप में माना जाता था (चित्र 1)।

वैश्विक जोखिम के अंतर्गत वैश्विक वृद्धि, 'अत्यधिक उच्च' जोखिम के रूप में बनी रही। समष्टि-आर्थिक जोखिम समूह के अंतर्गत घरेलू वृद्धि और राजकोषीय घाटा 'अत्यधिक उच्च' जोखिम की श्रेणी में मानी गयी है, जबकि एफआईआई का रिवर्सल/ एफडीआई में गिरावट, कॉर्पोरेट क्षेत्र की कमजोरियों, स्थावर संपदा की कीमतों का टूटना एवं पारिवारिक बचत से संबंधित जोखिम को वर्तमान सर्वेक्षण में 'उच्च जोखिम' की श्रेणी में रखा गया है। संस्थागत जोखिम में, बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में कमजोरी एवं ऋण में वृद्धि एवं साइबर जोखिम को 'उच्च जोखिम' कारकों के रूप में देखा गया। सर्वेक्षण के प्रारंभ से साइबर जोखिम पहली बार 'उच्च जोखिम' श्रेणी में देखा गया है (चित्र 2)।

सहभागियों का मत है कि कोविड-19 का प्रभाव 3-5 वर्षों तक मौजूद रहेगा और बैंक बुक क्रेडिट की गुणवत्ता, उद्यमियों की सामान्य रूप से जोखिम उठाने की क्षमता, पूंजीबाजार और स्थावर संपदा में निवेश तथा घरेलू बचत के स्वरूप को प्रभावित करेगा। इन सभी का प्रभाव घरेलू वित्तीय स्थिरता पर होगा।

चित्र 1: प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण में चिह्नित किए गए प्रमुख जोखिम समूह (अप्रैल 2020)*

प्रमुख जोखिम समूह	अक्टूबर -19	परिवर्तन	अप्रैल-20
ए. वैश्विक जोखिम		↑	
बी. समष्टि-आर्थिक जोखिम		↑	
सी. वित्तीय बाजार जोखिम		↑	
डी. संस्थागत जोखिम		↑	
ई. सामान्य जोखिम		↑	

स्रोत : भा.रि.बैं., प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण (अक्टूबर 2019 और अप्रैल 2020)

टिप्पणी :
जोखिम श्रेणी

बहुत अधिक	अधिक	मध्यम	कम	बहुत कम
-----------	------	-------	----	---------

पिछले सर्वेक्षण के बाद से जोखिम में परिवर्तन		
↑	↔	↓
बढ़ा	अपरिवर्तित रहा	घटा

*समय-समय पर किए गए (अप्रैल और अक्टूबर अर्ध वार्षिक आधार पर) प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण से यह ज्ञात होता है कि जोखिम संभावनाएं एक जोखिम श्रेणी से दूसरी श्रेणी में अंतरित (कमी/वृद्धि) हो सकती हैं जिसे रंग में परिवर्तन द्वारा दर्शाया गया है। किंतु समान जोखिम श्रेणी (अर्थात, समान रंग में दर्शाए गए बॉक्स) में भी जोखिम संभावना बढ़/घट सकती है या अपरिवर्तित रह सकती है, परिवर्तन तीर के निशान के माध्यम से दर्शाया गया है। जोखिम संभावनाओं में दर्शाया गया परिवर्तन लगातार दो सर्वेक्षणों के बीच तुलनात्मक विश्लेषण से संबंधित है।

चित्र 2. : प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण में चिह्नित किए गए विभिन्न जोखिम (अप्रैल 2020)*					
जोखिम समूह	जोखिम की मद	Oct-19	Changes	Apr-20	
अ. वैश्विक जोखिम	वैश्विक वृद्धि		↑		
	राष्ट्रिक जोखिम/संक्रमण		↑		
	फंडिंग जोखिम (बाह्य उधार)		↑		
	पण्य मूल्य जोखिम (कच्चे तेल की कीमतों सहित)		↑		
	अन्य वैश्विक जोखिम		↑		
आ. समष्टि-आर्थिक जोखिम	घरेलू वृद्धि		↑		
	घरेलू मुद्रास्फीति		↑		
	चालू खाता घाटा		↓		
	पूंजीगत अंतर्वाह/बहिर्वाह (एफआईआई का लौटना, एफडीआई में कमी)		↑		
	राष्ट्रिक रेटिंग में कमी		↑		
	राजकोषीय घाटा		↑		
	कॉर्पोरेट क्षेत्र का जोखिम		↑		
	आधारभूत संरचना के विकास की गति		↑		
	रियल एस्टेट कीमतें		↑		
	पारिवारिक इकाइयों की बचत		↑		
	राजनैतिक अनिश्चितता/शासन/नीति का कार्यान्वयन		↑		
	अन्य समष्टि-आर्थिक जोखिम		↓		
	इ. वित्तीय बाजार संबंधी जोखिम	विदेशी मुद्रा दर का जोखिम		↑	
		इक्विटी मूल्य में उतार-चढ़ाव		↑	
ब्याज दर जोखिम			↑		
चलनिधि जोखिम			↑		
बाजार संबंधी अन्य जोखिम			↑		
ई. संस्थागत जोखिम	विनियामक जोखिम		↑		
	आस्ति गुणवत्ता में कमी		↑		
	बैंकों की अतिरिक्त पूंजी संबंधी आवश्यकता		↑		
	बैंकों द्वारा फंडिंग तक पहुंच		↑		
	क्रेडिट वृद्धि का स्तर		↑		
	साइबर जोखिम		↑		
	परिचालन जोखिम		↑		
	संस्थागत अन्य जोखिम		↓		
घ. सामान्य जोखिम	आतंकवाद		↔		
	प्रकृति से संबंधित जोखिम		↓		
	सामाजिक अशांति (बढ़ती असमानता)		↑		
	अन्य सामान्य जोखिम		↓		

स्रोत : भा.रि.बैं., प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण - (अक्तूबर 2019 और अप्रैल 2020)

टिप्पणी :
जोखिम श्रेणी

बहुत अधिक	अधिक	मध्यम	कम	बहुत कम
-----------	------	-------	----	---------

पिछले सर्वेक्षण के बाद से जोखिम में परिवर्तन		
↑	↔	↓
बढ़ा	अपरिवर्तित रहा	घटा

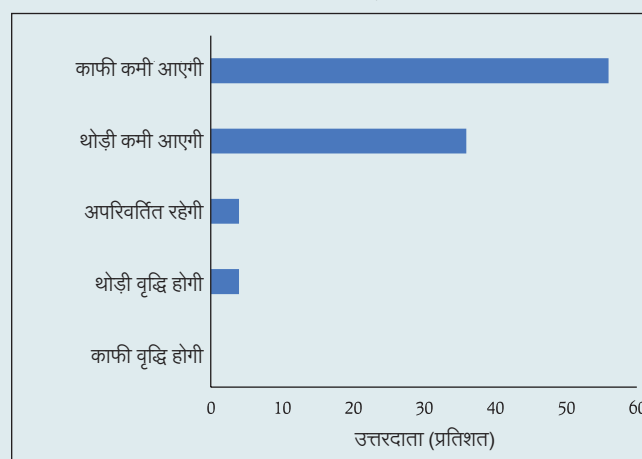
*समय-समय पर किए गए (अप्रैल और अक्तूबर अर्ध वार्षिक आधार पर) प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण से यह ज्ञात होता है कि जोखिम संभावनाएं एक जोखिम श्रेणी से दूसरी श्रेणी में अंतरित (कमी/वृद्धि) हो सकती हैं जिसे रंग में परिवर्तन द्वारा दर्शाया गया है। किंतु समान जोखिम श्रेणी (अर्थात्, समान रंग में दर्शाए गए बॉक्स) में भी जोखिम संभावना बढ़/घट सकती है या अपरिवर्तित रह सकती है, परिवर्तन तीर के निशान के माध्यम से दर्शाया गया है। जोखिम संभावनाओं में दर्शाया गया परिवर्तन लगातार दो सर्वेक्षणों के बीच तुलनात्मक विश्लेषण से संबंधित है।

नकदी प्रवाह की कमी के कारण एमएसएमई क्षेत्र प्रभावित हुआ है। कम मांग, श्रमशक्ति की कमी, रुकी हुई कार्यशील पूंजी आगे इस क्षेत्र के रोजगार पर दबाव डाल सकती है। कार्य करने के पैटर्न में परिवर्तन के कारण स्थावर संपदा के मूल्य तथा कमर्शियल स्थावर संपदा की ओर नकदी प्रवाह में काफी बदलाव आ सकता है जिससे स्थावर संपदा विकासकर्ता तथा उधार देने की स्थिति पर और अधिक दबाव आ जाएगा। कारपोरेट बांडों में बढ़ते हुए लीवरेज के कारण अत्यधिक मार्जिन की कमी पाई गई, जिससे क्रेडिट समीकरणों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है और फलस्वरूप रेटिंग नीचे चली गई हैं इससे ऋणों का पुनः वित्तपोषण और पूंजी जुटाने में कठिनाई पैदा हो सकती है।

वित्तीय क्षेत्रों में, बैंकिंग प्रणाली में मौजूद अनर्जक आस्तियों का ढेर और बैंकों की जोखिम विमुखता बड़ी चिंता का विषय बन गया है तथा यह आर्थिक संवृद्धि के प्रति अवरोध है रिजर्व बैंक द्वारा किए गए उपायों के बावजूद चलनिधि और दर संबंधी कार्रवाई का प्रसारण बहुत धीमा है। इसके साथ-साथ जोखिम विमुखता उत्पादन क्षेत्र (एनबीएफसी और एचएफसी सहित) की ओर क्रेडिट का प्रवाह एक चुनौती बना हुआ है। वित्तीय सेवाओं को क्रेडिट बाजार का अभिन्न एवं महत्वपूर्ण घटक मानते हुए अनेक सहभागियों का मत है कि वर्तमान वातावरण में भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से सहायता दिया जाना आवश्यक होगा।

लगभग 56 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि अगले एक वर्ष में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की संभावनाएं अत्यधिक खराब होने वाली हैं, क्योंकि बैंकिंग उद्योग के अर्जन पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ सकता है जिसके कारण हैं-लॉकडाउन समाप्त होने के बाद धीमी बहाली, निवल ब्याज मार्जिन कम रहना, आस्तियों की गुणवत्ता के प्रति बढ़ी हुई चिंताएं तथा प्रावधानीकरण अपेक्षाओं में संभावित वृद्धि होना है (चार्ट 1)।

चार्ट 1: अगले एक वर्ष में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में संभावनाएँ

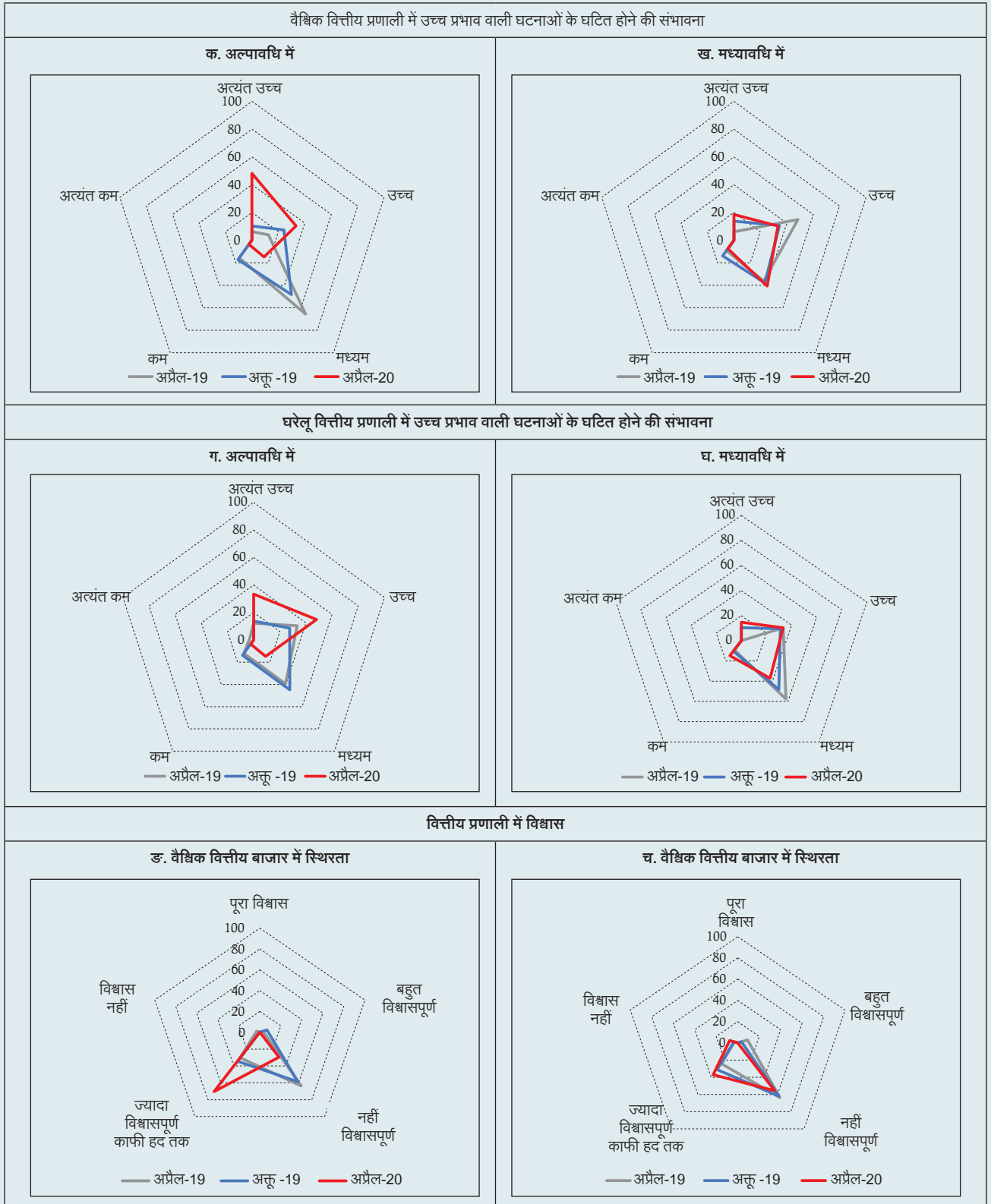


स्रोत: भा.रि.बं., प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण (अप्रैल-2020)

सर्वेक्षण के वर्तमान दौर में अधिकांश प्रतिभागियों का मानना है कि अल्पावधि (1 वर्ष तक) में वैश्विक वित्तीय प्रणाली में बड़ा असर डालने वाली किसी घटना के होने की संभावना है। हालांकि, सर्वेक्षण के मौजूदा दौर में अधिकांश प्रतिभागियों ने यह महसूस किया कि के मध्यम अवधि (1 से 3 वर्ष) में वैश्विक वित्तीय प्रणाली में बड़ा असर डालने वाली किसी घटना की संभावना मध्यम है। प्रतिभागियों का मत है कि भारतीय वित्तीय प्रणाली में अल्पावधि में बड़ा असर डालने वाली किसी घटना के होने की संभावना है जबकि मध्यम अवधि (1 से 3 वर्ष) में इसकी संभावना मध्यम रहेगी। लगभग 70% उत्तरदाता वैश्विक वित्तीय प्रणाली की स्थिरता के बारे में अधिक आश्वस्त नहीं थे (चार्ट 2)।

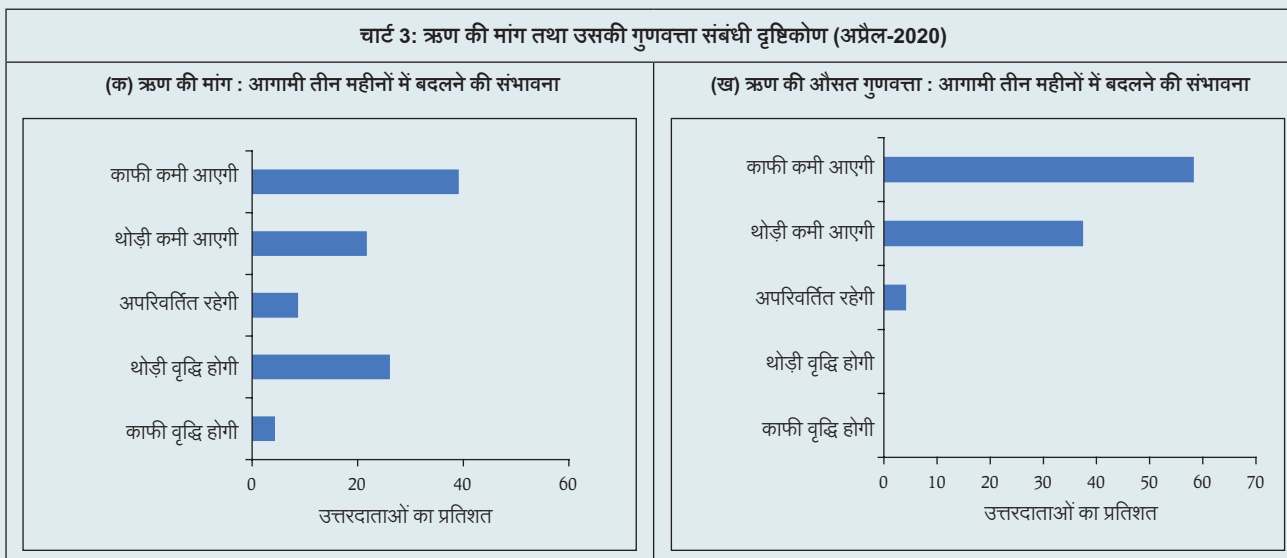
चार्ट 2: उच्च प्रभाव वाली घटनाओं के घटित होने का बोध एवं वित्तीय प्रणाली में विश्वास

उत्तरदाता (प्रतिशत)



स्रोत : भा.रि.बैं., प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण (अप्रैल 2019, अक्टू 2019 एवं अप्रैल 2020)

अगले तीन महीनों में ऋण की मांग में होने वाले संभाव्य परिवर्तन के मामले में अधिकांश उत्तरदाताओं का मानना था कि इसमें काफी कमी आएगी। ऋण की औसत गुणवत्ता के संबंध में अधिकांश उत्तरदाताओं ने यह व्यक्त किया कि अगले तीन महीनों में इसमें काफी कमी आएगी (चार्ट 3)।



स्रोत : भा.रि.बैं., प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण (अप्रैल-2020)

कोविड-19 महामारी : प्रभाव और आर्थिक बहाली

उत्तरदाताओं का मत है कि जहां अधिकांश क्षेत्रों को राजस्व का बड़ा एवं तत्काल नुकसान होने वाला है, वहीं उन क्षेत्रों में प्रतिकूल प्रभाव पाए गए हैं जिनमें उपभोग पर व्यय विवेकपूर्ण स्वरूप के हैं। सर्वेक्षण के परिणामों से पता चलता है कि कोविड-19 महामारी से 5 क्षेत्र प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं (सारणी 1)। लगभग 90 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि पर्यटन क्षेत्र के भीतर आगामी छह महीने में बहाली आने की संभावना बहुत क्षीण है। विमानन क्षेत्र इसका दूसरा नजदीकी क्षेत्र होगा जिसके बारे में 85 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने भावी संभावनाओं को क्षीण रहने की श्रेणी में रखा है।

सारणी 1: कोविड-19 महामारी द्वारा प्रतिकूल रूप से प्रभावित क्षेत्र और उनके संबंध में भावी संभावनाएं

(उत्तरदाताओं का प्रतिशत)

क्षेत्र	आगामी 6 महीने में बहाली का प्रतिशत			
	अच्छा	ठीक	कोई परिवर्तन नहीं	क्षीण
पर्यटन और आतिथ्य		5	5	90
निर्माण और स्थावर संपदा		37.5	12.5	50
विमानन		7.7	7.7	84.6
आटोमोबाइल		50		50
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम		40		60

स्रोत : भा.रि.बैं., प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण (अप्रैल-2020)

प्रतिभागियों से यह पूछा गया था कि कोविड-19 महामारी से आगे चलकर उत्पन्न होने वाली प्रमुख वित्तीय स्थिरता संबंधी चिंताओं को किस श्रेणी में रखेंगे (सारणी 2)। प्रतिभागियों की दो सबसे बड़ी चिंताएं टूटी हुई आपूर्ति श्रृंखला तथा घटता हुआ उपभोक्ता व्यय/विश्वास था, इसके बाद की चिंताएं विश्व में आने वाली मंदी तथा कार्यों पर चलनिधि/पूंजी पर पड़ने वाले वित्तीय प्रभाव को लेकर थीं।

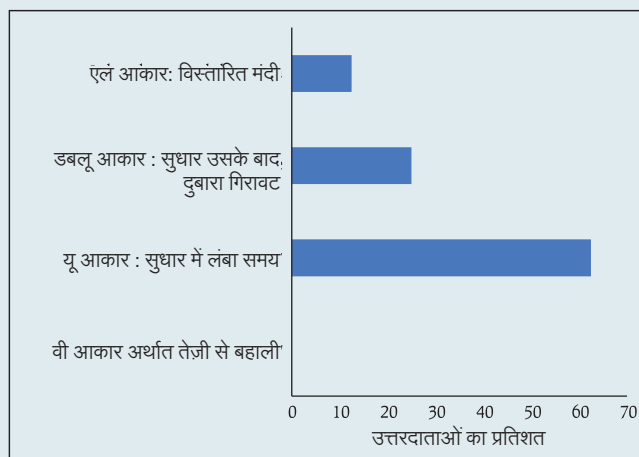
सारणी 2: कोविड-19 महामारी द्वारा प्रतिकूल रूप से प्रभावित क्षेत्र और उनके संबंध में भावी संभावनाएं

चिंताएं	श्रेणी
आपूर्ति श्रृंखला अवरोध	1
घटता हुआ उपभोक्ता विश्वास/व्यय	2
वैश्विक मंदी	3
कार्यों पर और/या चलनिधि एवं पूंजी पर वित्तीय प्रभाव	4
कार्यबल में कमी/कर्मचारियों पर दबाव	5
कर एवं व्यापार मामलों पर प्रभाव	6
न्यून उत्पादकता	7
निर्णय लेने में सूचनाओं का अभाव	8

स्रोत : भा.रि.बैं., प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण (अप्रैल-2020)

लगभग 63 प्रतिशत उत्तरदाताओं का अनुमान है कि कोविड-19 के बाद की बहाली यू- आकार की होगी अर्थात् तुरंत गिरावट होगी और उसके बाद सुधार आने में लंबा समय लगेगा (चार्ट 4)

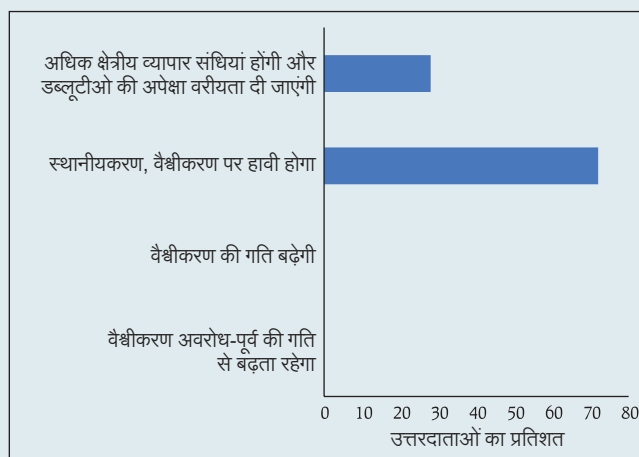
चार्ट 4: आर्थिक बहाली का संभावित आकार (अप्रैल 2020)



स्रोत : भा.रि.बैं., प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण (अप्रैल-2020)

72 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि आगे चलकर व्यापार के संबंध में स्थानीयकरण, वैश्वीकरण पर हावी रहेगा और क्षेत्रीय आधार पर अधिक व्यापार संधियां की जाएंगी और उसे वरीयता दी जाएगी (शेष 25 प्रतिशत) (चार्ट 5)।

चार्ट 5: वैश्वीकरण/वैश्विक व्यापार पर प्रभाव (अप्रैल 2020)



स्रोत : भा.रि.बैं., प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण (अप्रैल-2020)

अनुबंध 2

कार्यप्रणालियां

2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

बैंकिंग स्थिरता मानचित्र और संकेतक

बैंकिंग स्थिरता मानचित्र और संकेतक किसी दी गई अवधि के दौरान बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता पर प्रभाव डालने वाली स्थितियों और जोखिम घटकों में होने वाले परिवर्तनों का समग्र अनुमान प्रदर्शित करते हैं। बैंकिंग स्थिरता मानचित्र और संकेतक में पांच संयुक्त सूचकांकों का प्रयोग किया गया है जिनके पांच आयाम हैं – मजबूती, आस्ति गुणवत्ता, लाभप्रदता, चलनिधि और कार्यकुशलता। प्रत्येक संयुक्त सूचकांक बनाने में जिन अनुपातों का प्रयोग किया गया है उन्हें सारणी 1 में दिया गया है:-

सारणी 1 : बैंकिंग स्थिरता मानचित्र और संकेतक बनाने के लिए प्रयुक्त अनुपात

आयाम	अनुपात			
मजबूती	सीआरएआर #	टिअर II पूंजी के प्रति टिअर-I पूंजी #	पूंजी और आरक्षी के प्रति कुल आस्ति के रूप में लीवरेज अनुपात	
आस्ति-गुणवत्ता	कुल अग्रिम की तुलना में निवल एनपीए	कुल अग्रिम की तुलना में सकल एनपीए	सकल एनपीए के प्रति अवमानक अग्रिम #	मानक अग्रिमों की तुलना में पुनःसंचित- मानक- अग्रिम
लाभप्रदता	आस्तियों पर प्रतिफल #	निवल ब्याज मार्जिन #	लाभ में वृद्धि #	
चलनिधि	कुल आस्तियों की तुलना में चलनिधि आस्तियां #	कुल आस्तियों की तुलना में ग्राहक जमा राशियां #	ग्राहक की जमाराशियों की तुलना में गैर-बैंक अग्रिम	कुल जमाराशियों की तुलना में 1 वर्ष की अवधि के भीतर परिपक्व होने वाली जमाराशियां
कार्यकुशलता	आय की तुलना में लागत	स्टाफ खर्च की तुलना में व्यवसाय (क्रेडिट + जमाराशि)#		कुल खर्च की तुलना में स्टाफ व्यय

नोट: # जोखिम से प्रतिलोम संबंध है।

प्रत्येक संयुक्त सूचकांक जो बैंक की कार्यप्रणाली के आयाम का प्रतिनिधित्व करता है, वह शून्य और 1 के बीच का मान लेता है। प्रत्येक सूचकांक इसके निर्माण के लिए प्रयुक्त नमूना अवधि के दौरान एक संबंधित पैमाना होता है जिसमें उच्च मान का अर्थ होता है कि उस आयाम में जोखिम अधिक है। अतः किसी विशेष आयाम में सूचकांक का मान बढ़ना यह दर्शाता है कि उस आयाम में अन्य अवधियों की तुलना में संबंधित अवधि में जोखिम में वृद्धि हुई है। किसी आयाम के लिए प्रयोग में लाए गए प्रत्येक अनुपात द्वारा बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक भारित औसत निकाला जाता है जिसमें भारों को बैंकिंग प्रणाली की कुल आस्तियों की तुलना में किसी बैंक की व्यक्तिगत आस्तियों के अनुपात के रूप में निरूपित किया जाता है। किसी नमूना अवधि के लिए प्रत्येक सूचकांक का सामान्यीकरण निम्नलिखित फार्मूले के आधार पर किया जाता है:

$$\frac{(X_t - \min(X_t))}{(\max(X_t) - \min(X_t))}$$

जिसमें X_t अनुपात के मूल्य को t समय पर प्रदर्शित करता है। प्रत्येक आयाम के संयुक्त सूचकांक की गणना, उस आयाम के लिए प्रयुक्त सामान्यीकृत अनुपातों के भारित औसत के रूप में की जाती है जहां भार, सीएएमईएलएस रेटिंग के अनुमान हेतु निर्धारित अंकों पर आधारित होते हैं। इन पांच संयुक्त सूचकांकों के सामान्य औसत के रूप में बैंकिंग स्थिरता संकेतक का निर्माण किया जाता है।

समष्टि-दबाव परीक्षण

समष्टि-आर्थिक आघातों के प्रतिबैंकों की आघात-सहनीयतापता करने के लिए, मैक्रो दबाव परीक्षण क्रेडिट जोखिम के लिए किया गया। इसमें, बैंकों (सिस्टम एवं बड़े बैंक समूह स्तर पर) के जीएनपीए अनुपात पर एवं अंततः उनकी पूंजी पर्याप्तता (बैंकवार एवं सिस्टम स्तर पर 53 बैंकों के नमूनों के लिए) पर मैक्रो आघात का प्रभाव देखा गया।

जीएनपीए अनुपात का प्रभाव

यहाँ, गिरावट अनुपात (एसआर)¹ को समष्टि-आर्थिक चरों के एक फंक्शन के रूप में नमूने के तौर पर लिया गया था जिसमें विविध अर्थमितीय मॉडल का प्रयोग किया गया जिसमें चुनिंदा बैंकिंग प्रणालियों का समग्र समष्टि-आर्थिक चरों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया। जबकि प्रयुक्त बैंक समूह-वार गिरावट अनुपात मॉडल हैं: (i) मल्टीवेरिएट रिग्रेशन और (ii) वेक्टर ऑटोरिग्रेशन (वीएआर), नमूना प्रणाली स्तरीय गिरावट अनुपात की तुलना में (i) मल्टीवेरिएट रिग्रेशन (ii) वीएआर और (iii) क्वान्टाइल रिग्रेशन। समग्र बैंकिंग प्रणाली में गिरावट अनुपात के मौजूदा और पिछले मान शामिल होते हैं जबकि समष्टि-आर्थिक चरों में आधार कीमत पर सकल देशी उत्पाद (जीडीपी), भारत औसत उधार दर (डब्ल्यूएलआर), सीपीआई (संयुक्त) मुद्रास्फीति, जीडीपी अनुपात की तुलना में निर्यात, जीडीपी अनुपात की तुलना में चालू खाता शेष, और जीडीपी अनुपात की तुलना में सकल राजकोषीय घाटा शामिल होते हैं।

जहां मल्टीवेरिएट रिग्रेशन, बैंकिंग प्रणाली की जीएनपीए पर चुनिंदा समष्टि-आर्थिक चरों के प्रभाव का मूल्यांकन करने की अनुमति देता है, वहीं वीएआर मॉडल फीडबैक प्रभाव को भी संज्ञान में लेता है। इन पद्धतियों में, गिरावट अनुपात के सशर्त मध्यमान का अनुमान लगाया जाता है जबकि यह माना जाता है कि क्रेडिट गुणवत्ता के स्तर में परिवर्तन होने के बावजूद क्रेडिट गुणवत्ता पर समष्टि-चरों का प्रभाव समान रहेगा, जो कि हमेशा सत्य नहीं रह सकता है। इस अनुमान में छूट देने के लिहाज से क्रेडिट गुणवत्ता का अनुमान लगाने के लिए क्वान्टाइल रिग्रेशन को अपनाया गया, जिसमें सशर्त मध्यमान के स्थान पर सशर्त क्वान्टाइल का अनुमान लगाया जाता है और इस प्रकार यह सामान्यतर जोखिमों का सामना कर सकता है और यह समष्टि-आर्थिक आघातों के गैर-रैखिक प्रभावों का भी ध्यान रखता है।

गिरावट अनुपात (एसआर) पर समष्टि-आर्थिक आघातों के प्रभावों का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित अर्थमितीय मॉडल अपनाए गए :

प्रणाली स्तरीय मॉडल

प्रणाली स्तरीय जीएनपीए का अनुमान लगाने के लिए तीन भिन्न परंतु आपस में सम्पूरक अर्थमितीय मॉडल यथा – बहुविचर रीग्रेशन, वीएआर और क्वान्टाइल रीग्रेशन का उपयोग किया गया। अंतिम अनुमान इन तीन मॉडलों पर आधारित अनुमानों के औसत से उत्पन्न होता है।

• बहुविचर रीग्रेशन

निम्नलिखित बहुविचर रीग्रेशन मॉडल का प्रयोग समग्र एससीबी के गिरावट अनुपात अनुमान के लिए किया गया।

$$SR_t = \alpha_1 + \beta_1 SR_{t-1} - \beta_2 \Delta GDP_{t-2} + \beta_3 RWALR_{t-2} - \beta_4 \left(\frac{CAB}{GDP}\right)_{t-3} + \beta_5 Dummy$$

जहां, $\alpha_1, \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$ and $\beta_6 > 0$

• वेक्टर ऑटोरिग्रेशन (वीएआर) मॉडल

नोशनल/अंकन रूप में, ऑर्डर पी मध्यमान-समायोजित वीएआर (VAR (p)) को इस प्रकार लिखा जा सकता है:

$$y_t = A_1 y_{t-1} + \dots + A_p y_{t-p} + u_t; t=0,1,2,3,\dots$$

जहां, $y_t = (y_{1t}, \dots, y_{kt})'$ समय t पर वेरिएबल /चर का एक वेक्टर ($K \times 1$), A_i ($i=1,2,\dots,p$) निर्धारित ($K \times K$) कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हैं और $u_t = (u_{1t}, \dots, u_{kt})'$ एक K-आयामी व्हाइट न्वाइज या नवोन्मेषी प्रक्रिया है।

¹ गिरावट, एक अवधि के दौरान अनर्जक आस्तियों में नई अभिवृद्धि है। गिरावट अनुपात = अवधि की शुरुआत में नई अनर्जक आस्तियां/ मानक अग्रिमा

वीएआर मॉडल का अनुमान लगाने के लिए, गिरावट अनुपात, डब्ल्यूएलआर, सीपीआई (संयुक्त) मुद्रास्फीति, वास्तविक जीडीपी संवृद्धि और समग्र जीडीपी अनुपात की तुलना में सकल राजकोषीय घाटे का चुनाव किया गया। न्यूनतम सूचना दृष्टिकोण आधार पर और अन्य उपचारों के साथ ही वीएआर के उपयुक्त क्रम का चुनाव किया गया और इसके लिए क्रमांक 2 उचित पाया गया। चुने गए वीएआर के संवेग अनुक्रिया प्रणाली का उपयोग करते हुए विभिन्न प्रकार के समष्टि आर्थिक आघातों के प्रभावों का निर्धारण किया गया।

• *क्वान्टाइल रीग्रेशन*

निम्नलिखित क्वान्टाइल रीग्रेशन मॉडल का प्रयोग 0.8 पर गिरावट अनुपात के सशर्त क्वान्टाइल का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है :

$$SR_t = \alpha_1 + \beta_1 SR_{t-1} - \beta_2 \Delta GDP_{t-2} + \beta_3 RWALR_{t-2} - \beta_4 \left(\frac{CAB}{GDP}\right)_{t-3} + \beta_5 Dummy$$

बैंक समूह स्तरीय मॉडल /पद्धति

बैंक समूह-वार गिरावट अनुपात का अनुमान दो भिन्न परंतु आपस में सम्पूरक अर्थमितीय मॉडल: बहुविचर रीग्रेशन, वीएआर और क्वान्टाइल रीग्रेशन का उपयोग किया गया। इन दो मॉडलो पर आधारित अनुमानों के औसत से अंतिम अनुमान उत्पन्न होता है।

• *बहुविचर रीग्रेशन*

विभिन्न बैंक समूहों के गिरावट अनुपात का मॉडल बनाने के लिए निम्नलिखित बहुविचर रीग्रेशन का उपयोग किया गया:

सरकारी क्षेत्र के बैंक (पीएसबी)

$$SR_t = \alpha_1 + \beta_1 SR_{t-1} + \beta_2 \Delta CPI_{t-1} + \beta_3 WALR_{t-1} - \beta_4 \Delta GDP_{t-2} + \beta_5 \left(\frac{GFD}{GDP}\right)_{t-2} - \beta_6 \left(\frac{EXP}{GDP}\right)_{t-3} + \beta_7 Dummy$$

निजी क्षेत्र बैंक (पीवीबी) :

$$SR_t = \alpha_1 + \beta_1 SR_{t-1} + \beta_2 RWALR_{t-2} - \beta_3 \Delta GDP_{t-1} - \beta_4 \left(\frac{EXP}{GDP}\right)_{t-1} + \beta_5 Dummy$$

विदेशी बैंक (एफबी):

$$SR_t = \alpha_1 + \beta_1 SR_{t-1} - \beta_2 \Delta^2 CPI_{t-3} + \beta_3 \Delta \left(\frac{GFD}{GDP}\right)_{t-1} - \beta_4 \Delta \left(\frac{EXP}{GDP}\right)_{t-2} + \beta_5 Dummy$$

• *वीएआर मॉडल*

विभिन्न बैंक समूहों के गिरावट अनुपात का मॉडल बनाने के लिए, विविध क्रमों के विभिन्न वीएआर नमूनों के अनुसार अनुमान लगाया गया जो निम्नलिखित समष्टि चरों पर आधारित थे:

सरकारी क्षेत्र के बैंक: जीडीपी, सीपीआई (संयुक्त) मुद्रास्फीति, डब्ल्यूएलआर, जीडीपी अनुपात की तुलना में सीएबी और क्रम 2 के जीडीपी अनुपात की तुलना में जीएफडी।

निजी क्षेत्र के बैंक: जीडीपी, वास्तविक डब्ल्यूएलआर और क्रम 1 के जीडीपी अनुपात की तुलना में निर्यात।

विदेशी बैंक: सीपीआई (संयुक्त) मुद्रास्फीति, डब्ल्यूएलआर और क्रम 2 के जीडीपी अनुपात की तुलना में सीएबी।

गिरावट से जीएनपीए का अनुमान

ऊपर उल्लिखित नमूनों के माध्यम से जब एक बार गिरावट अनुपात का अनुमान लगा लिया जाता है उसके बाद निम्नलिखित तादात्म्य के आधार पर जीएनपीए का अनुमान लगाया जाता है:

$$GNPA_{t+1} = GNPA_t + Slippage_{(t,t+1)} - Recovery_{(t,t+1)} - Write-off_{(t,t+1)} - Upgradation_{(t,t+1)}$$

गिरावट अनुपातों से निकाले गए जीएनपीए, जिनका अनुमान ऊपर उल्लिखित क्रेडिट जोखिम अर्थमितीय मॉडलों द्वारा प्रक्षेपित किया जाता था, निम्नलिखित अनुमानों पर आधारित थे: जून 2020 और सितंबर 2020 तिमाही के दौरान 3 प्रतिशत तथा दिसंबर 2020 और मार्च 2021 तिमाही के दौरान 4 प्रतिशत की की क्रेडिट संवृद्धि; जून, सितंबर, दिसंबर और मार्च तिमाहियों में क्रमशः 3.0 प्रतिशत, 2.5 प्रतिशत, 3.3 प्रतिशत और 2.4 प्रतिशत की दर से सुधार; जून, सितंबर, दिसंबर और मार्च तिमाहियों में क्रमशः 4.6 प्रतिशत, 4.5 प्रतिशत, 6.0 प्रतिशत और 6.5 प्रतिशत की दर से बढ़े खाते डालना; जून, सितंबर, दिसंबर और मार्च तिमाहियों में क्रमशः 1.7 प्रतिशत, 1.3 प्रतिशत, 1.2 प्रतिशत और 1.3 प्रतिशत की दर से उन्नयन (अप-ग्रेडेशन)।

पूंजी पर्याप्तता पर प्रभाव

बैंक में पूंजी पर्याप्तता पर समष्टि आघातों का प्रभाव निम्नलिखित चरणों के जरिए निकाला गया:

- भावी पूंजी संचयन पर प्रभाव को कल्पित समष्टि परिदृश्य के तहत लाभ का अनुमान कर किया गया, यह मानकर कि केवल 25 प्रतिशत कर पश्चात लाभ (पैट) (जो कि न्यूनतम विनियामक अपेक्षा है) बैंक की पूंजी में जाता है।
- भविष्य में अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता और समष्टि दबाव परिदृश्य का अनुमान आंतरिक मूल्यांकन आधारित (आईआरबी) सूत्र का उपयोग कर जोखिम-भारित आस्तियों (आरडबल्यूए) का आकलन कर किया गया।

निम्नलिखित सूत्र का उपयोग किया गया:

$$CRAR_{t+1} = \frac{Capital_t + 0.25 * PAT_{t+1}}{RWAs(credit\ risk)_{t+1} + RWAs(others)_{t+1}}$$

$$Common\ Equity\ Tier\ 1\ Capital\ Ratio_{t+1} = \frac{CET1_t + 0.25 * PAT_{t+1}}{RWAs(credit\ risk)_{t+1} + RWAs(others)_{t+1}}$$

जहां पैट का पूर्वानुमान सेट्टेलाइट नमूनों का उपयोग कर किया गया है जिनकी विशदीकरण आगे के खंड में की गई है। कुल आरडबल्यूए में से क्रेडिट जोखिम आरडबल्यूए को घटाकर मिले आरडबल्यूए (अन्य) का अनुमान पिछले एक वर्ष के दौरान देखी गई औसत वृद्धि दर पर

आधारित पर था। नीचे दिए गए आईआरबी सूत्र का उपयोग करते हुए आरडबल्यूए (क्रेडिट जोखिम) का आकलन किया जाता है:

आईआरबी सूत्र: क्रेडिट जोखिम के लिए बैंकवार आरडबल्यूए आकलन निम्नलिखित आईआरबी सूत्र के आधार पर किया गया।

$$RWAs(credit\ risk) = 12.5 \times \left(\sum_{i=1}^n EAD_i \times K_i \right)$$

जहां EAD_i बैंक के सेक्टर i (i = 1,2,.....n) का डिफॉल्ट जोखिम है।

K_i क्षेत्र i के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकता है जिसकी गणना निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करते हुए की गई है:

$$= \left[LGD_i \times N \left[(1 - R_i)^{-0.5} \times G(PD_i) + \left(\frac{R_i}{1 - R_i} \right)^{0.5} \times G(0.999) \right] - PD_i \times LGD_i \right] \\ \times (1 - 1.5 \times b(PD_i))^{-1} \times (1 + (M_i - 2.5) \times b(PD_i))$$

जहां LGD_i क्षेत्र i की दी गई डिफॉल्ट हानि है, PD_i क्षेत्र i के डिफॉल्ट की संभाव्यता है, N (...) मानक सामान्य वितरण का संचयी वितरण फंक्शन है, G (...) मानक सामान्य वितरण के संचयी वितरण फंक्शन का व्युत्क्रम है, M_i क्षेत्र (इस मामले में सभी क्षेत्र के लिए 2.5 ली गई है) के ऋण की औसत परिपक्वता है, b(PD_i) सुस्पष्ट परिपक्वता समायोजन है और R_i अर्थव्यवस्था की सामान्य स्थिति के साथ क्षेत्र i का सह-संबंध है। b (PD) और R दोनों की गणना PD पर निर्भर है।

ऊपर आईआरबी सूत्र के लिए तीन प्रमुख इनपुट की आवश्यकता होती है, यथा क्षेत्र की PD, EAD और LGD। यहाँ बैंक डाटा का उपयोग कर संबंधित क्षेत्र की वार्षिक गिरावट से क्षेत्र की PD ली गई है। PD क्षेत्र विशेष में प्रत्येक के लिए चयनित 53 बैंकों के समान (अर्थात प्रणालीगत आघात) नमूने से लिए गए थे, जबकि, EAD क्षेत्र विशेष के लिए बैंक का उस क्षेत्र विशेष में कुल बकाया ऋण था। इसके अतिरिक्त, LGD पर पूर्वानुमान इस प्रकार लिया गया था: आधाररेखा परिदृश्य के अंतर्गत, LGD = 60 प्रतिशत (मोटे तौर पर पूंजी पर्याप्तता पर आरबीआई दिशा निर्देशों के अनुसार - ऋण जोखिम के लिए पूंजी की आवश्यकता की गणना के लिए आईआरबी पद्धति) जो माध्यम समष्टि अर्थशास्त्र जोखिम परिदृश्य में बढ़कर 65 प्रतिशत और गंभीर समष्टि अर्थशास्त्र जोखिम परिदृश्य में 70 प्रतिशत हो जाता है।

चयनित क्षेत्र : निम्नलिखित 17 क्षेत्र (और अन्य) दबाब की जांच के लिए चयनित किए गए।

सारणी 2: चयनित क्षेत्रों की सूची

क्र.सं.	क्षेत्र	क्र.सं.	क्षेत्र
1	इंजिनियरिंग	10	मूलभूत धातु और धातु उत्पाद
2	ऑटो	11	खनिज
3	सीमेंट	12	कागज
4	रसायन	13	पेट्रोलियम
5	विनिर्माण	14	कृषि
6	कपड़ा	15	रिटेल - हाउसिंग
7	खाद्य प्रसंस्करण	16	रिटेल - अन्य
8	रत्न और आभूषण	17	सेवाएँ
9	बुनियादी संरचना	18	अन्य

क्षेत्रगत वार्षिक गिरावट अनुपात (अर्थात क्षेत्रगत PD) का समष्टि परिवर्ती के साथ प्रसंभाव्य संबंध का अनुमान लगाने के लिए प्रत्येक क्षेत्र के लिए मल्टीवेरिएट रिग्रेशन का उपयोग किया गया था। इन अनुमानित रिग्रेशन का उपयोग कर प्रत्येक क्षेत्र के क्षेत्रगत पीडी की गणना कल्पित आधार-रेखा के साथ-साथ दो प्रतिकूल परिदृश्यों, यथा, मध्यम दबाब और गंभीर दबाब के अंतर्गत अगली चार तिमाहियों के लिए की गई थी। क्षेत्रगत रिग्रेशन के नमूने आगे के खंडों में प्रस्तुत किए गए हैं।

कल्पित समष्टि परिदृश्यों के अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता की गणना करने के क्रम में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर क्रेडिट संवृद्धि 4 प्रतिशत का अनुमान लगाया गया है। निम्नलिखित चरणों का उपयोग कर बैंकवार पैट की गणना की गई:

- प्रत्येक बैंक-समूह के लिए पैट के घटकों (अर्थात निवल ब्याज आय (एनआईआईआई), अन्य परिचालन गत आय (ओओआई), परिचालन गत व्यय (ओई) और प्रावधान तथा बड़े खाते डालना) की गणना आधार रेखा और प्रतिकूल परिदृश्यों के अंतर्गत आगे के खंडों में वर्णित विधि द्वारा की गई।
- प्रत्येक बैंक के पैट के घटकों के अंश (आयकर को छोड़कर) की गणना उनके संबंधित बैंक-समूह में की गई।
- संबंधित बैंक-समूह के पैट के घटक के अनुमानित मूल्य और पैट के घटक विशेष में उस बैंक के अंश की गणना कर प्रत्येक बैंक के पैट (आयकर को छोड़कर) के प्रत्येक घटक का अनुमान लगाया गया।

- अंत में, बैंकवार पैट का पूर्वानुमान पिछले चरण में अनुमानित उनके घटकों को उपयुक्त रूप से जोड़ते अथवा घटाते हुए लगाया गया और आयकर का दर 35 प्रतिशत प्रयोग में लिया गया।

उपर्युक्त सूत्रों, अनुमान और इनपुट का प्रयोग करते हुए, प्रत्येक बैंक पर पूंजी पर्याप्तता पर अनुमानित समष्टि परिदृश्यों के प्रभाव का अनुमान लगाया गया और अद्यतन वास्तविक तथ्यात्मक आंकड़ों से आधार रेखा के अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता में भावी बदलाव तथा आधार रेखा से प्रतिकूल समष्टि दबाव तक बैंक की पूंजी पर्याप्तता में बदलाव की गणना की गई। अंततः इन बदलावों को समुचित रूप से बैंकों में पाई गई अद्यतन पूंजी पर्याप्तता (स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच के अंतर्गत) पर लागू किया गया।

क्षेत्रगत पीडी का पूर्वानुमान

1. इंजीनियरिंग

$$\Delta PD_t = \alpha + \beta_1 \Delta PD_{t-1} + \beta_2 \Delta WALR_{t-2} - \beta_3 \left(\frac{EXP}{GDP}\right)_{t-2} - \beta_4 \Delta GVA(Industry)_{t-3} + \beta_5 Dummy$$

2. ऑटो

$$PD_t = \alpha + \beta_1 PD_{t-1} - \beta_2 \Delta GDP_{t-1} + \beta_3 WALR_{t-1} - \beta_4 \left(\frac{EXP}{GDP}\right)_{t-2} + \beta_5 \Delta CPI_{t-2} + \beta_6 Dummy$$

3. सीमेंट

$$PD_t = \alpha + \beta_1 PD_{t-1} - \beta_2 \Delta GDP_{t-2} + \beta_3 \Delta WALR_{t-1} - \beta_4 \left(\frac{EXP}{GDP}\right)_{t-2} + \beta_5 Dummy$$

4. रसायन और रासायनिक उत्पाद

$$PD_t = \alpha + \beta_1 PD_{t-1} + \beta_2 \Delta WALR_{t-1} - \beta_3 \Delta GDP_{t-1} + \beta_4 Dummy_t$$

5. विनिर्माण

$$PD_t = \alpha + \beta_1 PD_{t-1} + \beta_2 \Delta WALR_{t-1} - \beta_3 \left(\frac{EXP}{GDP}\right)_{t-1} - \beta_4 \Delta GDP_{t-1} + \beta_5 Dummy_t$$

6. कपड़ा

$$PD_t = \alpha + \beta_1 PD_{t-1} - \beta_2 \Delta GDP_{t-1} + \beta_3 \Delta WALR_{t-1} - \beta_4 \left(\frac{EXP}{GDP}\right)_{t-2} + \beta_5 \Delta CPI_{t-3} + \beta_6 Dummy$$

7. खाद्य प्रसंस्करण

$$PD_t = \alpha + \beta_1 PD_{t-1} + \beta_2 \Delta WALR_{t-3} - \beta_3 \left(\frac{EXP}{GDP}\right)_{t-1} - \beta_4 \Delta GDP_{t-2} + \beta_5 Dummy_t$$

8. रत्न और आभूषण

$$PD_t = \alpha + \beta_1 PD_{t-1} + \beta_2 \Delta WALR_{t-1} - \beta_3 \left(\frac{EXP}{GDP}\right)_{t-3} - \beta_4 \Delta GDP_{t-2} + \beta_5 Dummy_t$$

9. बुनियादी संरचना

$$PD_t = \alpha + \beta_1 PD_{t-1} - \beta_2 \Delta GDP_{t-2} + \beta_3 WALR_{t-1} - \beta_4 \Delta CPI_{t-1} + \beta_5 Dummy$$

10. मूलभूत धातु और धातु उत्पाद

$$PD_t = \alpha + \beta_1 PD_{t-1} - \beta_2 \Delta GDP_{t-3} + \beta_3 WALR_{t-1} - \beta_4 \left(\frac{EXP}{GDP}\right)_{t-1} + \beta_5 Dummy$$

11. खनिज और उत्खनन

$$PD_t = \alpha + \beta_1 PD_{t-1} - \beta_2 \Delta GDP_{t-2} + \beta_3 \Delta CPI_{t-1} - \beta_4 \left(\frac{EXP}{GDP}\right)_{t-2} + \beta_5 Dummy$$

12. कागज और कागज उत्पाद

$$PD_t = \alpha + \beta_1 PD_{t-1} + \beta_2 \Delta WALR_{t-4} - \beta_3 \left(\frac{EXP}{GDP}\right)_{t-2} - \beta_4 \Delta GDP_{t-1} + \beta_5 Dummy_t$$

13. पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद

$$PD_t = \alpha + \beta_1 PD_{t-1} + \beta_2 \Delta WALR_{t-2} - \beta_3 \left(\frac{EXP}{GDP}\right)_{t-2} - \beta_4 \Delta GDP_{t-2} + \beta_5 Dummy_t$$

14. कृषि

$$PD_t = \alpha + \beta_1 PD_{t-1} + \beta_2 \Delta WALR_{t-1} - \beta_3 \left(\frac{EXP}{GDP}\right)_{t-2} - \beta_4 \Delta GDP_{t-1} + \beta_5 Dummy_t$$

15. कृषि

$$\Delta PD_t = \alpha + \beta_1 \Delta PD_{t-1} + \beta_2 \Delta WALR_{t-1} - \beta_3 \left(\frac{EXP}{GDP}\right)_{t-2} - \beta_4 \Delta GDP_{t-2} + \beta_5 \Delta CPI_{t-1}$$

16. रिटेल - आवास

$$\Delta PD_t = \alpha - \beta_1 \Delta PD_{t-1} + \beta_2 \Delta WALR_{t-2} - \beta_3 \Delta GDP_{t-1}$$

17. रिटेल - अन्य

$$PD_t = \alpha + \beta_1 PD_{t-1} + \beta_2 \Delta WALR_{t-2} - \beta_3 \left(\frac{EXP}{GDP}\right)_{t-1} + \beta_4 Dummy_t$$

18. अन्य

$$PD_t = \alpha + \beta_1 PD_{t-1} + \beta_2 \Delta WALR_{t-2} - \beta_3 \Delta GDP_{t-1} + \beta_4 Dummy_t$$

बैंक-समूहवार कर पश्चात लाभ (पैट) का अनुमान

प्रमुख बैंकों-समूहों (यथा पीएसबी, पीवीबी, एफबी) के पैट के विभिन्न घटकों, जैसे कि एनआईआई,ओओआई,ओई और प्रावधान तथा बट्टे खाते डालना विभिन्न समय श्रृंखलाओं पर आधारित अर्थमितीय मॉडल (जैसा कि नीचे दिया गया है) के आधार पर अनुमान लगाया गया। अंततः निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करते हुए पैट का अनुमान लगाया गया:

$$PAT = NII + OOI - OE - Provisions \& writeoff - Income Tax$$

जहां, एनआईआई- निवल ब्याज आय, ओओआई- अन्य परिचालनगत आय और ओई- परिचालनगत खर्च है।

निवल ब्याज आय (एनआईआई): एनआईआई ब्याज से आय और ब्याज पर खर्च के बीच का अंतर है और निम्नलिखित रिग्रेशन मॉडल का प्रयोग कर उसकी गणना की जाती है:

$$LNII_t = -\alpha_1 + \beta_1 \times LNII_{t-1} + \beta_2 \times LNGDP_SA_{t-1} + \beta_3 \times Adv_Gr_{t-1} + \beta_4 \times Spread_t$$

एलएनआईआई, एनआईआई का लॉग है। एलएनजीडीपी_एसए सांकेतिक जीडीपी का मौसमी रूप से समायोजित लॉग है। एडीवी_जीआर अग्रिमों और ऋण में वर्ष-दर-वर्ष होने वाली संवृद्धि दर है। स्प्रेड, ब्याज कमाने वाली आस्तियों पर कमाए गए औसत ब्याज दर और ब्याज देने वाली देयताओं पर दिए गए औसत ब्याज के बीच का अंतर है।

अन्य परिचालनगत आय (ओओआई): लॉग ऑफ ओओआई (एलओओआई) के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की अन्य परिचालनगत आय को निम्नलिखित रिग्रेशन मॉडल का प्रयोग करते हुए अनुमानित किया गया:

$$LOOI_t = -\alpha_1 + \beta_1 \times LOOI_{t-1} + \beta_2 \times LNGDP_SA_t$$

एलओओआई, ओओआई का लॉग है।

परिचालनगत खर्च (ओई): अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ओई को ऑटोरिग्रेसिव मूविंग एवरेज (एआरएमए) मॉडल का प्रयोग कर अनुमानित किया गया।

प्रावधान (बट्टे खाते सहित): निम्नलिखित रिग्रेशन का उपयोग कर अपेक्षित प्रावधानों का अनुमान लगाया गया:

$$P_Adv_t = \alpha_1 + \beta_1 \times P_Adv_{t-1} - \beta_2 \times \Delta GDP_{t-2} + \beta_3 \times GNPA_{t-1} - \beta_4 \times Dummy$$

P_Adv, कुल अग्रिमों के अनुपात की तुलना में किया गया प्रावधान है। ΔGDP वास्तविक जीडीपी की वर्ष-दर-वर्ष संवृद्धि दर है। जीएनपीए कुल अग्रिमों की तुलना में सकल गैर-निष्पादन आस्ति अनुपात है और इसलिए कल्पित समष्टि दबाव के अंतर्गत आस्तियों की गुणवत्ता में हास का आय पर प्रभाव इस समीकरण से निकाला गया। डमी, समयावधि डमी है।

आयकर: लागू आयकर को कर पूर्व लाभ का 35 प्रतिशत माना गया है, जो आयकर की तुलना में कर पूर्व लाभ के पिछले अनुपात के रुझानों पर आधारित है।

एकल घटक संवेदनशीलता विश्लेषण-दबाव जांच

तिमाही निगरानी के रूप में, क्रेडिट जोखिम, ब्याज दर जोखिम, चलनिधि जोखिम आदि को शामिल करते हुए दबाव परीक्षण किए जाते हैं और इन आघातों के प्रत्युत्तर में वाणिज्यिक बैंकों की आघात सहनीयता का अध्ययन किया जाता है। यह विश्लेषण व्यक्तिगत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के स्तर पर और प्रणाली के स्तर पर भी किया गया।

ऋण जोखिम (संकेंद्रण जोखिम सहित)

बैंकों की आघात सहनीयता का पता लगाने के लिए समस्त पोर्टफोलियो में जीएनपीए के स्तरों में बढ़ोतरी करके ऋण निवेश को आघात दिया गया। ऋण संकेंद्रण जोखिम की जांच करने के लिए उच्चतम व्यक्तिगत उधारकर्ता (कर्ताओं) और उधारकर्ता (कर्ताओं) के सबसे बड़े समूह को चूककर्ता के रूप में लिया गया। यह विश्लेषण समग्र स्तर पर और व्यक्तिगत बैंक दोनों ही स्तरों पर किया गया। जीएनपीए में कल्पित वृद्धि को मानक से कम (अवमानक), संदेहास्पद और हानि की श्रेणियों में उसी अनुपात में बांट दिया गया जिस अनुपात में एनपीए का मौजूदा स्टॉक उपलब्ध था। तथापि, ऋण संकेंद्रण जोखिम के लिए संभावित आघातों के तहत अतिरिक्त जीएनपीए पर विचार किया गया ताकि उसे अवमानक श्रेणी में ही रखा जा सके। विभिन्न आस्ति श्रेणियों के लिए लागू मौजूदा औसत मानदंडों के आधार पर इन दबाव जांचों के लिए प्रावधानीकरण मानदंडों का उपयोग किया गया। अवमानक, संदेहास्पद और हानि अग्रिमों के लिए क्रमशः 25 प्रतिशत, 75 प्रतिशत और 100 प्रतिशत की प्रावधानीकरण आवश्यकताओं को संज्ञान में लिया गया। दबाव की परिस्थितियों के तहत गणना में लिए गए अतिरिक्त जीएनपीए पर इन मानदंडों को लागू किया गया। जीएनपीए में कल्पित वृद्धि के परिणामस्वरूप, एक तिमाही में अतिरिक्त जीएनपीए पर हुई आय में हानि को भी कुल हानियों में शामिल किया गया। इसके अलावा प्रावधानीकरण आवश्यकता में भी वृद्धि की गई। इस प्रकार प्राप्त की गई अनुमानित प्रावधानीकरण संबंधी अपेक्षाओं को बैंकों की पूंजी में से घटा दिया गया और दबावग्रस्त पूंजी पर्याप्तता अनुपातों की गणना की गई।

क्षेत्रगत जोखिम

एक बैंक के क्षेत्रगत ऋण जोखिम का पता लगाने के लिए क्षेत्र विशेष के जीएनपीए अनुपात को बढ़ाकर उस क्षेत्र के ऋण पोर्टफोलियो को आघात पहुंचाया गया। यह विश्लेषण समग्र स्तर पर और व्यक्तिगत बैंक दोनों ही स्तरों पर किया गया। एक क्षेत्र के जीएनपीए अनुपातों के मानक विचलन पर आधारित क्षेत्र विशेष आघात का प्रयोग व्यक्तिगत बैंक पर हुए प्रभाव का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। यह माना गया कि कल्पित आघातों के तहत अतिरिक्त जीएनपीए अवमानक श्रेणी में ही आएंगे। जीएनपीए में कल्पित वृद्धि के परिणामस्वरूप, एक तिमाही में अतिरिक्त जीएनपीए पर हुई आय में हानि को भी कुल हानियों में शामिल किया गया। इसके अलावा प्रावधानीकरण आवश्यकता में भी वृद्धि की गई। इस प्रकार प्राप्त की गई अनुमानित प्रावधानीकरण संबंधी अपेक्षाओं को बैंकों की पूंजी में से घटा दिया गया और दबावग्रस्त पूंजी पर्याप्तता अनुपातों की गणना की गई।

ब्याज दर जोखिम

भारतीय रुपए के प्रतिफल वक्र में आने वाले अंतर के कारण कल्पित आघात के तहत, पोर्टफोलियो की कीमत में गिरावट या आय में होने वाली गिरावट के कारण हानि हो सकती हैं। बैंकों की पूंजी में से इन कल्पित हानियों को कम कर दिया गया ताकि दबावग्रस्त सीआरएआर को प्राप्त किया जा सके।

ट्रेडिंग पोर्टफोलियो (एचएफटी+एएफएस) में ब्याज दर जोखिम के मामले में मूल्यन प्रभाव (पोर्टफोलियो हानि) की गणना के लिए अवधि विश्लेषण पद्धति पर विचार किया गया। दिए गए आघातों के आधार पर, प्रत्येक कालावधि के लिए, इन निवेशों पर पोर्टफोलियो हानि की गणना की गई। इसके परिणामस्वरूप प्राप्त हानि/लाभ का प्रयोग इससे प्रभावित सीआरएआर ज्ञात करने के लिए किया गया। एचटीएम पोर्टफोलियो में ब्याज दर आघातों का प्रभाव देखने के लिए अलग से एक प्रक्रिया अपनाई गई, जिसमें अवधि पद्धति का उपयोग करते हुए, ब्याज वहन करने वाली आस्तियों पर प्रत्येक कालावधि के लिए हानियों के मूल्यांकन की गणना की गई। एचटीएम पोर्टफोलियो पर जांच के लिए मूल्यांकन प्रभाव की गणना यह मानते हुए की गई कि एचटीएम पोर्टफोलियो दैनिक बाजार मूल्य पर आधारित (मार्क-टू-मार्केट) है।

इक्विटी मूल्य जोखिम

इक्विटी मूल्य जोखिम के अंतर्गत इक्विटी मूल्य सूचकांक में निश्चित प्रतिशत अंकों की गिरावट के आघात का बैंक की पूंजी और एनपीए स्तर पर प्रभाव का परीक्षण किया गया। पोर्टफोलियो मूल्य में गिरावट या इक्विटी मूल्य में बदलाव के कारण आय की हानि को कल्पित आघात के कारण बैंक की कुल हानि के लिए गिना गया। इस प्रकार आंकलित कुल हानि को बैंक की पूंजी में से कम किया गया।

चलनिधि जोखिम

चलनिधि दबाव जांच का उद्देश्य चलनिधि के अप्रत्याशित बहिर्गमन पर बाहर से चलनिधि की कोई मदद लिए बगैर बैंक की उसे वहन करने की क्षमता का पता लगाना है। अचानक जमाकर्ताओं का विश्वास खो देने के कारण विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां जमाराशि निकासी की विविध प्रकार की संभावनाएं (जमाराशि के प्रकार के अनुसार) सामने लाती हैं और साथ ही स्वीकृत/प्रतिबद्ध/गारंटीशुदा क्रेडिट (कार्यशील पूंजी की स्वीकृत अप्रयुक्त सीमा, प्रतिबद्ध क्रेडिट और क्रेडिट पत्रों तथा गारंटियों की अप्रयुक्त सीमा को ध्यान में रखते हुए) सीमाओं के अप्रयुक्त हिस्से के लिए मांग उत्पन्न करती हैं। दबाव परीक्षण इस बात को ध्यान में रखते हुए किया गया कि क्रेडिट के लिए अतिरिक्त और अप्रत्याशित मांग को बैंकों की केवल चलनिधि युक्त आस्तियों की सहायता से पूरा करने की उनकी क्षमता का पता लगाया जा सके।

चलनिधि दबाव परीक्षण के कल्पित बिंदु इस प्रकार हैं:

- यह माना गया कि बैंक केवल चलनिधियुक्त आस्तियों की बिक्री के जरिए जमाराशियों की दबावग्रस्त निकासी या क्रेडिट की अतिरिक्त मांग को पूरा कर लेंगे।
- किए गए निवेशों की बिक्री उनके बाजार मूल्य में दस प्रतिशत के हेयरकट पर कर ली जाएगी।
- दबाव परीक्षण "स्टैटिक मोड" के अंतर्गत किया गया।

बॉटम-अप दबाव परीक्षण करना: चुनिंदा बैंक

19 चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक पर बॉटम-अप संवेदनशीलता का परीक्षण किया गया। चुनिंदा बैंकों के लिए समान प्रकार के परिदृश्य और आघात के आकार दिये गए। यह जांच मार्च 2019 के आंकड़ों पर आधारित था। बैंकों द्वारा प्रत्येक मामलों में घाटे की गणना के लिए उनकी अपनी पद्धति अपनाई जाती है।

बॉटम-अप दबाव परीक्षण : चुनिंदा बैंकों के डेरिवेटिव पोर्टफोलियो

दबाव परीक्षण को शीर्ष 20 बैंकों के प्रतिनिधि नमूना समूह के डेरिवेटिव पोर्टफोलियो के संबंध में केंद्रित किया गया और इसके लिए डेरिवेटिव पोर्टफोलियो का अनुमानित मूल्य लिया गया। इस नमूने में शामिल प्रत्येक बैंक से कहा गया कि वे अपने संबंधित डेरिवेटिव पोर्टफोलियो के संबंध में दबाव परिस्थितियों के प्रभाव का मूल्यांकन करें।

घरेलू बैंकों के मामले में, घरेलू और विदेशी दोनों प्रकार के डेरिवेटिव पोर्टफोलियो को शामिल किया गया। विदेशी बैंकों के मामले में, इस प्रक्रिया में केवल घरेलू (भारतीय) स्थिति पर विचार किया गया। जिस डेरिवेटिव व्यापार में हेजिंग की प्रभावात्मकता साबित की जा चुकी थी उन्हें दबाव परीक्षण से छूट प्रदान की गई, जबकि अन्य सभी प्रकार के व्यापार को इसमें शामिल किया गया।

इस दबावग्रस्त परिदृश्य में चार संवेदनशीलता परीक्षणों को शामिल किया गया जिसमें स्पॉट यूएस डालर/ भारतीय रुपया दर और घरेलू ब्याज दरों को मानकों के रूप में शामिल किया गया था।

सारणी 3 : संवेदनशीलता विश्लेषण के लिए आघात

घरेलू ब्याज दरें		
आघात 1	एक दिवसीय	+2.5 प्रतिशत अंक
	1 वर्ष तक	+1.5 प्रतिशत अंक
	1 वर्ष से अधिक	+1.0 प्रतिशत अंक

घरेलू ब्याज दरें		
आघात 2	एक दिवसीय	-2.5 प्रतिशत अंक
	1 वर्ष तक	-1.5 प्रतिशत अंक
	1 वर्ष से अधिक	-1.0 प्रतिशत अंक

विनिमय दरें		
आघात 3	यूएस डालर/ भारतीय रुपया	+20 प्रतिशत

विनिमय दरें		
आघात 4	यूएस डालर/ भारतीय रुपया	-20 प्रतिशत

2.2 अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक

एकल घटक संवेदनशीलता विश्लेषण- दबाव परीक्षण

ऋण जोखिम

अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के ऋण जोखिम पर दबाव परीक्षण किया गया। यह परीक्षण एकल घटक संवेदनशीलता विश्लेषण पर आधारित था। ऐतिहासिक मानक विचलनों (एसडी) का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित चार विभिन्न परिदृश्यों के अंतर्गत सीआरएआर पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया गया:

- परिदृश्य I: जीएनपीए पर 1 मानक विचलन (एसडी) का आघात (अवमानक अग्रिमों में वर्गीकृत).
- परिदृश्य II: जीएनपीए पर 2 मानक विचलन (एसडी) का आघात (अवमानक अग्रिमों में वर्गीकृत).
- परिदृश्य III: जीएनपीए पर 1 मानक विचलन (एसडी) का आघात (हानि वाले अग्रिमों में वर्गीकृत).
- परिदृश्य IV: जीएनपीए पर 2 मानक विचलन (एसडी) का आघात (हानि वाले अग्रिमों में वर्गीकृत).

चलनिधि जोखिम

1-28 दिन की कालावधि वाले नकदी प्रवाह पर आधारित एक चलनिधि दबाव परीक्षण भी किया गया जिसमें आउटफ़्लो के 20 प्रतिशत से अधिक असंतुलन [नकारात्मक अंतर (नकदी आउटफ़्लो की तुलना में इनफ़्लो का कम होना)] को दबावग्रस्त माना गया।

- परिदृश्य I : 1-28 दिन की कालावधि में नकदी निकासी 50 प्रतिशत तक बढ़ना (नकदी जमा आने में कोई परिवर्तन नहीं)
- परिदृश्य II: 1-28 दिन की कालावधि में नकदी निकासी 100 प्रतिशत तक बढ़ना (नकदी जमा आने में कोई परिवर्तन नहीं)

2.3 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों

एकल घटक संवेदनशीलता विश्लेषण-दबाव परीक्षण

ऋण जोखिम

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (जमा स्वीकार करने वाली और जमा स्वीकार नहीं करने वाली -दोनों प्रकार की और प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण कंपनियां शामिल थीं) पर क्रेडिट जोखिम के संबंध में दबाव परीक्षण किया गया। ये परीक्षण एकल घटक संवेदनशीलता विश्लेषण पर आधारित थे। ऐतिहासिक मानक विचलन के आधार पर तीन विभिन्न परिस्थितियों में सीआरएआर पर इसके प्रभाव का अध्ययन किया गया:

- परिदृश्य I: मौजूदा स्तर से जीएनपीए में 0.5 मानक विचलन (एसडी) की वृद्धि।
- परिदृश्य II: मौजूदा स्तर से जीएनपीए में 1 मानक विचलन (एसडी) की वृद्धि।
- परिदृश्य III: मौजूदा स्तर से जीएनपीए में 3 मानक विचलन (एसडी) की वृद्धि।

जीएनपीए में परिकल्पित वृद्धि को अवमानक, संदेहास्पद और हानिगत श्रेणियों में उसी अनुपात में बांटा गया जिस अनुपात में वे जीएनपीए के मौजूदा स्टॉक में उपलब्ध थी। प्रावधानीकरण की अतिरिक्त अपेक्षाओं को मौजूदा पूंजी स्थिति से समायोजित किया गया। दबाव परीक्षण एकल एनबीएफसी स्तर के साथ ही साथ समग्र स्तर पर भी किया गया।

2.4 अंतर-संबद्धता- नेटवर्क विश्लेषण

नेटवर्क विश्लेषण के केन्द्र में मूलतः मैट्रिक्स अल्जेब्रा होता है, जिसमें वित्तीय क्षेत्र की संस्थाओं के बीच द्विपक्षीय एक्सपोजरों का उपयोग किया जाता है। वित्तीय प्रणाली में एक संस्था की सभी अन्य संस्थाओं को दी गई उधारियों अथवा ली गई उधारियों को स्कवायर मैट्रिक्स में रखा जाता है और उसके बाद उन्हें एक नेटवर्क ग्राफ में मैप किया जाता है। प्रणाली में अंतर-संबद्धता के स्तर को मापने के लिए नेटवर्क मॉडल में विभिन्न सांख्यिकीय तरीकों का प्रयोग किया जाता है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण तरीके निम्नलिखित हैं :

संबद्धता : यह एक सांख्यिकी होती है जो एक पूर्ण ग्राफ में सभी संभव श्रृंखलाओं से संबंधित नोड्स के बीच श्रृंखलाओं की सीमा को मापती है। एक निर्देशित ग्राफ में $K = \sum_{i=1}^N k_i$ के बराबर बाहरी अंशों की कुल संख्या दर्शाती है और N नोड्स की कुल संख्या के रूप में है, ग्राफ की संबद्धता $\frac{K}{N(N-1)}$ के रूप में दी गई है।

क्लस्टर गुणांक : नेटवर्क में क्लस्टरिंग यह माप करती है कि प्रत्येक नोड आपस में किस प्रकार अंतर-संबद्ध है। विशेष रूप से, इस बात की प्रबल संभावना होती है कि किसी नोड के दो पड़ोसी (वित्तीय नेटवर्क के मामले में बैंक के प्रतिपक्षी) आपस में भी पड़ोसी होंगे। किसी नेटवर्क के लिए उच्च क्लस्टरिंग गुणांक का अर्थ यह होता है कि प्रणाली में उच्च स्थानिक अंतर-संबद्धता मौजूद है। k_i , निकटवर्ती/पड़ोसियों वाले प्रत्येक बैंक हेतु उनके बीच सभी प्रकार के संभावित जुड़ावों की कुल संख्या $k_i(k_i-1)$ द्वारा दर्शायी जाती है। मान लेते हैं कि E_i एजेंट i बैंक के k_i निकटवर्तियों के बीच वास्तविक संबद्धता को प्रदर्शित करता है अर्थात जो i के k_i निकटवर्ती हैं वो आपस में भी निकटवर्ती हैं। i बैंक के लिए क्लस्टरिंग गुणांक C_i को इस सूत्र द्वारा व्यक्त किया है:-

$$C_i = \frac{E_i}{k_i(k_i - 1)}$$

समग्र रूप में नेटवर्क का क्लस्टरिंग गुणांक (सी) सभी C_i का औसत है:

$$C = \frac{\sum_{i=1}^N C_i}{N}$$

टियर नेटवर्क संरचना : विशिष्ट रूप से वित्तीय नेटवर्क में टियर संरचना की प्रवृत्ति देखी जाती है। टियर संरचना एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें विभिन्न संस्थाओं की अन्य नेटवर्क के साथ विविध अंशों पर या स्तरों पर संबद्धता होती है। मौजूदा विश्लेषण में सर्वाधिक संबद्ध बैंक मूल कोर में हैं। उसके बाद बैंकों को उनकी परस्पर संबद्धता के आधार पर मध्य कोर, बाहरी कोर और बाहरी घेरे (रेखाचित्र में केंद्र के आस-पास संबंधित सांकेद्रित वृत्त) में डाल दिया जाता है। बैंकों की संबद्धता की रेंज को प्रत्येक बैंक के इन-डिग्री और आउट-डिग्री अनुपात के अंश रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे सर्वाधिक संबद्ध बैंक के अंश से विभाजित किया जाता है। जो बैंक इस अनुपात के शीर्ष 10 प्रतिशत में आते हैं वे भीतरी कोर का निर्माण करते हैं। 90 और 70 प्रतिशत के बीच आने वाले बैंक मध्य कोर में आते हैं और 40 तथा 70 के बीच प्रतिशत वाले बैंकों की एक तीसरी परत होती है। शेष बैंकों को बाहरी घेरे में वर्गीकृत किया जाता है।

नेटवर्क चार्ट में रंग संकेत: नेटवर्क चार्ट में नीली और लाल गेंदें क्रमशः निवल उधारदाता और निवल उधारकर्ता को निरूपित करती हैं। परतदार नेटवर्क चित्र में शृंखलाओं के रंग संकेत नेटवर्क में मौजूद विभिन्न परतों से ली गई उधारियों को निरूपित करती हैं (उदाहरण के लिए हरे रंग की शृंखलाएं मूल कोर में स्थिति बैंकों से ली गई उधारियों को निरूपित करती हैं)।

ऋण-शोधन क्षमता संक्रामकता का विश्लेषण

संक्रामकता विश्लेषण एक प्रकार का दबाव परीक्षण होता है जिसमें एक या अधिक बैंकों के असफल हो जाने के कारण उत्पन्न दूरगामी प्रभावों के चलते बैंकिंग प्रणाली को होने वाले सकल घाटे का पता लगाया जाता है। आभासी संक्रामकता के लिए हम राउंड बाई राउंड या सीक्वेंशियल अल्गोरिथम का उपयोग करते हैं जिसे अब फरफाइन् (2003) के नाम से जाना जाता है। हम 0 समय पर असफल होने वाले ट्रिगर बैंक i से प्रारंभ कर प्रत्येक चक्र या पुनरावृत्ति में परेशानी में आनेवाले बैंकों को Dq , $q = 1, 2, \dots$ के रूप में निरूपित करते हैं। इस विश्लेषण के लिए, किसी बैंक को दबावग्रस्त तब माना जाता है जब इसका कोर सीआरएआर 7 प्रतिशत से नीचे चला जाए। प्राप्तकर्ता बैंक के लिए निवल प्राप्तियों को घाटे के रूप में माना जाता है।

चलनिधि संक्रामकता विश्लेषण

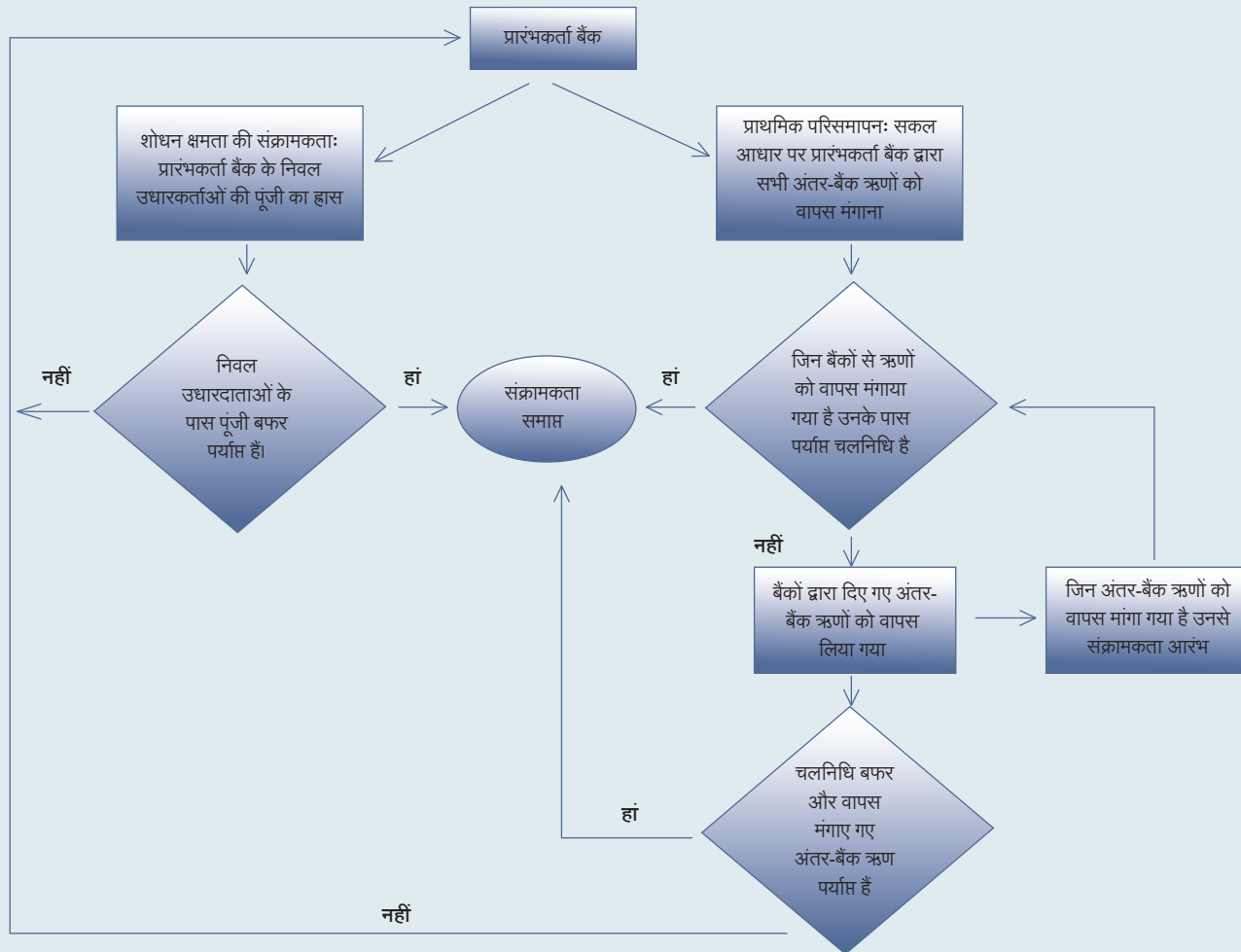
जहां ऋण शोधनक्षमता संक्रामकता विश्लेषण किसी निवल उधारकर्ता के विफल हो जाने की स्थिति में वित्तीय प्रणाली को होने वाली संभावित हानि का आकलन करता है वहीं चलनिधि संक्रामकता विश्लेषण किसी निवल उधारदाता के विफल हो जाने की स्थिति में इस प्रणाली को होने वाली संभावित हानि का अनुमान व्यक्त करता है। यह विश्लेषण बैंकों के बीच होने वाले सकल एक्सपोजर के संबंध में किया जाता है। एक्सपोजर में निधि आधारित और व्युत्पन्नी दोनों प्रकार के एक्सपोजर शामिल हैं। इस विश्लेषण की मूलभूत कल्पना यह है कि किसी बड़े निवल उधारदाता के विफल होने की स्थिति से उत्पन्न होने वाले चलनिधि दबाव से निपटने के लिए बैंक प्रारम्भ में अपनी चलनिधि भंडार या बफर का उपयोग करेंगे। चलनिधि आस्तियों के तहत विचार में ली जाने वाली मदें इस प्रकार हैं : (क) सीआरएआर का अतिरिक्त अधिशेष; (ख) एसएलआर का अतिरिक्त अधिशेष और (ग) निवल मांग और मीयादी देयताओं का 11 प्रतिशत। यदि एक बैंक केवल चलनिधि बफर की मदद से ही दबाव से निपटने में सक्षम होता है तो ऐसी स्थिति में आगे कोई और संक्रमण नहीं होगा।

तथापि, यदि केवल चलनिधि बफर पर्याप्त नहीं होते हैं तो बैंक को उन सभी ऋणों को वापस लेना होगा जो 'वापस लिए जाने योग्य' हैं, जिसके परिणामस्वरूप संक्रामकता होगी। विश्लेषण के प्रयोजन से केवल अल्पावधि की आस्तियां जैसे कि कॉल मार्केट में उधार दी गई राशि और अन्य बहुत ही अल्पावधि के लिए दिए गए ऋणों को ही वापसी योग्य माना गया है। इसके पश्चात किसी बैंक का अस्तित्व या तो बना रह सकता है अथवा उसका परिसमापन किया जाना होगा। इस मामले में इस प्रकार के उदाहरण हो सकते हैं जहां ऋणों की वापसी होने से बैंक का अस्तित्व बच गया हो परंतु इसके परिणामस्वरूप इससे आगे संक्रामकता हो सकती है जिससे अन्य बैंकों की परेशानी बढ़ सकती है। दूसरी कल्पना यह की गई है कि जब किसी बैंक का परिसमापन किया जाता है तो उस बैंक द्वारा उधार दिए गए ऋणों को सकल आधार पर वापस मांगा जाता है, जबकि परिसमापन किए बगैर जब बैंक द्वारा दिए गए अल्पावधि ऋणों को वापस मांगा जाता है तो ऋण को निवल आधार पर वापस मांगा जाता है (यह मानकर कि प्रतिपक्षी अपने उसी प्रतिपक्षी के प्रति पहले अपनी अल्पावधि देयताओं को कम करना चाहेगा)।

संयुक्त ऋणशोधन-चलनिधि संक्रामकता विश्लेषण

आम तौर पर एक बैंक की कुछ बैंकों के प्रति धनात्मक निवल ऋण प्रदान करने की स्थितियां और कुछ अन्य बैंकों के प्रति ऋणात्मक निवल उधार की स्थितियां -दोनों ही होती हैं। ऐसे किसी बैंक के विफल हो जाने पर ऋणशोधन तथा चलनिधि संक्रामकता दोनों साथ-साथ उत्पन्न हो जाएंगी। इस प्रक्रिया को निम्नलिखित फ्लोचार्ट द्वारा दर्शाया गया है:

एक बैंक के दबाव में आने के कारण संयुक्त ऋणशोधन-चलनिधि संक्रामकता संबंधी फ्लोचार्ट



यह माना गया कि प्रारंभकर्ता बैंक कुछ अंतर्जात कारण से विफल हुआ अर्थात् दिवालिया हो जाता है और इस प्रकार सभी उधारकर्ता बैंकों को प्रभावित करता है। उसी समय, वह अपनी आस्तियों को भी बेचना प्रारंभ करता है ताकि जहां तक संभव हो अपने दायित्वों को पूरा कर सके। परिसमापन की यह प्रक्रिया एक चलनिधि संक्रामकता उत्पन्न करती है क्योंकि प्रारंभकर्ता बैंक अपने दिए गए ऋणों को वापस मंगाना प्रारंभ कर देता है।

उधारदाता/ उधारकर्ता बैंक जो कि भली प्रकार पूंजीकृत होते हैं, वे आघात सहन कर जाते हैं और वे दूसरों को संक्रमित नहीं करते। दूसरी तरफ, वे उधारदाता बैंक जिनकी पूंजी एक निश्चित सीमा से कम हो जाती है वो एक नई संक्रामकता प्रारंभ कर देते हैं। उसी तरह वे उधारकर्ता जिनका चलनिधि बफर पर्याप्त होता है वे आगे कोई संक्रामकता फैलाए बिना दबाव सहन कर लेंगे। परंतु कुछ बैंक अपनी अल्पावधि आस्तियों को वापस मँगवाने के बाद ही चलनिधि दबाव का सामना करने में सक्षम होंगे। अल्पावधि आस्तियों को वापस मँगवाने की यह प्रक्रिया पुनः एक नई संक्रामकता आरंभ कर देगी।

ऋणशोधन और चलनिधि दोनों ही ओर से संक्रामकता तभी रुक पाएगी/ स्थिर हो पाएगी जब, प्रणाली द्वारा ऐसे हानि/ आघातों को आगे और विफलताएं न उत्पन्न करते हुए पूर्णतः अवशोषित किया जा सके।

अनुबंध-3
महत्वपूर्ण विनियामक उपाय

विनियामक पैकेज - कोविड-19

1. भारतीय रिजर्व बैंक

चलनिधि उपाय	औचित्य / प्रभाव
लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ) - कॉर्पोरेट बॉन्ड, वाणिज्यिक पत्र और अपरिवर्तनीय डिबेंचर में निवेश के लिए रिजर्व बैंक ने एमटीएम दिशानिर्देशों में नरमी बरतते हुए 3-वर्ष की अवधि के लिए कुल रूपए 1,00,000/- का टर्म रेपो नीलामी आयोजित किया।	प्रचुर मात्रा में तरलता उपलब्धता की वजह से वित्तीय बाजारों में उधार लेने में आने वाली लागत एक दशक में सबसे निचले स्तर पर आ गई। 23 मार्च, 2020 से 30 जून, 2020 के बीच 3-महीने की सीपी (एनबीएफसी), 3-महीने की सीपी (गैर-एनबीएफसी) और 3-महीने की सीडी पर ब्याज दर लगभग 320 बीपीएस, 365 बीपीएस, 472 बीपीएस रहा। समान अवधि की सरकारी प्रतिभूतियों पर 3-वर्षीय एए- रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड (सीबी) का विस्तार 26 मार्च, 2020 को 320 बीपीएस से घटकर 26 जून, 2020 को एनबीएफसी के लिए 114 बीपीएस रह गया। कम उधार लागत, टीएलटीआरओ निधि विनियोजन के साथ मिलने से 2020-21 की पहली तिमाही में रूपए 2.09 लाख करोड़ के कॉर्पोरेट बॉन्ड के निर्गम जारी करने का रिकॉर्ड बना।
अपनी मौद्रिक नीति के बेहतर प्रसारण को सक्षम करने के लिए, आरबीआई ने दीर्घावधि रेपो परिचालन (एलटीआरओ) की शुरुआत की, जिसके तहत रिजर्व बैंक ने नीति रेपो दर पर एक वर्ष और तीन वर्ष की अवधि का टर्म रेपो परिचालित किया। (1 लाख करोड़ रुपये का एलटीआरओ* 06 फरवरी, 2020 और 16 मार्च, 2020 को घोषित किया गया, जिसमें से कुल 1,25,000 करोड़ रुपये की नीलामी अब तक आयोजित की जा चुकी है।)	3 वर्षीय एलटीआरओ के साथ-साथ चलनिधि प्रचुरता ने अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति प्रतिफल को नीति रेपो दर के समीप बनाए रखा। फरवरी में एलटीआरओ की घोषणा के बाद से 3 महीने की टी-बिल प्रतिफल लगभग 195 बीपीएस हो गई है और आम तौर पर मार्च के बाद से लगातार रिवर्स रेपो दर से कम बनी रही। 3-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति प्रतिफल में भी 158 आधार अंकों की गिरावट आई, जबकि एलटीआरओ की घोषणा से लेकर और 10 जुलाई, 2020 के बीच 10 वर्षीय प्रतिफल में 74 बीपीएस की गिरावट आई। सरकारी प्रतिभूति बाजार में लचीलापन बना रहा और सरकारी उधार कार्यक्रमों के महत्वपूर्ण विस्तार और राज्य सरकारों की उधार सीमा में वृद्धि के बावजूद भी सरकारी प्रतिभूति प्रतिफल संकुचित बना रहा।
22 मार्च, 2020 को नीति रेपो दर 5.15 प्रतिशत था जिसे 22 मई, 2020 को कम कर के 4 प्रतिशत तक कर दिया गया। सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) की दर 5.40 प्रतिशत से घटाकर 4.25 प्रतिशत कर दी गई, जबकि चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत रिवर्स रेपो दर 4.90 प्रतिशत से घटाकर 3.35 प्रतिशत कर दी गई। मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने भी तब तक के लिए उदार रुख को जारी रखने का निर्णय लिया जब तक संवृद्धि को संभाल न लिया जाए तथा अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव को कम न कर लिया जाए साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करना कि मुद्रास्फीति लक्ष्य के अंदर बनी रहे।	उधार लागत को कम करने और संवृद्धि की संभावनाओं को बहाल करने के लिए।

चलनिधि उपाय	औचित्य / प्रभाव
सीआरआर एनडीटीएल के 100 आधार अंकों से घटकर 3 प्रतिशत हो गया। एमएसएफ के तहत, बैंकों को एसएलआर में से 3 प्रतिशत तक की राशि उधार लेने की अनुमति दी गई।	सीआरआर में कटौती करने से बैंकिंग प्रणाली में लगभग 1,37,000 करोड़ रुपये की चलनिधि इंजेक्ट हुआ जबकि एमएसएफ सीमा में वृद्धि ने उन्हें दैनिक स्तर पर चलनिधि प्रबंधन के लिए सक्षम बनाया।

तारीख	विनियामक उपाय	औचित्य
27 मार्च 2020	कार्यशील पूंजी सुविधाओं पर लगने वाले ब्याज में स्थगन	आर्थिक गिरावट को कम करना।
27 मार्च 2020	कार्यशील पूंजी वित्तपोषण को सहज करना।	आर्थिक गिरावट को कम करना।
27 मार्च 2020	शुद्ध स्थिर वित्तपोषण अनुपात (एमएसएफआर) के क्रियान्वयन में स्थगन।	बैंकों के लिए विनियामक राहता।
27 मार्च 2020	सीसीबी की अंतिम किस्त का स्थगन।	बैंकों के लिए विनियामक राहता।
27 मार्च 2020	बैंकों को मीयादी ऋण के लिए तीन महीने हेतु भुगतान किस्तों की अधिस्थगन के लिए अनुमति दी गई।	आर्थिक गिरावट को कम करना।
1 अप्रैल, 2020	निर्यात आय की प्राप्ति अवधि में विस्तार।	निर्यातकों की सहायता हेतु।
1 अप्रैल, 2020	एक वर्ष के लिए काउंटरसाइकिलिकल बफर (सीसीवाईबी) के कार्यान्वयन में विस्तार।	बैंकों के लिए विनियामक राहता।
17 अप्रैल, 2020	राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 31 मार्च 2020 तक जो अर्थोपाय अग्रिम सीमा तय थी उसमें 60 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई।	कोविड-19 रोकथाम और शमन प्रयास करने के लिए राज्यों को अधिक सुविधा प्रदान करना।
22 मई, 2020	निर्यात ऋण और आयात विप्रेषण के लिए समय-सीमा में विस्तार।	निर्यात / आयात को समर्थन देना।
22 मई, 2020	एक्जिम बैंक ने ऋण सीमा में रुपए 15,000 करोड़ की बढ़ोतरी की।	एक्जिम बैंक की विदेशी विनिमय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए।
22 मई, 2020	आस्ति वर्गीकरण मानदण्डों में रियायत देते हुए मीयादी ऋण हेतु अधिस्थगन अवधि में 3 महीनों के लिए बढ़ोतरी करते हुए इसे 31 अगस्त 2020 तक बढ़ाया गया।	आर्थिक गिरावट को कम करना।
22 मई, 2020	31 अगस्त, 2020 तक अतिरिक्त 3 महीने के लिए कार्यशील पूंजी सुविधाओं पर लगाने वाले ब्याज को स्थगित किया गया और स्थगित ब्याज को वित्त वर्ष के अंत में भुगतान किए जाने वाले वित्त पोषित ब्याज मीयादी ऋण में परिवर्तित किया जा सकता है। आस्ति वर्गीकरण मानदंडों में छूट।	आर्थिक गिरावट को कम करना।

तारीख	विनियामक उपाय	औचित्य
22 मई, 2020	31 मार्च 2021 तक कार्यशील पूंजी वित्त की गणना को सहज करना।	उधार-कर्ताओं को सहायता देने हेतु।
22 मई, 2020	1 मार्च, 2020 से 31 अगस्त, 2020 तक की अवधि को हटाने के लिए संकल्प समय-सीमा में विस्तार।	बैंकों के लिए विनियामक राहता।
22 मई, 2020	ग्रुप एक्सपोजर सीमा के लिए बड़े एक्सपोजर फ्रेमवर्क में ढील दी गई।	कम्पनियों को सहायता देने हेतु।
22 मई, 2020	राज्यों के लिए समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ) से निकासी को नियंत्रित करने वाले नियमों में ढील दी गई ताकि बाजार से लिए जाने वाले उधारों के मोचन को पूरा किया जा सके।	ताकि राज्य सरकारों की सहायता की जा सके।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी)

तारीख	विनियामक उपाय	औचित्य
20 मार्च 2020	कुछ मानदंडों के साथ एफएंडओ सेगमेंट के शेयरों के लिए, मार्केट वाइड पोजिसन लिमिट (एमडबल्यूपीएल) मौजूदा स्तर से 50 प्रतिशत तक संशोधित हुई। नकदी बाजार क्षेत्र में ऐसे शेयरों के मार्जिन दर चरणबद्ध तरीके से न्यूनतम 40 प्रतिशत तक बढ़ गई। कुछ मानदंडों के साथ गैर-एफएंडओ शेयरों के लिए, नकदी बाजार क्षेत्र में न्यूनतम मार्जिन दर चरणबद्ध तरीके से 40 प्रतिशत तक बढ़ी या पिछले एक महीने के दौरान अधिकतम इंटर-डे में उतार-चढ़ाव विविधताएं बनीं, जो भी अधिक हो।	व्यवस्थित ट्रेडिंग और निपटान सुनिश्चित करना, प्रभावी जोखिम प्रबंधन, कीमत खोज और बाजार अखंडता का रखरखाव करने के लिए।
20 मार्च 2020	इक्विटी इंडेक्स डेरिवेटिव्स में पोजिसन लिमिट (शॉर्ट एंड लॉन्ग) को संशोधित किया गया।	प्रभावी जोखिम प्रबंधन के लिए।
20 मार्च 2020	नगदी बाजार और एफएंडओ सेगमेंट में पेश किए गए डेरिवेटिव शेयरों के कीमत बैंडों के लचीलेपन से पहले 15 मिनट की विराम अवधि की शुरुआत।	प्रभावी जोखिम प्रबंधन के लिए।
23 मार्च 2020	व्यापारिक सदस्यों / समाशोधन सदस्यों द्वारा विनियामक आवश्यकताओं के साथ कुछ आवश्यक अनुपालन के लिए समय-सीमा में छूट।	बाजार सहभागियों पर अनुपालन दबाव को कम करने के लिए।

तारीख	विनियामक उपाय	औचित्य
23 मार्च 2020	नगद और एक दिवसीय निधि के लिए जोखिम-प्रबंधन ढांचे से संबंधित कुछ नीतिगत पहलों के कार्यान्वयन, म्यूचुअल फंडों के लिए निवेश मानदंड और कर्ज और मुद्रा बाजार प्रतिभूतियों का मूल्यांकन की तिथि को बढ़ाया गया।	समय-सीमा और अनुपालन आवश्यकता में अस्थायी छूट प्रदान करना।
26 मार्च 2020	घरेलू एक्सचेंजों के कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रेडिंग समय को शाम 5.00 बजे तक घटाया गया।	व्यवस्थित ट्रेडिंग और निपटान सुनिश्चित करने के लिए।
26 मार्च 2020	नामांकन एवं पारिश्रमिक समितियां और जोखिम प्रबंधन समितियां और हितधारक जैसे समितियों की बैठकें आयोजित करने संबंधित समय-सीमा में 3 महीने की अवधि तक छूट दी गई।	अनुपालन दबाव को कम करने के लिए।
26 मार्च 2020	कंपनियों को बोर्ड की बैठकों के लिए नोटिस और वित्तीय परिणाम जैसी कुछ जानकारी समाचार पत्रों में प्रकाशित करने की आवश्यकता होती है। उन्हें समाचार पत्रों में इस विज्ञापन को प्रकाशित करने संबंधी आवश्यकताओं से छूट दी गई।	अनुपालन दबाव को कम करने के लिए।
27 मार्च 2020	दैनिक आधार पर कमोडिटी और बाजार स्तर पर प्रतिभागियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए ओपेन ब्याज और टर्नओवर को स्टॉक एक्सचेंज द्वारा बताने संबंधी आवश्यकता को आस्थगित कर दी गई।	बाजार सहभागियों पर अनुपालन दबाव को कम करने के लिए।
27 मार्च 2020	अपने स्वयं के ढांचे को डिजाइन और कार्यान्वित करने के लिए एक्सचेंज/ क्लेयरिंग कार्पोरेशन को मंजूरी दी गई ताकि कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट में अंतिम निपटान कीमत (एफएसपी) या नियत तिथि दर (डीडीआर) का निर्धारण कर सके।	व्यवस्थित ट्रेडिंग और निपटान सुनिश्चित करने के लिए।
27 मार्च 2020	फ्रेश इशू साइज (आईपीओ / राइट इशू / एफपीओ) में परिवर्तन, सेबी (एसएसटी) विनियम, 2011 के कुछ प्रावधानों के अनुपालन के लिए समय-सीमा, और सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2018 में निहित अधिकारों के मुद्दों से संबंधित प्रावधानों में छूट दी गई।	समय-सीमा और अनुपालन आवश्यकता में अस्थायी छूट प्रदान करना।

तारीख	विनियामक उपाय	औचित्य
30 मार्च 2020	पोर्टफोलियो प्रबंधकों द्वारा मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने और वैकल्पिक निवेश निधि और उद्यम पूंजी निधि के लिए विनियामक फाइलिंग के लिए नियत तारीख के समय-सीमा में विस्तार।	समय-सीमा और अनुपालन आवश्यकता में अस्थायी छूट प्रदान करना।
30 मार्च 2020	कॉर्पोरेट्स चूक की पहचान और सेबी के कुछ प्रावधानों के अनुपालन के लिए समय-सीमा में विस्तार के संदर्भ में सीआरए में रियायत।	बाजार सहभागियों पर अनुपालन दबाव को कम करने के लिए।
30 मार्च 2020	डीडीपी / कस्टोडियन को मूल और / या प्रमाणित दस्तावेज (केवाईसी विवरण सहित) प्रस्तुत करने की आवश्यकता से एफपीआई में रियायत।	अनुपालन की आवश्यकता के संबंध में अस्थायी छूट के लिए।
30 मार्च 2020	अत्यधिक निधि मोचन के दबाव और अस्थायी चलनिधि आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु म्यूचुअल फंड के लिए उधार लेने की विनियामक सीमा कुछ शर्तों के अधीन 20 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक संशोधित की गई। कुछ रिपोर्टिंग आवश्यकताओं और डीलिंग रूम नीति में भी छूट दी गई है।	अस्थायी चलनिधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए।
30 मार्च 2020	उन सभी योजनाओं के लिए वैधता अवधि बढ़ा दी गई है, जहां सेबी द्वारा अवलोकन पत्र जारी किया गया था और अभी एक वर्ष के लिए शुरू किया जाना था। इसके अलावा, सभी म्यूचुअल फंडों और वैकल्पिक निवेश फंडों के लिए स्टैंडशिप कोड लागू करने की समय-सीमा बढ़ाई गई।	समय-सीमा और अनुपालन आवश्यकता में अस्थायी छूट प्रदान करना।
30 मार्च 2020	म्यूचुअल फंड लेनदेन पर स्टांप ड्यूटी की प्रयोज्यता के विस्तार पर सेबी के प्रतिनिधित्व के आधार पर, सरकार ने 1 जुलाई, 2020 से प्रभावी होने के लिए स्टैम्प ड्यूटी की प्रयोज्यता को 3 महीने के लिए स्थगित करने की अधिसूचना जारी की।	महामारी के बीच प्रतिभागियों को विनियामक राहत प्रदान करने के लिए।
6 अप्रैल 2020	अस्थायी अवधि के लिए विभिन्न म्यूचुअल फंड योजनाओं में सदस्यता और मोचन दोनों के लिए कट-ऑफ टाइमिंग कम की गई।	अस्थायी छूट प्रदान करने के लिए।

3. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई)

<p>23 मार्च 2020</p>	<p>आईआरडीएआई द्वारा वित्तीय राजधानी मुंबई में तालाबंदी के दौरान दो परिपत्र और एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई:</p> <ul style="list-style-type: none"> कोविड-19 के कारण अस्पताल में भर्ती से संबन्धित स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां में स्पष्टता जो नीति नियमों और शर्तों के अधीन है। मार्च 2020 में देय जीवन बीमा प्रीमियम के लिए अनुग्रह अवधि में 30 दिनों का विस्तार जो बाद में अप्रैल 2020 में देय प्रीमियमों तक के लिए बढ़ा दिया गया था। कोविड-19 से संबंधित मामलों के लिए सरलीकृत और त्वरित दावा निपटान प्रक्रिया और कोविड-19 के कारण जीवन बीमा से संबन्धित दावा निपटान की दैनिक निगरानी। लॉकडाउन के दौरान प्रीमियम भुगतान और विभिन्न अन्य सेवाओं के लिए डिजिटल और वैकल्पिक मोड का उपयोग। 	<p>बीमा क्षेत्र पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए।</p>
----------------------	---	--

4. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफ़आरडीए)

<p>24 मार्च 2020</p>	<p>नियोजक द्वारा सीएसआरएफ का प्राधिकरण।</p>	<p>कोविड-19 जनित व्यवधानों को देखते हुए और घर से कार्य करने संबंधी मानदंडों के तहत नियोजकों / कॉरपोरेट्स को कुछ शर्तों के साथ भौतिक मोड के बजाय ईमेल के माध्यम से अपने कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत एनपीएस सब्सक्राइबर पंजीकरण फॉर्म को अधिकृत करने की अनुमति दी गई।</p>
----------------------	---	---

5. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई)

<p>23 मार्च 2020</p>	<p>कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया कि सभी कार्यवाहियों की समय-सीमा अगले आदेश तक विस्तारित रहेगी जिसे 15 मार्च, 2020 से प्रभावी माना जाएगा।</p>	<p>कोविड-19 के कारण देश के सामने चुनौतियों को देखते हुए और मुकदमेबाजी की अवधि के भीतर उनकी याचिका / आवेदन / सूट / अपील / अन्य सभी कार्यवाही दाखिल करने में परिणामी कठिनाइयों को देखते हुए उच्चतम न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया।</p>
----------------------	--	--

24 मार्च 2020	कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने विशेष रूप से कोविड -19 के प्रकोप के मद्देनजर एमएसएमई को दिवाला होने से बचाने के लिए दिवाला कार्यवाही शुरू करने की आवश्यक आरंभिक सीमा को बढ़ाकर ₹1 लाख रुपये से ₹1 करोड़ रुपये कर दिया।	एमएसएमई को विशेष रूप से कोविड – 19 के प्रकोप के मद्देनजर दिवाला होने से बचाने के लिए आरंभिक सीमा को बढ़ाना।
28 मार्च 2020	आईबीबीआई ने भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यवसायी) विनियम, 2016 और भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों का शासी बोर्ड) विनियम, 2016 में संशोधन किया। इन संशोधनों में कोविड-19 प्रकोप के मद्देनजर दिवाला पारिस्थितिकी तंत्र में हितधारकों की दशा को सुधारने के लिए विनियमों के तहत निर्धारित कतिपय समय-सीमाओं में विस्तार का प्रावधान है।	इन संशोधनों में कोविड-19 प्रकोप के मद्देनजर दिवाला पारिस्थितिकी तंत्र में हितधारकों की दशा को सुधारने के लिए विनियमों के तहत निर्धारित कतिपय समय-सीमा में विस्तार का प्रावधान है।
29 मार्च 2020	आईबीबीआई ने भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉरपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) में संशोधन किया।	यह प्रदान करने के लिए कि कोविड - 19 प्रकोप के मद्देनजर केंद्र सरकार द्वारा लगाई गई लॉकडाउन अवधि को किसी भी गतिविधि के लिए समय-सीमा के प्रयोजनों के लिए नहीं गिना जाएगा जो कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के संबंध में लॉकडाउन के कारण पूरा नहीं किया जा सकता है। हालांकि, यह संहिता में प्रदान की गई समग्र समय सीमा के अधीन होगा।

अन्य (कोविड 19 विशिष्ट को छोड़कर) महत्वपूर्ण विनियामकीय पहल (नवंबर 2019-मई 2020)

1. भारतीय रिज़र्व बैंक

दिनांक	उपाय	तर्क/उद्देश्य
23 दिसंबर 2019	एनबीएफसी के पी2पी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऋण देने की अधिकतम सीमा: भारतीय रिज़र्व बैंक ने पी2पी प्लेटफॉर्मों के माध्यम से ऋण देने के अपने निर्देशों की समीक्षा की और किसी भी समय सभी एनबीएफसी - पी2पी ऋण प्लेटफॉर्मों में सभी उधारकर्ताओं को मिलाकर ऋणदाता की कुल जोखिम की अधिकतम सीमा ₹50 लाख निर्धारित की है। सभी पी2पी प्लेटफॉर्मों को मिलाकर ₹10 लाख से अधिक का निवेश करने वाले ऋणदाता को पेशेवर चार्टर्ड अकाउंटेंट से ₹50 लाख की न्यूनतम मालियत प्रमाणित करने वाला प्रमाण पत्र पी2पी प्लेटफॉर्मों को पेश करना होता है। इसमें यह भी अधिकार दिया गया है कि धन के हस्तांतरण के लिए बैंक द्वारा नियुक्त किए गए न्यासी द्वारा संचालित एस्करो खातों को उस बैंक के साथ बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है जिसने न्यासी को नियुक्त किया है।	उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए।

दिनांक	उपाय	तर्क/उद्देश्य
31 दिसंबर 2019	बड़े यूसीबी में प्रबंधन बोर्ड का गठन: आरबीआई ने यह अनिवार्य कर दिया है कि ₹100 करोड़ और उससे अधिक की जमा राशि वाले यूसीबी विशेषज्ञों वाले एक प्रबंधन बोर्ड का गठन करे जो नीति और यह बोर्ड द्वारा सौंपे गए अन्य मामलों को निरूपित करने में निदेशक मण्डल का सहयोग करे। इनके मुख्य कार्यों में एनपीए की वसूली के लिए कार्रवाई की सिफारिश करना, एकमुश्त निपटान या समझौता निपटान, निधि प्रबंधन की देखरेख, आंतरिक नियंत्रणों की निगरानी और अनुपालन सहित आंतरिक लेखा परीक्षा और निरीक्षण कार्यों की निगरानी शामिल हैं। इस बीओएम (सीईओ को छोड़कर) में न्यूनतम 5 सदस्य और अधिकतम 12 सदस्य होंगे। सीईओ गैर-मतदान सदस्य होंगे।	यूसीबी की निगरानी में बढ़ोतरी।
9 जनवरी 2020	आधार आधारित वीडियो प्रमाणीकरण: आरबीआई ने ग्राहक को जोड़ने हेतु ग्राहक की पहचान स्थापित करने के लिए सहमति आधारित वैकल्पिक विधि के रूप में वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया (वी-सीआईपी) की अनुमति दी है। वी-सीआईपी का निष्पादन कर रहे विनियमित इकाई (आरई) का अधिकारी आधार कार्ड जैसे वैध दस्तावेजों के साथ पहचान के लिए मौजूद ग्राहक का वीडियो रिकॉर्ड करने के साथ-साथ उसकी तस्वीरें भी लेगा। ग्राहक (जियोटैगिंग) का मौजूदा स्थान दर्ज किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ग्राहक भारत में स्वयं उपस्थित है।	ग्राहक पहचान प्रक्रिया (सीआईपी) के लिए डिजिटल चैनलों का लाभ उठाना।
23 मार्च 2020	प्राथमिकता क्षेत्रों को ऋण - बैंकों द्वारा आगे उधार देने के लिए एनबीएफसी को ऋण दिया जाना: आरबीआई ने वित्त वर्ष 2020-21 में आगे उधार देने हेतु एनबीएफसी को बैंक ऋण देने के लिए प्राथमिकता क्षेत्र के वर्गीकरण को बढ़ाया है। श्रेणी विशेष के अंतर्गत पंजीकृत एनबीएफसी (एमएफआई के अलावा) और एचएफसी को आगे उधार देने के लिए बैंक विशेष द्वारा उसके कुल प्राथमिकता क्षेत्र ऋण की 5 प्रतिशत की समग्र सीमा तक की बैंक क्रेडिट की अनुमति दी जाएगी।	कृषि, एमएसई और आवास जैसे लक्षित क्षेत्रों में ऋण बढ़ाने के लिए।

दिनांक	उपाय	तर्क/उद्देश्य
27 मार्च 2020	अपतटीय गैर-प्रदेय रूपया व्युत्पन्नी बाजार में बैंकों की भागीदारी: आरबीआई ने आईएफएसएसी बैंकिंग इकाई (आईबीयू) में परिचालन कर रहे भारतीय बैंकों (फेमा, 1999 के तहत एडी-1 लाइसेंस वाले) को अपतटीय गैर-प्रदेय फॉरवर्ड (एनडीएफ) रूपया व्युत्पन्नी बाजार में भाग लेने की अनुमति दी है। बैंक अपने आईबीयू के माध्यम से या भारत में अपनी शाखाओं के माध्यम से या अपनी विदेशी शाखाओं के माध्यम से इस तरह के लेनदेन कर सकते हैं।	घरेलू और विदेशी बाजारों के बीच अंतरपणन को कम कर विदेशी मुद्रा बाजार की मजबूती और भाव जागरूकता में सुधार के लिए।
30 मार्च 2020	पूर्णतः सुलभ मार्ग के तहत सरकारी प्रतिभूति की विशेष श्रृंखला: आरबीआई ने अनिवासी निवेशकों के लिए पूर्णतः सुलभ मार्ग (एफएआर) के तहत सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) की कुछ विनिर्दिष्ट श्रेणियां शुरू की ली। पात्र निवेशक किसी भी निवेश सीमा के बिना विनिर्दिष्ट सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं। वित्त वर्ष: 2020-21 से 5 साल, 10 साल और 30 साल की अवधि के लिए जारी सभी नई सरकारी प्रतिभूतियां एफएआर के तहत 'विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों' के रूप में निवेश के पात्र होंगे। यह योजना दो मौजूदा मार्गों, मध्यावधि ढांचे (एमटीएफ) और स्वैच्छिक अवधारण मार्ग (वीआरआर) के साथ-साथ परिचालित होंगे।	बांड बाजार को मजबूत करने के लिए।
20 अप्रैल 2020	बैंकों और एनबीएफसी द्वारा समय-समय पर धनशोधन की जोखिम के आकलन करने की आवश्यकता: केवाईसी निर्देशों में हाल में हुए संशोधनों में विनियमित संस्थाओं (आरई) को यह अधिकार दिया गया है कि वे समय-समय पर धनशोधन (एमएल) और आतंकवाद वित्तपोषण (टीएफ) जोखिम का आकलन करे ताकि ग्राहकों, देशों या भौगोलिक क्षेत्रों, उत्पादों, सेवाओं, लेनदेन या वितरण चैनल के धनशोधन और आतंकवाद वित्तपोषण संबंधी जोखिमों की पहचान और आकलन कर उसको कम करने के लिए प्रभावी उपाय किए जाएं। आरई को समग्र क्षेत्र-विशिष्ट सुभेद्यता, यदि कोई हो, का संज्ञान लेना चाहिए जोकि विनियामक/पर्यवेक्षक द्वारा समय-समय पर आरई के साथ साझा कर सकता है। चिह्नित जोखिमों को कम करने और उसके प्रबंधन करने के लिए आरई एक जोखिम आधारित दृष्टिकोण (आरबीए) भी लागू करेगा और इसके लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियां, नियंत्रण और प्रक्रियाएं होनी चाहिए।	धनशोधन (एमएल) और आतंकवादी वित्तपोषण (टीएफ) जोखिमों को जांच के दायरे में रखने के लिए।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

दिनांक	नीतिगत उपाय	नीतिगत तर्क
1 अक्टूबर 2019	म्यूचुअल फंड द्वारा कर्ज और मुद्रा बाजार लिखतों में निवेश हेतु मानदंडों की समीक्षा। यह निर्णय लिया गया कि म्यूचुअल फंड योजनाएं (क) सरकारी प्रतिभूतियों, (ख) अन्य मुद्रा बाजार लिखतों, तथा (ग) व्युत्पन्नी उत्पादों जैसे ब्याज दर स्वैप (आईआरएस) एवं ब्याज दर वायदा (आईआरएफ) जिनका उपयोग म्यूचुअल फंड द्वारा हेजिंग के लिए किया जाता है, को छोड़कर वाणिज्यिक पत्र (सीपी) सहित असूचीबद्ध लिखतों में निवेश नहीं करेंगे। हालांकि, म्यूचुअल फंड योजनाओं को कुछ शर्तों के अधीन योजना के कर्ज पोर्टफोलियो का 10 प्रतिशत तक असूचीबद्ध अपरिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) में निवेश करने की अनुमति है।	म्यूचुअल फंड द्वारा कर्ज और मुद्रा बाजार उपकरणों में निवेश में पारदर्शिता और प्रकटीकरण बढ़ाने के लिए।
10 अक्टूबर 2019 और 28 नवंबर 2019	डिपॉजिटरी रसीदें जारी करने के लिए ढांचा: भारत में निगमित और भारत के मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनी अनुमत प्रतिभूतियों को जारी कर सकता है या उनके धारक डिपॉजिटरी रसीदें जारी करने के लिए स्वीकार्य प्रतिभूतियों को स्थानांतरित कर सकते हैं।	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 41 के अनुसार, कंपनी (ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीदें जारी करना) नियम, 2014, डिपॉजिटरी रसीद योजना, 2014, भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना 15 दिसंबर, 2014, केंद्र सरकार की अधिसूचनाएं 18 सितंबर, 2019 और 07 अक्टूबर, 2019। विदेशी शेयर बाजारों में भारतीय कंपनियों की लिस्टिंग आसान करने के लिए।
15 अक्टूबर 2019	विभिन्न बाजार सहभागियों के लिए साइबर सुरक्षा और साइबर आघात-सहनीयता ढांचा: केआरए, आरटीए और स्टॉकब्रोकर्स जैसे बाजार प्रतिभागी केवाईसी रिकॉर्ड बनाए रखने और प्रतिभूतियों को रखने के कुछ महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। सेबी ने साइबर आघात-सहनीयता ढांचा निर्धारित किया है और बाजार सहभागियों को उसके कार्यान्वयन के लिए प्रणाली लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु निर्देश दिए हैं।	डाटा की शुचिता की रक्षा और निजता उल्लंघनों के खिलाफ सुरक्षा करना।
4 नवंबर 2019	सीआरए हेतु वर्धित मानदंड: सेबी ने अन्य बातों के साथ यह निर्धारित किया है कि सीआरए के एमडी/सीईओ अपनी रेटिंग समिति के सदस्य नहीं होंगे और रेटिंग समिति सीधे किसी मुख्य रेटिंग अधिकारी (सीआरओ) को रिपोर्ट करेगी। यह भी तय किया गया कि सीआरए बोर्ड दो समितियों का गठन करेगा-रेटिंग उप समिति एवं नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति और सीआरओ सीधे रेटिंग उप-समिति को रिपोर्ट करेंगे।	सीआरए गवर्नेंस और जवाबदेही को बढ़ाने के लिए।

दिनांक	नीतिगत उपाय	नीतिगत तर्क
7 नवंबर 2019	अनरेटेड कर्ज या मुद्रा बाजार लिखतों के अलग पोर्टफोलियो का निर्माण: कोई रेटेड कर्ज या मुद्रा बाजार लिखत बकाया नहीं रखने वाले जारीकर्ता को सेबी ने म्यूचुअल फंड योजनाओं द्वारा अनरेटेड कर्ज या मुद्रा बाजार लिखतों की अलग पोर्टफोलियो बनाने की अनुमति दी है।	क्रेडिट इवेंट के मामलों में सभी निवेशकों का उचित व्यवहार सुनिश्चित करने और चलनिधि जोखिमों से निपटने के लिए।
8 नवंबर 2019	सह-संबद्ध इक्विटी सूचकांकों में स्थिति प्रतितुलन के लिए क्रॉस-मार्जिनिंग सुविधा की शुरुआत	बाजार सहभागियों द्वारा जमानत के कुशल उपयोग को सुगम बनाने के लिए, कुछ शर्तों के अधीन अत्यधिक सह-संबद्ध इक्विटी सूचकांकों में स्थिति प्रतितुलन पर क्रॉस मार्जिनिंग सुविधा का विस्तार करने का निर्णय लिया गया था।
15 नवंबर 2019	ग्राहकों के डीमैट खातों को विशिष्ट ग्राहक कोड (यूसीसी) से जोड़ना।	स्टॉक ब्रोकरों द्वारा ग्राहकों की प्रतिभूतियों के डायवर्जन/धांधली का पता लगाने के लिए सेबी ने एक पूर्व चेतावनी तंत्र तैयार किया है। सुगम और आसान समाधान के लिए, ग्राहकों के यूसीसी को उनके डीमैट खातों के साथ जोड़ना आवश्यक माना गया था।
19 नवंबर 2019	नकदी खंड में ट्रेडिंग सदस्य (टीएम)/समाशोधन सदस्य (सीएम) द्वारा मार्जिन की उगाही और रिपोर्टिंग: सेबी ने तय किया है कि टीएमएस/सीएम नकदी खंड में अनिवार्य रूप से अपने ग्राहकों से प्रारंभिक वीएआर मार्जिन और अधिकतम हानि मार्जिन (ईएलएम) की उगाही करेंगे।	नकदी और व्युत्पन्नी दोनों खंडों के जोखिम प्रबंधन ढांचे को संरक्षित और सुव्यवस्थित करने के लिए
29 नवंबर 2019	डेट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ईटीएफ) /इंडेक्स फंड्स के लिए मानदंड: सेबी ने सभी डेट ईटीएफ और इंडेक्स फंड (केवल डेट ईटीएफ/जी-सेक, टी-बिल त्रिपक्षीय रेपो को छोड़कर) पर लागू मानदंड तय किए हैं। परिपत्र में अन्य विषयों के साथ सह सूचकांक में जारीकर्ताओं की न्यूनतम संख्या, जारीकर्ता का अधिकतम भारांक, घटकों की रेटिंग और सूचकांक में अनिवार्य डेट प्रतिभूतियों की प्रतिकृति पर मानदंड निर्धारित किए गए हैं।	प्रतिभूति बाजार में निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए।
3 जनवरी 2020	समाशोधन निगमों के डिफॉल्ट वॉटफाल में एक गैर-चूककर्ता सदस्य द्वारा योगदान।	सेबी ने कोर एसजीएफ के उपयोग की स्थिति में गैर-चूककर्ता सदस्यों द्वारा एक उच्चतम अतिरिक्त योगदान से संबंधित परिचालन मानदंड निर्धारित किए।

दिनांक	नीतिगत उपाय	नीतिगत तर्क
3 जनवरी 2020	जारीकर्ताओं को गैर-सहयोग (आईएनसी) रेटिंग के संबंध में रेटिंग प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए, यह निर्धारित किया गया था कि यदि किसी जारीकर्ता के पास 6 महीने से अधिक समय के लिए सभी बकाया रेटिंग गैर-सहयोगी के रूप में है, तो सीआरए ऐसे जारीकर्ता के लिखतों को आईएनसी स्थिति के साथ गैर-निवेश ग्रेड की रेटिंग तक डाउनग्रेड करेगा। यदि गैर-निवेश ग्रेड तक डाउनग्रेड होने की तारीख से जारीकर्ता द्वारा अगले तक 6 महीने तक असहयोग जारी रहता है तो कोई भी सीआरए ऐसे जारीकर्ता को तब तक कोई नई रेटिंग प्रदान नहीं करेगा जब तक कि जारीकर्ता सहयोग करना शुरू नहीं करता अथवा रेटिंग वापस नहीं ले ली जाती।	'जारीकर्ता सहयोग नहीं करता' (आईएनसी) रेटिंग के संबंध में सीआरए की रेटिंग प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए।
16 जनवरी 2020	'माल में ऑप्शन' की शुरुआत।	स्टॉक एक्सचेंजों को अब अपने कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट में 'माल में ऑप्शन' आरंभ करने की अनुमति है। सेबी ने इस तरह के ट्रेडिंग के लिए अपनाए जाने वाले उत्पाद डिजाइन और जोखिम प्रबंधन ढांचा के संबंध में जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए।
27 जनवरी 2020	कमोडिटी व्युत्पन्नी खंड के लिए मार्जिन ढांचा की समीक्षा: विभिन्न कमोडिटी व्युत्पन्नी के बीच चलनिधि में व्यापक भिन्नता और अस्थिरता के मद्देनजर, वस्तुओं को उनकी ज्ञात अस्थिरता और प्रारंभिक मार्जिन (आईएम) के न्यूनतम कीमत के अनुसार वर्गीकृत किया गया था और उनकी श्रेणियों के आधार पर जोखिम की मार्जिन अवधि (एमपीआरई) निर्धारित की गई है।	कमोडिटी डेरिवेटिव खंड में जोखिम प्रबंधन ढांचा को बढ़ाना।
24 फरवरी 2020	नकदी और व्युत्पन्नी खंड (कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट को छोड़कर) के लिए मार्जिन ढांचा की व्यापक समीक्षा की गई है।	जोखिम प्रबंधन ढांचे में अधिक दक्षता लाने के लिए।
25 फरवरी 2020	डिपॉजिटरी प्रणाली में गिरवी/पुनः-गिरवी के माध्यम से दिए जाने वाले मार्जिन बाध्यता: सेबी ने निर्धारित किया कि ट्रेडिंग सदस्य (टीएम)/समाशोधन सदस्य (सीएम) केवल मार्जिन गिरवी के माध्यम से जमानत के रूप में ग्राहकों से प्रतिभूतियों को स्वीकार करेगा। इसके अलावा, मार्जिन प्रयोजनों के लिए टीएम/सीएम के डीमैट खाते में प्रतिभूतियों का अंतरण (अर्थात स्वामित्व अंतरण संपार्श्विक व्यवस्था) निषिद्ध है।	एक ऐसा ढांचा तैयार करने के लिए जो ट्रेडिंग सदस्य (टीएम)/समाशोधन सदस्य (सीएम)/डिपॉजिटरी सहभागी (डीपी) के पास ग्राहकों की उपलब्ध प्रतिभूतियों के दुर्विनियोजन या दुरुपयोग के जोखिमों को कम करता है।

दिनांक	नीतिगत उपाय	नीतिगत तर्क
26 फरवरी 2020	स्टॉक एक्सचेंज इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से म्यूचुअल फंड योजनाओं में लेनदेन की सुविधा।	स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म की पहुंच बढ़ाने के लिए म्यूचुअल फंड/आस्ति प्रबंधन कंपनियों से सीधे म्यूचुअल फंड इकाइयों की खरीद और मोचन के लिए निवेशकों को मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के बुनियादी ढांचे तक सीधे पहुंचने की अनुमति है।

3. भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण

दिनांक	उपाय	तर्क/उद्देश्य
21 जनवरी 2020	आईएफआरएस का कार्यान्वयन: इंड-एस 109 और आईएनपीआरएस 17 के इंड-एस समकक्ष को अन्य सभी लागू मानकों के साथ-साथ लागू किया जाएगा। कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख आईएसबी द्वारा आईएफआरएस 17 को अंतिम रूप देने के बाद तय की जाएगी।	आईएफआरएस 17 के समकक्ष के कार्यान्वयन से पहले इंड-एस 109 को लागू करने के कारण परिसंपत्ति-देयता बेमेल होने के कारण वित्तीय विवरणियों में अस्थिरता से बचने के लिए।
28 जनवरी 2020	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय पर समूह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर दिशानिर्देश: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय के परिणामस्वरूप, सभी साधारण बीमा कंपनियों, स्वास्थ्य बीमा कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को एक परिपत्र जारी किया गया था। दिशा-निर्देशों में यह निर्दिष्ट किया गया है कि एक समूह आयोजक की हैसियत से एक बैंक अपने ग्राहकों की बीमा जरूरतों को पूरा करने के लिए कितनी भी बीमा कंपनियों के साथ समूह बीमा की व्यवस्था कर सकता है।	समूह बीमा पॉलिसियों का सुचारु परिवर्तन सुनिश्चित करने और विलय किए गए बैंकों के पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा के लिए।

4. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

दिनांक	उपाय	तर्क/उद्देश्य
1 नवंबर 2019	एनपीएस में ऑनलाइन शामिल होने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर और बैंक खाता सत्यापन हेतु सिक्का डालो प्रक्रिया।	वित्तीय सेवाओं के ऑनलाइन वितरण में तकनीकी नवाचारों और विकास को ध्यान में रखते हुए, ग्राहक के हितों में, यह निर्णय लिया गया है कि पीओपी को 'सिक्का डालो प्रक्रिया' के माध्यम से आवेदकों के बैंक खातों को सत्यापित करने की अनुमति दी जाए जिसमें उपलब्ध कराए गए खाते में पीओपी द्वारा नाममात्र राशि यथा रूप 1 अंतरित की जाएगी और अंतरीति बैंक से इसकी पुष्टि के साथ-साथ आवेदक का विवरण भी प्राप्त होगा। सीआरए के साथ ग्राहकों के बैंक खाते के विवरण को बदलने के लिए पीओपी द्वारा यह सुविधा प्रदान की जा सकती है।

दिनांक	उपाय	तर्क/उद्देश्य
21 नवंबर 2019	एनपीएस योजनाओं के लिए निवेश दिशानिर्देशों में बदलाव: पेंशन निधि को एक दिवसीय निधि और ऐसे सभी अल्पावधि निधियों में निवेश करने की अनुमति देना जिसकी अनुमति सेबी द्वारा समय-समय पर दी जा सकती है।	प्राधिकरण द्वारा एनपीएस योजना के लिए जारी निवेश संबंधी दिशा-निर्देशों में "अल्पावधि कर्ज लिखत एवं संबद्ध लिखतों" की श्रेणी के तहत प्राधिकरण ने पेंशन निधि को एक दिवसीय निधि और इस तरह के सभी अवधि के निधि में निवेश करने की अनुमति देने का फैसला किया है, अल्पावधि निवेश हेतु समय-समय पर जिसकी अनुमति सेबी द्वारा अधिशेष निधि के निवेश हेतु दी जाए।
21 नवंबर 2019	एनपीएस योजनाओं और पीएफआरडीए द्वारा प्रशासित अन्य पेंशन योजनाओं के तहत प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के लिए संशोधित मूल्यांकन दिशानिर्देश।	प्राधिकरण ने पीएफआरडीए द्वारा एनपीएस और अन्य प्रशासित योजनाओं के तहत प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के लिए संशोधित मूल्यांकन दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश सभी परिसंपत्ति प्रकार में प्रतिभूतियों के लिए मूल्यांकन के लिए मार्गदर्शन प्रणाली प्रदान करते हैं और विशेष रूप से कॉरपोरेट कर्ज के लिए जहां मूल्यांकन पद्धति को मैट्रिक्स स्तर मूल्यांकन से स्क्रिप स्तर मूल्यांकन में बदल दिया गया है।
2 दिसंबर 2019	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2019 ।	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत सेवानिवृत्ति सलाहकार के रूप में पंजीकरण करने के लिए सीएफपी प्रमाणित पेशवरों को दी गई छूट को समाप्त के लिए पीएफआरडीए (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016 के विनियम 7 के उप-विनियम (बी) के परंतुक (ii) को हटा दिया गया है।
17 दिसंबर 2019	स्पष्टीकरण: एनपीएस में भारत के प्रवासी नागरिकों (ओसीआईएस) का नामांकन ।	इस परिपत्र के जरिए यह स्पष्ट किया गया है कि एनपीएस द्वारा एनआरआई और ओसीआईएस को देय वार्षिकी पर उस देश में डीटीए (दोहरा कराधान अपवंचन समझौते) के अनुसार लागू दरों पर स्रोत पर कर लगाया जाएगा जहां वार्षिकी-ग्राही रहता है ।
4 फरवरी 2020	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2020 ।	पेंशन फंडों की पात्रता और पंजीकरण को प्रभावित करते हुए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे, जैसे पेंशन फंडों की धनात्मक मूर्त निवल मालियत मौजूदा पच्चीस करोड़ रुपये से बढ़ाकर पचास करोड़ रुपये कर दी गई है, किसी विदेशी कंपनी द्वारा इक्विटी शेयरों की कुल होल्डिंग को स्वयं या उसकी सहायक कंपनियों द्वारा पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 और बीमा कानून संशोधन अधिनियम, 2015 के अनुरूप बढ़ाकर उनचास प्रतिशत तक कर दिया गया है और पेंशन निधियों के लिए निरंतर पंजीकरण की अनुमति दी गई है।

दिनांक	उपाय	तर्क/उद्देश्य
19 फरवरी 2020	एनपीएस-लाइट अभिदाता के लिए ऑनलाइन अंशदान की सुविधा में बढ़ोतरी।	डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और एनपीएस-लाइट की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए, वैध पंजीकृत मोबाइल नंबरों के साथ इसके ग्राहक एक निर्दिष्ट लिंक के माध्यम से अपने एनपीएस-लाइट खातों में अंशदान कर सकते हैं। जिन अभिदाताओं के पास पंजीकृत मोबाइल नंबर नहीं है, वे अपने पीओपी (तत्कालीन एग्रीगेटर) को अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं।

5. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई)

दिनांक	उपाय	तर्क/उद्देश्य
15 नवंबर 2019	केंद्र सरकार ने दिवाला और शोधन अक्षमता (वित्तीय सेवा प्रदाताओं की दिवाला और समापन कार्यवाहियां तथा न्यायनिर्णयन प्राधिकरण को आवेदन) नियम, 2019 को अधिसूचित किया।	यह नियम बैंकों के अलावा अन्य प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय सेवा प्रदाताओं (एफएसपी) की दिवाला और समापन कार्यवाहियों के लिए एक सामान्य ढांचा प्रदान करता है। अंतिम लेखापरीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक के परिसंपत्ति आकार वाली गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (जिनमें आवास वित्त कंपनियां शामिल हैं) का दिवाला समाधान और समापन इस ढांचे के अनुसार की जाएगी।
22 नवंबर 2019	आईबीबीआई ने आईबीबीआई (निगमित ऋणियों के व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2019 (दिवाला विनियम) और आईबीबीआई (निगमित ऋणियों के व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं के लिए शोधन अक्षमता प्रक्रिया) विनियम, 2019 (शोधन विनियम) को अधिसूचित किया।	दिवाला विनियम में कॉरपोरेट देनदारों के व्यक्तिगत गारंटीकर्ताओं के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया का विस्तृत विवरण दिया गया है।
28 नवंबर 2019	आईबीबीआई ने आईबीबीआई (निगमित व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2019 को अधिसूचित किया।	सीआईआरपी और आईपीएस के संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही के हित में, और आईबीबीआई, आईपीए और आईपीएस को अपने सांविधिक दायित्वों का निर्वहन करने की सुविधा देने के लिए, संशोधन विनियमों के अनुसार आईपीएस को सीआईआरपी के जीवन चक्र को शामिल करते हुए प्रपत्र का एक सेट तैयार कर इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म आईबीबीआई की वेबसाइट https://www.ibbi.gov.in पर ऑनलाइन दायर करने की आवश्यकता होती है।

दिनांक	उपाय	तर्क/उद्देश्य
28 दिसंबर 2019	<p>दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (शोधन) अधिनियम, 2020 में निम्नलिखित प्रमुख संशोधनों को लागू किया गया:</p> <p>(1) अंतरिम वित्त</p> <p>(2) सीआईआरपी का प्रवर्तन</p> <p>(3) अधिस्थगन</p> <p>(4) पूर्व अपराधों के लिए देयता तथा एफएसपी का समाधान</p>	<p>यह अध्यादेश कुछ संशयों को दूर करने और संहिता के तहत प्रक्रियाओं के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रख्यापित किया गया था।</p>
21 मार्च 2020	<p>सरकार ने अधिसूचित किया कि एक आईआरपी/आईपी, अपने नियोजन की तिथि से कॉरपोरेट देनदार से एक अलग व्यक्ति के रूप में माना जाएगा और प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत 30 दिनों के भीतर एक नया पंजीकरण लेने के लिए उत्तरदायी होगा, जहां कॉरपोरेट देनदार नियोजन से पहले पंजीकृत किया गया था।</p>	<p>यह आईबीसी के तहत समाधान के दौर से गुजर रही कंपनियों को पिछले बकाए के अनिवार्य भुगतान किए बिना जीएसटी के वर्तमान प्रभार के भुगतान की अनुमति देता है।</p>